

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21, 1976 (फाल्गुन 2, 1897)

No. 81

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21, 1976 (PHALGUNA 2, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग Ш-खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सिम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

स्टेट बैंक श्राफ इंडिया स्थानीय प्रधान कार्यालय

स्चना

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जनवरी 1976

सं० — श्री एव० एस० गुप्ता, स्टाफ श्रीध-कारी श्रेणी III, जो कि 29 दिसम्बर, 1975 से 44 दिन के ग्रवकाण पर गये हैं के स्थान पर श्री आर० एन० श्रीवास्तव, स्टाफ श्रीधकारी श्रेणी III, प्रक्षेत्र संदर्शन ग्रीध-कारी क्षेत्र , प्रशासनिक ग्रीधकारी (ऋण) का कार्यभार संभालेंगे।

कार्यालय प्रबन्धक

भारतीय स्टेट बैंक केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 2 जनवरी 1976

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्तलिखित नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है:----

श्री एस० बाश्यम को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 1 जनवरी, 1976 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

1-469G1/75

20 जनवरी 1976

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित नियुक्ति की प्रधिमूचना दी जाती है:---

श्री एच० एन० पुरी को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में दिनांक 19 जनवरी, 1976 से उप शाखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

> टी० प्रार० वरदाचारी, प्रबन्ध निदेशक

स्टेट बैंक श्राफ़ पटियाला पटियाला, दिनांक । नवम्बर 1975

सं० एम० बी० थो० पी० 62—इस नोटिस द्वारा बैंक के निम्नलिखित ग्रीधकारियों के स्थानान्तरण एवं परि-वर्तन की सूचना दी जाती है:—

1. श्री इन्द्र भूषण गुप्ता, श्राफिसर ग्रेड तिथि 24-10-1975 को बैंक का कार्य श्राएम्स होने के समय से दश्या गंज देहली भाषा के मैंनेजर होंगे।

> एस० डी० गंडा प्रबन्ध निदेशक

(1065)

स्टेट बैंक ग्राफ सौराष्ट्र

भावनगर, दिनांक 30 जनवरी 1976

सं० 1/76—निम्नलिखित बैंक कर्मचारियों के नियुक्ति संबक्षित स्थानान्तरण एवं परिवर्तन के विषय में श्रीधमूचित किया जाता है कि श्री जी० श्रीधरन्, श्रीधकारी ग्रेष्ठ I ने श्री बी० एन० परीष्ठा के स्थान पर मद्रास शाखा का श्रस्थायी कार्यभार दिनांक 17 मई, 1975 के कार्योपरांत काल से दिनांक 16 जून, 1975 के कार्यारंभ काल तिक संभाला।

श्री ए० ए० किडवाई, श्रिधिकारी ग्रेड I ने श्री एल० श्रार० ग्ररोरा, ग्रिधिकारी ग्रेड I के स्थान पर कानपूर शाखा का ग्रस्थायी कार्यभार दिनांक 3 मई, 1975 के कार्या-परांत काल से संभाला।

श्री ए० एम० नायक, श्रिधकारी ग्रेड I ने श्री बी० श्रार० देसाई, श्रिधकारी ग्रेड ए० के स्थान पर फोर्ट, बम्बई शाखा का अस्थायी कार्यभार दिनांक 2 जून, 1975 के कार्योपरांत कालसे दिनांक 14 जून, 1975 के कार्यारंभ काल तक संभाला।

श्री श्रभिराम साहू, श्रधिकारी ग्रेड I ने श्री बी० जी० डांगे, श्रधिकारी ग्रेड ए० स्थाम पर हैदराबाद शाखा का ग्रस्थायी कार्यभार दिनांक 3 सितंबर, 1975 के कार्योपरांत काल से दिनांक 15 सितंबर, 1975 के कार्यारंभ काल तक संभाला।

> बीं ० एस ० नवाथे, प्रबंध निदेशक

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1976

सं० 5 सी० ए०(1)/21/75-76:---- इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4 सी०ए०(1)/22/71-72 दिनांक 1-7-71 के सन्दर्भ में चार्टण प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त श्रिधकारों को प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रिजस्टर में निम्नलिखित सदस्य का नाम पुनः स्थापित कर दिया है

ऋ० सं०	स॰सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	11627	श्री नित्यानन्द पाटक, ए० सी० ए० डोडोसा रीजनल ट्रेनींग कम्पनी लिमिटेड, पो० बा० 971, डोडोमा,तानजानिया।	24-12-75

दिनांक 24 जनवरी 1976

सं० 4 सीं०ए०(1)/14/75-76—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण में एतत् हारा यह सूचित कथा जाता है कि चार्टर प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा 1 (क) हारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुय भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रिजस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है:—

ऋ० सं०	स०सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	1948	श्री वीं० एस० काबरा, लक्ष्मी भवन, बिरहाना रोड, कानपूर ।	6-1-1976
2.	6957	श्री झी० मिसकयूत्थ, 6, म.रीया मेनसन, सी० टी० एस० रोड, कलीना वम्बई-29।	6-7-1975

सं० 8 सीं० ए०(1)/18/75-76—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10(1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतत् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रेक्टिस प्रमाण-पन्न उनके नामों के श्रागे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये है क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण-पन्नों को रखने के इच्छक नहीं:—

茶の	सं० स०सं०	नाम एवं पता	নি খি
1.	3101	श्री एस० भ्रार० तमाने, ए० सी० ए०, "सरवोदया", रानाडे रोड, भिवाजी पार्क, दादर, बम्बई-400028।	1-1-1976
2.	8823	श्री बी० के० सिगानीया, एफ० सी० ए०, 8, रामानन्द चैटरजी स्ट्रीट, कलकत्ता-70009।	1-1-1976
3.	16493	श्री जै० एम० खनना, ए० सी० ए०, बी०-3/19, कृष्णा नगर, देहली।	25-8-1975

दिनांक 27 जनवरी 1976

सं० 5 सी० ए० (1) / 22 / 75-76—इस स्थान की अधिसूचना सं० 4 सी० ए० (1) / 21 / 74-75 दिनांक 4 फरवरी, 1975 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1974 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रिजस्टर में निम्नलिखित सदस्य का नाम पुनः स्थापित कर दिया है:

ऋ० सं०	स०सं०	नाम एवं पता	तिथि
1	15548	श्री जतन राज गुलेचा, ए० सी० ए०, के० ग्रा० गीता श्राइस्न, बाजुवा, डिस्ट्रिक बड़ोदा, (गुजरात)	29-12-75

दिनांक जनवरी 1976

सं० 13 परीक्षा (1) एम०/76—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगु-लेशन्स, 1964 के रेगुलेशन 20 के अनुसरण में दि कोंसिल आफ दि इन्स्टीन्यूट श्राफ चार्ट्ड एक्काउन्टेन्ट्स श्राफ इण्डिया की यह नोटिफाई कराने में प्रसन्नता है कि उपर्युक्त रेगुलेशन के अन्तर्गत इंटर्नेस परीक्षा 3, 4, 5 और 6 मई 1976 को, पुराने पाठ्यक्रम में इन्टरमीडिएट परीक्षा 3, 4, 5, 6, 7, श्रीर 8 मई 1976 इन्टरमीडिएट परीक्षा नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 3, 4, 5, 6, 7, 8 श्रीर 10 मई 1976 श्रीर फाइनल परीक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 श्रीर 11 मई 1976 को होगी। परीक्षाएं निम्नलिखित केन्द्रों पर होंगी बगर्ते कि प्रत्येक केन्द्र परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी उपस्थित होते हैं :---

ज्याचा जगरनल हाल है :	
1. ग्रागरा	2. श्रहमदाबाद
3. इलाहाबाद	4. बंगलौर
5. बड़ीदा	6. बैलगांव
7. बम्बई	8. कलकत्ता
9. चन्डीगढ़	10. कोयम्बटूर
11. दिल्ली	12. इर्नाकुलम
13. गोहाटी	14. हैदराबाद
 इन्दौर 	16. जयपु र
17. जोधपुर	18. कानपुर
19. लुधियाना	20. मद्रास
21. मदुराई	22. मंगलौर
23. मेंसूर	24. नागपुर
25. पटना	26. पूना
27. राजकोट	28. ज्ञिवेन्द्रम
29. उदयपुर	30. विशाखापटनम
31. विजयकाडा	

इन परीक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन निर्धारित फ़ामों पर करना अपेक्षित है, जिसकी प्रतियां कोंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स आफ इंडिया , पोस्ट बाक्स नं० 268 इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-1 से प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्नों तथा नई दिल्ली में भुगतान योग्य एवं उपर्युक्त सचिव के पक्ष में देय परीक्षा शुल्क के लिए एक डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा भारतीय शुल्क के लिए एक डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा भारतीय पोस्टल आडर इन्टरैन्स परीक्षा के लिए ६० 60/इंटरमीडिएट परीक्षा पुराने पाठ्यक्रम में होने के लिए ६० 75/न तथा दोनों ग्रुपों में प्रवेश के लिए ६० 80/- अथवा फाइनल परीक्षा के केवल एक ग्रुप में प्रवेश के लिए ६० 55/के साथ इस प्रकार भेजना आवश्यक है कि कोंसिल के सचिव के पास 3 मई 1976 तक पहुंच जायें।

दिनांक 31 जनवरी 1976 (चार्ट्ड एक्काउन्टैट्स)

सं० 20-पी० जी० (परीक्षा)/एम० 76---चार्टर्ड एक्का उन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1964 के विनियम 179 की अनुसूचित 'सी०' के पैरा-ग्राफ 5 के अनुसरण में दि कोसिल भ्राफ दि इंस्टीट्यूट भ्राफ चार्टर्ड एक्का उन्टेन्ट्स भ्रोफ इण्डिया को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता है कि उपर्युक्त नियमों की श्राधीन मैनिजमेन्ट एका उन्टेन्सी कोर्स पार्ट I की एक परीक्षा 3, 4, 5 श्रौर 6 मई 1976 को होगी। परीक्षा निम्नलिखित स्थानों पर होगी।

	·		
1	भ्रागरा	2.	ग्रहमदाबाद
3.	इलाहाबाद	4.	बैंगलोर
5.	बड़ीदा	6.	बैलगांव
7.	बम्बई	8.	कलकत्ता
9.	चण्डीगढ़	10.	कौयम्बटूर
11.	दिल्ली	12.	इनकुलम
13.	गोहाटी	14.	हैदराबाद
15.	इन्दौर	16.	जयपुर
17.	जोधपुर	18.	कानपुर
19.	लुधियाना	20.	मद्रास
21.	मदुराई	22.	मंगलौर
23.	मैसूर	24.	नागपुर
25.	पटना	26.	षूना
27.	राजकोटा	28.	स्रिवेन्द्रम
29.	उदयपुर	30.	विषाखापटनम

परीक्षा के प्रवेश के लिए आवेदन पन्न निर्धारित पन्न में भरना होगा जिसकी प्रतियां सचिव दि कोंसिल आफ दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया, पोस्ट बाक्स नं० 268, इन्ब्राप्रस्था मार्ग, नई दिल्ली-1 से प्राप्त किये जा सकते हैं। इस प्रकार का प्रत्येक आवेदन पन्न आवश्यक दस्तावेज प्रमाण और सचिव के नाम में देय और नई दिल्ली में भुगतानयोग्य ६० 100/- के डिमाण्ड ड्रापट

31. विजयवाडा

के साथ इस प्रकार भेजा जाये तो उनके पास ग्राधिकतम 3 मार्च 1976 तक ग्रावश्य ही पहुंच जाये।

दिनांक 9 फरवरी 1976

चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस

सं० 1-सी० ए० (87) 75---चार्टर्ड एक्काउन्टेन्ट्स ऐक्ट, 1949 (1949 का 38वां) की धारा 30 की उपधारा (1) के ग्रधीन प्रदत्त ग्रधिकारों का प्रयोग करते हुए कौंसिल श्राफ दि इन्स्टीट्यूट श्राफ चार्ट्ड एक्काउन्टेन्ट्स श्राफ इंडिया ने चार्टर्ड एक्काउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1964 में निम्नलिखित संशोधन किये जो पहले हीं प्रकाशित ग्रौर केन्द्रीय सरकार हारा ग्रनुमोदित किये जा चुके हैं जैसा कि उपर्युक्त धारा की उपधारा (3) के अंतर्गत ग्रपेक्षित था।

उपर्यक्त रेगुलेशन में :---

(1) रेगुलेशन 63 के उप-रेगुलेशन (1) में "छः सौ" शब्द के स्थान पर "सात सौ" शब्द बदल दें। (II) रेगुलेशन 112 के उप-रेगुलेशन (4) में "तीन सी" शब्द के स्थान पर "साढ़ें तीन सौ" शब्द बदल दें।

पी० एस० गोपालकृष्णन, सचिव ।

दि इन्स्टीट्यूट श्राफ कांस्ट आन्ड वर्क्स एक्काउन्टेन्ट्स ग्राफ इंडिया

कलकत्ता, दिनांक 14 जनवरी 1976 (कांस्ट एक्काउन्टेन्ट्स)

सं० 18 सी० डब्ल्यू० आरं० (24)/76—दी कांस्ट् फ्रान्ड वर्क्स एक्काउन्टेन्टस रेग्युलेशन्स 1959 के विनियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टिट्यूट श्राफ कांस्ट आन्ड वर्क्स एक्काउन्टेन्टस आफ इंडिया के परिषद् ने कहे गये रेग्युलेशन्स के विनियम 17 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री भी० जगन्नाथन् वी० काम०, वी० एल० एम० वी० ए०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, चीफ एक्काउन्टान्ट्स, माडल, नेवरहु।, इगएवुज, प्रोग्नामस इन्स, 4707, उडवर्ड एभन्यू छेटाय्ट एम०, 148201 यू० एस० ए० (सदस्यता संख्या 1721) का नाम सदस्य पंजिका में पुन: स्थापित किया गया।

एस० एन० घोष, सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 1976

सं० एन० 17/13/76-पी० एण्ड डी० (5)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महा निदेशक ने यह निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'क' 'ख' तथा 'ग' के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ श्रवधियां नियत दिवस 31 जनवरी, 1976 की मध्य रावि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए प्रारम्भ व समाप्त होंगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :---

	प्रथम ग्रंश	दान श्रवधि	प्रथम लाभ अवधि			
वर्ग	जिस मध्य रावि जिस मध्य रावि को प्रारम्भ होती को समाप्त होती है है		जिस मध्य राह्री को जिस मध्य राह्री प्रारम्भ होती है। समाप्त होती है			
क	31-1-1976	31-7-1976	30-10-1976	30-4-1977		
ख	31-1-1976	27-3-1976	30-10-1976	25-12-1976		
ग्	31-1-1976	29-5-1976	30-10-1976	26-2-1977		

श्रनुसूची :---

फकीर चन्द, निदेशक (योजना एवं विकास)

^{&#}x27;'महाराष्ट्र राज्य में ओरंगाबाद जिले के श्रौद्योगिक नगर चिखलथाना में समाविष्ट क्षेत्र'' ।

कृषि पुनिंबत निगम

बम्बई, दिनांक श्रक्तूबर 1975

सं० जी० एस० म्रार०—कृषि पुनर्वित्त निगम म्रिधिनियम, 1963(1963 का 10) की धारा 32(2) के म्रनुसरण में 30 जून, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के कामकाज के बारे में बोर्ड की रिपोर्ट म्रीर 30 जून, 1975 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम का तुलन-पत्न म्रीर लाभ-हानि लेखा नीचे प्रकाशित किये जाते हैं :——

कृ०पु० निगम एक दृष्टि में

(लाख रुपयों में)

	 30 जून को समाप्त हुए वर्ष को			 उपयोग				
स्रोत								
	1973	1974	1975		1973	1974	1975	
चुकता शेयर प्ंजी श्रौर श्रारक्षित राशियां उधार	1082	1650	2272	प्रदान किया गया पुन वित्तः (बकाया)	-			
भारत सरकार से लिये गये उधार (जिसमें से ग्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (ग्राईडीए)/ ग्रंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमीण ग्रीर विकास बैंक (ग्राईबीग्रारडी)	12485	16350	19662	राज्य भूमि विकास बैंक	19560	27151	34382*	
की सहायता का ग्रंश) भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार दीर्घ-	(4521)	(8386)	(11698)	जिसमें से श्रं वि संघ (परियोजनाम्रों के श्रधीन प्राप्त)	(6877)	(11984)	(16756)	
कालीन प्रवर्तन निधि	3450	5400	8820	अनुसूचित वाणिज्य बैं क	1111	2708	5150	
ग्रत्पकालीन	370	1160	450	(जिसमें ग्रं वि संघ/ ग्रंपु वि बैंक की परि- योजनाग्रों के ग्रधीन	,			
खुले बाजार से लिये गये				प्राप्त)	(105)	(433)	(1388)	
ज्ञारसालय गय	3871	6621	9921	राज्य सहकारी बैंक	944	1115	1154	

स्थापना से लेकर ग्रब तक का विकास

(लाख रुपयों में)

जून के भ्रंत की स्थिति	1964	1965	1966	1967	1968
 शेयर पूंजी श्रौर श्रारक्षित राशियाँ	500	500	500	500	500
विशेष जमा राणियाँ		1 1	24	36	49
राजकीय सहायता ऋण उधार :	3	5	11	12	14
(1) भारत सरकार से .	500	500	500	500	800
(2) भारतीय रिजर्व बैंक से .			-		
(i) घ्रल्पावधि .					
(ii) दीर्घाविध .					
(3) बांड ग्रौर डिबेंचर .दिया गया पुनर्वित्त			,		
(ঘুৱ)		45	490	697	1263
(i) डिबेंचर .		45	475	667	1190
(ii) ऋण		_	15	30	73
भ्रन्य भ्रास्तियां	205	5	12	22	51
निवेश भौर नकदी स्रारक्षित राशियां	820	992	552	358	85
सकल भ्राय	37	40	43	50	60
कराधान के पहले लाभ .	35	36	39	44	43
देय कर	18	18	23	24	24
कराधान के बाद लाभ	17	18	16	20	19
भ्रदा किया गया लाभांश .	21	21	21	21	21

1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969
2272	1650	1082	1044	523	509	500
179	141	117	99	87	74	61
		14	14	14	14	14
19662	16350	12485	7713	6675	4475	2575
9270	6560	3820	839	752		
450	1160	370	339	752		
8820	5400	3450	500			
9921	6621	3871	2771	1946	1094	
40686	30974	21614	12341	8893	5889	3040
34382*	27151	19560	10964	8124	5460	2785
6304	3823	2054	1377	769	429	255
1417	929	632	360	258	159	122
26	8	4	2	1003	250	52
2214	1553	924	606	427	273	110
442	309	171	109	69	67	48
231	160	89	58	34	37	26
211	149	81	5 1	35	30	22
89	66	44	31	21	21	21

^{*}इसमें 68. 40 लाख रुपयों का वितरण शामिल है। इसके लिए 30 जून, 1975 के बाद डिबेंचर जारी किये गये थे।

सारणी 1

पुनर्वित्त का प्रयोजनवार वितरण

0 0 0	~	_	• -
निम्नलिखित	TOT	क	दोरात
1 1. (1./(1./4/21	7.71		4. /

(लाख स्पये)

प्रयोजन	30 जून निम्नलिखित वर्षों के दौरान							जोड़ २० 	
	1968 तक		1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	· 30 जून 1975 तक
लघु सिंचाई	129	1154 (64.7)		2306 (75.3)	2674 (76.4)			8378 (78.7)	33822 (79.9)
भूमि विकास तथा भूमि संरक्षण	1012 (80.0)				237 (6.8)		178 (1.8)	201 (1.9)	3003
कृषि मशीनीकरण		11 (0.6)	16 (0.6)		36 (1.0)			1223	1893 (4.5)
बागन भ्रौर बागवानी					205 (5.9)		219 (2.3)		1329 (3.1)
मुर्गीपालन भ्रौर भेड़पालन	 ()	1 (0.1)	6 (0.2)	()	<u> </u>	15 (0.2)	9 (0.1)	65 (0.6)	96 (0.2)
मछली पालन	20 (1,6)				59 (1.7)		86 (0.9)	178 (1.7)	464 (1.1)
डेरी विकास	()	 ()	()	()	39 (1.1)	26 (0.3)	82 (0.8)	158 (1.5)	305 (0.7)
भांडार सुविधायें/बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड)	 ()	100 (5.6)			248 (7.1)				
क्रुषि विमानन	 ()	 ()	 ()	 ()	()	()	12 (0,1)		12(0.1)
जोड़	1265	1784 (100.0)	2860 (100.0)	3062	3498 (100.0)	9414 (100.0)	9784 (100.0)	10640 (100.0)	42307 (100.0)

कोष्टकों में दिये गये ग्रांकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं।

सारणो 2

पुनिविस्त का एजेंसीबार वितरण निम्नलिखित वर्षों के दौरान

(लाख रुपये)

एजेंसी	30 जून		निम्नलिखित वर्षी के दौरान									
	1968 तक	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74		5 30 जून 1975 तक			
 राज्य भूमि विकास बैंक	1190	1595	2675	2665	2839	8614	7776	7706	35060			
	(94.1)	(89.4)	(93.5)	(87.0)	(81.2)	(91.5)	(79.5)	(72.4)	(82.9)			
जिसमें श्रं वि संघ की सहा-												
पता का श्रंम					537	6358	5292	5198	17385			
प्रनुसूचित वाणिज्य बैंक	5 5	53	56	278	326	449	1736	2787	5740			
	(4.3)	(3.0)	(2.0)	(9.1)	(9.3)	(4.8)	(17.7)	(26.2)	(13.6)			
जिसमें स्रंपुवि बैंक की	·			111	8	4	1	10	134			
महायता का श्रंश												
् जेसमें भ्रं वि संघ की सहा-						-	342	979	1321			
पताकाश्रंण			•									
राज्य सहकारी बैंक	20	136	129	119	333	351	272	147	1507			
	(1.6)	(7.6)	(4.5)	(3.9)	(9.5)	(3.7)	(2.8)	(1.4)	(3.5)			

कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं।

कृषि पूर्निवस निगम

बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट 1974-75

जुलाई 1974 से जून 1975 तक के वर्ष के दौरान निगम की पुनिविक्त सहायता का वितरण पहली बार 100 करोड़ रुपयों की राशि से अधिक होकर 106 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। (सारणी 1) पिछले वर्ष के दौरान कुल वितरण 98 करोड़ रुपये हुआ था जिसमें भिम विकास बैंकों के सामान्य कार्यक्रमों के अधीन दिये गये ऋणों में से अंतराष्ट्रीय विकास संघ (भ्रांविसंघ) की परियोजनाओं के लिए अंतरित 6 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस अंतरण को छोड़कर इस वर्ष के दौरान उक्त वितरण 15 प्रतिशत बढ़ गया है। प्रभाव की वर्तमान परिस्थितियों देश के बहुत से भागों में बिजली की कमी और अतिदेयों के संदर्भ में यह वितरण संतोषप्रद माना जा सकता है हालांकि यह पहले के निरूपित स्तरों तक नहीं पहुंच पाया है।

- 1. 2 निगम के प्रारंभ से लेकर ग्रब तक का कुल वितरण 423 करोड़ स्पयों से ग्रधिक हो गया है। ग्रं वि संग्र से सहायता प्राप्त योजनाओं के संबंध में निगम द्वारा किया गया वितरण 187 करोड़ रुपयों से ग्रधिक हो गया है जिसके फलस्वरूप करीब 1450 लाख डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। ग्रल्प विकसित क्षेत्रों में निगम के कार्यकलापों में निश्चित रूप से बृद्धि हुई है। निगम की गतिविधियां देश के प्राय: प्रत्येक जिले तक पहुंच गई हैं। निगम कम ग्रभिरुचि वाले क्षेत्रों में ग्रधिक विकासात्मक कार्य कर सका है। ग्रालोच्य वर्ष के दौरान श्रंपुवि वैंक/ग्रंवि संघ के साथ हुए चार विशिष्ट ऋण करारों के समझौते किये जाने के भ्रलावा, निगम ने ग्रंवि संघ से सामान्य ऋण प्रणाली प्राप्त की है जिससे कु० पु० निगम ग्रीर ग्रंवि संघ के बीच ग्रीर ग्रधिक गहरे सबंधों की स्थापना हुई है।
- 1.3 विगत तीन वर्षों के दौरान उन भ्रलग-भ्रलग राज्यों की स्थिति में काफी उलटफेर हुई है जिन्हें निगम के कुल वितरण का करीब 90 प्रतिशत वितरित किया गया है।

सारणी 3 निगमं से आहरित प्नर्विंदस की राणि के अनुसार राज्यों का श्रेणीकम

राज्य					- -	1972-73	1973-74	1974-75	संचयी जोड़*
उत्तर प्रदेश	•					1	1	1	1
महाराष्ट्र	•	•	•	٠,	, •	5	2.	2	2
तमिलनाडु						2	. 3	8	3
हरियाणा	•		•			4	5	4	4
कर्नाटक				-		7	4	5	5
मध्य प्रदे ण	•					9	. 7	3	6
गुजरात		-	2			3	6	9	7
ग्रांध्र प्रदेश	•	-				8	10	7	8
बिहार	•		•	•	•	10	8	6	9
पंजाब		•		•		6	9	10	10

^{*}यह तीन वर्ष की प्रविधः 1972–75 तक का संचयी <mark>जोड़ हैं। इसमें ''सामान्य'' कार्यक्रम से अंतरित राशियाँ</mark> शामिल नहीं हैं।

सारणी 4 पुर्निवत्त का राज्यवार वितरण

(लाख रुपयों में)

								(लाख	ारुपयों में)
			 निम्नलिखित	वर्षों के दौरा	न				जोड़
क्षेत्र/राज्य/संघणासित क्षेत्र	30 जून 1968 तक	1968-	1969-	1970- 71	1971- 72	1972-	1973- 74	1974- 75	~ 30 जून 1975 तक
1. उत्तरी क्षे स्र									
दिल्ली .	. -	 ;	6				7	12	2
			(0,2)				(0.1)	(0.1)	(0.1)
हरियाणा	59	244	263	362	326	1020	803	1075	415
	(4.7)	(13.7)	(9.2)	(11.8)	(9.3)	(10.8)	(8.2)	(10.1)	(9.8)
हिमाचल प्रदेश							4	4	
							(0.1)	(0.1)	(0.1)
जम्मू ग्रौर कश्मीर	11	21	20	11	7				7 1
	(0.9)	(1.2)	(0.7)	(0.4)	(0.2)				(0.1)
पंजाब	76	. 577	654	556	376	607	489	407	3751
	(5.0)	(32.3)	(22.9)	(18.2)	(11.0)	(6.5)	(5.0)	(3.8)	(8.8)
राजस्थान		6	77	77	83	136	283	350	1012
		(0.3)	(2.7)	(2.5)	(2.4)	(1.4)	(2.9)	(3.3)	(2.4)
	146	848	1020	1006	802	1763	1586	1848	9019
	(11.6)	(47.5)	(35.7)	(32.9)	(22.9)	(18.7)	(16.3)	(17.4)	(21.3)
2. उत्तरपूर्वीक्षेत्र									
भ्रसम	26	44	4		32		29		134
	(2.0)	(2.5)	(0.1)		(0.9)		(0.3)		(0.3)
मेघालय		`			`				` _
नागालैंड							4	4	8
							(0.1)	(0.1)	(0.1)
	26	44	4	<u></u>	32		33	4	142
	(2.0)	(2.5)	(0.1)		(0.9)		(0,4)	(0.1)	(0.4)
3. पूर्वी क्षेत्र									
बिहार		18	61	113	67	154	585	932	1931
		(1.0)	(2.1)	(3.7)	(1.9)	(1.6)	(5.9)	(8.8)	(4.6)
उड़ीसा		4	18	6	8	11	8	82	137
		(0.2)	(0.6)	(0.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(0.8)	(0.3)
पश्चिम बंगाल		2	1	10	5	4	22	69	112
	·	(0.1)	(0,1)	(0.3)	(0.2)	(0.1)	(0,2)	(0.6)	(0,3)
		24	80	129	80	169	615	1083	2180
		(1.3)	(2.8)	(4.2)	(2.3)	(1.8)	(6.2)	(10.2)	(5.2)

सारणी 4 (जारी)

पुनर्जित्स का राज्यवार जितरण

(लाख रुपयों में)

क्षेत्र/राज/संघशासित क्षेत्र				निम्नलिखित	वर्षों के दौरा	 न			जोड़ 30 जुन
	1968 तक	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	•
4. मध्य क्षेत्र									
मध्य प्रदेश		31	49	91	187		645	1234	
		(1.8)	. ,	, ,	, ,	, ,	(6.6)	(11.6)	(6.0)
उत्तर प्रदेश		122	256	293	604	1134	18498	1849	5765
		(6.8)	(9,0)	(9.6)	(17.3)	(12.3)	(15.3)	(17.3)	(13.6)
		153	305	384	791	1462	2143	3083	8322
		(8.6)		(12.5)					(19,6)
5. पश्चिमी क्षेत्र	<u></u>				<u> </u>	-—- —			
गोवा					⊢ ~		3	5	8
	,				•		(0.1)	, ,	(0.1)
गुजरात	14	193	131	190	262	2794	788	427	4809
	(1.1) 108	(10.8)	(4,6)	(6,2)		(29.7)	(8.0)	(4.0) 1358	(11.3)
महाराष्ट्र	(8.5)	(4,6)	349 (12.2)	233 (7.6)	456 (13.0)	732 (7.8)	1271 (13.0)	(12,7)	4589 (10.8)
, ,									
	(9.6)	274 (15.4)	480 (16.8)	423 (13.8)	718 (20.5)	3526 (37.5)	2062 (21.1)	1790 (16.8)	$9397 \\ (22.2)$
 विकाणी क्षेत्र 	<u></u>	,,	_ 	r#)— — — — — — — — — — — — — — — — — — —			<u></u>	ــر <u>ـــنة عبدج ــــر حــر بـــر ـــد</u>	_
श्रान्ध्र प्रदेश	637	172	607	342	285	847	423	792	4205
	(50.4)	(9.6)	(21.2)	(11.2)	(8.2)	(0.0)	(4.3)	(8.4)	(9.9)
कर्नाटक	125	136	166	274	325	405	1099	1008	3589
	(9.9)	(7.6)	(5.8)	(8.9)	(9.3)	(4.3)	(11.2)	(9.5)	(8.4)
केरल	10	7	35	82	97	28	103	100	461
	(0.8)	. (,0,4).	(1.2)	(2.7)	. (2.8)	(0.3)	(1.0)	(0,9)	(1.1)
पांडिचेरी							8	15	23
							(0.1)	. ,	(0.1)
समिनाडु	199	126	162	422	368	1213	1712	817	5019
	(15.7)	(7.1)	(5.7)	(13.8)	(10.5)	(12.9)	(17.5)	(7.7)	(11.8)
	971	441	970	1120	1075	2493	3345	2832	13247
	(76.8)	(24.7)	(33.9)	(36.6)	(30.8)	(26.5)	(34.1)	(26.6)	(31.3)
कुल जोड़	1265	1784	2860	3062	3498	9414	9784	10640	42307
(1 से 6 तक) (100.00)(100.00)((100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

1974-75 के दौरान उत्तर प्रदेश, पुर्निवत्त के वितरण का सबसे ग्रधिक भाग (18 करोड़ रुपये) प्राप्त करने में अग्रणी बना रहा है और इसके वाद अम से महाराष्ट्र (14 करोड़ रुपये) और मध्य प्रदेश (12 करोड़ रुपये) आते हैं। बिहार (9 करोड़ रुपये) लगातार पीछे रहते हुए छठे स्थान पर रहा है। (सारणी 4) निगम के आरंभ से लेकर, अब तक निगम की सहायता का सबसे श्रधिक फायदा उठानेवाले जिन राज्यों में से प्रत्येक ने कुल वितरण का 10 प्रतिशत से श्रधिक भाग प्राप्त किया है, वे इस प्रकार हैं—उत्तर प्रदेश (58 करोड़ रुपये), तिमलनाडु (50 करोड़ रुपये), गुजरात (48 करोड़ रुपये) और महाराष्ट्र (46 करोड़ रुपये)। इसके मुकाबले अन्य चार राज्यों अर्थात् हरियाणा और आंध्र प्रदेश (प्रत्येक 42 करोड़ रुपये), पंजाव (38 करोड़ रुपये) और कर्नाटक (35 करोड़ रुपये) में से प्रत्येक ने 8 से 10 प्रतिशत के बीच उक्त वितरण प्राप्त किया है। (सारणी 4) उत्तरी, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में वितरण का निष्पादन पिछले वर्ष से अधिक रहा है जबिक उत्तर पूर्वी पिण्चमी और दक्षिणी क्षेत्रों में इसमें हास हुआ है।

- 1. 4 लघु सिचाई सहायता का मुख्य प्रयोजन बना हुआ है किन्तु इस का सापेक्ष महत्व प्रलग अलग राज्यों में थोड़ा सा बदल गया है। (सारणी 1) कृषि उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिये जाने से इस प्रयोजन के लिए जल स्रोतों की उपलब्धि का सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक अध्ययन करने के कार्यक्रम के साथ ऋण प्रणाली में तीव्रता लाना प्रावश्यक होगा। प्रत्येक राज्य में भूमिगत जल अनुसंधान के प्रभारी विभाग के कार्य में तीव्रता लाये जाने पर विद्यमान भूमिगत जल स्रोतों के वैज्ञानिक उपयोग की संभायन का का पता लगेगा। भूमि विकास और भूमि संरक्षण की योजनाओं ने प्रभी तक जोर नहीं पकड़ा है। कमान क्षेत्र की परियोजनाओं में खेतों के उपरी विकास के लिए प्रवि संघ से सहायता प्राप्त तीन परियोजनाओं को प्रतिम रूप दे दिया गया है। खेतों के इसी प्रकार के उपरी विकास के लिए अन्य कमान क्षेत्रों में अध्यक्ष्य कार्य को तेज कर दिया गया है और निकट भविष्य में इनमें से कुछ अध्ययनों के फलदायक होने की अशा है। कृषि मशीनीकरण, मुर्गीपालन और भेड़ पालन, मछली पालन और उरी विकास की योजनाओं में अधिक अभिरचि दिखाई जा रही है। कृषि मशीनीकरण, मुर्गीपालन और एता और हिरयाणा में अवि संघ के लेखे से कु० पु० निगम का वितरण 5 करोड़ रुपये है, वहां गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रन्य राज्यों में मांग ने जोर पकड़ा है; व्यक्तिगत किसानों की ट्रेक्टरों के लिए मांग के प्रलावा कृषि-सेवा केन्द्रों की स्थापना की मांग एक नयी विशेषता है। कृषि मणीनों के पर्याप्त वितरण की प्राणा की जाती है क्योंकि पंजाव और हरियाणा की परियोजनाओं के लिए प्रायातित ट्रैक्टरों का प्राना प्रारंभ हो गया है। च्यिष बागन और स्थापना की नीलामी वोली प्रपनाई जाती है, अवि संघ देशी ट्रैक्टरों के वित्तपोषण को शामिल करने के लिए राजी हो गया है। यथि बागन और बागनानी के अंतर्गत काफी बड़े वायदे किये गये हैं तथापि विकसित पौदों के उत्पादन और अन्य अनिवार्य प्रारंभिक कार्यों पर जोर देने के कारण वितरण ने अभी तक जोर नहीं पकड़ है।
- 1.5 गतवर्ष श्रौर इस वर्ष के श्रन्त तक वायदों के प्रतिशत के रूप में वितरण नीचे येदर्शा गये हैं (सारणी 5)। आलोच्य वर्ष के दौरान सभी योजनाओं के श्रंतर्गत कुल आहरण राशियां निगम के वायदे की 188 करोड़ रुपयों की राशि का करीब 57 प्रतिशत है जबिक गत वर्ष के दौरान उक्त प्रतिशत 52 था। (बिवरण 1)।
- 1.6 निगम के ग्रव सत्तावन सदस्य बैंक पुनिवित्त कार्यक्रम में भाग लेते हैं जिनमें 16 भूमि विकास बैंक, 30 वाणिज्य वैंक ग्रीर 11 राज्य सहकारी बैंक ग्रामिल हैं। भूमि विकास बैंक (भूवि बैंक) पुनिवित्त के वितणर हेतु मुख्य एजेंसी बने हुए हैं। (सारणी 2) ग्रालोच्य वर्ष के दौरान उनके द्वारा वितरित राग्नि 77 करोड़ रुपये हैं जो पिछले वर्ष की ग्रयिक्षा थोड़ी सी ही कम है किन्तू कुल वितरण 72 प्रतिग्रत है जो पिछले वर्ष के 79 प्रतिग्रत के मुकाबले काफी कम है। निगम की स्थापना से लेकर ग्रव तक इन संस्थाओं को किया गया कुल वितरण 351 करोड़ रुपये ग्रयि व श्रित है। इसके विपरीत वाणिज्य बैंकों ने ग्रपनी स्थित में उल्लेखनीय सुधार किया है। ग्रालोच्य वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्राप्त की गयी 28 करोड़ रुपयों की राग्नि उनके सभी पिछले वर्षों के कुल ग्राहरणों के लगभग बराबर है। राज्य सहकारी बैंकों द्वारा प्राप्त किये गये पुनिवित्त में कमी हई है ग्रीर उनकी यह राग्नि 1.5 करोड़ रुपये है ग्रयवा वह पिछले वर्ष की राग्नि करीब ग्राधी है।

					सारणी 5				
				वायवों से वि	तरण का प्र	तिशत			करोड़ रुपए
ऋ० सं०	प्रयोजन	·-/·	<u>-</u>	1973-74 तक कृपु निगम के वायदे	30 जून 1974 तक स्थाहरित रा	3 से 4 का शे प्रतिशत	1974-75 तक कृपु निगम के वायदे	30 जून 1975 तक श्राहरित र	6 से 7 का ाशि प्रतिशत
1	2			3	4	5	6	7	8
1.	लघु सिचाई	•		335.3	254.5	75.9	465.8	338.3	72.6
3.	ं भूमि विकास ग्रौर भूमि सं . कृषि मशीनीकरण	रदाण		$\begin{array}{c} 41.0 \\ 10.2 \end{array}$	$ \begin{array}{c} 28.0 \\ 6.7 \end{array} $	68.3 65.7	46.9 32.7	$30.0 \\ 18.9$	64.0 57.8
	. बागान ग्रौर बागबानी . मुर्गी ग्रौर भेड़ पालन	•	-	$20.8 \\ 1.4$	11.3	54.3 21.4	$\begin{array}{c} 25.0 \\ 2.1 \end{array}$	13.3	53.2 47.6
6.	. मॅछली पालन .			4.4	2.9	65.9	8.3	4.6	55.4
	. डेरी विकास . भंडार सुविधाएं <mark>श्र</mark> ौर	बाजार	केन्द्र	4.8	1.5	31.3	9.7	3.1	32.0
	(मार्केट यार्ड) .	•		17.6	11.5	65.3	18.3	13.8	75.4
	· 	जोड़ ——	<u> </u>	435.5	316.7	72.7	608.8	423.0	69.5

- 1.6 यद्यपि इस वर्ष के लिए प्रत्याशित उपलब्धि मुलतः 150 करोड़ रुपये रखी गई थी किन्तु वर्ष के मध्य में की गई समीक्षा के फलस्वरूप इस कार्यक्रम में संशोधन करके उक्त उपलब्धि की राशि 120 करोड रुपए कर दी गई है । 106 करोड रुपए का जो वितरण हुन्ना है वह संशोधित प्रत्याणा से भी कम है । इस वर्ष के दौरान, पंजाब, हरियाणा न्नौर कर्नाटक में करीब 48 करोड़ रुपए के उधार कार्यक्रम वाले श्रंविसंघ की सहायता प्राप्त टुक्टर कार्यक्रम के पूर्ण होने की ग्राशा की गई थी किन्तू ग्रौपचारिकताश्रों के पूरे होने में देरी होने के कारण उक्त कार्यक्रम श्रागे बढ़ा दिया गया है । प्रारंभिक वर्षों में गुजरात श्रौर तमिलनाडु जैसे जिन राज्यों ने पर्याप्त उधार दिए थे वे भी ग्रभाव की परिस्थितियों, बिजली की कमी, उधारदान्नी संस्थान्नों के भारी श्रतिदेयों ग्रादि जैसे प्रमुख कारणों से केवल सीमित कार्यक्रम ही पूरा कर सके हैं। गुजरात के भावि बैंकों की सहायता राशि 1972-73 के 27.9 करोड़ रुपयों से घटकर 1973-74 में 6.7 करोड़ रुपए हो गए थी ग्रीर वह 1974-75 में ग्रीर घटकर 3.1 करोड़ रुपए रह गई है। तमिलनाडु के भृवि बैंकों की उक्त सहायता राशि 1973-74 में 16.6 करोड़ रुपयों से घटकर 1974-75 में 7.1 करोड़ रुपए रह गई है । प्रायः सारे देश में बिजली की कमी के कारण कुन्नों में बिजली लगाने की प्रगति में बाधा पड़ी है। तकनीकी न्नौर वित्तीय दोनों ही पक्षों में नियंत्रण के कमिक रूप से लागु किए जाने के फलस्वरूप कार्यक्रम की गति धीमी हो गई है।
- 1.8 निगम के ब्यवसाय की प्रवृत्तियां यह देशाती है कि उसके बहु-एजेन्सी दृष्टिकोण में स्थिरता ग्रागई है। जिन वाणिज्य बैंकों ने कृषि-ऋण के क्षेत्र में विलंब से प्रवेश किया था, उनके व्यवसाय ने जोर पकड़ा है। सहकारी बैंकों को कई भ्रन्तनिहित लाभ हैं किन्तु वे ग्रपने भ्रापको प्रौद्योगिकी के विकास भ्रौर परिवर्तनों की भ्रावश्यकतान्त्रों के श्रनुकुल नए रूप में ढालने में सुस्त रहे हैं । यह बहुत कुछ संगठन श्रौर सरकारी सहायता का विषय है जो मुख्यतः 'विस्तार' सहायता तथा श्रेशतः साधनों के रूप में प्राप्त होनी है । यद्यपि ग्रिधिकांश राज्यों में तत्कालीन 'भूमि बधक' बैंकों के नाम बदलकर 'भूमि विकास बैंक' कर दिए गए हैं किन्तु उनके दृष्टिकोण ग्रथता कार्य-संचालन की पद्धति में कोई मौलिक ग्रंतर नहीं देखा गया है। भृषि बैंकों की प्रबंध-व्यवस्था ग्रौर उनके विन्यास को नया रूप देने की तत्कालिक भ्रावण्यकता है ताकि उनके संगठन के विन्निभ स्तरों पर योग्य व्यावसायिक प्रबंध-व्यवस्था उपलब्ध हो सके । सहकारी ऋण प्रणाली में ग्रल्पाविध ग्रीर दीर्घाविध स्कंधों के बीच किसी संपर्क अथवा ऐक्य का ग्रभाव होने से इन बकों की स्थिति वाणिज्य बैंकों की तुलना में ग्रलाभकारी हो गई है। जिन राजयों में राज्य सरकारें वाणिज्य बैंकों को समान श्रवसर प्रदान करने की ग्रनिच्छक हैं, जैसा कि गुजरात और तमिलनाडु में हो रहा है, वहां उन्नति श्रवरुद्ध हो गई है । यद्यपि कई वर्षी से तलवार समिति की सिफारिशें राज्यों के सामने हैं तथापि बहुत से राज्यों में इस संबंध में कार्रवाई शुरू नहीं की गई है । जिन राज्यों ने इस बारे में श्रपेक्षाकृत श्रधिक स्वतंत्रता से सोचा है वहां प्रगति उत्साहवर्धक हुई है, जैसा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मामले में हुम्रा है ।
- 1.9 निगम ने श्रपनी स्थापना से लेकर अब तक 423 करोड़ रुपयों के कुल वितरण किए हैं जो आधार स्तर पर लगभग 530 करोड़ रुपयों के निवेश के द्योतक हैं भ्रौर इनमें सदस्य-बैंकों, राज्य सरकारों भ्रौर ग्रंतिम हिताधिकारियों के श्रंशदान शामिल हैं । विभिन्न योजनाम्रों के प्रधीन उपलब्ध माद्यतन स्रांकड़ों के स्राधार पर वास्तविक उपलब्धि की स्थिति नीचे दी गई है :

नलकूप .					•	•				-	1,18,	000 यूनिट
खोदे गए कुंए	, .	-									2,33,	000 यूनिट
बिजली के पं	प सेट/तेल	। इंजन				•		•			3,33,	000 यूनिट
उद्वाहक सि	चाई .	-			-							425 यूनिट
श्चन्य (बरमा	भ्रोर रह	Ξ)						•			8,	900 यूनिट
हेक्टेयर					हेक्टेयर							हेक्टेयर
काफी					6,400	नारियल					•	17,800
चाय					1,550	सुपारी					•	1,000
रबर			:		1,200	संब						6,500
इलायची	•				1,250	नीब् प्रजाति	ा के	फल ग्री	र भ्रन्य	फल	•	4,000
काजू		•		•	1,100							
तंबाकू	•				480							

निगम ने भ्रपने कार्यकलाप के 12 वर्षों के दौरान 8.22 लाख हेक्टेयर भूमि को बहु फसली क्षेत्र के श्रन्तर्गत लाने में सहायता पहुंचाई है। एक श्रोर जहां बड़ी सिचाई परियोजनाश्रों के कमान क्षेत्र के श्रन्तर्गत विकसित भूमि 3.5 लाख हेक्टेयर है वहां दूसरी श्रोर भूमि संरक्षण योजनात्रों के प्रधीन उन्नत किए गए क्षेत्र में थोड़ी सी युद्धि हुई है और वह बढ़कर 2.30 लाख हेक्टेयर हो गया है। बागान और बागबानी की विभिन्न योजनान्त्रों के स्रधीन विकसित कुल क्षेत्र 41,300 हेक्टेयर के श्रासपास है।

जिन अन्य कार्यकल(प	ंकेलिए	[निगम	द्वारा पुनिव	त्त सुविध	।एं प्रदाः	तको गईहैं	वे नीचे	थ्रनुसार है : -		
भंडार .							•	9.60 लाख	मीटरी	टन क्षमता
बाजारकेन्द्र	•		•			•		6 यूनिट		
ट्रैक्टर .			•				•	7,615 यूनिट		
कंबाइन/फसल काटने व	की मशीन	रें/बुल डे	ोजर/बिजली	चालित	जोतने	की मणीनें		300 यूनिट		
जालवाले पोत/संत्रीकृत	न (वें		•					808 यूनिट		
दुधारूपशु .			•	•	•	•	•	20,700 पशु		
मुर्गीपालन केपक्षी			•		•	•		2,30,000 चूजे		
भेड़ .			•	•			•	16,800 पशु		
कृषि विमान		•	•					2 यूनिट		

स्वीकृतियां

ग्रालोच्य वर्ष के दौरान स्वीकृत योजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष 236 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता से सम्बन्धित 623 योजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें क्रुपु निगम के वायदे की राणि 204 करोड़ रुपए हैं जबिक पिछले वर्ष 251 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता से सम्बन्धित 550 योजनाएं मंजूर की गई षीं जिनमें क्रुपु निगम के वायदे की राणि 220 करोड़ रुपए थी। (विवरण 2) लघु सिचाई की योजनाश्रों का स्थान ग्रग्रणी बना हुग्रा है। उनकी संख्या 303 (49 प्रतिशत) है ग्रौर उनमें क्रुपु निगम के वायदे की राणि 148 करोड़ रुपए श्रथवा निगम के कुल वायदों का 72 प्रतिशत है। इस पर भी ग्रन्थ प्रयोजनों के लिए स्वीकृत योजनाश्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इनकी संख्या 320 है ग्रौर इनसे सम्बन्धित क्रुपु निगम का पुनर्वित्त 56 करोड़ रुपए है। इनमें कृषि मणीनीकरण ग्रौर मछलीपालन की योजनाएं काफी ग्रधिक हैं ग्रौर इनके लिए क्रमश: 33 करोड़ रुपयों ग्रीर 6 करोड़ रुपयों के वायदे किए गए हैं जबिक पिछले वर्ष के दौरान उक्त राशियां 9 करोड़ ग्रौर 1 करोड़ रुपए थीं।

- 2.2 श्रालोच्य वर्ष के दौरान हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेण राज्यों के लिए निधियों के काफी वायदे किए गए हैं। 1973-74 के मुकाबले श्रालोच्य वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश श्रौर महाराष्ट्र के लिए किए गए निगम के वायदों में कमी का कारण यह तथ्य है कि श्रंवि संघ की परियोजनाश्रों के श्रन्तर्गत निगम पहले ही ऐसे बहुत से कार्यक्रमों का श्रनुमोदन कर चुका है जिनको शीध्रता से कियान्वित किया जा रहा है। (विवरण 3)
- 2.3 ब्रालोच्य वर्ष के दौरान भूमि विकास बैंकों के लिए स्वीकृत योजनाक्रों की संख्या 116 है जबिक पिछले वर्ष की यही संख्या 139 थी। (विवरण 4) इन योजनाक्रों के लिए कृपु निगम के वायदों की राणि भी 115 करोड़ रुपए हैं। जो कि पिछले वर्ष के 133 करोड़ रुपयों के मुकावले कम हैं। उक्त कमी का प्रधान कारण यह है कि निगम ने सघन क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार करने का आग्रह किया था जिससे श्रिधक श्रच्छे तकनीकी मानक और पर्यवेक्षण सुनिष्चित्त हो सकें। वाणिज्य वैकों के लिए स्वीकृत योजनाएं 1973-74 की 407 योजनाक्षों से बढ़कर इस वर्ष 501 हो गई हैं। वायदा राणि भी 85 करोड़ रुपयों से थोड़ी सी बढ़कर 87 करोड़ रुपए हो गई है। राज्य सहकारी बैंकों को निगम के 2.3 करोड़ रुपयों के वायदेवाली 6 योजनाएं स्वीकृत की गई है। यह राणि पिछले वर्ष की वायदा राणि से थोड़ी सी कम है। (राज्य सहकारी बैंक श्रिधकांगत: भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधारों से कृषि निवेशों के लिए मध्याविध ऋण प्रदान करते हैं।)

30 जून 1975 तक स्वीकृत 2053 योजनाम्रों में से 826 योजनाएं भूमि विकास बैंकों के लिए हैं, 1176 योजनाएं वाणिज्य बैंकों द्वारा कियान्वित की जानी हैं म्रीर 51 योजनाएं राज्य सहकारी वैंकों के लिए स्वीकृत की गई हैं। (विवरण 7) स्वीकृत योजनाम्रों के लिए 887.4 करोड़ रुपयों की कुल वायदा राणि में से भूमि बैंकों, वाणिज्य बैंकों भ्रीर राज्य सहकारी बैंकों के वायदों की राशियां कमण: 628.4 करोड़ रुपए, 223.2 करोड़ रुपए भ्रीर 25.8 करोड़ रुपए हैं।

विचाराधीन योजनाएं

2. 4. जून 1975 के श्रन्त तक 520 योजनाएं विचाराधीन थीं । इनमें से 136 योजनाएं सभी दृष्टियों से पूर्ण हैं जबिक 384 योजनाएं श्रतिरिक्त जानकारी के श्रभाव में रुकी हुई हैं। विचाराधीन योजनाश्रों में से 262 योजनाएं राज्यों के कम विकसित/ कम बैंक वाले क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। इनका ब्यौरा विवरण 12 में दिया गया है। इसके श्रलावा जो 379 प्रस्ताव कई तरह से श्रधूरे थे वे जांच श्रथवा लिखापढ़ी की विभिन्न श्रवस्थाओं में हैं।

क्षेत्रीय प्रसंतुलन---

राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया

2.5. विभिन्न राज्यों के बीच निवेश के क्षेत्रीय श्रसंतुलन में सुधार लाना एक कठिन प्रक्रिया है। विभिन्न श्रवस्थापना सुविधान्नों को प्रदान करके तथा प्रदान की जानेवाली सेवान्नों की उपयुक्त दरें निर्धारित करके राज्य सरकारों को निवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एक निश्चित भूमिका निभानी है। जहां तक राज्य सरकार भूवि बैंकों ग्रथवा विशेष रूप से गठित निगमों द्वारा निवेश कार्यक्रम को क्रियान्वित करना चाहेंगी वहां कुछ ईक्विटी सहभागिता और श्रन्य प्रकार की वित्तीय सहायता की आवण्यकता पड़ेगी । ये वायदे कुछ राज्य करने में सुस्त रहे हैं श्रीर इसके फलस्वरूप योजनाश्रों को प्रारम्भ करने में विलंब हुश्रा है । ऐसा लगता है कि जिन कतिपय राज्यों ने निगम से पहले ही महत्वपूर्ण सहायता का लाभ उठाया है वे पिछड़ गए हैं श्रीर इसके परिणामस्वरूप श्रत्य विकसित राज्य श्रागे श्रा गए हैं। यदि ये राज्य श्रागी स्थिति बनाए रख सके तो श्रगले वर्ष की संभावनाएं श्रच्छी होंगी ।

- 2. 6. पिछली रिपोर्ट में राज्यों के तीन विशिष्ट समूह दर्शाए गए थे। 1974-75 के निष्पादन के श्राधार पर स्थित की समीक्षा करने पर यह मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ग्रौर बिहार राज्यों में कार्य का तेजी से श्रागे बढ़ना जारी है। वित्तीय नियंत्रण ग्रौर प्रशासकीय दक्षता के श्राधार पर इस प्रगति को बनाए रखने के लिए एक ही राज्य के भीतर के क्षेत्रों में असंतुलन की कम करने के लिए प्रयत्न करने होंगे। राज्य सरकारों के वास्तविक समर्थन से इसकी उपलब्धि संभव हो जानी चाहिए। इस समय राजस्थान में श्रीव संघ द्वारा सहायता की गई बार परियोजनाएं चल रही हैं जो किसी एक राज्य की विशिष्ट परियोजनाग्रों की सबसे ग्रिधक संख्या हैं। ये परियोजनाएं लघु सिचाई को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों की हैं। लघु सिचाई के लिए निगम से उपलब्ध होनेवालो संक्रिय सहायता के कारण अब राज्य में चतुर्दिक विकास की घड़ी श्रा गई है। राज्य सरकार के विभागों के हाल ही में किए गए पुनर्गठन के कारण आगे के और कार्यक्रम भी संभव हो सकेंगे। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, उसके छः जिलों के लिए श्रीव संघ की सहायता वाला एक छृषि विकास कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है ग्रौर ज्यों ही आवण्यक ग्रौपवारिकताएं पूरी हो जाएंगी त्यों ही उसका क्रियान्वयन शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। उड़ीसा, में, पिछले वर्ष के प्रयत्नों के ग्रनुक्रम में कृषु निगम की 16.8 करोड़ रुपयों की सहायता वाली योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जिनका वित्तपोपण राभूवि बैंकों और वाणिज्य बैंकों द्वारा किया जाना है। ग्रालोच्य वर्ष के दौरान इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाने से उड़ीसा में ठोस प्रगति होनी चाहिए।
- 2.7. निगम प्रपने सतत प्रयासों के बावजूद जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, प्रसम, मेघालय, मिणपुर, मिजोराम, नागालैण्ड ग्रौर त्रिपुरा की प्रगति से संतुष्ट नहीं है। (विवरण 6) निगम ने जम्मू ग्रौर कश्मीर में बागबानी विकास की एक योजना को तैयार करने के लिए स्वयं को ग्रीव संघ ग्रौर राज्य सरकार से संबद्ध करने का निश्चय किया है। मुग्रर पालन विकास की संभावना के ग्रध्यन के ग्राधार पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्यों में विशिष्ट योजनाएं तैयार की गई हैं ग्रौर वे राज्य सरकारों तथा घिच रखनेवाले बेंकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बागान, बागबानी ग्रौर वानिकी विकास की संभावना पर एक दल द्वारा निवेश-पूर्व प्रध्यम किया गया है। निगम के श्रध्यक्ष ने राज्य सरकार के ग्रधिकारियों ग्रौर घिच रखने वाले ग्रन्य पक्षों से विचार-विमर्श करने के लिए इस क्षेत्र का दो बार व्यापक दौरा किया है। कलकत्ता में परामर्शदाता यूनिट के एक ग्रधिकारी ने कार्यक्रमों का पता लगाने के लिए राज्य ग्रधिकारियों की सहायता करने हेतु श्रसम की बार-बार यात्राएं की हैं। कृषि निवेश के लिए परियोजना दृष्टि-कोण को स्पष्ट करने के लिए ग्रसम, मणिपुर ग्रौर त्रिपुरा में विचारगोष्टियां ग्रायोजित की गई हैं। जुलाई 1974 में कलकत्ता में एक क्षेत्रीय सम्मेलन ग्रायोजित किया गया था जिसमें लघु सिचाई के विकास के लिए कार्यक्रमों का पता लगाने की प्रक्रिया समझाई गई थी। इस रिपोर्ट में ग्राग चलकर इन विकासों का विस्तार से वर्णन किया गया है।
- 2.8. निगम द्वारा स्वीकृत योजनाश्रों के विश्लेषण से यह पता लगता है कि 36 जिलों को छोड़ कर देश के प्रत्येक जिले में किया-न्वयन के लिए कृपु निगम द्वारा स्वीकृत एक न एक प्रकार की योजना है। जून 1975 के श्रन्त में जिन में उक्त जिले स्थित हैं, वे नीचे दिए गए हैं:—

	•								
हिमाचल			•	7	नागालैंड			•	2
जम्मू श्रौर	कक्मीर	•	•	5	उत्तर प्रदेश	•		•	2
राजस्थांन	Ŧ		•	5	गुजरात .		•	•	2
श्रसम	•		•	3	पांडिचेरी .	•		•	2
बिहार	-	•		3	उड़ीसा .	•	•	•	1
मेघालय	•		•	2	पश्चिम बंगाल			•	1
मध्य प्रदेश	т		•	1					

- 2.9. श्रालोच्य वर्ष के दौरान निगम ने लघु कृषक विकास (एस० एफ० डी०)/सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक (एम० एफ० ए० एल०) एजेंसियों द्वारा प्रायोजित 19 योजनाएं मंजूर की हैं। इनमें पूर्वी श्रौर उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की योजनाएं भी शामिल हैं। जून 1975 के ग्रन्त तक लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वावधान में स्वीकृत योजनाश्रों की कुल संख्या 104 हैं (विवरण 8) इनमें से 58 योजनाएं भूवि बैंकों, 41 योजनाएं वाणिज्य बैंकों श्रौर 5 योजनाएं राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जानी हैं। इनमें से 62 योजनाएं लघु सिचाई के निवेशों के लिए हैं श्रौर शेष 42 योजनाएं डेरी विकास (22), मुर्गीपालन (9) भेड़पालन (3) भिन विकास (2) तथा बागान श्रौर वागबानी (6) के लिए हैं।
- 2.10. इस वर्ष के दौरान इन योजनाश्रों के श्रम्तर्गत श्राहरित राशि 4.7 करोड़ रुपये हैं। वाणिज्य बैंकों ने 54 लाख रुपयों की राशि ली है जबकि भ्विबैंकों द्वारा श्राहरित कुल राशि 4.2 करोड़ रुपये हैं।

इस वर्ष के महत्वपर्ण निर्णय

जुलाई 1974 में बैंक दर में बुद्धि के पारणामस्वरूप ब्याज दर के विन्यास में सामान्य वृद्धि के संदर्भ में निगम ने प्रपत्ती पुनिक्त दर की समीक्षा की है । दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि से किये गये ऋणों पर रिजर्व बैंक ने 6 प्रतिशत ब्याज दर रखी है और बाजार उद्यारों की दरों में भी थोड़ा सा संशोधन हुआ है। रिजर्व बैंक ने भी भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर बसूल की जाने वाली त्यूनतम दर में संशोधन किया है और उसे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 रिजर्व कर दिया है। उस समय वर्तमान तथ्यों पर ध्यान रखते हुए यह निश्चय किया गया था कि 13 प्रगस्त 1974 को प्रथाय उससे पहले स्वीकृत सभी योजनाओं के संबंध में योग संस्थाओं से ली जाने वाली निगम की पुनिवृत्त दरलघु सिजाई और भूमि विकास योजनाओं के लिए 7 र्ह प्रतिशत वार्षिक और प्रनार की योजनाओं के लिए 8 प्रतिशत वार्षिक होगी। वित्तपोयक संस्थाओं द्वारा अंतिम उधार के लिए 11 प्रतिशत वार्षिक है। छोटे किसानों के मामले में, खास तौर पर मुर्गिपालन, डिरी और पशुपालन की योजनाओं के लिए 11 प्रतिशत वार्षिक है। छोटे किसानों के मामले में, खास तौर पर मुर्गिपालन, डिरी और पशुपालन की योजनाओं के लिए, बैंकों को, यदि वे चाहें तो, 10 रे प्रतिशत वार्षिक ब्याज बर्चुल करने की प्रनुपति दी गयी है। यह भी निश्चय किया गया है कि जिन राज्यों में भूमि विकास बैंक प्रपत्ती उधार लेने और उधार देने की दरों के बीच प्रधिक अंतर रखना चाहते हैं, उनमें वे अंची दर वसूल कर सकत है और इस स्थिति में राज्य में कार्यरत वार्षिक वी जनके द्वारा जारी किये गये अल्ला पर उतनी ही उची दर वसूल कर सकत है और इस स्थिति में राज्य में कार्यरत वार्षिक पर उपार के लिए स्वतत्त्र होगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुनिवृत्त नार्षिक करने के समय का विचार किये हैं होनी चाहिए।

- 3.2. जिन क्षेत्रों में लघु सिचाई परिमोजनियें प्रारंभ हो चुकी हैं यहां के सदस्य बैंकों की पुनवित्त उपलब्ध करने ग्रीर ग्रामीण विद्युतीकरण विगम की योजनियों के ग्रन्तर्गत न श्रानेवाल क्षेत्रों को छोड़कर ग्रन्य क्षेत्रों में पंपसेटों को विजली देने के लिए बिजली बोडों में जमाराणियां रखने के हेतु किसानों को ऋण देने के लिए निगम सहमत हो गया है। इन जमाराणियों में कम तनाववाली पारेषण लाइन बिछाने श्रीर कुछ विविध मदों की लागत ग्रामिल है। जमाराशि की श्रीधकतम सीमा प्रति कुंग्रां 3,000 हपये है। विभिन्न सामग्रियों की लागत में प्रमय वृद्धि को हरान में रखते हुए निगम ने 1 ग्रास्त 1974 के बाद दिये गये बिजली के कनेक्ग्रनों के संबंध में उक्त राशि बढ़ाक के 4,500 हरये कर दी है। वंबधित राज्य बिजली बोडों से जिन हिताधिकारियों के पपसेटों को बिजली कनेक्ग्रन दिये गये हैं उनके नामों की सूची सहित प्रमाणपन्न प्राप्त होने पर भविष्य हैं इस दर पर दिये जानेवाले बिजली कनेक्ग्रनों के लिए बैंक सीधे ही राज्य बिजली बोडों को प्रति-पूर्ति करेंगे। प्रसिटों के लिए दिये जानेवाले ऋणों के समान ही इन जमाराणियों की ग्रवधि 7 वर्ष होगी। राज्य बिजली बोडों द्वारा ग्रीफने पास रखी जानेवाली जमाराणियों पर ब्याज दर वही होगी जो किसानों द्वारा बैंकों को देय हो।
- 3.3. स्टेट बैंक ग्राफ़ इंडिया की ग्रनुषंगी संस्थाग्रों से पुनिवत्त पोषण हेतु प्राप्त प्रस्तावों के णीघ्र निपटान के लिए इन बैंकों से प्राप्त ग्राहरण ग्रावेदन-पत्नों की जांच पड़ताल करने का कार्य निगम के उन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को सौपूक्त गर्द हैं जिनके कार्य-क्षेत्र के ग्राव्त ग्रनुषंगी संस्थाग्रों के प्रधान कार्यालय स्थित हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के ग्राधकार क्षेत्र के बाहर की क्षेत्रों में बूद्यां- निवत की जानेवाली योजनात्रों के सम्बन्ध में बैंकों से प्राप्त होनेवाले ग्राहरण श्रावेदनपत्नों पर निगम के प्रधान कार्यालय द्वारा क्षेत्र की जाती रहेगी। श्रन्य बैंकों के निवेदन करने पर उनके पुनिवत्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में समान व्यवस्था करने की संभाव्यदान्त्र विचार किया जाएगा।
- 3.4. जिन मामलों में श्रास्थिगत ब्याज की सुविधा प्रदान की गई थी उन पर निगम श्रव तक $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत विभिन्न की दर पर श्रितिरिक्त ब्याज वसूल करता रहा है। निगम द्वारा जिन मामलों में ब्याज के श्रास्थगन की सुविधा दी गई है, उनके सम्बन्ध में 18 नवम्बर 1974 को श्रथवा उसके बाद स्वीकृत योजनाश्रों के लिए यह दर 6 प्रतिशत वार्षिक करदी गई है। निगम के बोर्ड द्वारा समीक्षा किए जाने पर श्रव 9 जून 1975 को श्रथवा उसके बाद स्वीकृत सभी योजनाश्रों के सम्बन्ध में यह दर (ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दरों के स्तर के बराबर किए जाने के लिए) लघु सिचाई श्रीर भूमि विकास योजनाश्रों के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत श्रीर श्रन्य प्रकार की योजनाश्रों के लिए 8 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।
- 3.5. जिन मामलों में सदस्य वाणिज्य बैंक निगम द्वारा प्रस्तावित प्रोफार्मा में श्रावेदन-पत्न भेजने के बदले प्रारम्भ में ही प्रस्ताव भेजते थे, उनमें यह परिपाटी थी कि निगम श्रन्तरिम स्वीकृति भेज देता था और नियमित ऋण श्रावेदन-पत्नों को प्राप्त होने पर शतौं को सूचित करते हुए श्रंतरिम स्वीकृति जारी करता था । निगम ने श्रव श्रन्तरिम स्वीकृतियां जारी न करने का निश्चय किया है। निगम ने सदस्य वाणिज्य बैंकों द्वारा योजनात्रों के साथ ही भेजे जानेवाले ऋण श्रावेदन के संशोधित प्रपत्न निर्धारित कर दिए हैं।
- 3.6. निगम ने सदस्य बैंकों द्वारा भेजे जाने वाली विवरणियों को युतियुक्त बनाने की दृष्टि से प्रांतरिक समिति भी गठिस की है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विभिन्न प्रयासों ग्रीरक्षेतीय कार्यालयों द्वारा समय-समय पर मंगाई जानेवाली सूचना को दोहराए जाने से बचाया जा सके ग्रीर श्रावश्यक न्यूनतम सीमा तक श्रांकड़ों का प्रस्तुत किया जाना कम किया जा सके।
- 3.7. निगम विशेष मामले के रूप में लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक श्रौर कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वावधान में प्रायोजित मोजनाश्रों के लिए शतप्रतिशत पुनर्वित्त प्रदान करता रहा है। यह सुविधा 30 जून 1975 तक उपलब्ध थी श्रौर श्रव यह 31 दिसम्बर 1975 तक प्रदान की जाएगी।

3-469GI/75

3.8. तिळले वर्ष की िपोर्ट में कृषि पुनिवित्त निर्गम श्रिधिनियम, 1963 की घारा के उस संशोधन का उल्लेख किया गया था जो निगम के निदेण का शोई को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह योग्य संस्थाओं को प्रदान किये जाने वाले पुनिवित्त के सम्बन्ध में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सरकारी गारंटी और 'अन्य जमानत' दोनों में ही छूट दे दे । इस संशोधन के अनुसरण में निगम की निदेशक बोर्ड ने यह निश्चत किया है कि प्रदेग मामले के गुण दोषों के आधार पर निगम के जो बैंक शेयरधारी हैं उनसे अर्थात् स्टेट बैंक आफ इंडिया, उसके अनुषंगी बैंकों और 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और किसी ऐसे लाइसेंसी छून अनुसूचित वाणिज्य बैंक से उन योजनाओं के सम्बन्ध में कोई सरकारी गारंटी अथवा 'अन्य जमानत' न ली जाए जिन में निगम के नाम पर जमानत का निर्माण करने में किठनाई होती है। कुछ अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक यह अध्यावेदन करते था रहें हैं कि संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से पुनिवित्त के आवेदनण्य भेजने और उनसे गारंटी प्राप्त करने की त्रियादिधि जिल और अधिक नमय लेने वाली है और इस लिए वे यह सुझाव देते रहें हैं कि उन्हें पुनिवित्त के लिए कोई जमानत दिए बिना ही अपने आप निभाव प्राप्त करने के लिए मीधे ही निगम से अर्थना करने की अनुमति दी जाए। इस प्रार्थना पर विचार करने के बाद निगम के बोर्ड ने ग्रंतिम उधाकरती को तमय पर विचीय निभाव की उपलब्धि में शिक्षता लाने के लिए यह निश्चय किया है कि राज्य सहकारी बैंक को दिए जाने वाले वित्तीय निभाव के सम्बन्ध में अन्य जमानत और या गरकारी प्रतिभूति से निम्निलिखिन शतों के अधीन छूट दी जाए: (i) जिन योजनाओं के सम्बन्ध में ऐसा विभाव मांगा गया है वे तकनीकी इंग्टि से सं मांग ग्रंथिक इंग्टि से च्यवहार्य हों, (ii) संबंधित राज्य सहकारी बैंक 'क' श्रेणी के लेखा परीक्ष वर्गी रण वाला अनुस्ति प्रतिक लेखा परीक्ष वर्गी रण वाला अनुस्ति परीक्ष के लेखा परीक्ष वर्गी रण वाला अनुस्ति परीक्ष के लेखा परीक्ष वर्गी रण वाला अनुस्ति होता है। (iii) इस योजना में भाग लेने वाला के द्वीय सहकारी बैंक कोया मांग का 80 प्रतिशत हो। और (iv) सहकारी संस्थाओं से ली जाने वाली जमानत रिजर बैंक द्वारा समय समय पर निर्धीरित शर्तों के अनुरूप हो।

कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 के संशोधन

निगम द्वारा किए जाने वाले कारोबार की व्याप्ति और मात्रा हाल ही के वर्षों में काफी बढ़ गई है और उस में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक गति आएगी। निगम की महत्वाक ध्वाश्यों को साकार करने के लिए यह आवश्यक था कि कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 पर नए निरे में विचार किया जाए ताकि वर्तमान सांविधिक परिसीमन उपयुक्त परिचालन-नीतियों के निरुपण और पर्याप्त साधन जुटाये जाने में वाधक नहो। निगम द्वारा स्थापित एक आंतरिक सिमिति ने कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों की परीक्षा की है और उस में कितिय मंगोधनों का सुआव दिया है। इन्हें रिजर्व बैंक और भारत सरकार से विचार-विमर्श करने के पश्चात् अतिम रूप दे दिया गया है। कृषि पुनर्वित निगम अधिनियम, 1963 के कितिया उपबंधों में संशोधन करने का एक विधेयक अप्रैल 1975 में संसद में प्रस्तावित किया गया था।*

वित्तीय स्वरूप के संशोधन

- 4. 3. "कोग्य संस्था" पद को व्यापक बनायां जा रहा है ताकि उसमें ऐ सी अन्य संस्थायें शामिल हो सकें जो इस बारे में रिज़र्व बैंक की सिफा-रिश पर कन्द्रोध सरकार आरा अनुमोदित की जाये । "योग्य संस्थाओं" का क्षेत्र व्यापक बना दिया गया है ताकि निगम कतिपथ वर्ग की संस्थाओं को सीक्षे ही विनोध सहायता प्रदान कर सके । इस पर भी यह इंरादा है कि ऐसे प्रत्यक्ष विन पोषण को फिलहाल चुने हुए सरकारी विकास निगमों और सहकारी संस्थाओं तक, वहीं तकनीकी और वित्तीय मानदंड लागू करने के बाद, सीमित कर दिया जाए जो अन्य संस्थाओं हारों कार्यान्विस की जाने वाली इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिये लागू किये जाते हैं।
- 4. 4 चूंित वर्तमान प्राधिकृत पूंजी केवल 25 करोड़ है जिसमें से 20 करोड़ रुपये पहले ही ग्रदा किये जा चुके हैं, वर्तमान सीमा में वृद्धि करने के लिए गोध ही कार्रवाई करने की ग्रावण्यकता है। यह ग्रांशा है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व श्रनुमति से रिजर्व बैंक द्वारा निगम की शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपयों तक बढ़ा दी जायेगी। प्राधिकृत शेयर पूंजी भें वृद्धि होने के फलस्वरूप जारी की जानेवाली ग्रतिरिक्त हिस्सा पूंजी का कम में कम 50 प्रणित रिजर्व बैंक लेगा।
- 4. 5 एक नया खंड धारा 20(1) (ङ) जोड़ा गया है जिसके फलस्वरूप निगम के लिए यह संभव हो सकेगा कि वह उपहार, अनुदान, दान अथवा सरकार या अन्य स्रोतों ने प्राप्त होने वाले उपदान स्वीकार कर सके। इन मदों को निगम की आमदनी, लाभ और उपलब्धियां नहीं माना जायेगा। यह नयी व्यवस्था उन परिस्थितियों में निपटने के लिए उद्दिष्ट है जिनमें निगम या तो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों से अनुदान, अर्थित महायता, आदि ऐसे मामलों में प्राप्त करे जिनमें कोई राज्य सरकार ब्याज की दरों में बभी करके आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार हो अथवा जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अनुदान प्रदान किये जाते हैं।

[ः] इम् बीव यह विधेयक जुलाई/अगस्त 1975,में लोक सभा राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है झौर इस पर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल् मुई है ।

^{4. 2} अपने पुनिवत/प्रदान करने के कार्य के अलावा निगम द्वारा विकास और संवर्धन के लिए किये जाने वाले योगदान पर बल देने के लिए निगम का नाम बदल कर 'कृषि पुनिवत्त और विकास निगम' कर दिया जायगा। कृषि पुनिवित्त निगम अधिनियम के अन्य संशोधनों को स्थूल स्प से तीन शीर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा संकता है अर्थात् (i) निगम के कारोवार में वृद्धि की सुविधा और उसकी साधन स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वित्तिय महत्व के संशोधन (ii) प्रशासकीय स्वरूप से संशोधन और (iii) नेमी स्वरूप के संशोधन।

- 4.6 किसी भी योग्य संस्था के जिन बांड्रों को दिवाँ की कैंदी कैंदी कैंदी के जारी किये जाने के दिनांक से पच्चीस वर्धों की अविध में अनिधिक अविध में की जानी हो निगम उन्हें खरीद सकेता है और जनमें अभिवान कर सकता है तथा ऐसे बांडों अथवा दिवेंचरों को बंच सकता है। यह खड़ मूल अधिनियम में किये गर्य उप उपबंध के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसके अधीन निगम किसी भी योग्य संस्था के दिवेंचरों के नये में इजरों केवल अभिदान ही कर सकता है।
- 4.7 मूल ग्रिधिनियम का खंड 22(3) (ष्रु) निगम को भारत के बाहर से पूंजीगत आल की खरीद के किए श्राप्यियि श्रक्षियमी की गारंटी प्रदान करने की श्रनुमति देता है। भारत में पूंजीगत वाल की खराद के लिए इस प्रकार की गारंटी देने के लिए निगम की शक्ति पर लगाये गये प्रतिबंध को "भारत के बाहर से" शब्दों को निकाल कर समाप्त कर दिया गया है।
- 4.8 पिछली रिपोर्ट में कृषि पुनर्वित्त निगम ग्रिधिनियम की धारा 22 (4) में किये गये संशोधन का उल्लेख किया गया था। सशोधित धारा से निगम के निदेशक बोर्ड को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह प्रत्येक मामले में योग्य सम्याओं में ली जाने वाली करावीं गारेटी तथा "ग्रन्य जमानत" दोनों के संबंध में गुणदोप के पायार पर छूट प्रशान कर दे। विलंब से बचने ग्रांट प्रनाग्रह की दृष्टि से इस धारा में एक नया खंड जोड़ दिया गया है जिससे निगम की यह मुथिआ प्राप्त हा सके कि वह किसी भी योग्य संस्था अथवा योग्य संस्थाओं के किसी भी वर्ग अथवा जिन योजनाओं के लिए निगम हारा निभाय प्रदान कर रहा है उनके स्वरूप ग्रोर क्षेत्र को ध्यान भे रखते हुए उन्हें जमानत से छूट प्रदान कर दे।
- 4. 9 मूल अधिनियम के इस प्रतियंध को हटाने का प्रस्ताव है कि निगम कार्यकारी पूंजी निधियां प्रदान नहीं कर सकता। इससे निगम के. लिए चुने हुए मामलों में योग्य संस्थाओं को दीर्घाविध और अल्याविध समेकित ऋण प्रदान करने था मार्ग प्रकरिक्षों जायेगा।
- 4.10 परिचालन दक्षता के हित में उस उप बंध को हटाने का प्रस्ताव है जो निगम को पह ब्यादेश देता है कि वह 50 लाख रुपयों या उससे प्रधिक के किसी भी लेन-देन के लिए रिजर्व वैंक की लिएखेत अनुगति प्राप्त करें।

प्रशासकीय स्वरूप के संशोधन

4.11 म्रिधिनियम की धारा 17 में किये गये संशोधन के फलस्व्रूप निगम अपने निदेश हमंडल ढारा गठित समितियों को शक्तियां प्रदान कर सकेगा। मूल म्रिधिनियम की धारा 22 में एक नथा खंड जोड़ दिया गया है जिससे निगम स्वयं ही अनुसंधान, सर्वेक्षण और प्रौद्योगिकी म्राधारित म्राधिक सर्वेक्षण कर सकेगा अथवा उन्हें अपनी म्रोर से अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से करा सकेगा। इस प्रकार निगम कम विकसित म्रथवा विशेषकर देश के कम बैंकिंग सुविधावाले क्षेत्रों में पूर्व निदेश सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर सकता है ताकि समाज की भलाई के लिए कृषि विकास की उपयोग में न लाई गई विशाल संभावना का पता लगाया जा सके ग्रीर उसका दोहन किया जा सके।

नेमी स्वरूप के संशोधन

4. 1.2 इस वर्ग के संशोधन इसलिए ग्रावश्यक हो गये हैं कि "केन्द्रीय भूमि बंघक बैंक" "केन्द्रीय भूमि विकास वैंक" कहलाने लगे हैं ग्रीर "बैंककारी कंपनियां ग्रिधिनियम" का नाम बदलकर श्रव "बैंककारी विनियमन ग्रिधिनियम" हो गया है। एक संशोधन के ग्रनुसार बंबई में एक क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की भी व्यवस्था की गयो है जो वर्तमान उपबंधों के ग्रिधीन संभव नहीं है। निगम के बढ़ते हुए कारोबार को पूरा करने के लिए, निगम के लेखों की शीघ्रतिशीघ्र लेखा परीक्षा करने के लिए एक ग्रौर लेखा परीक्षक की नियुक्ति ग्रावज्यक हो गयी है ग्रौर इसका मुझाव विया गया है।

अंबि/संघ अंपुवि बैंक की परियोजनाएं

इस वर्ष के दौरान ग्रंबि संघ ने कृषि विकास के लिए पांच ग्रोर परियोजनाएं स्वोकृत की हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं — राजस्थान ग्रोर मध्य प्रदेश की डेरी विकास परियोजनाएं, पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना ग्रोर मध्य प्रदेश चंयल कमानक्षेत्र की विकास परियोजना ग्रोर कृषि पुनिवत्त निगम ऋण परियोजना निगम ग्रांध्र प्रदेश, कर्नाटक राजस्थान ग्रांर महाराष्ट्र के सूखाप्रवण छः जिलों में कार्यान्वित की जानेवाली परियोजनाश्रों की समझौता वार्ताश्रों से भी संबद्ध था। इस कार्यक्रम के ग्रंतर्गत संबंधित राज्यों में खेता के ऊपरी निवेशों की प्रतिपूर्ति या तो कृषि पुनिवित्त निगम ऋण परियोजना श्रथवा ग्रंबि संघ ऋण की चालू परियोजनाश्रों के ग्रंबीन की जायेगी।

5. 2 जून 1975 के ग्रंत में ग्रपुवि बैंक/ग्रंवि संघ द्वारा सहायता की गई 22 परियोजनाओं में 11 कृषि ऋण परियोजनाएं, 3 कमान क्षेत्र विकास परियोजनाएं, 3 डेरी विकास परियोजनाएं, 2 वाजार केन्द्र (यार्ड) परियोजनाएं, एक सेव ग्रांभसंस्वरण ग्रांर विपणन परियोजना एक बीज परियोजना ग्रौर निगम को दी गयी एक सामान्य ऋण प्रणाली योजना शामिल है। इनमें से दो परियोजनाएं नामतः तराई बीज परियोजना ग्रौर चम्बल कमान क्षेत्र की विकास परियोजना के लिए ग्रंपुवि बैंक द्वारा सहायता दी गयी है ग्रांर शेष परियोजनाग्रों का वित्तपोपण ग्रंविसंघ द्वारा जायोगा। परियोजनाग्रों का प्रयोजनवार कुल ऋण कार्यक्रम तथा जून 1975 के ग्रंत तक, ग्रंबि संघ द्वारा ग्रव तक की गयी प्रतिपूर्ति की राशि की संक्षिप्त स्थिति दर्शानेवाला विवरण सारणी 6 में दिया गया है। प्रत्येक परियोजना का विस्तृत ब्योरा विवरण 10 में दिया गया है।

जून 1975 के श्रंत तक श्रंवि संघ/श्रंपुवि बैंक परियोजनामों के श्रन्तगैत निगम द्वारा कुल 198 करोड़ रुपसों का कुल वितरण किया गया है। वितरण की गति में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। निगम ने श्रव तक भारत सरकार से 117 करोड़ रुपयों श्रथवा विश्व बैंक/श्रंवि संघ वायदों के 29 प्रतिशत की स्वतः ही सितपूर्ति की है। (निगम वितरणों के एक विशिष्ट प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति का हकदार है जो या तो उसके प्रथवा उसके हिताधिकारी के स्तर पर किया जाएगा।)

सारणी 6

							(करोड़ रुपयों में)
प्रयोजन				कुल उधार कार्यक्रम	कु० पु० निगम के कार्यक्रम के लिए ग्रंबिसघ/ग्रंपु० वि० बैंक की सहायता की राशि*	तक कु० पु० तिगम	30 जून 1975 को भारत सरकार की माध्यम से भां जिल्ला की माध्यम से भां जिल्ला की किया की किया की साम की साम की साम साम की साम
1. लघुसिचाई - .				417.5	240.6	175.3	108.9
2. भूमि विकास .				16.6	10.9	. 3.3	3.1
 कृषि मशीनीकरण 			•	78.4	47.5	7.7	3.7
्4. बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड)	विकास	. •	•,	. 23. 7	16.9	0.8	
 खराब होनेवाली बागबानी 	उपजों का	श्रभियसं	करण		•. •		
भौर विषणन .	. ·			4.5	3.7		
6. डे,री विकास .			er	72.0	45.5		
7. कमान क्षेत्र का विकास		,	•	48.5	25.7		<u> </u>
8. बीज उत्पादन			,	9.3	6.7	1.3	1.3
9. विशाखीकृत प्रयोजन	•	•	"	9.0	4.0		
जोॢड़	•			679.5	401.5	188.4	117.0

^{*}प्रशिक्षण/ग्रव्ययन के लिए ग्रंवि संय द्वारा **कृ**षु निगम ऋण परियोजना के श्रधीन 10 लाख डालर प्रदान किये जायेंगे ।

- 5.3 विकास की विभिन्न मदों के लिए विनिधानित ऋण में से गुजरात के लिए श्रंबि संघ द्वारा 1970 में स्वीकृत पहली कृषि ऋण परि-योजना के लिए उसका पूरा उपयोग कर लिया गया है। उस राज्य में कृषि विकास की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने आगे के कार्य-कम के लिए प्रस्ताव तैयार किये हैं। श्रान्ध्र प्रदेश, हरियाणा और तिमलनाडु में कार्यान्वित की जा रही लघु सिचाई वर्ग की परियोजनाओं के लिए विनिधानित मूल ऋणों का पूरा उपयोग कर लिया गया है। इस प्रकार के निवेश की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, निदेशों के जिन श्रन्य वर्गों, अर्थात भूमि विकास और लघु सिचाई वर्गों में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई थी, उनके ऋणों का पुनः विनिधान किया गया है। इसके लिये अंब संघ की श्रनुमति प्राप्त कर ली गयी है। पुनः विनिधानित ऋणों का भी तिमलनाडु और श्रान्ध्र प्रदेश की परियोजनाओं के लिए पूरा श्राहरण कर लिया गया है जबिक हरियाणा परियोजना के लिए थोड़ी सी राशि बकाया रहती है जिसका उपयोग 19765-76 में कर लिया जायेगा। कर्नाटक और महाराष्ट्र की ऋण परियोजनाओं में लघु सिचाई कार्यक्रम का काफी बड़ा भाग पहले ही पूरा किया जा चुका है और शेष भाग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा कर लिया जायेगा।
- 5. 4 उत्तर प्रदेश, बिहार ग्रीर मध्य प्रदेश की हाल ही में स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा निधियों का वितरण काफी उत्साहवर्धक है। उत्तर प्रदेश में, जून 1975 के श्रंत में ऋणों का वितरण लगभग 15.5 करोड़ रुपये है। इसी श्रविध के दौरान कृषु निगम ने बिहार परियोजना के श्रंतर्गत भूवि बैंकों/प्रास बैंकों को 8 करोड़ रुपयों तक का पुर्निवत्त प्रदान किया है। मध्य प्रदेश में, प्रास वैंकों/भूवि बैंकों द्वारा जून 1975 के श्रंत तक किये गये वितरणों की राणि 13.9 करोड़ रुपये है। इस पर भी इन परियोजनाश्रों की प्रगति को विजली की कमी के कारण पंपसेटों में बिजली न लगने से थोड़ा साधक्का लगा है। इन समस्याश्रों को सुलङ्गाया जा रहा है ग्रीर ऐसी ग्राशा है कि श्रानेवाले महीनों में वितरण जोर पकड़ेगा।
- 5.5 गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तिमलनाडु की कृषि ऋण परियोजनाओं में कृषि मशीनीकरण के उपकरणों की निधियां शामिल हैं। यह मूल ध्रनुबंध कि चल रही परियोजनाओं के ट्रैक्टर-घटक का ब्रायात विश्व बैंक के श्रन्य सदस्य देशों से किया जाना चाहिए, श्रंवि संघ द्वारा इस बीच संशोधित किया गया है ताकि उसके ब्रंतर्गत देशी ट्रैक्टर का प्राप्त किया जाना भी ख्रा जाए। जो पंजाब कृषि

ऋण परियोजना, विशिष्ट रूप से केवल ट्रैक्टरों, कटाई यंत्रों, स्वचालित कवाइनों और चक्कितयों तथा हलों की फालों श्रादि जैसे कृषि मणीनी-करण उपकरणों की प्राप्त के लिए उद्दिष्ट है, उसके श्रन्तगंत 1,000 ट्रैक्टरों की पहली खेप प्राप्त कर ली गयी है। हाल ही में 4,000 ट्रैक्टरों की दूसरी खेप को प्राप्त करने के लिए श्रीपचारिकताएं पूरी हो गयी हैं श्रीर उसकी काफी अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम ने हिरियाणा कृषि ऋण परियोजना के श्रेतर्गत 2,800 ट्रैक्टरों के लिए श्राईर दिये हैं जबकि श्राध्न प्रदेश श्रीर कर्नाटक परियोजनाशों के संबंध में ट्रैक्टरों को प्राप्त करने के लिए श्रीपचारिकताएं प्रायः पूरी हो चुकी हैं। तमिलनाडु परियोजना में, ट्रैक्टरों की प्राप्त के लिए प्रारंभिक कार्य-वाही की जा चुकी है। इन बातों को देखते हुए ऐसा संभावना है कि इस वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में परिकल्पित ट्रैक्टरों की उपलब्धि का कार्य विलक्ष पूरा श्रथवा प्रायः पूरा हो जायेगा। पूरे किये जाने वाले उधारों की कुल राश्विलगभग 60 करोड़ हपये है।

- 5. 6 निगम ने कुल 84 लाख रुपयों का पहला वितरण बिहार बाजार केन्द्र (मार्केट यार्ड) परियोजना के श्रंतर्गत किया था। बिहार और कर्नाटक दोनों ही परियोजनाओं में बाजारों के लिये भूमि के श्रजन में विलंब, बाजार समितियों के लेखों के लेखा परीक्षण में विलंब श्रोर बाजार शुल्क के संग्रहण में कभी जैसी कितियय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन मामलों को निपटाने के लिए कार्रबाई शुरु कर वी गई है।
- 5. 7 कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में डेरी विकास निगमों की स्थापना सहित उनकी डेरी परियोजनाओं के कार्य-कम के कार्यान्वयन और समन्वय के लिए श्रावश्यक संगठन विन्यास की स्थापना हो गई है। क्रपु निगम ने डेरी संघों के विस्पोषण से गंबंधित वैंकिंग व्यवस्था को भी ग्रतिम रूप दे दिया है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंध कार्यपालक कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य के गी झ ही संबंधित डेरी विकास निगमों द्वारा प्रारंभ किये जाने की संभावना है। ग्रलग श्रलग डेरी संघों की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किये जा रहे हैं।
- 5 : 8 राजस्थान में दो कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना कर ली गई है। ये दोनों प्राधिकरण राज्य के राजस्थान नहर प्रौरं चम्बल कमान क्षेत्र की विकास परियोजनायों के ग्रंतर्गत सिचाई और खेत के उपरी भाग के सारे विकास कार्यों के कार्यान्वयन ग्रीर योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। राजस्थान भूमि विकास निगम की एक. ऐसी एजेंसी का भी गठन किया गया है जो वास्तव में परियोजना निर्माण कार्य ग्रीर मुख्य परियोजना के श्रन्य ग्रनुषंगी कार्याकलापों को निष्पादित करेगी। निर्माण कार्य के नक्षे तैयार करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाये जा रहे हैं। इस बीच ग्रंवि संघ के एक परामर्शदाता ने विस्तार करेगे के श्रंतर्गत कार्य प्रारंभ कर दिया है।
- 5.9 निगम एक श्रायोजित नीति के रूप में, कम विकसित राज्यों, विशेषकर पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए प्रयत्न करता रहा है। इस संदर्भ में, ग्रंवि संघ की सहायता से पिष्टम बंगाल में एक समेकित कृषि विकास परियोजना की स्वीकृति काफी महत्व रखती है। इस परियोजना में श्रन्य वातों के साथ-साथ, छिछले श्रौर गहरे नलकूपों का निर्माण जिनमें से गहरे नलकूप सहकारी संस्थाधों श्रीर लबु सिचाई निगम के जरिये बनाये जायेंगे, राज्य सरकार द्वारा पहले ही प्रारंभ की गयी 600 नदी उद्वाही योजनाश्रों की समाप्ति, कृषि सेवा केन्ब्रों का गठन श्रौर तीन बाजारों का निर्माण जैसे खेतों के ऊपरी भागों के निवेणों की परिकल्पना की गई है। राज्य की छोटी धौर छिन-भिन्न जोतों को देखते हुए इस परियोजना में उथले नलकूपों के कार्यक्रम पर काफी भरोसा किया गया है। चृकि ग्राज्य का सहकारी ऋण विन्यास कमजोर बना हुआ है, उसक्षेत्र के बाणिज्य बैंकों को इस उत्तरदायित्व का काफी श्रंश सौंपा गया है और उनसे यह श्रीशा की गई कि वे इस परियोजना के अन्तर्गत खेतों के ऊपरी भाग के निवेणों के लगभग 70 प्रतिशत का वित्त पोषण करें।
- 5.10 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में ग्रंबिसंघ से प्राप्त होनेबाली सामान्य ऋण प्रणाली के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था। भारत सरकार श्रोर ग्रंबि संघ के श्रीव संघ के श्रीव संघ के बीच परियोजना से संबंधित श्रोपचारिक समझौतावार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। कृषि पुनिवत्त निगम की ऋण परियोजना योजना ग्रंबि संघ ऋण की ऐसी चल रही ग्रन्य परियोजनाश्रों से भिन्न है, जिनमें ग्रलग राज्यों ग्रथवा किसी राज्य के भागों ग्रथवा विकास की विशिष्ट विकास मदों के लिए निधियों का वायदा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उधारों के लिए कृषि विकास की परियोजनाश्रों के मूल्यांकन के लिए निगम के दक्षता को मान्यता प्रदान करते हुए कृषु निगम ऋण परियोजना के ग्रंतर्गत परियोजनाश्रों का पता लगाने, उनका मूल्यांकन करने ग्रीर उनके लिए निधियों के बायदे करने का उत्तरदायित्व निगम पर छोड़ दिया गया है। निगम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए उपलब्ध संगठन-विन्यास को देखते हुए निवेशों के उपयोग में काफी ग्रनाग्रही रहेगा। जिन क्षेत्रों में एक ही प्रयोजन के लिए ग्रंबि संघ की सहायता वाले विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए ऋण उपलब्ध हैं, उनमें निगम पहले प्रदान किये गये ऋणों का पूरा उपयोग किये जाने पर निवेशों को जारी रख सकेगा। इस परियोजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।
- 5.11 श्रंवि संघ की कित्यय श्रौर परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। निगम श्रंवि संघ के विभिन्न श्रायोगों के साथ प्रारंभिक चरणों से ही स्वयं सहयोग करता रहा है ताकि कार्यान्वयन की स्थिति में कम से कम समस्यायें हों। ग्रंवि संघ का एक श्रायोग मई 1975 में समेकित स्ई विकास परियोजना के श्रांकड़ों को ग्रद्धतन करने के उद्देश्य से भारत श्राया था। भारत सरकार के श्रनुरोध पर विश्व बैंक/खाद्ध ग्रौर कृषि संगठन के दो प्रारंभिक सर्वेक्षण श्रायोग देश की वृक्ष-फसलों में निवेशों को प्रोत्साहन देने श्रौर समुद्री मछलीपालन के विकास की संभावनाश्रों का पता लगाने के उद्देश्य से भारत श्राये थे। इस के श्रवावा, मध्य प्रदेश में वन्य परियोजना, जम्मू श्रौर कश्मीर में बागवानी परियोजना श्रौर श्रिखल भारतीय बीज परियोजना के निर्माण श्रायोग भी ग्राए थे। ग्रंवि संघ के कर्मचारी वर्ग के सदस्यों ने महाराष्ट्र, उड़ीसा श्रौर ग्रांध्र प्रदेश के कमात क्षेत्र की विकास परियोजनाश्रों को सहायता प्रदान करने की संभावनाश्रों का पता लगाया है। जब ये परियोजनाएं साकार हो जायेगी, विश्व बैंक समुह बारा कृषि ऋण सहायता की मान्ना श्रौर उसकी सीमा में पर्याप्त विशाखन हो जायेगा।

विकास की सांस्थानिक प्रणाली

निगम की श्रान्तरिक कियाविधियों का पुर्नगठन श्रीर उन्हें सरल तथा कारगर बनाना लामप्रद रहा है। जिवारार्थ प्राप्त होनेबाली योजनाओं की संख्या बढ़ गयी है श्रीर इसके साथ ही साथ स्वीकृत योजनाओं की संख्या पिछले वर्ष की 550 योजनाओं की तुनना में बढ़कर लगभग 625 हो गयी है। निगम के कारोबार के बढ़ते हुए कार्यकलापों के परिप्रेक्ष्य में उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को निगम की महत्वाकाक्षाओं को साकार करने के लिए विभिन्न एजें सियों की कृषि विकास की सक्षम योजनाएं तैयार करने श्रीर साथ ही उनके लिए पूर्निवत्त सहायता प्रदान करने सथा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तपोषक बैंकों के समझ आनेवाली बाधाओं को दूर करने में सहायता पहुंचा कर महत्वपूर्ण भूमिक। निभानी है। इस कार्य के लिए कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की गयी है। क्षेत्रीय कार्यालयों पर निगम के ऋण कार्य कमों को पूरा करने के लिए प्रचार करने श्रीर उनके लिए काकी साधन जुटाने का भी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

- 6. 2 इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कार्यानय के बरिष्ठ प्रिविकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी प्रिविकारियों की एक संयुक्त बैठक बम्बई में गार्च 1975 में प्रायोजित की गयी थी। इस बैठक में विचार-विमर्श इन विषयों पर केन्द्रित था: निगम में प्रारंभ किया गया निष्पत्त बजट और विभिन्न राज्यों में कृषि निवेणों के विशाखन के क्षेत्र और उनको व्याप्ति, अंवि संघ की सहायता बाली जो परि-योजनायों चल रहीं है उनके कार्यान्वयन की गित में आनेवाले गितरोधों को दूर करने और वित्तपोषक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गयो यीजनाओं को स्वीकृति में विलंब को कम करने, आहरणों और दस्तावेजों से संबंधित पढ़ित्यों को सरल बनाने, योजनाओं के वितीय मूल्यांकन की कार्य पढ़ित, योजना—निर्माण से संबंधित तकनीकी पहलू और स्वीकृत योजनाओं के मूल्यांकन संबंधी अध्ययन की अनुवर्तों के येर्रवाई। बैठक में भाग लेनेवालों को अंवि संघ से अभी अभी समझौता की गई कृषु निगम की ऋण परियोजना की प्रमुख विगेषनाओं का संक्षित विवरण दिया गया। इस संक्षित विवरण से क्षेत्रीय कार्यालय समझौते के विभिन्न अपबंधों और परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित अपने उत्तरदायित्यों को समझ सके। चूंकि अंवि संघ से इस परियोजना के लिए निगम द्वारा पुनिवत्त के वितरण के केवल 55 प्रतिगत की प्रतिपूर्ति की जाएगी, इन कार्यालयों पर निगम द्वारा समय समय पर जारी किये जानेवाली बांडों और शेयरों के लिए प्रवार करने की अपनेक्षक अधिक जिम्मेशरी होगी ताकि निगम के वायदों को पूरा करने के लिए समुचित साधन उपलब्ध हो सकें।
- 6.3 कई राज्यों में कृषि पुनर्वित्त निगम के एकमात सबसे बड़े प्रयोजन-तथु सिंचाई की योजनाओं की संख्या और राशियों दोनों में ही, गिरावट की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है। इस बैठक में उधार कार्यक्रम की गति को बनाये रखने के लिए पुनर्वित्त के प्रमुख प्राप्ति-कर्ताओं विषशोकर राज्य भूमि विकास बैंकों के कारोबार का विशाखन करने की भ्रावश्यकता पर विशेष रू। से ध्यान दिया गया था। मोजना निरुपण
- 6. 4 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में ऐसी व्यवहार्य कृषि विकास योजनात्रों के निरूपण के लिए पर्याप्त दक्षता का स्रभी तक विकास नहीं हुआ है, जिनका सहज ही वित्तपोपण किया जा सके। राज्य स्तर पर विशेष रूप से योजनात्रों का ठीक ठीक पता लगाने, उनका प्रवर्तन करने, उनकी स्कीमों के निरूपण और साथ ही उनकी कार्यान्वित करने की श्रत्यधिक श्रावश्यकता सनुभव की जा रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निगम ने श्रसम, मणिपुर और तिपुरा में इन राज्यों के राज्य श्रीर जिला स्तरीय श्रीधकारियों के लाग के लिए विचार-गोष्ठियां श्रायोजित की थीं। इन विचारगोष्ठियों में, कृषु निगम को पुर्निवत सहायता से विभिन्न प्रकार की विकास योजनात्रों के निरूपण की सकनीक उनमें भाग लेनेवालों को समझायीं गयीं थीं। राज्य सरकारों के प्रतिविधियों के श्रवाबा इन राज्यों में कार्यरन व।णिजिय और सहकारी कै श्रिधकारियों ने भी इन विचारगोष्ठियों का लाभ उठाया।

कृषि विकास योजनाश्रों के मूल्यांकन के लिए एक महस्वपूर्ण मानवण्ड किसी भी परियोजना की तकनीकी निर्देषिता होता है। विभिन्न राज्य र रवारों और वित्तपोषक संस्थाश्रों द्वारा श्रावश्यक तकनीकी श्रावश्यकताओं का पालन किए जाने की श्रावश्यकता के महत्व को समझने में सेहायता पहुंचाने श्रीर विभिन्न एजेंसियों के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा योजनाएँ तैयार करते समय परिमार्जनों को ग्रानाने में समर्थ बनाने के लिए निगम ने दो विचार-गोष्ठियां श्रायोजित की थीं। इनमें से एक सितम्बर 1974 में बम्बई में और दूसरो फश्वरों 1975 में लखन के में श्रायोजित की गई थीं। इन विचारगोष्ठियों में राज्य सरकारों/वाणिज्य श्रीर सहकारी वैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

पनामशं सेवा युनिट

6.5 कलकत्ता में संगठित दूसरे परामर्श यूनिट ने दिसंबर 1973 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इसके गरिणाम-ध्वका लखनऊ स्थित परामर्श यूनिट का पुनर्गठन किया गया है ताकि उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश , जम्मू और करमीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश मा जाएं। कलकत्ता यूनिट का क्षेत्राधिकार बिहार, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, असम और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों ते असीमत कर दिया गया है। परामर्श यूनिट के अधिकारी तैयार की जा रही नयी योजनाओं की संभावनाओं के बारे में राज्यों के अधिकारियों से विवार-विमर्श करने के लिए वहां गये थे। उधार देने के कार्यक्रम के बारे में इन राज्यों की प्रतिक्रिया तथा जो योजनाएं मंजूर की गयी हैं उनकी संख्या इस बात की द्योतक हैं कि परामर्श-यूनिटों ने राज्य सरकारों द्वारा निगम को स्वीकार्य योजनाएं तैयार किये जाने के लिए सहायता प्रदान करने के कितने प्रयत्न किये हैं। कलकत्ता का परामर्श-यूनिट उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सुश्चर पालन के विकास, असम में गांव पंचायत सहकारी समितियों के माध्यम से विकास मौर बागान बागबानी तथा वानिकी के निवेश-पूर्व सर्वक्षण से विशिष्टत: संबंद्ध रहा है। एक यूनिट ने उड़ीसा में लघु सिचाई कार्यक्रमों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका श्रदा की है और इसके बहुत से भाग को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार एक यूनिट अवि संघ के सहयोग से जम्मू और कश्मीर में बागबानी के निवेशपूर्व श्रद्धियन से संबंधित है। इन दोनों ही गरान में यूनिटों ने स्राने क्षेत्रों में भूमि विकास

बकों के संगठन-स्वरूप का भ्रध्ययन किया है भ्रौर उनके निष्कर्शी से प्रयान कार्यालय को इन राज्यों के विकास के स्थरूर के बारे में भ्रानी राय बनाने में सहायता मिली है ।

निर्धारण

- 6.6 निगम ने, योजनाश्रों की वर्तमान प्रणालियों, स्राधिक निर्धारण की पद्धतियों और उनकी विषा वस्तु तथा उपयोगिता की सीमा के (सनुवर्ती) श्रध्ययन करने और उनमें सुधारों के सुझाव देने के लिए एक श्रांतरिक समीक्षा दल का गठन किया है। क्षुनु निगम की क्षिमीक्षा सिमिति ने दल के जांच-परिणामों का मोटे तौर पर श्रनुमोदन कर दिया है। क्षेत्रीय स्तर पर इन जांच-परिणामों को अपनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विस्तृत श्रनुदेश जारी कर दिये गये हैं।
- 6.7 प्रतिनिधि जोत के प्राधार पर किसी भी एक प्रादर्श फार्म के संबंध में किसी योजना के लाभों प्रौर लागतों का निर्धारण प्रथमपत सिद्ध हुआ है और विशेषकर उन योजनाओं के संबंध में एकदम ही अनुप्युक्त सिद्ध हुआ है जिनमें खेतों की व्यापक पारस्मरिक विभिन्नताओं अथवा एक ही योजना क्षेत्र में मिट्टी-जलवायु की परिस्थितियों में अंतर होने के कारण विभिन्न कुबकों के लाभों और लागतों के स्तर में काफी भिन्नता होने की आणा है। एक जैसी मिट्टी-जलवायु के मिश्रित क्षेत्रवाली योजनाओं के लिए भी एक से अधिक नमूनों की आवश्यका। हो सकती है। इसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि ऐसी योजनाओं का निर्धारण किया जाए जिनमें नमूने के खेन तैयार करके बहुविधि नमूनों के प्रयोग किये जाएं ताकि कुबकों के विभिन्न वर्गों (छोटे कुबकों और अस्त्रा) को सिचित और ऑसिचित कामों, आदि से होने वाले लामों और लागतों का पता लग सक। केवल वार्षिक पूंजी खर्च के संदर्भ में योजनाओं की वित्तीय संभाव्यता को परखने का मानदंड भी अभयित सिद्ध होगा क्योंकि यह सभी मामलों में प्रमाणिक नहीं हो सकता। इसलिए, भविष्य में योजनाओं की वितीय संभाव्यता और उनके बैंकों द्वारा स्वीकार किये जाने की योग्यता का निर्धारण दो प्रलग प्रलग प्रलग प्रलग की निर्धारण वो प्रलग कि वित्रा की कियायता का निर्धारण वो प्रलग प्रलग किये योग्यता को उधार लेनेवाले की वार्षिक अदायगी क्षमता के अनु रूप बनाना होगा। हिलाधिकारी की घरायगी क्षमता की धारणा की ठीक तरह से परिभाषा की जानी चाहिए और इस संबंध में समीक्षा दल द्वारा दिये गये सुझाबों की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए ऋणों की किथतों के लिए राणि को बांटने के मानदंड तैयार किये जाने हैं। निर्धारण में सानु मूर्तिवाधिता से बचने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भी कृषि पर होनेवाले व्यय, फसल प्रणालियों, फसलों की उपजें, फउलों की संख्याओं, मूल्य आदि जैसे कृषि के बजट-विश्लेषण संबंधी ऐसे विस्तृत प्रांकड़े एकत्र करने होंगे, जो परियोजना वाले स्थानों और उनसे बाहर के स्थानों के होंगे।

मिम विकास बैंक

- 6.8 यद्यपि, उधार देने की उत्पादोन्मुख प्रणालियों को लागू करने में थोड़ी प्रगति हुई है, ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि विकास बैंकों को प्रपने नये कारोबार में कमी की संभावना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपलब्ध भूमिगत जल के स्रोतों के सुसंबद्ध प्रौर वैज्ञानिक उपयोग से संबंधित नियमों को लागू किए जाने में निहित कार्यान्वयन के प्रधीन रहनेवाली परियोजनाम्नों के निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए उचित तंत्र और संभावनाम्नों का व्यापक अन्वेषण जारी रखने के लिए सिक्षय अयत्नों की सहायता प्राप्त नहीं हुई। उदाहरण के लिए गुजरात, हरियाणा और तिमलनाडु जैसे राज्यों में जहां विगतकाल में भूमिजल का काफी उपयोग पहले ही किया जा नुका है वहां लघु सिचाई योजनाम्नों से संबंधित नये कारोबार की संभावनायें स्पष्टतः कन प्रतीत हो सकती हैं। परन्तु प्रध्ययनों से यह पता चला है कि ऐसी संभावनायें विद्यमान हैं और कम से कम कुछ क्षेत्रों में चयनात्मक आधार पर निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके विपरीत ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां इसकी काफी गुंजाइण है और जहां उपयोगिता के अधिकान स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ समय लगेगा। इस प्रकार, यद्यपि इस समग्र प्रणाली में और उधार देन की गुंजाइण है परन्तु अलग अलग राज्यों में यह कारोबार इस पर बहुत म्रधिक निर्मर करेगा कि भूमिगत जल के संसाधनों के अध्ययनों में तेजी लाई जाए।
- 6.9 विगत वर्षों में सतही जल स्रोतों स्रौर जहां उद्वाही सिचाई की गुंजाइश है वहां उसका बेहतर उपयोग करने तथा पानी को लाने-ले जाने में उसके रिसने से होनेवाली उस क्षति को रोकने पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है जिससे स्रौर स्रधिक भूमि की सिचाई संभव हो सकेंगा। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों के विभागों को उचित रूप में मजबूत बनाना श्रीर धलग स्रलग बेंकों में ही सुयोग्य तकनीकी कक्ष स्थापित करना स्रावश्यक होगा। बैंक जो कारोबार करने के आशे हैं, उन्हें उसके विभिन्न स्वरूपों पर पुनविवार करना चाहिए। उनके दीर्घ जीवन की इस स्रवस्या में इस बात की आवस्यकता है कि वे अपने उपार देने के कार्यक्रमों का विशाखान करें ताकि वे स्रपते कारोबार की मान्न बिनाये रख सकें।
- 6.10 प्राथमिक समितियों शाखाओं के स्तर पर श्रितिदेयों के उच्च स्तर का बना रहना भी एक दूसरा श्रसंतोषजनक पहलू है। भूमि विकास वैंकों के श्रितिदेयों में भारी वृद्धि हुई है श्रीर वे 1969-70 के 12.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 1972-73 में 76.33 करोड़ रुपये हो गये हैं। यद्यपि वसूली की राशि में पर्याप्त सुधार हुआ है श्रीर अतिदेय 1973-74 के श्रंत में कन होकर 62.17 करोड़ रुपयें (श्रनंतिम) हो गये थे। यह एक श्रच्छा अनुत है कि बैंक बसूती के निर्दयाय बनाये रखने में सहन रहे हैं। 1974-75 के प्रारंभिक श्रांकड़ों में श्रीतिदेयों की राशि में गिरायट की प्रवृत्ति बनी हुई है।
- 6.11 बैंकों को फिर भी सतर्क रहना होगा ग्रौर ग्रतिदेयों के स्तर को कम करने के लिए कारगर नीतियां ग्रपनानी होंगी। एक ग्रौर जहां ग्रतिदेयों के स्तर के लिये कई स्पष्टीकरण दिये जा सकते हैं वही दूसरी ग्रोर राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी किये गये ऋणों के लिये उन्नत भूल्यांकन का सुनिश्चित किया जाना,विभागीय कर्मचारियों पर श्रयेक्षाकृत कम निर्भरता ग्रौर व्यवस्थापकों द्वाराइस समस्या पर एकनिष्ठता

से ध्यान देना ही इसका एकमात्र उपाय है। इस बीच भूमि विकास बैंकों के 1975-76 से प्रारंभ होनेवाले उधार देने के कार्यक्रम के विनियमन के लिए एक जैसे मानदंड तैयार कर लिये गये हैं थ्रौर वे उन्हें सूचित कर दिये गय हैं। इस कार्यक्रम का विनियमन प्रमुख रूप से धितिदेयों के स्तर और प्राथमिक समिति शाखा स्तर की मांग के संबंध में किया जाएगा ।

बाणिज्य बंक

- 6.12 हाल ही के वर्षों में वाणिज्य बैंक बड़ पैमाने पर कृषि विकास के कायक्रमों मू सिक्रय भाग लेते आहर है। हालांकि, कई राज्य सरकारों द्वारा यह बहु एजेंसी दृष्टिकोण व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। गुजरात और तिमिलनाडु की राज्य सरकारें श्रभी वाणिज्य बैंकों को श्रपनी जायज भूमिका श्रदा करने की श्रनुमति देने में हिचकिचा रहीं हैं। वाणिज्य बैंकों द्वारा श्रिधकांश उधार बैंकिंग की कम सुविधावालें क्षेत्रों में दिया गया है श्रीर उसका लघु सिचाई और श्रन्य प्रयोजनों के लिये बराबर बराबर विशाखन हुआ है।
- 6.13 1974-75 के दौरान वाणिज्य बैंकों को 104.5 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायतावाली 501 योजनाएं स्वीकृत की गयीं विविध्य सहायतावाली 501 योजनाएं स्वीकृत की गयीं विविध्य में प्रिमित्र के 129 करोड़ रुपयों की 116 योजनाएं स्वीकृत की गयीं हैं। निगम ने श्रव तक इन वैंकों को 1176 योजनाएं स्वीकृत की हैं। जिनके लिए उसने 223.2 करोड़ रुपयों का वायदा किया है। यह निगम द्वारा जून 1975 के श्रन्त तक स्वीकृत कुल योजनाशों का 52 प्रतिकृत है। इन योजनाशों के श्रन्तगत कारोबार के स्वरूप की विविध्या आती है और उसके श्रन्तगत लेंयु- सिचाई, भूमि विकास, कृषि मशीनी करण, बागान श्रीर बागवानी,मुर्गीपालन श्रीर साथ ही बाजार केन्द्र परियोजनायों जैसे प्रयोजन श्राते हैं।
- 6.14 1974-75 के दौरान, वाणिज्य बैंकों ने 28 करोड़ रुपयों के पुनिवित्त का लाभ उठाया है। यह राशि इस वर्ष् के दौरान निमम द्वारा कुल विवरित राशि का 26 प्रतिशत है और वह पिछले सभी वर्षों में उनके द्वारा ग्राहरित कुल राशि के लगभग बराबर ही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में श्राहरित राशि की मात्रा बहुत ग्रिधिक है। वाणिज्य बैंक विभिन्न राज्यों में श्रंवि संघ द्वारा सहायता की गई परियोजनाओं में श्रुत्यन्त, सिक्ष्य रूप से भाग ले रहे हैं। निगम और वाणिज्य बैंक कार्यकलापों के एक नये क्षेत्र अर्थात् देश के विभिन्न राज्यों में वन विकास योजनाओं का विश्वपोषण में प्रवेश कर रहे हैं। इस उद्देश्य से कि कार्यक्रम की जटिलता और विशालता को देखते हुए ये बैंक अपने साधनों को एकत्र करने के श्रलावा उनमें पर्याप्त दक्षता प्राप्त कर सकें, निगम इस प्रकार के कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए बहर्विकिंग व्यवस्था के बारे में विचार कर रहा है।

प्रशिक्षण

- 6.15 कृषि पुनर्वित्त निगम को ब्रानेवाले रोबार की भारी माक्षा को संभालने के लिए स्वयं को सुसज्जित करना है। कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थाओं में पर्याप्त विशेषज्ञता का निर्माण करना भी श्रत्यावस्यक है। इसमें तभी सुविधा हो सकती है जब प्रशिक्षित कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में अनुपूर्ति करने की स्थिति विद्यमान हो। निगम द्वारा नियुक्त, प्रशिक्षण की अनीपचारिक समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था और उसने एक डिसूदीय कार्यक्रम का सुझाव दिया है-एक वरिष्ठ और मध्य स्तरीय कर्मचारियों के लिए भीर दूसरा कनिष्ठ श्रीधकारियों के लिए।
- 6.16 कृ पु निगम ऋण परियोजना से निगम पर यह उत्तरदायित्व ग्रा गया है कि वह मुख्यतः भूवि बैंकों के वरिष्ठ ग्रीर मध्यस्तरीय कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण पाठयकम तैयार करें। इसमें परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित ग्रन्य संस्थान्नों के ग्रिधिकारियों तथा सरकारी मिधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की रूप-रेखा पहले ही तैयार की जा चुकी है। इस प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह होगा कि परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित कर्मचारियों की कार्यदक्षता ग्रीर कुशलता में वृद्धि की जाए। इसके ग्रंतर्गत परियोजना प्रवर्तन, उनका पता लगाना ग्रीर निरूपण, (तकनीकी ग्रीर ग्राधिक) मूल्यांकन, ग्राहरण, प्रलखन, वितरण, स्वीकृति के बाद का सत्यापन, चूक किये गये ऋणों की ग्रदायगी ग्रीर वसूली ग्रीर कुशल वित्तीय व्यवस्था, ग्रादि जैसी मदें ग्रायेंगी।
- 6.17 वरिष्ठ और मध्य स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य भूमि विकास बैंकों के प्रमुख कार्यपालक-ग्रिधिकारियों, वाणिज्य बैंकों के कृषि विक्त विभागों के विभागाध्यक्षों ग्रीर भारतीय रिजर्व बैंक, कृषु निगम ग्रीर राज्य सरकारों से लिये जानेवाले कतिषय श्रिष्टिकारियों के लिए होगा। प्रारंभ में, भविष्य के पाठयक्रमों की विषयवस्तु को निश्चित करने में सहायता पहुंचाने के लिए दो प्रायोगिक पाठ्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। मुख्य कार्यपालक श्रिधकारियों के लिए श्रायोजित पहले प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में चुनौतीपूर्ण नई मांगों को पूरा करने के लिए बैंक प्रबन्ध-व्यवस्था ग्रीर संगठन को नया रूप देने श्रादि जैसे पहलुग्रों पर श्रिधक वल दिया जायेगा।
- 6.18 निगम ने एक प्रशिक्षण कक्ष का गठन किया है जो कृषु निगम ऋण परियोजना के श्रंतर्गत उस पर श्रानेवाले उत्तरादायित्वों को संभालने के लिए कार्रवाई की पहल करेगा श्रीर अनुवर्ती कार्रवाई भी करेगा। यह कक्ष प्रशिक्षण पाठ्यकम के लिए आवण्यक पाठ्यविवरण, श्रध्ययन सामग्री आदितीयार करेगा। इन आवण्यकताओं की पूर्ति के लिए पूना स्थि तभारतीय रिजर्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के संकाय की संख्या में उचित वृद्धि की जायेगी। श्रध्यक्ष की देखरेख में गठित एक समिति प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर कृषु निगम को परामर्थ देगी।
- 6.19 कृपुनिगम ऋणपरियोजना के अन्तर्गत निगम को भूवि बैंकों के कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियों की आवश्यक्षताओं का भी मूल्यांकन करना पड़ता है तथा उसे अवि संघ को स्वीकार्य एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करना होगा। भूषि बैंकों के कनिष्ठ स्तरीय कर्मचारियों की प्रक्षिण आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिये प्रत्येक राज्य के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया जा रहा

है जिसमें कृषु निगम के श्रधिकारी, संबंधित राज्य भूमि विकास बैंकों के मुख्य कार्यपालक-श्रधिकारी और सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा नामित व्यक्ति होंगे । इस श्रध्ययन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निगम के प्रशिक्षण कक्ष द्वारा तैयार किये जायेंगे श्रौर यह राज्य स्तरीय दलों ढ़ारा श्रध्ययनों के संचालित किये जाने का सामान्य पर्यवेक्षण भी करेगा ।

- 6.20 इस वर्ष के दौरान निगम के दो श्रधिकारी वाशिगटन स्थित श्राधिक विकास संस्थान द्वारा संचालित ग्रामीण ऋण परियोजना पाठ्यकम के लिए भेजे गये हैं जब कि एक श्रन्य श्रधिकारी ने कृषि उद्योगों के पाठ्यकम में भाग लिया है।
- 6.21 निगम के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रंपुत्रि बैंक/अंगि संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में तान्जानिया और तुर्की में श्रंवि संघ के श्रायोगों की कृषि ऋण परियोजनाश्चों के मूल्यांकन में भाग लिया है।
- 6.22 इस वर्ष के दौरान निगम ने भ्रंवि संघ परियोजना के अन्तर्गत भाग लेनेवाले राभूवि बैंकों श्रौर वाणिज्य बैंक के प्रतिनिधियों के लाभार्थ भोपाल में एक श्रावर्तक कार्य शिविर श्रायोजित किया है।

मृल्यांकन

- 6.23 म्रधिकाधिक निवेशों के परिप्रेक्ष्य में कृषकों को प्राप्त होने वाले लाभों का व्यवस्थित मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है ताकि निवेश पूर्व की धारणान्नों की तुलना निवेशोत्तर उपलब्धियों से की जा सके। परियोजनान्नों के ऐसे मूल्यांकन से न केवल ग्रातिरिक्त वास्तविकता उत्पादन भौर भविष्य में परियोजना निर्माण में के लिए ग्रावश्यक ग्राधारभूत सामग्री के रूप में होनेवाला लाभ प्राप्त होता है ग्रापितु हिताधिकारियों के निवेश से ग्राधिकतम लाभ प्राप्त करने में होनेवाली जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनका भी पता लगता है। इन्हीं उद्देश्यों को नया में रखकर निगम ने एक मूल्यांकन कक्ष स्थापित किया है।
- 6.24 मूल्यांकन के एक अंग के रूप में, निगम ने 4 योजनाश्रों, नामतः शोलापुर जिले (महाराष्ट्र) के 4 तालुकों में पंपसेटों सहित खुदाई कुंशों की योजना, कर्नाल 1 योजना (हरियाणा) के अन्तर्गत छिछले नलकूपों का लगाया जाना, नलगोंडा जिला (आंध्र प्रदेश) के मिर्यालगुडा तालुका में नागाजनसागर भूमि विकास परियोजना और चित्रदुर्ग (कर्नाटक) के दावनगरे श्रीर हरिहर में भद्रा भूमि विकास परियोजना का अध्ययन प्रारंभ किया है और तदनुसार उसने 4 क्षेत्रीय यूनिटों की स्थापना की है। प्रत्येक योजना के अन्तर्गत चुने हुए कृषकों के नमूने के संबंध में उपयुक्त लागत सूचियों के माध्यम से खेती के कारोबार संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण पढ़ित अपनायी गयी है। कर्नाल 1 योजना से संबंधित अन्वेषण अग्रिम चरण में है। इस प्रकार लागत-सूचियों द्वारा संग्रहीत श्रांकड़ों का अभिसंस्कार करने उन्हें सारणीवद्ध करने का कार्य श्रव हाथ में ले लिया गया है।

भावी स्वरूप

देश के कृषि विकास संबंधी प्रयत्नों की दिशा में निगम द्वारा किये गये शीर्षस्थ प्रयत्नों को श्रब श्रधिकाधिक मान्यता प्रदान की जा रही है। निगम के कार्यं कलापों का प्रमुख प्रतिवल यह होगा कि निगम के लिए निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जाए ग्रथित कृषि में तकनीकी श्रीर वित्तीय दृष्टि से ठोस निवेशों की व्यवस्था की जाए, जिन क्षेत्रों में पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं की जा रहीं थीं वहां निवेशों को प्रोत्साहित किया जाए कि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों श्रीर छोटे कृषकों की ग्रधिकाधिक संख्या को निवेश करने श्रीर इन प्रयोजनों में श्रपेक्षाकृत श्रधिक माला में विशाखन लाने के लिए साधन उपलब्ध किये जाएं। इन उद्देश्यों की पूर्ति इस ब्रावश्यकता पर बल देती है कि निगम को साधनों की ग्रावश्यकता सहायता मिलनी चाहिए श्रीर इसे सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक श्रीर भारत सरकार से निरन्तर संपर्क बनाय रखा जाता है। साधनों को जुटाने के लिए किये गये हाल के प्रयत्नों की यह विशेषता रही है कि बाजार-उधारों का उत्तरोत्तर सहारा लिया जा रहा है।

- 7. 2 निगम देश के कम विकसित और बैंकों की कम सुविधा वाले क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में आवश्यक गितशीलता लाने के उद्देश्य से निगम ने, बागान, बागबानी, और वन विकास में बैंक को स्वीकार्य निवेशों की संभावनाओं की परीक्षा करने के लिए अपने अधिकारियों का एक अध्ययन दल गठित किया है। अध्ययन दल ने अप्रैल 1975 में अस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि इस क्षेत्र में वन और बागान फसलों के विकास का कार्यक्रम उसी स्थिति में तैयार किया जा सकता है जब वन और बागान फसल विकास निगम जैसी कोई उपयुक्त संस्था स्थापित की जाए। इन विकासों के लिए निवेश की अगित उस गित पर निर्भर करेगी जिससे संगठन-विन्यास स्थापित किया जाएगा। इस दृष्टि से बागवानी के विकास की समस्या और भी कठिन है कि तैयार किये गये फल उत्पादनों के लिए देश के भीतर और बाहर के बाजारों में बहुत अधिक स्पर्धा है। यही कारण है कि बागवानी फसलों के विकास की कोई भी योजना फलों के अभिसंस्करण की अनुपूरक योजना पर निर्भर करेगी और ऐसे उपऋमों की अतिम सफलता अतिम उत्पादन के कारगर विपणन पर निर्भर करेगी। विपणन के पहलू की ओर ध्यान आक्षित करने के लिए दल ने यह सिफारिश की है कि इस क्षेत्र के लिए एक संयुक्त-क्षेत्रवाले उपक्रम के रूप में एक बागवानी विकास और अभिसंस्करण कंपनी की स्थापना की जाए ताकि अच्छी किस्म का उत्पादन और स्पर्धावाले विपणन के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
- 7.3 इस क्षेत्र में चाय बागान एक महत्वपूर्ण भूमिका ग्रदा करते हैं। इस पर भी अनेक ऐसे चाय बागानों का पुनःस्थापन किया जा सकता है जिन्हों 'बीमार' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दल ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के 15 करोड़ रुग्यों के प्रारंभिक श्रंशदान से कृपु निगम में एक श्रार्वती निधि की स्थापना की जाए।
 4—469G1/75

- 7.4 यह संतोष का विषय होगा कि दल की रिपोर्ट से पर्याप्त उत्साह उत्पन्न हो और इन क्षेत्रों की राज्य सरकारें और श्रागे सोचने के लिए प्रेरित हों तथा वे श्रपने क्षेत्रों में बागवानी, वागानों श्रौर वातिकी के संवर्धन की श्रपनी क्षमताश्रों की कोटि के श्रनुरूप विकास कार्य करने में लग जाएं।
- 7.5 निगम ने परामर्शदाताश्चों की एक संस्था की सहायता से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सुश्चरपालन के विकास का निवेश-पूर्व सर्वेक्षण किया है। इसके बाद चार राज्यों श्चर्यात् श्चसम, मेघालय, मिणपुर श्रीर नागालैंड में तकनीकी श्वधिकारियों के एक दल द्वारा श्चनुवर्ती श्रध्ययन किये गये हैं। सुश्चर-पालन के विकास की गुंजाइश श्रीर उसके लिए सांस्थानिक वित्त की व्यवस्था करने की श्वावण्यकता को मानते हुए दल ने यह महसूस किया है कि इन राज्यों में वर्तमान परिस्थितियों की विलक्षणताश्चों को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों में ऋणों का स्वरूप श्रीर साथ ही उनका प्रयोजन श्चन्य राज्यों में भिन्न ही होगा।
- 7.6 इन भ्रध्ययनों के श्राधार पर नागालैंड भ्रौर मणिपुर्र राज्यों में मुश्रर पालन के एकीकृत विकास के ऐसे ठोस प्रस्ताव तैयार कर लिए गर्य हैं जिनका कार्यान्वयन वाणिज्य वैंकों द्वारा किया जाएगा। इन योजनाश्रों का मुख्य उद्देश्य यह है कि छोटे कृषकों को लाभदायक सहायक धंधे प्रदान किये जाएं भ्रौर इन राज्यों में सुभ्रर-पालक के गुणात्मक श्रौर साथ ही मान्ना संबंधी पहलुश्रों पर जोर देकर उनकी श्राय में वृद्धि की जाए।
- 7.7 पिछली रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि दक्षिणी क्षेत्रों के छोटे बागान मालिकों की समस्याग्रों का प्रध्ययन करने के लिए एक ग्रनीपचारिक सलाहकार समिति की स्थापना की गई है। इस समिति के निर्णयों के श्रनुसार निगम के प्रधिकारियों ने सकलासपुर क्षेत्र (कर्नाटक राज्य) में काफी के छोटे उत्पादकों की समस्याग्रों का पता लगाने के लिए वाणिज्य और सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों की सहायता से एक श्रध्ययन किया था। यह श्रध्ययन काफी के छोटे बागान मालिकों अर्थात् इस क्षेत्र में काफी की खेती कि ग्रंतर्गत ग्रानेवाली 25 एकड़ से कम भूमित्राले लोगों तक सीमित था। इस क्षेत्र के छोट बागान मालिकों में से प्रधिकांश के पास काफी की खेतीवाली भूमि दो एकड़ से भी कम है। इस श्रध्ययन से छोटे बागान मालिकों को प्रभावित करने वाली बुराईयां स्पष्ट रूप से उजागर हो गई हैं और इससे काफी उत्पादन के ग्रंतर्गत ग्रानेवाले क्षेत्र को बढ़ाने के श्रलाया वर्तमान बागानों में काफी उत्पादकता में बृद्धि करने की जो गुजाइश है, उसका पता लगा है। छोटे बागान मालिकों को एकमुख्त तकनीकी तथा ग्राधिक सहायता की ग्रावख्यकता है। दल ने यह श्रनुमान लगाया है कि करीब 4000 एकड़ भूमि को फिर से काफी की खेती के ग्रंतर्गत लाये जाने, करीब 3000 एकड़ भूमि में फिर से पौद लगाने और करीब इतनी ही भूमि में नई पौद लगाने की श्रावख्यक होगा। यह श्रनुमान है कि छोटे बागान मालिकों के बागानों के पुनः स्थापन से उनकी श्राय में चौथे वष या उसके बाद से प्रति एकड़ 600 रु० की वृद्धि होगी जबिक फिर से पौद लगाने/तयी पौद लगाने से उनको श्राय में सातवें वर्ष से प्रति एकड़ 490 रुपये की वृद्धि होगी। यह परियोजना प्रायोगिक स्वरूप की है और इससे बहुमूल्य ग्रनुभव तथा ग्रन्य स्थानों पर दूसरे प्रकार के बागानों के लिए पोषक ग्राधार प्राप्त होगा।
- 7.8 निगम की दूसरी चिंता यह है कि छोटे किसानों श्रीर समाज के श्रन्य कमजोर वर्गों को प्रदान किये जाने वाला पुनर्वित्त का महत्वपूर्ण भाग कित माध्यम से दिया जाए। निगम ने, कुषु निगम ऋण परियोजना के श्रन्तर्गत श्रीय संघ से यह वायदा किया है कि वह इस पुनर्वित्त के कम से कम 50 प्रतिशत का इस वर्ग के लाभार्थ दिया जाना सुनिष्चित करेगा। पूरे देश के लिए सामान्यतः जो 'गरीबी रेखा' मानी जाती है उत्तराध्यान रखते हुए इन कमजोर वर्गों की परिभाषा निष्चित करने के लिए उसका सरल श्रर्थ लगाया गया है। यह पहले श्रपनायी गयी परिभाषा में किया गया एक स्पष्टतः सुधार है।
- 7.9 निष्पत्ति-बजट बनाने को प्रिक्षिया के एक श्रंग के रूप में राज्य सरकारों श्रीर कुछ भूमि विकास बैंकों श्रीर वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधियों की ग्रलग ग्रलग बैंठकों श्रायोजित की गयी हैं। इन बैंठकों ने बैंकों को स्वीकृत योजनाश्चों की प्रगति का मूल्यांकन करने, ग्रनुमोदित कार्यक्रयों के किशान्वयन में उनके सामने श्रानेवाली समस्याश्रों श्रीर निगम से किए गए श्राहरणों के माध्यम से भावी कार्य के लिए उनसे की जानेवाली श्राशाश्चों पर ध्यान देने का कार्य किया है।
- 7.10 निगमद्वारा सदस्य-बैंकों को वितरित राशियों के मूल्यांकन से यह पता लगा है कि जहां विभिन्न ऐजेंसियों का ध्यान योजना निरूपण श्रीर कृषु निगम से स्वीकृतियां प्राप्त करने की श्रीर गया है वहां श्रनुभोदित कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन म सुधार की गुंजाइश है। निगम द्वारा वायदा की गई राशि श्रीर उसमें से वित्त पोषक बैंकों द्वारा किए गए वास्तविक श्राहरणों के बीच श्रभी भी काफी कभी है। क्रियान्वयन की इस धीमी गति पर उन सब लोगों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए जो कृषि विकास के कार्यक्रमों से संबद्ध हैं।
- 7.11 निगम, एक नये स्वरूप के जिस कार्यकलाप का उपक्रम कर रहा है, वह वन-विकास का वित्तपोषण है। कृषि के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट "वानिकी-उत्पादन—मानव निर्मित वन" में अपना ध्यान वन विकास निगमों की स्थापना के द्वारा इस देश में वन सम्पदा के विकास की और केन्द्रित किया है। संरक्षण पर आधारित परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में उत्पादन-वानिकी के संक्रिय कार्यक्रम का दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है। वन विकास के लिए भारी परिव्ययों और प्रारंभ से लेकर उत्पादन तक के लिए लम्बी अवधि की आवश्यकता होगी। वन-विकास के कार्यकलाप भी विविध और जटिल हैं। एक और जहां आवश्यक अवस्थापना-सुविधायों प्रदान करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों के निर्धारित सामान्य बजट विनिधानों से पूरा किया जाना चाहिए वहीं दूसरी और वन के वास्तविक विकास के लिए

निधियों की पूर्ति संस्थानिक बित्त से करनी होगी। निगम का यह मत है कि इस प्रकार के कार्यक्रम के सफल कियान्वयन के लिए बैंकिंग की बहु-विध व्यवस्थाओं की शावश्यकता होगी। सामान्यतः यह श्राशा की जाती है कि किसी परियोजना में दो या तीन वाणिज्य बैंक भाग लेंगे। एक बार व्यायक दृष्टिकोण निश्चित हो जाने पर पर्यवेक्षण, मिली जुली जमानत, प्रलेखन श्रादि के लिए सभी वित्तपोषक संस्थाओं की जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है।

- 7.12 निगम ने पिष्चम बंगाल, विहार श्रीर श्रांध्र प्रदेश के लिए तीन वन परियोजनायें सिद्धान्ततः श्रनुमोदित कर दी हैं। इन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने की बैंकिंग व्यवस्थाओं का शीघ्र ही निर्धारण किया जायेगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, श्रन्दमान और निकोबार द्वीप, उड़ीसा श्रीर केरल ने भी श्रपने क्षेत्रों में वन विकास के कार्यक्रम तैयार किये हैं। श्रंवि संघ के एक वानिकी श्रायोग ने निगम द्वारा श्रनुमोदित तीन परियोजनाओं के विषय में निगम से महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया है। यदि देश के विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक श्राधार पर बनों का विकास तेजी से किया जाता हैं, इस विकास के लिए श्रंवि संघ से भी निधियां प्राप्त हो सकती हैं। इस प्रक्रिया में यह बात आनंदवायक कि है कुछ राज्यों, विशेषतः पूर्वी श्रीर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सरकारों, ने श्रपने श्रपने राज्यों में वन विकास निगमों की स्थापना के लिए पहल की है।
- 7. 13 विभिन्न कारणों के फलस्वरूप, सिचाई के मुख्य निर्माण कार्यों से उत्पन्न सिचाई-सुविधाओं का ग्रिधकांगतः कम उपयोग हो पाया है। सिचाई ग्रायोग ग्रीर राष्ट्रीय कृषि श्रायोग ने इस वात पर जोर दिया है कि कृषि के ग्रिधिकतम उत्पादन हेतु उपलब्ध कृषि सुविधाओं के पूर्ण उपयोग के लिए सिचाई, भूमि ग्रीर कृषि कार्यों से सम्बंधित विभागों के बीच समन्वय की ग्रावश्यकता है। इस पृथ्ठभूमि में ही भारत सरकार ने कमान क्षेत्र के स्वायत्त विकास प्राधिकरणों की स्थापना का निश्चय किया था ताकि अन्य बातों के साथ-साथ यह निश्चित हो सके कि विभिन्न नियमों की पूर्ति ग्रीर खेतिहरों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए समेकित कार्रवाई की जा सके। जहां एक ग्रीर संस्थागत वित्त जमीन को ग्रावार-प्रकार देने ग्रीर उसे समतल बनाने जैसी खेतों के ऊपर की मदों के लिए उपलब्ध होगा, वहीं दूसरी ग्रीर योजना साधनों से सिचाई प्रणालियों के पुनःस्थापन ग्रीर उनके ग्राधुनिकीकरण के साथ-साथ उन्हें मजबूत बनाने ग्रयवा सड़कों ग्रीर बाजारों जैसी श्रवस्थापना सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
- 7 . 14 निगम कमान क्षेत्र की विकास परियोजनाम्रों के हेतु संस्थागत वित्त प्रदान करने के कार्य में सिक्रय रूप से सम्बद्ध है । म्रंपुवि बैंक/ म्रंबि संघ ने कमान क्षेत्रों के विकास की तीन परियोजनाम्रों की मंजूरी दी है जिनमें से दो राजस्थान में म्रौर एक म्रन्य मध्य प्रदेश में है । इन परि-योजनाम्रों के म्रन्तर्गत खेतों के ऊपर किये जाने वाले निवेश के लिए निधियां निगम के माध्यम से प्रदान की जायेंगी ।
- 7.15 इस वर्ष के दौरान, निगम ने श्रांध्र प्रदेश ग्रौर महाराष्ट्र के कमान क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए संस्थागत वित्त पोषण से सम्म बन्धित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए उनकी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की, एक बैठक ग्रायोजित की थी। इस बैठक में योजना ग्रायोग ने भी भाग लिया था। राज्य भूमि विकास निगमों द्वारा किसानों के वित्त पोषण की निश्चित मात्रायें, बंधकों का संग्रहण ग्रौर बैंक 'ऋणों की वसूलियां जैसी समस्यायें श्रव हल कर ली गई हैं।

वित्त

1973-74 स्रोर 1974-75 के दो वर्षों के दौरान भ्रपने उधार कार्यक्रम के वित्तपोशण के लिए निगम की निधियों के प्रधान स्रोत स्रोर साथ ही 1970-71 से 1974-75 तक के पांच वर्षों के दौरान विभिन्न मदों की प्रवृत्तियां नीचे दी गयी सारणी में दर्शायी गयी हैं। :---

सारणी 7 निधियों के स्रोत

									(करोड़	रुपयों में)
		~				कुल से		कुल से	जुलाई 1970-	कुल में
			स्रो	ন'	. 1973-74	प्रतिशत	1974-75	प्रतिशत	ज्न 1975	प्रतिशत
1.	चुकता शेयर पूंजी श	प्रीर श्रा	रिक्षित रा	शियां/						
	ग्रिधिशेष	-			0.68	0.7	6,22	5.1	17.63	4.5
2.	भारतीय रिजर्वबैंक	द्वारा	की गयी	विशेष						
	जमा .		•		0.24	0.2	0.38	0.3	1.04	0.3
3.	भारत सरकार से लिए	र्गए उ	धार							
	(क) अयंविसंघकी वि	निधि			38.62	37.8	33.12	27.1	115.75	29.8
	(ख) ग्रन्य				0.03				36.07	9.3
4.	भारतीय रिजर्व बैंक रे	ते लिए	गए उधार							
	(क) रा०कृ०ऋ०	(दी०	দা০ স০)	निधि	23.00	22.5	40.00	32.8	98.00	25.2
	(ख) ग्रन्य			•	7.90	7.7		-:-	15.73	4.1
5.	बांड .			•	27.50	26.9	33.00	27.1	88.27	22.7
6.	बैंकों हारा ग्रदायगियां				4.23	4.1	9.27	7.6	16.00	4.1
	जोड़ 	•	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	102.20	100.00	121.99	100.00	388.49	100.00

8.2 शेंयर पूंजी

इस वर्ष के दौरान निगम ने 5 करोड़ रुपयों के चुकता मूल्य के शेयरों की चौथी सीरीज ज़ारी की है। इन शेयरों पर गारंटीकृत न्यूनतम लाभांश 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से निर्धारित किया गया है। 30 जून 1975 को निगम की कुल चुकता पूंजी 20 करोड़ रुपये थी। 30 जून 1975 को निगम की शेयर पूंजी में शेयरधारियों के विभिन्न वर्गों का अभिदान नीचे दर्शाये गये ब्रनसार है :--

सारणी 8

शेयर पूंजी में स्रभिदान

(करोड़ रुपयों में)

						1	ा	
संस्था के स्रोत						संख्या	न् य	कुल से प्रतिगत
भारतीय रिजर्व बैंक		•		•		11,529	11.53	57.65
केन्द्रीय भूमि विकास बैंक	•					3,263	3.26	16.30
राज्य सहकारी बैंक .		•	•	•		1,762	1.76	8.80
ग्र नुसूचित वाणिज्य बैंक		•	•	•		3,231	3.23	16.15
भारतीय जीवन बीमा निगम		•		•		193	0.19	0.95
भ्र न्य बीमा भ्रौर निवेश कंपनिय	rt	•	•			2 1	0.02	0.10
सहकारी बीमा समितियां			•	•		1	0.01	0.05
जोड़	-				•	20,000	20.00	100.00

8.3 कृषि पुर्नित्रत्त निगम श्रधिनियम, 1963 में किये गये एक संशोधन के श्रनुसार रिजर्य बैंक केन्द्रीय सरकार के पूर्व श्रनुमोदन से निगम की प्राधिकृत पूंजी की जो वर्तमान सीमा 25 करोड़ रुपये है उसे बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर सकता है। चूंकि निगम की उधार लेने की शक्ति चुकता। पूंजी श्रीर श्रारक्षित निधि के 20 गुने तक सीमित है, निगम के लिए यह श्रावश्यक है कि वह कृषि निवेशों के लिए बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए श्रपनी शेयर पूंजी श्रीर तदनुसार श्रपनी उधार लेने की शक्ति को मजबूत बनाये। निगम का प्रस्ताव है कि वह शीध्र ही 5 करोड़ रुपयों के नये शेयर जारी करेगा।

भारत सरकार से लिए गए उधार

8.4 इस वर्ष के दौरान ग्रंबि संघ/प्रंपुवि बैंक परियोजनाश्रों के श्रधीन ऋणों की रुपया तुल्य राशि की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार से लिए गये उधारों की राशि 33.1 करोड़ रुपये है जिससे भारत सरकार से लिए गए कुल उधारों की राशि बढ़कर 196.6 करोड़ रुपये हो गयी है। ग्रालीच्य वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने 1 ग्रगस्त 1974 से श्रपनी उधार दरों में प्रतिशत की बृद्धि करके उन्हें 9 श्रीर 15 वर्षीय ऋणों के संबंध में कमशः $6\frac{2}{4}$ प्रतिशत श्रीर $7\frac{1}{4}$ प्रतिशत बना दिया है तथा ब्याज की ठीक समय पर श्रदायगी करने के लिए $\frac{1}{4}$ प्रतिशत की छूट दी गयी है।

बाजार के लिए गये उधार

8.5 इस वर्ष के दौरान निगम ने दो बार बाजार ऋण जारी किये हैं। उसने 33.00 करोड़ रुपयों की राशि जुटाने के लिए पहली बार अक्तूबर 1974 में (VII सीरीज) और दूसरी बार मई 1974 में (VIII सीरीज) बांड जारी किये हैं। 10 वर्ष की पुगाई अवधिवाले ये बांड 99.00 रुपये पर जारी किये गये हैं और इन पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय हैं। वर्ष के अंत में बाजार से लिए गये उधारों की कुल राशि 99.21 करोड़ रुपये हो गयी है। आगे की सारणी में वर्ष के दौरान जारी की गई दोनों सीरीजों के लिए विभिन्न वर्गों के आभिदाताओं से प्राप्त राशियां और पिछले इजरों में उनका संचित अभिवान दर्शाया गया है:

सारणी 9 बांडों का अभिदान

(करोड़ रुपयों में)

श्रभिदाता		·*************************************		I से IV	VII	VIII	जोड़
1. स्टेट बैंक श्राफ इंडिया श्रीर	 : उसके सह	ायक बैंक		15.89	3, 19	3.68	22.76
 राष्ट्रीयकृत बैंक . 	•	•	•	30.66	6.60	7.20	44.46
3. भ्रन्य वाणिज्य बैंक .				3.83	0.97	1.33	6,13
4. भारतीय जीवन बीमा निग	म .		•	0.65	0.15	0.15	0.95
5. ग्रन्य बीमा कंपनियाँ			•	0.13	0,06	0.02	0.21
 सहकारी बैंक . 				14.80	5.42	3.69	23.91
7. श्रन्य	٠.			0.25	0.11	0.43	0.79
जोड़ .			_	66.21	16.50	16.50	99.21
7.2	•	-	-	*			

भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार

- 8.6 1974-75 के दौरान भारतीय रिजर्य बैंक ने राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से आहरण के लिए 40 करोड़ रूपयों की और अधिक सीमा मंजूर की है और निगम ने इस पूरी सीमा के उधार प्राप्त किए हैं। पहले के ऋणों की अदायगी के लिए 5.80 करोड़ रूपयों की व्यवस्था करने के बाद रिजर्य बैंक को निगम द्वारा देय राणि जून 1975 को 88.2 करोड़ रूपये थी।
- 8.7 इसके ग्रितिरिक्त निगम भारतीय रिजर्य बैंक से ग्रन्थाविध ऋणों के लिए 15.00 करोड़ रुपयों की सीमा का भी लाभ उठाता जा रहा है ग्रीर इस लेखे के श्रधीन 30 जून 1975 को 4.5 करोड़ रुपयों की राशि बकाया थी। चूंकि यह सुविधा केवल बैंक दर पर प्राप्त होती है जो इस समय काफी श्रधिक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष है, ग्रन्य स्रोतों से निधियाँ प्राप्त होने तक और चालू साधनों से श्रधिक के वितरणों को पूरा करने के लिए इस वर्ष इस वर्ष के ग्रधीन लिए गये उधारों का उपयोग केवल न्यूनतम श्रविध के लिए ग्रीर श्रत्यंत श्रावश्यक सीमा तक किया गया है।

ऋणों की अदायगी

8.8 इस वर्ष सदस्य बैंकों से प्राप्त ऋणों की ग्रदायगी की राणि पिछले वर्ष के 4.23 करोड़ रुपयों की तुलना में 9.27 करोड़ रुपये है। 30 जुन 1975 के ग्रन्त तक कुल ग्रदायगी की राणि 16.21 करोड़ रुपये है श्रौर इसका एजेंसीवार विवरण नीचे दिया गया है:--

सारणी 10 श्रदायगियां

(करोड़ रूपयों में)

~ ^					श्च	श्रदायगियाँ				
एजेंसी					क्रुपु निगम की योजनाएँ	श्रंवि संघ द्वारा सहायता की गई योजनाएँ	जोड़			
1. श्रनुसूचित वाणिज्य बैंक	1			+	5.26	0.67	5.93			
2. राज्य भूमि विकास बैंक					0.46	6.29	6.75			
 राज्य सहकारी बैंक 			•		3.53		3.53			
जोड्	7	•			9.25	6.96	16.21			

^{8.9} इस वर्ष के दौरान सदस्य बैंकों द्वारा की गयी ऋणों की श्रदायिगयाँ पिछले वर्ष की तुलना में 5 करोड़ रुपये श्रधिक है। श्रंवि संघ की चालू ऋण परियोजनाओं के श्रधीन भूवि बैंक के डिबेंचरों के वार्षिक विमोचन के फलस्वरूप श्रपेक्षाकृत इस श्रधिक राशि की प्राप्ति संभव हो सकी है। यह श्राणा की जाती है कि इससे निगम के पास उपलब्ध निधियों का शीझता से वार-बार उपयोग किये जाने में सुविधा होगी।

सदस्य

8.10 दो श्रौर वैंक श्रथित श्रलगमने बैंक नीदरलैंड एन० वी० श्रौर पूर्वाचल एक लिमिटेड निगम के सदस्य बन गए हैं। कृष्णराम बलदेव बैंक लिमिटेड निगम का सदस्य नहीं रह गया है। इस प्रकार 30 जून 1975 को निगम के सदस्यों की संख्या 110 है जब कि जून 1974 के श्रत में यह 109 थी।

निदेशक बोर्ड

- 8.11 इस वर्ष निदेशक बोर्ड की 6 वैठकें हुई हैं। श्री विभुवन प्रसाद सिंह का मई 1975 में देहांत हो गया है। वे 18 श्रप्रैल 1970 से 3 नवम्बर 1972 तक निगम के निदेशक भी थे। बोर्ड ने उनके परिवार को श्रपनी हार्दिक संवेदनायें भेजी हैं। हिंदी का प्रयोग
- 8.12 निगम के दैनिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग का प्रचार करने के लिए उसे भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन सिमिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्नों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं। सभी प्रधिकृत प्रधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां भ्रादि, हिन्दी श्रौर श्रंग्रेजी में एक साथ प्रकाणित की जाती हैं। निगम की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी श्रौर श्रंग्रेजी दोनों में ही छापी जाती हैं। हिन्दी के प्रयोग का प्रचार करने के लिए श्रौर कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान कर ने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो कदम उठाये गये हैं निगम ने उनसे स्वयं को संबद्ध कर लिया है।

लाभ

8.13 1974-75 के दौरान निगम को विनियोजन के लिए प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि 166.24 लाख रुपए है। यह राशि विशेष प्रारक्षित निधि में वित्त ग्रिधिनियम 1971 के प्रधीन प्रनुमत वर्तमान लाभों के 10 प्रतिशत के लिए 45 लाख रुपए की व्यवस्था करने के बाद बची है। निदेशक बोर्ड इस राशि को नीचे लिखे प्रनुसार विनियोजन करने की सिफारिश करता है:---

(लाख रुपये)

म्रारक्षित निधि को म्रंतरप	ग		-						77.63
शेयरों पर लाभांश	•	٠	•	•	•	•	•	•	88.61
								 	166.24
									निदेशकों की स्रोर से

19 ग्रगस्त 1975

ग्रध्यक्ष

परिशिष्ट कृषि पुनवित निगम

ऋण परियोजना

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (अवि संघ) ने कुपु निगम ऋण परियोजनाओं के लिए 750 लाख डालर के ऋण मंजूर किए हैं और श्रंवि संघ के साथ इस सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है उस पर 28 अप्रैंस 1975 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजनाओं में लघु सिंचाई और कृषि की जिन अन्य विविध परियोजनाओं के लिए भाग लेनेवाले बैंकों द्वारा दिए जानेवाले ऋणों के सम्बन्ध में कुपु निगम द्वारा पुनर्वित प्रदान किया जाना है, उनके हिताधिकारियों द्वारा निवेशों के वित्तपोषण के लिए दो वर्षीय कार्यक्रम शामिल है: अवि संघ द्वारा मजूर किए गए ये ऋण उन ऋणों के अलावा होंगे जो कुछ राज्यों में आजकल चल रही वर्तमान श्रंवि संघ ऋण परियोजनाओं के लिए मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना की समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर 1977 है। परियोजना के घटक नीचे लिखे अनुसार हैं :

- (i) लघु सिचाई ग्रौर अन्य विशाखीकृत कृषि निवेशों का वित्तपोषण, ग्रंवि संघ द्वारा लघु सिचाई वर्ग के श्रधीन प्रतिभूति के लिए 690 लाख डालर निर्धारित किए गए हैं जबकि लघु सिचाई को छोड़कर अन्य विशाखीकृत प्रयोजनों के श्रधीन 50 लाख डालर उपलब्ध किए जाएंगे।
- (ii) ग्रल्पाविध ग्रौर दीर्घविध सहकारी ऋण संस्थाग्रों के विलयन की संभाव्यता का ग्रध्ययन।
- (iii) भूबि बैंकों के कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की श्रावश्यकताश्रों का श्रध्ययन श्रौर इन कर्मचारियों का प्रशिक्षण; श्रौर
- (iv) जो भूवि बैंक, वित्त पोषक संस्थायें श्रौर श्रन्य एजेंसियां, परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बद्ध हैं, उनके वरिष्ठ ग्रौर मध्यस्तरीय कर्मचारियों के लिए दो वर्ष का एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

जार दर्शाई गई (ii) से (iv) मदों के कार्यान्त्रयन के लिए खर्च किए जानेवाले व्यय के लिए 10 लाख डालर की ऋण-व्यवस्था की गयी है।

परियोजना के श्रन्य पहलुग्नों का नीचे के पैराग्राफ़ों में उल्लेख किया गया है। धिकारी

'हिताधिकारी' की किसी ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के किसी समूह, सहकारी समिति, निगम या ब्रन्य रुत्ता के रूप में परिभाषा की गयी है जो परियोजना के श्रधीन भाग लेनेवाले बैंक से ऋण प्राप्त करने के योग्य हैं।

II परियोजना में भाग लेने के लिए योग्य बैंक

इस परियोजना में राज्य भूमि विकास बैंक, उनकी शाखाएं और प्राथमिक भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और श्रमुस्वित वाणिज्य बैंक भाग लेने के योगा हैं। फिर भी राज्य सहकारी बैंकों को प्रदान किए जानेवाले पुनर्वित्त के लिए श्रीय संघ से दाया की जानेवाली राश्रि 5000,000 डालर से श्रिधिक नहीं होनी चाहिए। भाग लेने वाले बैंकों को परियोजना के श्रधीन परिक्किल्पत तकनीकी और वित्तीय नियमों का पालन करना होगा।

क्रंपु निगम प्रत्येक भाग लेनेवाले बैंक से पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए श्रलग-श्रलग ऐसे समझौते वरेगा जिनमें उन मतीं का ब्यौरा दिया जाएगा जिनके श्रधीन श्रन्तिम उधार कत्तिश्रों को निधियाँ उपलब्ध की जायेंगी श्रौर इन निधियों पर इस परियोजना के श्रधीन पुनर्वित्त प्राप्त किया जाएगा।

Ⅲ लघु सिंचाई

(ग्र) योग्य प्रयोजन

"लघु सिचाई" पद के ब्रन्तर्गत भूमिगत जल श्रौर सतही स्रोतों का दोहन ब्राता है श्रौर इसके श्रन्तर्गत खुदाईवाले कुश्रों, नलकूपों, गहरे तत्रकूपों, पम्प सेटों, उद्वाहन सिचाई यूनिट ग्रादि जैंसे साधन श्राते हैं। लघु सिचाई में वित्त-पोषिल सिचाई स्रोतों के कमान क्षेत्रों का विकास क्रौर जल मार्गों के निर्माण के लिए दिए ऋण का श्रंश भी शामिल है।

(आर) उधार की शर्ते

(क) श्राजन ग्रंब संघ की चालू योजनाओं के ग्रधीन 'लघु कुषक' की ऐसे (एक) किसान के रूप में परिभाषा की गई है जिसकी विकासोत्तर शुद्ध ग्रामदनी 2400 रुपये हो शौर उसके निवेशों की सागत की श्रधिकतम सीमा 100,00 रुपये हो। इस प्रकार इस तरीके से परिभाषा किए गए लघु कृषक रियायती दरों पर ग्रथीत कम नकद ग्रदायगी ग्रौर ऋण के भुगतान की लंबी ग्रविध के लिए ऋण पाने के योग्य हैं। इस परिभाषा में संशोधन किया गया है और इसे छुपु निगम ऋण परियोजनाग्रों के ग्रधीन ग्रिधिक उदार बना दिया गया है। अब "लघु कृषक" पद की जो परिभाषा की गई है उसके श्रन्तगंत ऐसा कोई भी कृषक श्राता है जो स्वयं ग्रौर ग्रपने परिवार के पारिवारिक साधनों से 1972 के मूल्य के ग्राधार पर 2,000 रुपयों से ग्रनधिक की विकासपूर्व ग्राय प्रदान करनेवाली भूमि जोतता हो। जिस राज्य में भूमि स्थित है उसके ग्रखिल भारतीय श्रमिक सूचकांक को लागू करने पर ग्रागामी वर्षों में होनेवाले किन्हीं प्रकार के मूल परिवर्तनों का ध्यान रखकर इस राशि समायोजन किया जा सकता है। पारिवारिक माधनों में होनेवाली उक्त शुद्ध ग्राय को निर्धारित करने के प्रयोजन से "भूमि" के ग्रन्तगंत, ऐसी सारी जमीनें श्रायगी जिन पर कृषक द्वारा वास्तव में खेती की जाती है चाह वे कृषक के स्वामित्व की हो या ग्रन्य प्रकार की। "पारिवारिक साधनों में होनेवाली गुद्ध ग्राय" की परिभाषा के ग्रन्तगंत भूमि से होनेवाली सकल ग्रामदनी में से वास्तव में किए गए लागत खर्चों को घटाकर बची हुई राणि है। (लागत खर्चों से कृषक द्वारा लगाई गई खेती की उपज बढ़ानेवाली चीजों जिनम, बीज, उर्वरक मजदूरी पर काम करनेवाले मजदूरों, भाड़े पर लिए गए बैंलों, परिवार के बैलों द्वारा उपयोग किए गए खर्च का नकदी मूल्य ग्रामिल है।)

इस बीच निगम ने 1974 के कैंलैंडर वर्ष के लिए 1972 के मूल्यों पर ग्राधारित तदनुरूपी संशोधित श्रांकड़ों का हिसाब लगाया है जो 2,000 रुपये होता है। निगम के क्षेत्रीय कार्यालय ग्राधारभूत कृषि ग्रांकड़ों को एकत करने के लिए स्थानीय क्षेत्रों का मुश्राइना करेंगे ताकि विभिन्न निवेशों से होनेवाली विकास-पूर्व ग्रौर विकासोत्तर श्रामदनी का ग्रनुमान लगाया जा सके। इन ग्रध्ययनों के श्राधार पर ग्रामदनी सीमाग्रों का एकड़ सीमाग्रों में रूपान्तरण कर दिया जाएगा। खेतों के बहुत से नमूनों की सहायता से क्षेत्रीय कार्यालय इस नायक हो सकेंगे कि वे कृषकों के विभिन्न समूहों के लिए एकड़ स्तर का पता लगा सकें।

रियायतों के योग्य होने के लिए लघु कृषकों द्वारा की जानेवाली निवेश लागत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इससे वित्त-पोषक संस्थायों पर अपेक्षाकृत अधिक भारी जिम्मेदारी आ जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निवेशों का भुगतान वृद्धिशील उपार्जित श्राय से हो जाए।

इस परियोजना का दूसरा पहलू यह है कि लघु सिचाई ग्रीर विशाखीकृत निवेशों के लिए ऋण का पचास प्रति<mark>शत भाग</mark> ग्रयित् 370 लाख डालर विशेष रूप से इसलिए ग्रलग रखा गया है कि उससे छोटे कृषकों को दिए जानेवाले ऋणों के लिए पुनर्वित प्रदान किया जाए।

(ख) नगद भगतान

निवेश लागत के एक भाग को पूरा करने के लिए हिताधिकारियों को अपने श्रम तथा नकदी या चीजों के रूप में श्रंण-दान करके अभिदान करना होगा। भूमि विकास बैंकों के मामले में नकद, भुगतान में कृषकों द्वारा भूवि बैंकों के शेयरों की श्रमिन वार्य खरीद शामिल होगी। नकद भुगतान के प्रयोजन के लिए हिताधिकारियों को तीन वर्गों में बांटा गया है; (i) 1972 के मूल्यों के श्राधार पर 2,000 रुपयों तक की विकास पूर्व की शुद्ध आयवाले लघु कृषक (ii) 1972 के मूल्यों के आधार पर 2,001 रुपयें और जै,500 रुपयों के बीच विकास पूर्व की शुद्ध आयवाले कृषक श्रौर (iii) श्रन्य कृषक श्रथात् 3,501 रुपये श्रौर उससे अधिक की विकास पूर्व की शुद्ध आयवाले कृषक । इन तीन वर्गों के कृषकों के लिए नकद भुगतान से सम्बन्धित निर्धारित श्रांकड़े नीचे दिए गए हैं:

कृपः	कों का वर्ग		 -	 		 निवेश लागत	न प्रतिशत का प्रतिशत
							लघु सिचाई नवेश
,	1. लघु कुषक			 	•	5	5
	2. वर्ग (ii) के कुषक		•	•		10	10
	3. ग्रन्य कृषक	•	•		•	10	, 15

लघु कृषकों के मामले में भूवि बैंकों द्वारा श्रनियार्य शेयर पूंजी की राशि को एक या दो किश्तों से वसूल किए जाने पर कोई श्रापत्ति नहीं है!

(ग) ऋणों की पुनाई ग्रवधि

परियोजना के श्रधीन हिनाधिकारियों को दिए गए ऋणों की श्रवधि उनकी श्रदायगी की क्षमता पर ग्राधारित होगी ग्रौर वह ग्रास्ति के उपयोगी जीवन के श्रनुरूप होगी परन्तु वह नीचे दर्शायी गयी ग्रवधि से श्रधिक नहीं होगी —

	लघुकुषक	ग्रन्य कृषक
(
ा. पंपसेट चाहे उसका वित्तपोषण घ्रलग ऋण या समिष्टिक ऋण के रूप में किया गया हो	7 वर्ष	७ वर्ष
2. भ्रत्य लघु सिचाई प्रयोजनों के लिए	1.5 वर्ष	9 व र्ष

निगम के विवेक पर 'खरीफ' ग्रौर 'रबी' की पूरी फसल को ध्यान में रखते हुए ऋण की पहली किस्त की तारीख से 23 महीनों से श्रनधिक की उचित रियायती श्रवधि मंजूर की जा सकती है बगतें कि दी गई रियायतों से श्रदायगी की श्रवधि ऊपर दर्शाई गई ग्रवधियों से श्रिधक न हो।

भाग लेनेबाले बैंकों को परियोजना के ग्रधीन लिए गए पुनर्वित्त की ग्रदायगी ऐसी वार्षिक किस्तों में करनी होगी जिनकी मात्रा हिताधिकारियों द्वारा भुगतान की जानेवाली किस्तों से सम्बद्ध होगी। भूमि विकास बैंकों के मामले में इसका ग्रर्थ यह होगा कि विशेष विकास डिबेंचरों के कुछ भाग का वार्षिक विमोचन हो जाएग्।

(घ) तकनीकी नियम

लघु सिचाई निवेशों के मामले में भाग लेनेवाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना समझौते में उल्लिखित कुओं के बीच के स्थान ग्रीर उनकी सघतता के सिद्धान्त का पालन किया जाए। लघु सिचाई के प्रयोजन के लिए किसी योजना का ग्रानुमोदन किए जाने से पहले भूमिगत जल स्रोतों का विस्तृत तकनीकी श्रध्ययन किया जाए। विभिन्न राज्यों के भूभिगत जल निदेशालयों से विचार-विमर्श करके केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड उन क्षोतों की एक सूची तैयार करेगा जहां भूमिगत जल के श्रधिदोहन का खतरा है। इन क्षोत्रों में नए सिरे से वित्तपोषण करने से पहले राज्य भूमिगत निदेशालयों को चाहिए कि वे निवेशों की सार्थकता के लिए एक विशेष श्रध्ययन कर लें।

परियोजना में भाग लेनेवाले भूवि बैंक भ्रौर उसके प्राथमिक बैंक के लिए उधार की वही गर्ते भ्रौर मानवंड लागू करना लाजिमी होगा जो परियोजना के बाहर के इसी प्रकार के उधारों पर लागू किए जाते हैं। भाग लेनेवाले वाणिज्य बैंकों से यह श्राणा की जाती है कि वे परियोजना क्षेत्रों में उधारों के एक जैसे वर्गों के लिए उधार देने की एक जैसी गर्ते लागू करें भ्रौर वे लघु कुषक विकास एजेंसियों की योजनाभ्रों को छोड़कर अन्य योजनाभ्रों के लिए श्रिधिक लाभदायक मतौं पर उधार न दें।

(इ) ग्रतिदेय के मानदंड

भूमि विकास बैंकों की योजनाश्रों के कृपु निगम के निर्धारण से सम्बन्धित एक प्रमुख विचारणीय बात यह है कि जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक ग्रथवा राज्य भूमि विकास बैंक की जो शाखायों योजनाश्रों को क्रियान्वित करेंगी उनके वित्तीय दृष्टि से शोधनक्षम होना चाहिए। ग्रतिदेयों के स्तर में हुई विद्ध से भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक श्रौर कृषि पुनर्वित निगम चितित हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश श्रौर बिहार राज्यों में श्रवि संघ के श्रधीन चलनेवाली परियोजनाश्रों के लिए कृपु निगम

पर उन प्राभूषि बैंकों राभूषि बैंकों की गाखाओं, जिनके अतिदेय किसी वर्ष के ग्रंश के 25 प्रतिशत से अधिक हैं, को उस समय तक पुनिंवित्त प्रदान करने की पाबन्दी लगा दी गई है जब तक संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिए अभिदान करके उन्हें सैद्वान्तिक रूप से कम नहीं किया जाता। भारतीय रिजर्व बैंक भी भूवि बैंकों के सामान्य डिबेंचर कार्यक्रमों को उनकी ग्रतिदेय राशियों के सन्दर्भ में विनियमित करने के लिए कतिपय मानवंड लागू करता आ रहा है। अतः यह समय इस सम्बन्ध में एक जैसे सिद्वान्तों को अपनाने के लिए अनुकृत है।

1 प्रस्तुबर 1977 से या जिस किसी श्रन्य तारीख के लिए श्रंवि संघ सहमत होगा उससे रा भूवि बैंकों, उनकी शाखाश्रों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे प्रत्येक वर्ष की मांग के 65 प्रतिशत का ऐसा नकदी बसूली स्तर प्राप्त कर लें जो मांग के 10 प्रतिशत के लिए राज्य सरकारों द्वारा ईक्विटी शेयरों में उनके द्वारा किए जाने वाले श्रिभिषान सहित मांग से बसूली की दर को 75 प्रतिशत या उससे श्रिक बढ़ाने में कारगर हो।

मन्तरिम उपाय के रूप में 30 सितम्बर, 1977 तक राभूवि बैंकों को, राभूवि बैंकों की शाखाओं या प्राथमिक बैंकों के माध्यम से दिए जानेवाले उधारों के लिए उपलब्ध किए जानेवाले पुनर्वित को नीचे दिए गए ग्राधार पर प्राभूवि बैंकों/शाखाओं द्वारा गत वर्ष (जुलाई-जून) में जारी किए गए सभी ऋणों की कुल राशि के सन्दर्भ में निर्धारित किया जाना है:

म्रतिदेय राशि (मांग का प्रतिशत) प्राभूविबैंक राभूविबैंकों की शाखायें	जारी किए जानेवाले श्रधिकतम ऋण (गत वर्ष जारी किए गए ऋणों का प्रतियत)
0-25	निर्माध
2635	80
3645	70
4655	60
5660	5 0
61100	कुछ नहीं

ऐसे प्रतिदेयों को कम करने के लिए क्रुपु निगम राज्य सरकारों द्वारा भुगतान की गयी विमोचनीय ईक्विटी पूंजी को हिसाब में ले सकता है बगर्ते कि ईक्विटी की राशि मांग के 10 प्रतिगत से प्रधिक न हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए किसी विशेष वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए वसूली कार्य में गिराषट न माने पाये ऐसे मामलों की समीक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक वांडिक खंड मनुबद्ध किया जाएगा जिनमें भ्रतिवेयों की वृद्धि गत वर्ष के भ्रतिवेयों के स्तर की तुलना में मांग के 10 प्रतिशत से ग्रधिक हो।

राज्य सहकारी बैंकों, उनकी शाखाश्रों ग्रौर प्राथमिक समितियों के मामलों में वसूलीस्तर मांग का 65 प्रतिशत होता चाहिए जो राज्य सरकार के मिषदान मांग के 10 प्रतिशत तक के सहित मांग के 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

(च) पुनर्वित के लिए जमानत

प्रत्येक योजना के लिए भाग लेनेवाले बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों श्रौर कृषु निगम द्वारा प्रदक्ष पुनर्विक्त के लिए जमानत का निर्धारण कृषु निगम द्वारा किया जाएगा।

(छ) भ्याज दर

परियोजना के प्रधीन कु० पु० निगम द्वारा प्रदान किये गये पुनर्विस पर ली जाने वाली ब्याज दर ग्रौर ग्रन्तिम उधार कर्तान्नों से ली जाने वाली ब्याज दर क्रुपु निगम द्वारा संबंधित स्वीकृति पक्षों में दर्शायी जायेगी। ये दरें पुनर्विस के लिए वार्षिक 7.5 प्रतिशत ग्रौर ग्रन्तिम उधारकर्तान्नों के लिए वार्षिक 10.5 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसके ग्रलावा भाग लेनेवाले बकों को निवेश लागत का 0.5 प्रतिशत मूल्यांकन शुरुक "एक ही बार", लेने की ग्रनुमित होगी।

(ज) खातों मादिका रखा जाना

भाग लेनेवाले बैंकों को परियोजना उधार भौर लच्च कृषकों को दिए जानेवाले उधारों के लिए मलग-प्रलग खाते रखने चाहिए। बैंकों को लेखापरीक्षा किए गए भपने वार्षिक लेखों को कृषु निगम द्वारा प्रमाणित परियोजना उधार के विवरण के साथ भपने विसीय वर्ष की समाप्ति के 4 महीनों के भीतर कृषु निगम के माध्यम से ग्रंबि संघ को प्रस्तुत करने चाहिए।

(झ) भाय की वित्तीय दर

निगम केवल उन्हीं शोधनक्षम योजनाश्चों के लिए पुनर्वित्त प्रधान करेगा जो सतर्क श्रध्ययन के ग्राधार पर वित्तीय रूप से व्यवहार्य मानी जायेंगी श्रौर जिनकी ग्राय की न्यूनतम वित्तीय दर 15 प्रतिशत होगी श्रौर जिनमें सन्तोषप्रद तकनीकी ग्रौर प्रशासनिक प्रयन्थ्य होगी।

5-469GI/75

(इ) सामान्य ग्रौर विशेष विकास डिबेंचरों के कार्यक्रम का समन्वय

भारतीय रिजर्व बैंक भी भूमि विकास बैंकों के सामान्य डिबेंचर कार्यक्रम को विनियमित करते हुए श्रतिदेय राशियों के लिए वही मानदंड श्रपनाएगा जो ऊपर बताए गए हैं। भूवि वैंकों के वित्तीय निष्पादन का श्रन्वीक्षण करने और सभी भूवि बैंकों के डिबेंचरों को जारी करने के प्रयोजन से एक समिति गठित की जा रही है।

(ई) लघु कृषक विकास एजेंसी (लवि एजेंसी) की योजनाएं

वर्तमान परिस्थितियों में लक्कवि एजेंसी योजनाम्रों के भ्रन्तर्गत दिए गए पुनर्वित्त के सम्बन्ध में इस परियोजना के म्रधीन किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी क्योंकि इसमें श्राधिक सहायता का श्रंग शामिल है। फिर भी, भारत सरकार भौर कुपु निगम इन कार्यक्रमों को भी कृपु निगम ऋण परियोजना के अन्तर्गत शामिल करने के लिए ग्रंवि संघ से लिखा पढ़ी कर सकते हैं।

IV. विशाखीकृत उधार

(क) थोग्य प्रयोजन

विशाखीकृत उधार के श्रन्तर्गत श्रानेवाले प्रयोजनों में डेरी, मुर्गीपालन, रेशम उत्पादन, मछली पालन, बागबानी, बागान, ग्रादि शामिल होंगे। इन प्रयोजनों में इसके सिवाय कोई श्राग्रह नहीं है कि इन परियोजना के ग्रधीन इनसे संबंधित विपणन ग्रथवा भंडारण की योजनायें श्रंवि संघ के पूर्व श्रनुमोदन के बिना मंजूर नहीं की जा सकती।

(ख) उधार की मर्तें

विशाखीकृत उधारों के प्रयोजनों के लिए हिताधिकारियों को भी उन्हीं तीन वर्गों में बांटा गया है जिनमें उन्हें लघु सिचाई वर्ग के मामले में नकद भुगतान के प्रयोजनों के लिए बांटा गया है। इन योजनाओं के सम्बन्ध में लघु कृषक हिताधिकारी की परिभाषा "किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जो लघु सिचाई को छोड़कर इस योजना से संबंधित किसी ऐसे कार्यकलाप में शुरू से लगा हो जिससे ऐसे व्यक्ति या उसके परिवार के पारिवारिक साधनों में विकास पूर्व की गुद्ध ध्राय में 2,000 रुपयों से ध्रनधिक वृद्धि होती हो।" बड़े किसानों द्वारा इस परिभाषा का लाभ उठाये जाने की संभावना को रोकने के लिए निगम का यह धर्त लगाने का प्रस्ताव है कि गैर जमीनी कामों को शुरू करने के लिए दिए जानेवाले ऋणों के मामले में (लघु कृषकों का पता लगाने के लिए) ग्रामदनी की नई ग्रधिकतम सीमा ग्रावेदनकर्ता ग्रौर उसके परिवार के जानेमाने-कार्यों से होने वाली कुल शुद्ध वार्षिक ध्रामदनी पर लागू की जानी चाहिए।

(ग) नकद भुगतान

लघु कृषकों, 2,001 रुपयों से 3,500 रुपयों के बीच की विकास पूर्व की शुद्ध श्राय वाले कृषकों और श्रन्य कृषकों का श्रभिदान, निवेश लागत का कमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत श्रौर 15 प्रतिशत होगा। कृषक के श्रभिदान में भूवि बैंक के श्रनिवार्य शेयरों की खरीद, स्वयं का श्रम श्रौर नकदी या चीजों के रूप में श्रन्य श्रभिदान भी शामिल रहेंगे।

(घ) पुगाई म्रवधि

ऋणों के ग्रवायगी की श्रवधि ग्रग्निम उधारकर्ताश्रों की श्रदायगी क्षमता पर ग्राधारित होगी परन्तु (जहां ग्रावण्यक हो वहां रियायती श्रवधि को मिलाकर) 15 वर्षों मे श्रधिक नहीं होगी।

(ङ) श्राय की वित्तीय दर

योजना वित्तीय रूप से सक्षम होनी चाहिए भ्रौर उसकी न्यूनतम श्राय की दर 15 प्रतिणत होनी चाहिए भ्रौर उसके लिए उपयुक्त तकनीकी भ्रौर प्रणासनिक प्रबन्ध-व्यवस्था होनी चाहिए।

5 लाख डालर (40 लाख रुपये) के कृपु निगम के पुनर्वित्त वाली विशाखीकृत उधार की ग्रलग-ग्रलग योजनायें ग्रंबि संघ की पूर्व ग्रनुमति के लिए उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट श्रौर श्रावश्यक श्रांकड़ों सहित ग्रंबि संघ को भेजनी होंगी।

(च) ब्याज दर

परियोजना के प्रधीन विशाखीकृत प्रयोजनों के लिए कृपु निगम के पुनर्वित्त पर ग्रौर श्रन्तिम उधारकर्ताश्रों से ली जाने वाली ब्याज दरें कृपु निगम द्वारा संबंधित स्वीकृत पत्नों में निर्धारित की जायेंगी। कृपु निगम के पुनर्वित्त के लिए ब्याज दर वार्षिक 8 प्रतिशत ग्रौर श्रन्तिम हिताधिकारियों के लिए वार्षिक 11 प्रतिशत में कम नहीं होगी। भाग लेनेवाले बैंक भी निवेश की लागत का 0.5 प्रतिशत मूल्यांकन शुल्क के रूप में "एक बार ही" ले सकते हैं।

V. अध्ययन और प्रशिक्षण

(क) श्रध्ययन

राज्यों में भूमि विकास बैंक अधिनियम श्रौर सहकारी समितियां श्रिधिनियम के जो संबंधित उपबन्ध लागू है वे भूमि विकास बैंकों को अल्पाविध ऋण देने की अनुमित नहीं देते। इस फलस्वरूप भूवि बैंकों से पूंजी-ऋण प्राप्त करने के लिए उधार-कर्ता को अपने उत्पादन ऋणों के लिए या तो ग्राम सहकारी समितियों या याणिज्य बैंकों से निवेदन करना पड़ता है। वसरी श्रोर वाणिज्य बैंकों के मामले में उधारकर्ता एक ही स्रोत से दीर्घाविध ऋणों श्रौर श्रल्पाविध ऋणों दोनों ही के लिए एकमुश्त रकम प्राप्त

कर सकता है। ग्रल्पावधि ग्रौर दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाग्रों का विलय करने की समस्थाग्रों ग्रौर संभाव्यता का ग्रध्ययन करने के लिए क्रुपु निगम ऋण परियोजना में एक ग्रध्ययन दल की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

(खा) प्रशिक्षण

इस प्रयोजन के लिए कि परियोजना उधार के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो कृप निगम के लिए यह मावश्यक है कि वह 31 प्रक्तूबर 1975 से पहले भवि बैंक के किनष्ठ स्तरीय कर्मचारियों की प्रशिक्षण श्रावश्यकताओं का मुल्यांकन करने के लिए ग्रध्ययन करायें। उसे इस ग्रध्ययन के ग्राधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करके ग्रंवि संघ के श्रनुमोदनार्थ भेजना होगा, श्रौर इसके पश्चात् श्रवि संघ श्रौर कृषु निर्गम के बीच हुए समझौते के श्रनुसार इस कार्यक्रम की कार्यान्वित करना होगा। यह प्रध्ययन करते समय राज्य भूमि विकास बैंकों को सिक्रय रूप से संबंद करना होगा।

भाग लेनेवाली संस्थाओं के वरिष्ठ श्रौर मध्यस्तरीय कर्मचारियों के लिए भी निगम एक दिवर्षीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्त्रित करेगा।

कु० पू० निगम को इन वर्गों के प्रधीन ग्रंबि संघ द्वारा विनिधानित निधि (8 लाख डालर) भारत सरकार से प्रनदान के श्राधार प्राप्त होगी।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- राशियों का निकटतम श्रंकों में पूर्णीकन कर दिया गया है।
- 2. विवरणों में निम्नलिखित चिन्हों/संक्षिप्त नामों का उपयोग किया गया है।

- चिन्ह

@प्रदयतन उपलब्ध मांकडे

-- शुन्य या नगण्य

संक्षिप्त नामः--प्रयोजन

लसिं≕लघु सिंचाई भूवि = भूमि विकास/उद्घार/संरक्षण कृम ≔कृषि मशीनीकरण बान/बानी=बागान/बागवानी -मुपा/भेषा ≕मुर्गी पालन/भेड़ पालन मछ≔मछली पालन डेवि≕डेरी विक(स भं/बा=भंडार सुविधायें/बाजार केन्द्र

कृवि चकुषि विमानन

एजेंसी

- 1. राभ वि बैंक--राज्य भूमि विकास बैंक
- 2. वा बैंक---वाणिज्य बैंक
- 3. रास बैक--राज्य सहकारी बैक

विवरण 1 वायदों की तुलना में पूर्वित करने की प्रवृत्ति

			9		(
वर्षं (जुलाई——जून)	प्रत्येक वर्ष के श्रन्त में स्वीकृत	प्रावस्थाकम के ऋपु निगम वे	ų.	वितर	ग ग	वितरित राशियों का वायदे से प्रतिशत्				
	म स्वाकृत ८ योजनाम्रों की संख्या	वर्ष के दौरान	वर्ष के ग्रन्त तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के ग्रन्त तक	वर्ष के दौरान	वर्षके श्रन्ततक			
1963-64	3	,								
1964-65	13	447	447	4.5	45	10.1	10.1			
1965-66	36	828	873	445	490	53.7	56.1			
1966-67	42	940	1430	208	698	22.1	48.8			
1967-68	128	1850	2548	567	1265	30.6	49.6			
1968-69	233	4594	5859	1784	3049	38.8	52.0			
1969-70	371	6166	9215	2860	5909	46.4	64.1			
1970-71	458	6658	12567	3062	8971	46.0	71.4			
1971-72	711	8633	17604	3498	12469	40.5	70.8			
1972-73	923	16671	29140	9414	21883	56.5	75,1			
1973-74	1457	18820*	43556*	9784	31667	52.0	72.7			
1974-75	2053	18754	60873	10640	42307	56.8	69.5			

^{*}इसमें 557 करोड़ रुपयों की वह राशि शामिल नहीं है जो श्रवि संघ की परियोजनाओं को श्रन्तरित कर दी गई है।

विवरण 2 1974-76 के दौरान स्वीकृतियां---प्रयोजनवार

(लाखा रुपयों में)

•						(લાહ્ય સ્ત્રમાં મ)
प्रयोजन	,——,——,———— <u> </u>	3	गेजनाश्रों की सं ख् गा	विस्तीय सहायता	ह्रपु निगम के गायदे	राज्य सरकारों बैंकों के बायदे
लघु सिंचाई .		·	303	16610	14817	1793
भूमि विकास स्रोर भूमि संरक्षण			1	290	232	58
कृषि मशीनीकरण .			129	4214	3338	876
बागान श्रीर वागवानी .		•	35	458	364	9
मुर्गीपालन भ्रौर भेड़ पालम			26	158	134	2
मछलीपालन .		•	77	681	563	11
डेरी विकास ∦ .		•	39	887	742	14
भंडार सुविधाये श्रीर बजार केन्द्र	•	•	13	287	249	3
	जोड़		623	23585	20439	3140
<u></u>	1974-75	विव के दौरान स्वीकृति		भोर राज्यवार		(लाखा रुपये
 क्षेत्र/राज्य/		 योजनाम्रों की				राज्य सरकारीं/
संघगासित क्षेत्र		संख्या		हायता	के वायवे	बैंकों के वायदे
		,, 	= - =	1		
दिल्ली		1		76	61	1
ह रियाणा		26	Ş	3704	3171	53
हिमाचल प्रदेश		1		ß	6	_
जम्मू श्रौर कक्मीर		1		34	26	
पंजाब		16		702	566	13
राजस्यान		16		990	8 5 1	13
		60	5	812	4681	83
II उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	<u> </u>			**************************************		
प सम		3		80	78	
मेशासय		2		5	5	
ंभागा चैंड				irel	-+-	
		5		85	83	
II पूर्वीक्षेत्र				4-8 <u>-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4</u>		
बिहार		28	:	2294	2069	22
उड़ीसा		38		1844	1684	16
पश्चिम बंगाल		9		142	127	1

	विवरण 3	(जारी)		
1	2	3	4	5
IV मध्य क्षेत्र		,		
मध्य प्रदेश	38	922	795	127
उत्तर प्रवेश	75	4278	3714	559
· · ·	113	5195	4509	686
V पश्चिम क्षेत्र			-1 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4	
गोवा	14	54	43	, 11
गुजरात	15	748	623	125
म हाराष्ट्र	175	2787	2357	480
-	204	3589	3023	566
VI दक्षिणी केल		——————————————————————————————————————		
श्रांध्र प्रदेश	49	3329	2960	369
कर्नाटक	36	850	685	165
केरल	51	225	184	4 1
पांडिचेरी	1	6	6	⊸
· तिमलनाडु · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , . , . 29 ·	514	428	8 .6
-	166	4924	4263	661

विवरण 4 1974-75 के वौरान स्वीकृतियां--एजेंसीबार

23585

623

कुल ओड़ $(I \, \hat{\mathsf{H}} \, \, VI)$

(लाख रुपये)

3146

20439

एजेंसी	योजनामों की संख्या	वित्तीय सहामता	कृपु निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बैंकों के वायदे
राज्य भूमि विकास वैक	- 116	12883 (54.6)	11469 (56.0)	1414
प्रमुस्थित वाणिज्य बैंग	501	10462	8741 (42.9)	1711
राज्य सहसारी बैंक	. 6	250 (1.1)	229 (1.1)	21
जोड़	623	2 3585 (100.0)	20439 (100.0)	3146

विवरण 5 30 जून 1975 तक मंजूर की गई योजनाझों का वितरण—प्रयोजनवार

(लाख रुपए)

प्रयोजन	योजनाम्रों की संख्या	वित्तीय स हाय ता	क्कपुनिगम के वायदे	राज्य सर्रकारों/ बैंकों के वायदे	वितरण
लघु सिचाई	1139	74312	66661	7651	33822
भूमि विकास/उद्धार भूमि संरक्षण	91	8138	6416	1722	3003
कृषि मशीनीकरण	244	6679	5219	1460	1893
बागान श्रौर बागबानी	262	5251	4136	1115	1329
नुर्गीपालन श्रौर भेड़पालन	56	327	270	57	96
म छली पालन	97	1480	1092	388	464
डेरी विकास	119	2165	1807	358	305
भंडार सुविधाएं श्रौर बाजार		,			
केन्द्रां (मार्कोट यार्ड)	44	2355	2125	230	1383
कृषि विमानन	1	1.6	12	4	12
 जोड़	2053	100723	87738	12985	42307

विवरण 6 30 जून 1975 तक मंजर की गई योजनाओं का राज्य, एजेंसी **धौ**र प्रयोजन के श्रनुसार वितरण

(लाख रुपये)

						कृपु निगम	कि वायदे		वितरण
क्षेत्र/रा ज्य/संध् मासित क्षेत्र	एजेंसी की	प्रयोजन	योजनाम् की	गें वित्तीय सहायता	——— कुल वायदे	प्रावः 	स्थाकरण	1974- 75	30 जून 1975
	क्टूट- सं ख् या	·	ः सं ख् या	We I'm		1974 - 75 तक	1974- 75 के वौरान	्र के दौरा	तक
I उत्तरी क्षेत्र				 ,			,		
चिल्ली	2	कुम	2	91	73	35	30	11 -	17
		मुपा/ भे पा	1	20	16	16			
		केवि .	1.	28	28	. 17 _	9	. 1	. 2
	3	मुपा	1	12	12	12	_		6
			5	151	129	80	39	12	25
हरियाणा .	. 1	लसिं	32	4818	4337	2693	743	431	2658
		भूषि	2	234	194	106	84	17	20
		हां म	. 2	558	419	419	382	174	211
		बान/बानी	2	54	40	40	——		30
	2	लिं स	29	1859	1533	1533	799	258	785
		कुम	14	564	425	425	390	152	159
		मुपा/भेपा	2	18	17	7	5	2	2
· ·		डेविः	8	328	286	76	50	24	29

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1975 तक मंजूर की गई योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार विसरण

(लाख,रूपये)

			-7 .		कृ पु '	निगम के ब	ायदे	1974- 75	वितरण ————
नेत्र /राज्य/संभक्षासित क्षेत्र	एजेंसी की	प्रयोजन	भोजनाश्रों की	विसीय सहायता		प्रा व स	याकरण	~ /	30 जून 1975
	क। क्टूट संख्या		कर सं च्या	<u>αβι</u>	ખી ખ	1974- 75 तक	1974- 75 के दौरान	,	तक -
	3	डेवि भं/बा	2 3		108 243	108 343	18	17	15
			96	8806	7602	5650	2471	1075	4152
हिमाचल प्रदेश	1	बान/बानी [']	1		28	10	6		8
	2	भेंपा/मपा डेवि	1 1		6 3	3	2		
			3	46	37	15	8	4	8
जम्मू और शक्मी र	1 · ·	भ ूबि कुम	1			3	3		
		_{क्रम} बान/बानी	3			89	1		71
	2	, मुपा/भेपा डे वि	2	8	: 8	6 7			
				8 190) 148	105	5 12	}	71
पजाब	Ţ	लसि भूवि	28			2837			
		.भू.व कुम बान/बानी	11 2 2	2 190	143	219 143 127		- 114	114
	2	लसि क्रम	10 20	898	717		171	34	233
		_{टुर} ः मुपा/भेपा डेवि	1 6	1	1	1			
		भं/बा	1						
	.3	कृम डेब्रि भं/वा	1 4	4 107	89	89	32	2	
		म/या	 9(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			···

विवरण 6 (जारी) 30 जून 1975 तक मंजूर की गई योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

(लाख रूपमे)

					कृ पु f	नेगम ने व	ायदे	विव	ारण
भेत्र/रा <i>ञ्म</i> /संबंगासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट	प्रयोजन	योजनाः की	ों वित्तीय सहायत	•••••• कुल । वायदे	प्रावस्था व	रण 	197 4- 75	30 जून 1975
	संख्या		सं ख् या	WE IS		1974- 75 सक	1974- 75 के बौरान	के दौरान	
राजस्थात	1	 	42	2 2493	2297	1400	561	209	751
		भूवि		4 454	340	249	69	1	11
		बान/बामी		l 39	29	20	9	3	12
	. 2	लसिं		311	248	179	71	74	149
		भूषि		2 218	174				
		कुम	;	3 100	79	39	28	30	36
		मुपा/भेपा		1 5	4	2	2	~-	
		भं/अग	***	7 230	183	139	95	33	53
			6	8 3850	3354	2028	835	350	1012
			27	0 19465	16875	12815	4224	1848	9019
II उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			 		,				
भ्रसमं	. 1	बान/बानी		1 5	4	1	1		
	2	लसि		2 127	124	88	88		
•		कुम		1 3	3				
		बान/बानी	. ,	8 160	138	138			134
		डेवि		1 11	11	2	2		
		भ/बा	•	1 29	26	14	14		
	3	बान/बानी		1 6	6	6		<u> </u>	
·		•	1	5 341	312	249	105		134
मेचालय	3	मुपा/भेपा	[2 5	5				
		डेवि		1 2	2	2			
				3 7	7	2			
नागालैण्ड	3	भूवि	1	30	30	16	8	4	8
			1	9 378	349	267	113	4	142
🖽 पूर्वीक्षेत्र						- 	<u></u>	,	
बिहार	1	लसिं -	1			1578	891	712	1390
		भूवि		112	83			· - \ TT	83
		बान/बानी	:	12	11	1	1		

विवरण 6 (जारी)

30 जूम 1975 तक मंजूर की गई योजनाम्रों का राज्य, एजेंसी भ्रौर प्रयोजन के ग्रनुसार वितरण

(लाख रुपये)

					कृपु (नेगम के व	ायदे	वित	रण
क्षेत्र/राज्यं/संघमासित क्षेत्र	एजेंसी की कूट	प्रयोजन	योजनाश्रो की	i वित्तीय सहायता	 कुल वायदे	प्रावस्थ	 गकरण 	1974- - 75	30 जून 197
	संक्या		सं ख् या	WE TAN	3173	1974- 75 तक	19 74- 75 के दौरान	- के दौरान :	
	2	 रुसि	25	2065	1833	787	397	74	277
		भूषि	1	4	4	1	1		b
		कृम	4	227	189	127	92	61	96
		भं/वा	12	340	305	177	177	85	8 5
	3	डेंबि	2	70	53	32	23		
			57	6431	5716	2786	1582	932	1931
उड़ीसा	. 1	लसि	9	1448	1327	159	155	29	29
		भृषि	5	95	72	41	17	6	23
		कुम	1	80	60	30	20	7	
		बा न/बानी	k 8	244	192	110	30	4	4
	2	ससि	25	1129	1065	96	83	26	2
•		भू वि	. 3	92	77	44	32	7	
		जु म	1	25	20	8	5	1	
		बान/जा ली	3	86	73	21	11	2	
		क्रेमि	1	9	. 8	2	2		
	3	দ ক্ত	1	18	18	11	7		
		डे वि	1	19	19	6	4		
			58	3245	2931	528	366	82	13
पश्चिम बंगास .	. 1	लसिं	10	298	273	160	101	28	4:
		वान/बानी	6	48	44	14	. 3		
	2	लसि	7	63	56	50	20	20	38
		कुम	4	71	64	26	26	6	(
		बान/बानी	3	28	24	14	8	11	17
		मछ	2	2	2	2	1	1	2
		डे नि	2	9	8	4	. 4	3	:
			34	519	471	270	163	69	112
			149	10195	9118	3584	2111	1083	2180

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1975 तक मंजूर की ग ई मीजनाम्रों के राज्य, ए	एजेंसी श्रौर प्रयोजन के श्रनुसार वितरण
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------

(लाख रुपमे)

						क्रुपु निगम	के वायदे	1	वितरण
भे <i>त्र </i> राज्य संचशासित क्षेत्र	एजेंसी की	प्रयोजन	वोजनामों की	वित्तीव सहायता	कुल नाथवे	प्रावस	थाक रण	 1974- 75 के	30 जून 1975
	क्टूट संख्या		सं ब या		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		197 4 - 75 के वौरान	दौरान	तक
IV मध्य-क्षेत्र									
मध्य प्रदेश: .	. 1	लसि भूकि	82	5886 166	5319 125	3586 89	1630 47	796 	1 871 11
	2	हाम लसि सार	1 91	1 0 0	75 3 048	75 1879	1117	28 316	71 516
	3	कुम ंडेवि भं/बा	18 1 1	329 10 27	263 8 20	91 1 20	91 1 · 9	94	94
·	3	म/भा	197	9931	8859	57 4 1	2895	1234	2557
उत्तर प्रवेक .	. 1	ल सि		11364		6108	1735	1326	4715
	0	भूषि बान/बानी लसि	2 8	10 182	7 137	1 52	1 26		
	2	लास भूमि कुम	49 1 77	1418 927 1902	1261 675 1 5 01	704 —— 662	463 446	186 10 320	245 134 485
	3	के जि डे जि	5 2	101	83 48	55 48	23	7	32
	J	भं/बा	1	155	155	155		<u></u>	150
			259	16123	14174	7785	2710	1849	5765
			456	26054	23023	13526	5605	3083	8322
V पश्चिमी नेस गोना	. 2	. लिंस - 	1	5	3	3			3
		म छ	15	5 5	44	10	6 	5 5	5
	1	र्लास	51	6029	5427	5427	·======		8.
गुजरास .	. 1	लास क्रम बार/बादी	1	351	263	263		313	4314 233

विवरण 6 (जारी) 30 जून 1975 तक मंजूर की गई योजनाओं के राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के धनुसार वितरण

विवरण 6 (जारी) 30 जून 1975 तक मंजूर की गई योजनाओं के राज्य, एजेंसी और प्रमोजन के अनुसार वितरण

डे घि

मछ

जारी

विवरण 6 (जारी)

30 जून 1975 तक मंजूर की गई योजनाओं के राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरण

(लाख रूपये)

,		•			कृ	.पु. निगम	के वायदे		वितरण
क्षेत्न/राज्य	एजेंसी की	प्रयोजन	योजनाम्रों	वित्तीय	 कुल	प्रावस्थाकरण		30 जून	
संघगासित क्षेत्र	कूट संख्या		की संख्या	संल्थता	वायदे	1974-75 तक	1974-75 दौरान क		
तमिलनाडु	, 1	लसि	78	5342	4833	4474	690	662	4164
-		भूवि	3	629	472	472	7	12	469
		बान/बानी	15	902	676	218	101	37	118
	2	भूवि	1	5	4	4			3
		कुम	2	20	16	2	2		
		बान/बानी	35	162	149	139	13	13	124
		मछ	12	235	184	149	139	52	57
		मुपा/भेपा	1	1	1	1	1		1
		डे वि	5	60	48	32	21	1	5
		कवि	1	16	12	12			12
	3	मछ .	2	104	74	64	21	20	46
		मुपा/भेपा	1	5 1	38	38	38	20	20
			156	7527	6507	5605	1032	817	5019
			691	27471	23532	19366	4897	2832	13247
जोड़ $(I$ से $old VI$ तक $)$	•		2053 1	00723	87738	60873	18754	10640	42387

विवरण 7 30 जून 1975 तक स्वीकृत भोजनात्रों का वितरण -एजेंसीवार

(लाख रूपये)

एजेंसी		योजनात्र्यों की सं ख ्या	वित्तीय सहा य ता	कृषु निगम के वायदे	राज्य सरकारों/ बै कों के वायदे	वितरण
राज्य भूमि विकास बैंक		826	71179 (70.7)	62840 (71.6)	8339	35060
ग्रन् सूचित वाणिज्य बैक		1176	26555 (26,4)	22322 (25.4)	4233	5740
राज्य सहकारी बैंक	•	51	2989 (2.9)	2576 (3.0)	413	1507
जोड़		2053	100723 (100.0)	87738 (100.0)	12985	42307

को अकों में दिसे गमे आंकड़े जोड़ का प्रतिशत हैं।

ाववरण 8 30 जूम 1975 तक लयु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर की गई योजनाओं का बितरण लाख रुपये

	·				- - - शि ण् रीग			लाख रुपय		
क्रम	क्षेत्न/राज्य/संघ	एजेंसी	प्रयोजन	यो जना ग्रों की	विशीय सहायसः		पु निगम के [ः] 	वायदे 	·	वितरण
सं०	शासित क्षेत्र	. *		सं ख् या		कुल	प्रावस्था	करण	1974- - 75事	30 जून 1975
							1974से 75 तक	1974- 75 के दौरान	दौरान	तक
1. उत्तर	————— तिक्षेत्र			-, · ·, ·		····				
दिल्ली		वाणिज्य बैंक	डे वि	1	28	28	17	17	1	2
हरिय	ाणा .	राज्य भूमि विकास बैंक	भूवि	1	17	17	10	5		
		वाणिज्य बैंक	मुपा/भेपा	1	1 1	. 11	2	2	2	2
	_		डेवि	3	112	112	34	27	16	16
हिमा	वल प्रदेश .	वाणिज्य बैंक	मुपा/भेषा	1	6	6	2	2		
			डेवि	1	3	3	2	2		_
, जम्मू	स्त्रीर कश्मीर .	राज्य भूमि विकास बैंक	भूबि	1	6	6	2	2		
	•	वाणिज्य बैंक	मुपा/भेपा	.1	3	3	3	2		
			मुपा/भेषा २०-	1	6	6	3	1		
_•		c	डेवि ———	1	10	10	7	5		
षंजाब		राज्य भूमि विकास वैंक		4	228	228	228	72	45	109
		नाणिज्य बैंक	मुपा/भंपा -े कि	1	1	1				
			डेवि –—∜–	5	96	96	56	32	8	22
राजर	थान	राज्य भूमि विकास बैंक	लिंस	5	540	540	348	209	117	204
				27	1067	1067	714	378	189	355
2. उत्तर	पूर्वीक्षेत्र	_				·				
भसम		बाणिज्य बैक	लसि	2	98	98	6 6	6 6		
			डे वि	1	11	11	2			
मेषाल	ा य	राज्य सङ्कारी बैंक	मुपा/भेपा	2	5	5		 .		
			डे वि	1	2	2				
				6	116	116	68	68		
3. पूर्वी	क्षेत्र									
बिहार	τ [.	वाणिज्य बैंक	लसि	1	61	61	18	18		
उड़ीस	Π_{a} .	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	3	242	242	41	41	5	5
		वाणिज्य बैंक	लसि	2	397	397	59	47	12	12
			बान/बानी	2	14	14	1	1	 -	
			डेबि	1	5	5	1	1		,
		राज्य सहकारी बैंक	डेवि	1	16	16	5	3		T
पश्चि	म बंगाल .	राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	4	49	49	29	12	6	16
		_	बान/बानी	3	21	21	4	3		
		वाणिज्य बैंक	लसि	3	19	19	15	7	10	10
			डेवि	1	5	5	2	2	3	3
				21	829	829	175	135	36	46

विवरण 8 (जारी) 30 जून 1975 तक लघु कृषक विकास/सीमांत कृषक और कृषि अमिक एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर की गई योजनाओं का वितरण (लाख रुपये)

न्म <i>क्षेत्र∣राज्य∣</i> संघ	एजेंसी	प्रयोजन	_	विसीय सहायता		पु निगम व	के वायदे 	वितर	ग
ं० शासित क्षेत्र	34/11	2000	संख्या		कुल	प्रावस्था	करण	19 7 4- - 75 के	
						1974- 75 तक	1974- 75 के दौरान	दौरान	
. मध्य क्षेत्र	·			·				<u> </u>	**
मध्य प्रवेश .	. राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	7	242	242	164	83		
उत्तर प्रवेश	. राज्य भूमि विकास बैंक	लसि	7	7 7 3	773	634	163	104	525
	बाणिज्य बैंक	लसि	1	12	12	10	5		1
		डेबि	1	15	14	14	8		
		•	16	1042	1041	822	259	104	526
. पश्चिमी क्षेत्र									
मु जरा ल .	. वाणिज्य बैंक	डेबि	1	12	12	~	~		
	. राज्य भूमि विकास बैंक	लसिं	9	106	106	106	55	9	9
		बान/बा नी	1	97	97	11	7		_
	काणिज्य वैंक	डेवि	1	5 	5	5	3	1	
			12	220	220	122	65	10	1 1
. दक्षिणी क्षेत्र				<u></u>	b k - Pm mprm				
त्रान्ध्र प्रदेश	. राज्य भूमि विकास बैंक	ल सि	3	257	257	223	82	63	106
	वाणिज्य बैंक	लर्सि	1	18	18	10	7	1	
		मुपा/भेपा	1	8	8	3	3		
		डेवि	. 1	31	28	18	18		
कर्नाटक	. राज्य भूमि विकास नैंक	लसिं	3	484	484	464	112	69	244
	वाणिज्य बैंक	लसि	2	54	53	37	31		
		मुपा/भेपा	1	4	4	2	2		
केरल	, वाणिज्य बैंक	मुपा/भेपा	2	8	8	8	3		_
		डे वि	1	7	7	7	3		
	राज्य सहकारी बैंक	मुपा	1	22	22	11	1 1		
पांडिचेरी	. राज्य भूमि विकास बैंक	लसिं	1	16	16	16			
	वाणिज्य बैंक	डेवि	1	20	20	20	13		6
तामिलनाडु	, राज्य भूमि विकास बैंक	लस <u>िं</u>	4	158	158	138	77		21
			22	1087	1083	957	362	133	379
कुल जोड़ (1 से 6	तक)	•	104	4361	4356	2868	1267	472	1317

विवरण 9

अंतर्रोष्ट्रीय विकास संघ/अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बक की परियोजनाएं--प्रत्येक परियोजना का संक्षिप्त वितरण ।

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कृषि ऋण परियोजनाओं में लघु सिंचाई (ग्रथीत् खोदे गये कुएं व बोरिंग किये गये कुएं उथले, मध्यम ग्रीर गहरे नलकूपों, उद्बाहक सिंचाई की इकाइयां ग्रीर कुग्रों में पंपसेट तथा रहटें ग्रादि लगाना, पाइप लाइनें बिछाना तथा भूमि को समतल बनाने का ग्रनुषंगी कार्य के भारी निवेशों, भूमि विकास तथा ग्रायात किये गये ग्रीर देशी ट्रेक्टरों, कटाई की मशीनों (हावेस्टर्स) तथा कंबाइनों की खरीद के वित्तपोषण की परिकल्पना की गई हैं। ग्रन्य परियोजनाग्रों के मामले में उनके नाम ही उनके ग्रधीन हाथ में ली जाने वाली विकास की मदों के द्योतक हैं। कुपु निगम की ऋण परियोजना सामान्य स्वरूप की है जो निगम की लघु सिंचाई ग्रीर ग्रन्य विविध प्रयोजनों के लिए उधार प्रदान करने के कार्यकलापों में सहायक है।

प्रत्येक परियोजना की क़ुल लागत, भ्रं सिसंघ/भ्रंपु. निवि बैंक की सहायता, निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता, परियोजनाभ्रों को कार्यान्वित करने वाली एजसियों का संक्षिप्त विवरण तथा परिकल्पित विकास के स्वरूप भ्रौर प्रगति का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है:

- 1. क. कृपू निगम की परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 1685.00 लाख डालर (135 करोड़ रुपये)——निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली अंतर्रा-ष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 750.00 लाख डालर (60 करोड़ रुपये)।
- ग. लघु सिंचाई और ऋण प्रदान करने के श्रन्थ विविध स्वरूपों, परियोजना के कार्यान्वयन से संबद्ध संस्थानों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण और देश की श्रल्पावधि और दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के विलय की संभावना के श्रध्ययन से संबंधित निगम द्वारा किये जाने वाले निवेश की गतिविधियों के लिए प्रदान किये गये कृषि ऋण के हेतु सहायक वित्तपोषण कार्यक्रम।
 - घ. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक श्रौर श्रनुसूचित वाणिज्य बैंक।
 - ड. 2 वर्ष--समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर 1977
- त्र. ऋण को प्रभावी बनाने की पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के लिए कृ० पु० निगम द्वारा कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। भारत सरकार के साथ पूरक ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं—वित्तीय संस्थाम्रों, विशेषकर भूमि विकास बैंकों, के कर्म-चारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भारत सरकार को भेज दिया गया है। भूमि विकास बैंकों के वित्तीय कार्य तथा डिबेंचरों के आरी किये जाने की ग्रन्वीक्षण समिति का गठन ग्रौर उसके विचारार्थ विषय भारत सरकार को सूचित कर दिये गये हैं। परियोजना के स्वरूपों का ब्यौरा देते हुए विभिन्न एजेंसियां को एक सामान्य परिपन्न जारी कर दिया गया है।
 - 2. क. मांध्र प्रदेश कृषि परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 450.00 लाख डालर (33.8 करोड़ रुपये)—अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 244.00 लाख डालर (18.3 करोड़ रुपये)—इनमें से निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 242.00 लाख डालर (18.1 करोड़ रुपये)।
 - ग. लघु सिंचाई के निवेशों, भूमि विकास श्रौर कृषि मशीनीकरण के साज-सामान का वित्तपोषण।
 - ध. ग्रांध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड ग्रौर चुने हुए वाणिज्य बैंक ।
- ङ. 3 वर्ष-—इस बीच समाप्ति के दिनांक 30 जून 1974 को बढ़ाकर 30 जून 1975 कर दिया नवा है और उक्त दिनांक को लघु सिचाई ग्रीर भूमि विकास समाप्त कर दिया गया है। कृषि मशीनीकरण के उपकरण की ग्रवधि ग्रीर बढ़ाकर 30 जून 19.77 कर दी गई है।
- च. कृषि मशीमीकरण कार्यक्रम को छोड़ कर परियोजना पूरी हो गई है। ट्रैक्टर प्राप्त करने की श्रौपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं।
 - 3. क. बिहार क्रुंषि ऋण परिमोजना
 - ख. परियोजना की लागत 600.00 लाख डालर (45 करोड़ रूपमे)——निगम के माध्यम सेप्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 320.00 लाख डालर (24 करोड़ रूपमे)
 - ग. लघु सिंचाई कार्यक्रम जिसमें नलकूप लगाना धीर सतह के जल को थोड़ा ऊपर उठाकर पंप करने के लिए डीजल पंप सेटों का लगाना शामिल है।
 - घ. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक श्रीर चुने हुए वाणिज्य बैंक।
 - इ. तीन वर्ष--समाप्ति का दिनांक दिसंबर 1978 ।

- च. राज्य भूमि बिकास बैंक ने 8. 5 करोड़ रुपयों तक का वितरण किया है—कुछ ग्रवरोधों, जैसे ग्रीशोगिक विकास मंत्रालयों से तकनीकी मंजूरी की प्रांति में विलंब ग्रीर तलवार समिति की सिकारिशों को लाग न करने से प्रगति धीमी हो गई है।
 - 4क. बिहार बाजार केन्द्र (मार्केट याड) परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 233.00 लाख डालर (16.9 करोड़ रुपये) —-श्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 140.00 लाख डालर (10.1 करोड़ रुपये) —-निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 138.00 लाख डालर) (10.00 करोड़ रुपये)।
- ग. बिहार के लगभग 50 नगरों में विषणन मुविधाश्रों में निवेश के लिए, इन सुविधाश्रों में प्रवेश मार्गी का निर्माण, जमीन समतल करना, बाड़ लगाना, गोदाम, व्यापारियों की दुकानें, श्रादि के निर्माण जैसे नागरिक निर्माण कार्य शामिल हैं।
 - ध स्टेट बैंक श्राफ इंडिया
 - ङ. पांच वर्ष--समाप्ति का दिनांक 30 जून 1978
- च. निगम ने परियोजना के अन्तर्गत 84 लाख रुपये का पहला वितरण किया है। निगम ने 13 मंडियों के लिए स्वीकृति प्रदान की है—परियोजना को कार्यान्वित करने की धीमी प्रगति का मुख्य कारण यह है कि वाजार केन्द्रों (मार्केट यार्ड) के लिए भूमि प्राप्त करने और बाजार समितियों को उनका कब्जा सींपने में देर हुई है—इस मामले को सुलझाया जा रहा है।
 - 5. क. गुजरात कृषि ऋण परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 670.00 लाख डालर (50.2 करोड़ रुपये) प्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 350.00 लाख डालर (26.3 करोड़ रुपये) जिसमें से निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 347.00 लाख डालर (25.3 करोड़ रुपये) है।
 - ग. लघु सिचाई निवेशों स्रौर कृषि मशीनीकरण उपकरण (ट्रैक्टरों) स्रौर भूमिगत जल के स्रध्ययन का वित्रपोयण
 - घ. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
 - ङ तीन वर्ष--समाप्ति के दिनांक 30 जून 1974 को बढ़ाकर 31 मार्च 1975 कर दिया गया है।
 - च. इस बीच यह परियोजना पूर्ण हो गयी है--राज्य सरकार द्वारा ग्रावर्तक परियोजना बनायी जा रही है।
 - 6. क. हरियाणा कृषि ऋण परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 622.00 लाख डालर (45.3 करोड़ रुपये) निगम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली श्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 250.00 लाख डालर (18.2 करोड़ रुपये)
- ग. लघु सिचाई निवेशों का विस्तपोषण जिनमें उथले नलकूप बैठाने का कार्य और कृषि मणीनीकरण के श्रायातित और देशी साज सामान ग्रर्थात् ट्रैक्टरों, कटाई सयंत्रों और स्वचालिस कंबाइनों का विस्त पोषण शामिल है।
 - घ. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक स्रौर चुने हुए वाणिज्य बैंक
 - ङ. तीन वर्ष --इस बीच समाप्ति के दिनांक 31 मार्च 1975 को बढ़ाकर 31 मार्च 1976 कर दिया गया है।
- च. परियोजना के अन्तर्गत मूल रूप से अपेक्षित लघु सिचाई कार्यक्रम का पूरा उपयोग किया गया है। अंवि संघ द्वारा ट्रेक्टर वर्ग से लघु सिचाई वर्ग की 80.00 लाख डालर के ऋण का पुनर्विनिधान स्वीकार कर लिया गया है। इस कार्यक्रम का थोड़ा सा बकाया भाग पूरा किया जाना है। हरियाणा कृषि श्रीद्योगिक निगम ने पूर्तिकार को 2,800 ट्रेक्टरों का श्रार्डर दिया है।
- 7. क. हिमाचल प्रदेश सेब ग्रभिसंस्करण ग्रीर विपणन परियोजना (कृपु निगम का कार्यक्रम)
- खः परियोजना की कुल लागत 215.00 लाख डालर (16.1 करोड़ रुपये) प्रांतराष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 130.00 लाख डालर (9.8 करोड़ रुपये) निगम के माध्यम से प्रवान की जाने वाली ग्रन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 3.7 करोड़ रुपये।
- ग. बागबानी पैदावार श्रभिसंस्करण तथा विपणन निगम की स्थापना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सेब श्रभिसंस्करण तथा विपणन उद्योग के सुधार के लिए वित्त पोषण—इस सहायता के श्रन्तर्गत डिब्बाबंदी करने के कारखाने, संग्रहण केन्द्र, वाहनान्तरण केन्द्र, ठंडे गोदाम की इकाइयों का निर्माण श्रीर रस गाढ़ा करने के संयंत्र श्राते हैं —पैदावार का समय पर परिवहन करने के लिए हवाई रज्जु मार्गी श्रीर नई सड़कों के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है।
 - घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक
 - इ. चार वर्ष --समाप्ति का दिनांक 31 दिसम्बर 1978
- च तीन सहभागी बैंकों के बीच 12 डिब्बाबंदी करने के कारखानों, 3 संग्रहण केन्द्रों, 4 ठंडे गोदाम की इकाइयों के वित्तपोषण के लिए प्रयोगात्मक विनिधान किया गया है,-जिस रूप में इन मदों का वित्तपोषण किया जाना है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है।
 7—469 GI/75

- 8. क. कर्नाटक कृषि ऋण परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 754.00 लाख डालर (54.9) करोड़ काये)—प्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 400.00 लाख डालर (29.1) करोड़ रुपये) -इसमें से द्विगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता की राशि 377.00 लाख डालर है (30.8) करोड़ रुपये) है।
 - ग. लघुसिचाई निवेशों श्रीर भूमि उद्घार तथा दैक्टरों श्रीर भूमि उद्घार के साजसामान की खरीदी का वित्तपोषण
 - घ. कर्नटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंग ग्रौर जुने हुए वाणिज्य बैंक ।
 - क. तीन वर्ष-इस बीच समाप्ति के दिनांक 31 प्रक्तूबर 1975 को बढ़ाकर 31 सितम्बर 1976 कर दिया गया है।
- च. लघु सिंचाई संघटक का काफी भाग वितरित किया जा चुका है---देशी श्रौर विदेणी दोनों प्रकार के ट्रैक्टरों को खरीद के लिए श्रौपचारिकता पूरी हो गई हैं--वित्तपोधक बैंकों को 2,000 ट्रक्टरों की व्यवस्था के मुकाबले लगभग 2,800 ट्रक्टरों के प्रार्थनापन्न प्राप्त हो गये हैं।
 - 9. क. कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 130.00 लाख डालर (9.5 करोड़ रुपये) श्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 80.00 लाख डालर (6.4 करोड़ रुपये) की सहायता जिसमें से 79.00 लाख डालर (6.4 करोड़ रुपयों) की सहायता की राश्चि निगम के माध्यम से प्रदान की जानी है।
 - ग. सिविल निर्माण कार्यों, संरचनाभ्रों, जनोपयोगी सेवायों, साज-सामान ग्रादि सहित बाजार की सुविधाएँ।
 - घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक
 - ङ. पांच वर्ष-समाप्ति का दिनांक 31 दिसंबर 1979
 - च. निगम ने 7 बाजारों की स्वीकृति दी है जिनसे संबंधित वित्तिय सहायता 1.3 करोड रुपयें हैं।
 - 10. क. कर्नाटक डेरी विकास परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 435 लाख डालर (34.8 करोड़ रुपये)---श्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 300.00 लाख डालर (24 करोड़ रुपये)---निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सहायता 209.00 लाख डालर (16.7 करोड़ रुपये)
- ग. कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए समेकित कार्यक्रम । इसके लिए संकरण के द्वारा श्रच्छी नस्ल के पणु पैदा करने तथा पणु स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी सेवाग्रों और दूध संग्रहण , श्रभिसंस्करण श्रौर विपणम के लिए विकास मुविधान्नों की व्यवस्था की जायगी।
 - घ. कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, कनौटक सहकारी शिखर वैंक श्रीर चुने हुए वाणिज्य बैंक।
 - घ. श्राठ वर्ष--समाप्ति का दिनांक 31 मार्च 1982
- च. निगम ने चार डेरी संघों के वित्तपोषण के लिए एक बैंकिंग योजना तैशार की है—कर्नाटक डेरी विकास निगम ने परि-योजना के क्षेत्रों में दुग्ध मार्गों की पहचान के लिए अग्रणी दलों की नियुक्ति की है ।
 - 11. क. मध्य प्रदेश कृषि ऋण परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 603.00 लाख डालर (45.2 करोड़ रुपये) प्रतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 330.00 लाख डालर '25.00 करोड़ रुपये) जो निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- ग. खेतों पर किये जानेवाले निवेशों का वित्तपोषण इन निवेशों में खुदाईवाले कुग्रों का निर्माण, वर्तमान कुश्रों में सुधार, 'बिजली तथा डीजल पंपसेट ग्रीर रहटें लगाना तथा भूमि को समतल करने का श्रनुषंगी कार्य ।
 - घ. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक
 - ङ. तीन वर्ष--समाप्ति का दिनांक 31 दिसंबर 1976
- च. भूमि विकास/बैंक/प्राथमिक सहकारी बैंकों ने 18 करोड़ रुपये वितरित किये हैं। प्रगति संतोष जनक है। फिर भो, पिछले दिनों बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने, प्राथमिक सहकारी बैंकों के कुछ उधार कर लेने वालों से मुद्रीक शुल्क के भुगतान ब्रादि में हुए विलंब से वितरणों की गति पर प्रभाव पड़ा है-इन मामलों पर राज्य सरकार ध्यान दे रही है।
 - 12 क. मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 312.00 लाख डालर (250.00 करोड़ रुपये) —-श्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 164.00 लाख डालर (13.1 करो रुपये) --इसमें से निगम के माध्यम से 137.00 लाख डालर (10.9 करोड़ रुपये) प्रदान किये जायेंगे।
 - ग. 3 डेरी संयंत्रों, 3 पशुष्रों के चारादाना की मिलों, 1 पशु प्रजनन फार्म ग्रादि का तिमीण है।

- घ. चुने हुए काणिज्य बैंक
- ङ. 6 वर्ष ---समाप्ति का दिनाक 30 जून 1982
- च. बैंकिंग योजना को श्रंतिम रूप दिया गया है—-राज्य सरकार ने परियोजना की कार्यान्विति से संबंधित श्रधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्नारंभ किया है।
 - 13.क. मध्य प्रदेश के चम्बल कमान क्षेत्र की विकास परियोनजा।
- ख. परियोजना की लागत 458.00 लाख डालर (36.6 करोड़ रुपये)—प्रतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 240.00 लाख डालर (19.2 करोड़ रुपये)। इसमें से 31.00 लाख डालर (2.5 करोड़ रुपये) की राणि, निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- ग. सिचाई श्रौर नालियां बनाने का कार्य, खेतों के ऊपर काविकास सड़कें, घाटी-कटाव नियंक्षण , मणीनी साज सामान-तकनीकी सहायता ।
 - घ. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक श्रीर श्रनुसूचित वाणिज्य बैंक
 - ङ. तीन वर्ष-समाप्ति का दिनांक 31 दिसंबर 1979
 - च. यह योजना म्रंवि संघ द्वारा हाल ही में मंजूर की गयी है।

14.क. महाराष्ट्रकृषि ऋण परियोजना

- ख. परियोजना की लागत 524.00 लाख डालर (38.2 करोड़ रुपये) स्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 300.00 लाख डालर (21.8 करोड़ रुपये) । इसमें से निगम के माध्यम से 254.00 लाख डालर (18.5 करोड़ रुपये) प्रदान किये जाएंगे।
- ग. नल कूपों, उद्याहक सिचाई, खुदाई के कुग्रों, खुदाई के कुग्रों में सुधार श्रौर कुग्रों में विजली लगाने सहित लघु सिचाई कार्यक्रम श्रौर भूमि को समतल बनाने के निवेश।
 - घ. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड श्रीर चुने हुए वाणिज्य बैंक
 - ङ. तीन वर्ष--समाप्ति का दिनांक--31 दिसंबर 1975
- च. खुदाई के कुन्नों के कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक है । राज्य भूमिगत सर्वेक्षण न्नौर विकास ऐजेंसी ने संपूर्ण राज्य की प्राथिमिक पनधारात्रों का विस्तृत ग्रध्ययन कर लिया है। परियोजना के साजसामान के लिए क्व पु निगम के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा।
 - 15. क पंजाब कृषि ऋण परियोजना
- ख. परियोजना की लागत---400 लाख डालर (30.1 करौड़ रुपये)--म्नंबि संघ की सहायता 275.00 लाख डालर (20.0 करोड़ रुपये) जो निगम के माध्यम सेन्नदान की जाएगी।
 - ग. ग्रायातित भौर देशी ट्रैक्टरों कटाई यंत्रों भौर स्वचालित कंबाइनों की खरीद का वित्तपोषण
 - घ. पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड श्रीर चुने हुए बाणिज्य बैंक।
- ऊ. दो वर्ष—समातिट का जो निर्धारित दिनांक पहले 31 दिसंबर 1972 था उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 1973 किया गया था और उसे बाद में दो वर्षों के लिए और बढ़ाकर 31 दिसम्बर 1975 कर दिया गया है।
- च. इस परियोजना के श्रंतर्गत 1000 ट्रैक्टरों की पहली खोप का विरतरण पूरा हो गया है । ट्रैक्टरों (4,000) की दूसरी खोप के लिए श्रच्छा उत्साह है।
 - 16. क. चम्बल कमान क्षेत्र को विकास परियोजना (क्षु पु निगम का कार्यक्रम)---राजस्थान
- ख. परियोजना की लागत—120 लाख डालर (9.6 करोड़ रुपये)—म्प्रपृवि बैंक की सहायता—65 ल ख डालर (5.2 करोड़ रुपये)——जो निगम के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
- ा. इस परियोजना में नालियां, नहरों की मेटें बनाना, नहरों की क्षमता में वृद्धि, नियंत्रण संरचनाओं का गिर्माण श्रथवा सुधार, खेतों के ऊपर का वह विकास शामिल है जिसके श्रंतर्गत नालियों के लिए गड्डे खोदना, जमीन के श्राकर-प्रकार देना, सड़कों का निर्माण, वनरोपण, भूमिकटाव का नियंत्रण श्रीर उर्वरकों की पूर्ति भी श्राते हैं।

- घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक
- इ. 6 वर्ष--समाप्ति का दिनांक--30 जुन 1981
- च. राज्य सरकार ने कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कर ली है । 'चक' के ग्राधार पर विकास की योजनायें निगम के परामर्श से तैयार की जा रही हैं।
 - 17. क. राजस्थान नहर कमान क्षेत्र की विकास परियोजना (क्रुपू निगम का कार्यक्रम)
- ख. परियोजना की लागत 398.00 लाख डालर (31.8 करोड़ रुपये)—-ग्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 225.00 लाख डालर (18.0 करोड़ रुपये) जो निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी ।
- ग. इस परियोजना में वितरक नहर की मेढें बनाना, सड़क निर्माण, चारागाहों का विकास, वन रोपण, उर्वरकों की व्यवस्था तथा खेतों का ऊपरी विकास, जिसमें भूमि को भ्राकार प्रकार देना, भूमि उद्घार तथा जलमार्ग के लिए मेढें बनाना शामिल है।
 - घ. चुने हुए वाणिज्य बैंक
 - ङ. 5 वर्ष---समाप्ति का दिनांक 30 जून 1980
- च. राज्य सरकार ने कमानक्षेत्र के विकास प्राधिकरण की स्थापना कर ली है—'चक' के श्राधार पर विकास के लिए योजनायें निगम के परामर्श तैयार की जा रही है।

18.क. राजस्थान डेरी विकास परियोजना*

- ख. परियोजना की लागत---518.00 लाख डालर (41.4 करोड़ रुप्ये) --प्रंवि संघ की सहायता 270.00 लाख डालर (21.6 करोड़ रुपये) इसमें हे निगम के माध्यम से 223.00 लाख डालर (17.2 करोड़ रुपये) प्रदान किये जाएंगे।
- ग. लगभग 1800 डेरी सहकारी सिमितियों क निर्माण जो डेरी श्रौर वारा संयंत्रों से सुसज्जित 5 दुग्ध उत्पादक संघों के समूह होंगे।
 - घ. राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक श्रौर ग्रनुसूचित वाणिज्य बैंक
 - ङ. 7 वर्ष--समाप्ति का दिनांक--31 दिसंबर 1982
 - च. बैंकिंग योजना को श्रंतिम रूप दिया जा रहा है।

19. क. तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना

- ख. परियोजना की लागत 623.00 लाख डालर (46.8 करोड़ रुपये)—अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 350.00 लाख डालर (26.2 करोड़ रुपये) जिसमें से 298.00 लाख डालर (22.9 करोड़ रुपये) की सहायता निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- ग. लघु सिचाई निवेशों का वित्तपोषण जिसमें फिल्टर बिदुवाले नलकूष, उथले तथा मध्यम नलकूषर लगाना, भूमि समतल, भूमि में नालियाँ बनाना और ट्रैक्टर शामिल हें ।
 - घ. तमिलनाडु सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड ।
 - ङ. तीन वर्ष-इस बीच समाप्ति के दिनाँक 31 दिसम्बर 1974 को बढ़ाकर 31 दिसम्बर 1976 कर दिया गया है।
- च. ऋण का लघु सिचाई घटक (जिसमें भूमि विकास ग्रीर भूमि पर नालियां बनाने की राशियों में से फिर से विनिर्धानित राशियां शामिल हैं।) ऋषि मशीनीकरण कार्यक्रम के विनिधान का उपयोग कर लिया गया है ग्रतएव परियोजना की सामप्ति का दिनांक बढ़ाया जा रहा है—न्तमिलनाडु सरकार ग्रीर भूमि विकास बैंकों ने ट्रेक्टर प्राप्त करने का कार्य ग्रपने हाथों में ले लिया है ग्रीर उन्होंने प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को सूचित किया है कि वे किसानों से उनके माडलों के चुनाव के ग्रनुसार ग्रावेदन पत्न एकितिकत कर लें।

20. क. तराई बीज परियोजना-- उत्तर प्रदेश।

ख. परियोजना की लागत 224.00 लाख डालर (16.8 करोड़ रूपये)—म्प्रंतर्राष्ट्रीय पुर्नानमणि भौर विकास बैंक की सहायता 130.00 लाख डालर (9.8 करोड़ रूपये) जिसमें से 90.00 लाख डालर (6.8 करोड़ रूपये) की सहायता निगम के भाष्यम से प्रदान की जाएगी।

- ग. उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र का भूमि विकास ताकि प्रधिक उपजाऊ किस्म के खाद्याक्षों की उपलब्सि में वृद्धि हो सके।
- घ. स्टेट बैंक ग्राफ इंडिया
- ङ. 30 जून 1974
- च. परियोजना की समाप्ति के दिनांक में वृद्धि करने के मामले पर भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की जानी हैं।
- 21. क. उत्तर प्रवेश कृषि ऋण परियोजना
- ख. परियोजना की लागत 725.00 लाख डालर (54.3 करोड़ रुपये)—श्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 380.00 लाख डालर (28.5 करोड़ रुपये) जो कि निगम क माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- ग. खेतों के ऊपर के निवेकों उदाहरणार्थ ईंट कीचिनाईवाले या खुदाईवाले कुन्नों [या नलकूपों, उथले नलकूपों, मामूली गहराईवाले नलकूपों तथा रहटों के निर्माण, स्रौर बिजली तथा डीजल पंपसेट लगाने के निवेकों का विक्तपोषण
 - घ. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास श्रौर बैंक श्रौर चुने हुए वाणिज्य बैंक
 - ङ. तीन वर्ष--समाप्ति का विनांक 31 दिसंबर 1976
- च. भूवि बैंकों/प्रा स बैंकों ने 15.5 करोड़ रुपयों का वितरण किया है--उधार दिये जाने की प्रगति काफी संतोष जनक है।
 - 22. क. पश्चिम बंगाल कृषि विकास ऋण परियोजना*
- ख. परियोजना की लागत 59.00 लाख डालर (47 करोड़ रुपये)—-श्रंवि संघ की सहायता 340.00 लाख डालर (27.2 करोड़ रुपये) इसमें से 150.00 लाख डालर (12.0 करोड़ रुपये) निगम के माध्यम से प्रदान किये जाएंगे।
- ग. उथले ग्रौर गहरे कुन्नों का निर्माण, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, वाजारों के विकास जनदी की उद्याहक सिंचाई का पूरा किया जाना।
 - घ. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और पश्चिम बंगाल राज्य लघु सिंचाई निगम
 - इ. चार वर्षे⊸-समाप्ति का दिनांक 31 मार्च 1980
- च. भारत सरकार के साथ पूरक ऋण करार पर हस्ताक्षर हो गये है—ऋण के प्रभावी होने की शतों को पूरा करने की प्रारंभक कार्रवाइयां पूरी की जा रही हैं। सहभागिता करनेवाले बैंकों श्रीर उनके द्वारा पहले से ही वित्तपोषित योजनाश्रों को श्रापस म बदलने के लिए मार्गदर्शी सिद्धीत तैयार किये जा रहे हैं।
 - *ये 1974--- 75 के दौरान स्वीकृत परियोजनायें हैं।

शीर्षक

कः. परियोजना का नाम ख० परियोजना की लागत, ग्रंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता, कृषि पुनर्वित्त निगम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली राशि ग० परियोजना का विवरण घ० कार्यान्वित करनेवाली एजेंसी ङ० कार्यान्वयनकी ग्रवधि च० परियोजना की प्रगति।

विवरण 10 30 जून 1975 को श्रंपुवि बैंक (श्राईबीग्रारडी) /ग्रंवि संघ (ग्राईडीए) की परियोजनाओं की स्थिति

परियोजना	प्रयोजन	उधार देने का कुल कार्यक्रम	कृपु निगम को प्राप्त होनेवाली प्रपुवि बैंक/ श्रंवि संघ की सहायता की राशि	प्राभूवि बैंकों/प्रास बैंकों द्वारा किये गये वितरण	क्रुपु निगम द्वारा किये गये वितरण	भारत सरकार र प्राप्त राणि
क. अंपुत्र बंक की परियोजनायें						
क. तराई बीज परियोजना (उत्त ख. चम्बल कमान क्षेत्र की विकास		927	675	182	134	125
(राजस्थान)	भूवि	619	520	~		
		1546	1195	182	134	125
ब. अंबि संघ की परियोजनायें						
क. क्रुपुनिगम की ऋण परियोजना	ल सि	11100	5520			
	श्रन्य प्रयोजन	900	400		~	
		12000	5920			
ख. कृषि ऋण/परियोजनायें	•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-dd
1. माध्यप्रदेश	लसि	2111	1393	2412	1872	10.00
	भूवि	230	154	252	151	1377
	कृ म	383	383			
		2724	1930	2665	2023	1377
2. बिहार	लसि	3943	2400	848	790	449
3. गुजरात	ल िं स	4027	2344	4027	3635	
	रु म	351	182	319	239	2550
·		4378	2526	4346	3874	2550
4. हरियाणा	ला स	1962	903	1852	1689	
	कृम	1433	917	139	304	809
	<u> </u>	3395	1820	1991	1993	809
5. कर्नाटक	लिंस	2548	1682	1963	1665	
	भूवि	768	574	209	126	1120
	• <u>•</u> क्टम	820	820			 -
		4136	3076	2172	1791	1120

विवरण 10 (जारी) 30 जन 1975 को श्रंपुवि बैंक (आईबीशारडी)/अंबि संघ (ग्राईडीए) की परियोजनाश्रों की स्थिति

					उधार देने	कृपु निगम	प्राभूवि	कृपु निगम ೧	भारत
					का कुल	को प्राप्त	बैंकों/प्रास	द्वारा किये	सरकार से
					कार्यक्रम	होने वाली	बैंकों द्वारा	गये वितरण	प्राप्त राशि
परियोजना				प्रयोजन		श्रंपुवि बैं क/	किये गये		
						श्रंवि० संघ	वितरण		
						की सहायता	@		
						की राशि	·		
6. मध्य प्रदेश	•			लसि प्रौर	3763	2395	- 1809	1388	83
				भूवि.	158	100 J			
					3921	2495	1809	1388	83
7. महाराष्ट्र			•	ल सि	2748	1651	2699	2429	
				भूवि०	415	198		J	156
					3163	1849	2699	2429	156
₃. पंजाब .	•	;		कृम	. 4002	2002	305	223	18
9. तमिलनाडु				ल सि ०	3001	1861	3001	2762	.192
				भूवि०	88	61	88	52	• "151
				कुम	702	364		ر 	-
					3791	2286	3089	2814	192
0. उत्तरप्रदेश	•			लसि०	4594	2850	1547	1297	76
1. पश्चिम बंगाल				लसि०	1953	1072			_
				कुम	152	80			-
				भां/बा	85	48			_
					2190	1200			_
. अन्य परियोजनायें					40237	24474	21471	18662	1157
1. बिहार बाजार	केन्द्र परि	योजना			1491	1002	94	84	-
2. हिमाचल प्रदेश	ासेब ग्र	भिसंस्करप	। ग्रौर	विपणन परि-					
योजना .			•		452	372			_
3. कर्नाटक कृषि			जना		792	635			-
4. कर्नाटक डेरी ी					2750	1672			_
5. चम्बल कमान				(म०प्र०)	1840	246			_
6. मध्य प्रदेश डेर					2497	1091			_
7. राजस्थान -	नहर क	मान क्षेत्र	की	विकास परि-					
योजना	,		•		2395	1800		 ,	· · · · ·
8. राजस्थान डेर्र	विकास	परियोजन	Τ.		1957	1784			
					14174	8602	94	84	

विवरण 11 राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के श्रनुसार 1974-75 के दौरान निगम द्वारा किए गए वितरण

			जारी किये गर्य	कृपु निगम द्वारा	(लाख रुपये)
६० क्षेत्न/राज्य/ ६० संघशासित क्षेत्र	′ एजेंसी	प्रयोजन	जारा किय गय डिबेंचरों/जुटाये गये ऋणों की कुल राशि	क्षपु (नगम द्वारा श्रभिदत्त डिवेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों बैंकों काश्रभिदान
. उत्तरी भेत					
दिल्ली . ,	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	14	11	3
		डेरी विकास	1	1	
			15	12	3
हरियाणा	. राभॄवि बैंक	लघु सिंचाई	478	431	47
	L.	भूमि विकास	22	17	5
		कृषि मशीनीकरण	230	174	56
	वाणिज्य बैंक	लघु सिंचाई	287	258	29
		कृषि मणीनीकरण	203	152	5 1
		मुर्गीपालन	2	2	
		डे री विकास	25	24	1
	राज्य सहकारी बैंक	भंडार/बाजार केन्द्र	17	17	
		•	1264	1075	189
हिमाचल प्रदेश	. राभूवि बैंक	बागान/बागवानी	5	4	1
पंजाब .	. राभूवि बैंक	लघु सिचाई	116	109	
		भूमि विकास	64	52	12
		कृषि मशीनीकरण	152	114	38
•	वाणिज्य बैंक	ल ष ुसिचाई	43	34	, 9
		कृषि मशीनीकरण	61	45	16
		डेरी विकास	8	8	
		भंडार/बाजार केन्द्र	29	23	6
	राज्य सहकारी बैंक	भंडार/बाजार केन्द्र	24	22	2
			497	407	90
राजस्थान	राभू वि	लघु सिचाई	220	209	11
		भूमि विकास	1	1	
		बागान/बागवानी	5	. 3	2
	वाणिज्य बै ंक	े लघु सिंचाई	92	74	10
		कृषि मशीनीकरण	37	30	7
		भंडार/बाजार केन्द्र	42	33	9
			397	350	47
II. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र			3		
नागालैंड	राज्य सहकारी बैंक	भूमि विकास	4	4	
			4	4	

विवरण 10 30 जून 1975 को अंपुर्वि बेंक (आईबीआरडी)/अंबि संघ (आईडीए) की परियोजनाओं की स्थिति

(लाखा रुपये)

					(लाखा रुपय)
क० क्षेत्र/राज्य सं० संघणासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/जुटाये गये ऋणों की कुल राशि	कृपु निगम द्वारा श्रभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों, बैंकों का ग्रभिदान
III. पूर्वीक्षेत्र				- 	, .'
बिहार	राभूवि बैंक	लधु सिंचाई	791	712	79
	वाणिज्य बैंक	लघुँ सिचाई	135	74	61
		कृषि मशीनीकरण	118	61	57
	•	भंडार/बाजार केन्द्र	97	85	12
			1141	932	209
उड़ीसा	रा भूवि बै क	ल धु सिं <mark>वाई</mark>	31	29	2
		भूमि विकास	7	6	1
		कृषि मशीनीकरण	10	7	, 3
		बागान/बागवानी	6	4	2
	वाणिज्य बैंक	लघु सिचाई	27	26	1
		भूमि विकास	8	7	1
	•	कृषि मणीनीकरण	1 .	1	—
		बागान/बागवानी	3	2	1
			93	82	11
पश्चिम बंगाल .	राभूवि बैक	ल षु सिंचा ई	31	28	3
	वाणिज्य बैंक	लघु सिचाई	20	20	
		कृषि मशीनीकरण	6	6	
		बागान/बाग व ानी	11	11	
		मछलीपालन	1	1	
		डेरी विकास	3	3	
			72	69	3
मध्यप्रदेश .	रा भूवि वै क	लघु सिचाई	881	796	85
		कृषि मशीनीकरण	37	28	9
	वाणिज्य बैंक	लघु सिचाई	352	316	36
		कृषि मशीनीकरण	117	94	23
			1387	1234	153
V. मध्य क्षेत्र					
उत्तर प्रदेश	राभू वि बै क	लघु सिचाई	1460	1326	134
	वाणिज्य बैंक	लघु सिचाई	207	186	21
		भूमि विकास	12	10	2
		कृषि मशीनीकरण	406	320	86
		डेरी विका स	8	7	1
			2093	1849	244

विवरण 11 (जारी) राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अमुंसार 1974-75 के बौराम निगम द्वारा किए गए बितरण

(लाखारुपये)

					(लाखारुपय)
क० क्षेत्र/राज्य/ सं० संघशासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/जुटाये गये ऋणों की कुल रागि	कृपु निगमद्वारा श्रभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैकों का श्रभिदान
V पश्चिमी क्षेत्र					
गोवा	वाणिज्य बैंक	मछलीपालन	5	5	- -
			5	5	
गुजरात	राभ्षि बैंक	लघ सिंचाई	348	313	35
3,	वाणिज्य बैंक	कृषि मशीनीकरण	100	82	18
		डेरी विकास	37	32	5
		-	485	427	58
महाराष्ट्र .	. राभूवि बैंक)	लघ सिचाई	1125	1013	112
	वाणि ज ्य बैंक	लघ सिंचाई	220	200	20
			28	22	6
			18	14	4
			105	84	21
			11	9	2
	राज्य सहकारी बैंक	प्रयोजन मछलीपालन लघु सिचाई कृषि मशीनीकरण डेरी विकास लघु सिचाई कृषि मशीनीकरण मृगीपालन/भेड़ पालन डेरी विकास भड़ार/बाजार केन्द्र पि बैंक लघु सिचाई कृषि मशीनीकरण मृगीपालन लघु सिचाई भूमि विकास वागान/वागवानी क लघु सिचाई भूमि विकास वागान/वागवानी क लघु सिचाई कृषि मशीनीकरण मृगी पालन/भेड़ पालन लघु सिचाई भूमि विकास वागान/वागवानी कृषि मशीनीकरण वागान/वागवानी मृगीपालन/भेड़पालन मछलीपालन भड़ार/वाजार केन्द्र		16	~
			1523	1358	165
VI बंक्षिणी क्षेत्र					
श्रांध्र प्रदेश	रा भूवि बैं क	लघु सिंचाई	785	712	73
	~	भूमि विकास	67	50	17
			12	9	3
	वाणि अय बक	लघु सिंचाई	114	97	17
			14	11	3
		मृर्गी पालन/भेड़ पालन	17	13	4
			1009	892	117
कनटिक .	. राभूविबैंक	ल घु सिचा ई	768	717	51
		भूमि विकास	45	34	11
			59	44	15
	वाणिज्य बैंक		25	22	3
			72	5 5	17
			33	28	5
			19	16	3
			60	44	· 16
			39	12	27
	रा ज्य सहकारी बैं क	भंडार/बाजार केन्द्र	36	36	
			1156	1008	148

(विवरण 11 जारी) राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार 1974-75 के वौराम निगम द्वारा किये वितरण

(लाखा रुपये)

क्र० सं∘	क्षेत्र/राज्य/ संघगासित क्षेत्र	एजेंसी	प्रयोजन	जारी किये गये डिबेंचरों/जुटाये गये ऋणों की कुल राशि	कृषु निगम द्वारा ग्रभिदत्त डिबेंचर/ वितरित ऋण	राज्य सरकारों/ बैंकों का श्रभिदान
के	 रल	वाणिज्य बैंक	भूमि विकास	8	6	2
			बागान/ <mark>बागवानी</mark>	57	43	14
		याणिज्य बैंक	लघु सिचाई	16	13	3
			कृषि भगीनीकरण	8	7	1
			बागान/बागवानी	2	2	
			मछली पालन	36	28	8
			डेरी विकास	1	1	
				128	100	28
			डेरी विकास	3	3	
		राज्य सहकारी बैं क	मछलीपालन	12	12	
		·		15	15	~
त्रि	मे लना श्रु	राभूवि बैंक	लघु सिंचाई	736	662	74
			भूमि विकास	16	12	4
			बागान/ बाग वानी	49	37	1/2
		वाणिज्य बैंक	बागान/बागवानी	16	13	.3.
			मछली पालन	65	52	13
			ं डेरी विकास	1	1	
		राज्य सहकारी घैंक	मछलीपालन	26	20	6
			मुर्गीपालन/भेड़ पालन	27	20	7
				936	817	11
		नुल जोड़ (1 से 6	तक)	12225	10640	1585

विवरण 12 30 जून 1975 की विचाराधीन योजनाएं

सेंच में पहिला स्वाप्त के स्वाप्				30 4	197:	5 का विचा	4			
सेत से प्राणं प्रपेशित (ज्ञार कि से प्राणं प्रपेशित (ज्ञार कि से सिंदाणा (ज्ञार के प्रतेश कि सिंदाणा (ज्ञार के प्रतेश कि सिंदाणा (ज्ञार के प्रतेश								ावच	ाराधान याजनामा का 	स ख् या
तुल्ली 3 2 1		त						जोड़		अतिरिक्त श्रांकः श्रपेक्षित हैं
हिराराणा 14 4 10 हिरास्त प्रवेण 5 5 जन्म प्रोर कामगीर	ा. उत्तरी क्षेत्र	:								
हिरायाण 14 4 10 हिरायक प्रदेश 5 5 जन्म प्रोर काश्मीर 5 जन्म प्रोर काश्मीर 9 1 8 राजस्थात 9 1 8 राजस्थात 43 14 29 74 21 53 2 क्संट-पर्वो केंब्र समम 4 4 4 मंशालय 9 9 नागालैण्ड 13 13 3 पर्वो केंब्र समम 4 16 8 हिराय 13 13 3 3 पर्वो केंब्र समम 4 16 8 8 19 69 1 59 परिचम बंगाल 4 2 2 2 1 58 19 69 1 59 केंब्र समझ 1 52 25 27 113 68 45 5 राज्य 13 68 45 5 राज्य 13 68 45 5 5 राज्य 13 68 5	विल्ली	•.		• .		. •		. 3 .	2 ,	1
जन्न प्रीर काश्मीर पंजाब 9 1 8 राजस्थान 43 14 29 74 21 53 2. उत्तर-पर्बी केंब सदम 4 — 4 में पालम 9 — 9 नापालैण्ड — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			•					14	4	10
पंजाब			•					5	·	5
पंजाब		•					•		-	
2. उत्तर-पर्वो क्षेत्र श्रम								9	1	8
2. उत्तर-पर्वो क्षेत्र क्षम	राजस्थान .	•						43	14	29
2. उत्तर-पर्वो क्षेत्र क्षम							_	74	21	53
ससम 4 — 4 मंचालय 9 — 9 — 9 लागालैण्ड ————————————————————————————————————							-		,	, — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
सेवालय 9 - 9 न 9 न 13 13 3 पर्ने सेंब				,						
नागालैण्ड				٠.	-	•	•			
13		•	•		•	•	•	9		9
विहार 24 16 8 3हीसा 60 1 59 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1	नागालैण्ड .	•	•	•	•	•	• •			-
बिहार 24 16 8 उद्धीसा 60 1 59 परिचम बंगाल 4 2 2 2 88 19 69 4 सध्य प्रदेश	4 - 4						_	13		13
उदीसा . 60 1 59 पश्चिम बंगाल . 4 2 2 88 19 69 4. मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश . 61 43 18 उत्तर प्रदेश . 52 25 27 113 68 45 5. पश्चिमी क्षेत्र गोवा . 2 - 2 गुजरात . 24 - 24 महाराष्ट्र . 77 3 74 103 3 100 6. दक्षिणी क्षेत्र प्रान्तिक . 29 - 29 केरल . 8 4 4 पांडिचेरी 26 तमिलनाडु . 25 104	3 पर्वीक्षेत्र									·
उदीसा . 60 1 59 पश्चिम बंगाल . 4 2 2 88 19 69 4. मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश . 61 43 18 उत्तर प्रदेश . 52 25 27 113 68 45 5. पश्चिमी क्षेत्र गोवा . 2 - 2 गुजरात . 24 - 24 महाराष्ट्र . 77 3 74 103 3 100 6. दक्षिणी क्षेत्र प्रान्तिक . 29 - 29 केरल . 8 4 4 पांडिचेरी 26 तमिलनाडु . 25 104	बिहार .	•	•			•		24	16	8
श्रिक्ष विशेष विष विशेष विश				•	•			60	1	59
4. सध्य प्रदेश स्था ती 43 18 जिल्ला प्रदेश 52 25 27 विश्व कि 27 विश्व कि 25 25 27 विश्व कि 27 विश्व कि 28 विश्व कि 29 विश्व कि 29 कि 29 कि 29 कि 26 विश्व कि 25 विश्व कि 25 विश्व कि 25 विश्व कि 26 विश्व कि 27 विश्व कि 27 विश्व कि 28 विश्व कि 29 विश्व कि 29 कि 27 विश्व कि 28 विश्व कि 29 विश्व क	पश्चिम बंगाल	•	•	•	•	•	•	4	2	2
मध्य प्रदेश 61 43 18 उत्तर प्रदेश 52 25 27 113 68 45 55 पश्चिमी क्षेत्र गोवा 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							_	88	19	69
उत्तर प्रदेश 52 25 27 113 68 45 5. पिश्विमी क्षेत्र गोवा 2 - 2 गुजरात 24 - 24 महाराष्ट्र 77 3 74 103 3 100 6. विश्वणी क्षेत्र थान्ध्र १ विश्वणी क्षेत्र १ विश्वणी क्याप्य १ विश्वणी क्षेत्र १ विश्वणी क्षेत	4. मध्य प्रवेश						_			-
5. पश्चिमी क्षेत्र गोवा	मध्य प्रदेश .		•							
5. पश्चिमी क्षेत्र गोवा	उत्तर प्रदेश	•	•	•	•	•	.• _	52	25	27
गोवा								113	68	45
गुजरात	 पश्चिमी क्षेत्र 						-			(444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
महाराष्ट्र	गोवा .		•		•	•	•	2		
6. विश्वणी सेन मान्ध्र प्रदेश	गुजरात .	•	•	-	•					24
6. विक्षणी क्षेत्र ग्रान्ध्र प्रदेश कर्नाटक केरल पांडिचेरी तिमलनाडु 129 25 129 25	महाराष्ट्र .	•	•	•	•	•	•	77	3	74
मान्ध्रप्रदेश 67 21 46 कर्नाटक 29 - 29 केरल 8 4 4 पांडिकेरी							-	103	3	100
कर्नाटक	6. वक्षिणी क्षेत्र						_	, 	,	
केरल	मान्ध्र प्रदेश		•		•	•	•		21	
पांडिचेरी	क्नटिक .	•	•	•	•	•	•			
तिमलनाडु	करल .	•	•	•	•	•	•		4	4
129 25 104	पा ड चरा . तमिलनाडु .	•		•	•	•				25
							_	129	25	104
फोड (1 से 6 तक)	जोड़ (1 से 6 तक)						-	5 Ż O	136	384

विवरण 13

30 जून 1975 को शेयरधारियों की सूची

। भारतीय रिर्जन बंक

II राज्य भूमि विकास बैंक (19)

- 1. आंध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
- 2. ग्रसम सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
- 3. बिहार राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटड
- 4. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
- हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
- हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
- जम्मू और कश्मीर सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
- कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
- 9. केरल सहकारी केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
- 10. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
- 11. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
- 12. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
- पांडिचेरी राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
- 14. पंजाब राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
- 15. राजस्थान केन्द्रीय सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
- 16. तमिलनाडु सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड
- 17. त्रिपुरा सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड
- 18. उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड
- 19. पश्चिम बंगाल केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक लिमिटेड

III राज्य सहकारी बैंक (24)

- 1. भान्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 2. श्रसम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
- बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 5. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 6. गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 7. हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 8. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 9. जम्मू और काश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 10. कर्नाटक राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
- 11. केरल राज्य सहसारी बैंक लिमिटेड
- 12. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 13. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

- 14. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 15. मेघालय सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड
- 16. नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 17. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 18. पांडियेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 19. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 20. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 21. तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 22. विपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड
- 23. उत्तर प्रवेश सहकारी बैंक लिमिटेड
- 24. पश्चिम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

IV अनुसुचित वाणिज्य बेंक (62)

- 1. स्टेट बैंक श्रॉफ़ इंडिया
- 2. स्टेट बैंक श्रॉफ़ बीकानेर श्रौर जयपूर
- स्टेट बैंक आंफ़ हैदराबाद
- स्टेट बैंक भ्रॉफ़ इंदौर
- स्टेट बैंक श्रॉफ़ मैंसूर
- स्टेट बैंक भ्रॉफ़ पटियाला
- 7. स्टेट बैंक ग्रॉफ़ सौराष्ट्र
- स्टेट बैंक ब्राफ़ तावणकोर
- 9. इलाहाबाद वैंक
- 10. बैंक ग्राफ बड़ौदा
- 11. बैंक श्राफ इंडिया
- 12. बैंक श्राफ महाराष्ट्र
- 13. कनारा बैंक
- 14. सैन्द्रल बैंक भॉफ़ इंडिया
- 15. देना बैंक
- 16. इंडियन बैंक
- 17. इंडियन घोषरसीज बैंक
- 18. पंजाब नेशनल बैंक
- 19. सिडीकेट बैंक
- 20. यूनियन बैंक ग्रॉफ़ इंडिया
- 21. यूनायटेड बैंक ग्रॉफ़ इंडिया
- 22. यूनायटड कमशियल बैंक

- 23. श्रान्ध्र बैंक लिमिटेड
- 24 बैंक ऑफ़ कराड लिमिटेड
- 25. बैंक ऑफ़ मदुरा लिमिटेड
- 26. बैंक ऑफ़ राजस्थान लिमिटेड
- 27. बरेली कारपोरेशन (बैंक) लिमिटेड
- 28. बेलगाम बैंक लिमिटेड
- 29. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
- 30. कैथालिक सीरियन बैंक लिमिटेड
- 31. कारपोरेशन बैंक लिमिटेड
- 32. फोडरल बैंक लिमिटेड
- 33. हिन्दुस्तान कमिशयल बैंक लिमिटेड
- 34 कर्नाटक बैंक लिमिटेड
- 35. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
- 36. कुम्भकोणम् सिटी युनियन वैंक लिमिटेड
- 37. लक्ष्मी कर्माशयल बैंक लिमिटेड
- 38. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
- 39. नारंग बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
- 40. नेडुंगडी बैंक लिमिटेड
- 41. न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
- 42. श्रोरियंटल बैंक ऑफ़ कामर्स लिमिटेड
- 43. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटड
- 44. पूर्वाचल बैंक लिमिटेड
- 45. रत्नाकर बैंक लिमिटड

- 46. सांगली बैंक लिमिटड
- 47. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
- 48. तमिलनाडु मर्लेन्टाइल बैंक लिमिटेड
- 49. युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड
- 50. युनाइटेड बेस्टर्न बैंक लिमिटेड
- 51. तंजाबुर पर्मेनेंट बैंक लिमिटेड
- 52. विजया बैंक लिमिटेड
- 53. वैश्य बैंक लिमिटेड
- 54. एल्गमेने बैंक नीदरलैण्ड्स एन० वी०
- 55. ग्रमोरिकन एक्स्प्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन
- 56. बैंक भ्राफ भ्रमेरिका ट्रस्ट एण्ड सेव्हिंग्स एसोसिएशन
- 57. बैंक श्राफ तोकियो लिमिटेड
- 58. बैंक नैशनले डिपरिस
- 59. चार्टर्ड बैंक
- 60. ग्रिडलेज बैंक लिमिटेड
- 61. मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
- 62. मित्सूई बैंक लिमिटेड

V बीमा और निवेश क्रंपनियां आंबि (4)

- 1. जीवन बीमा निगम
- 2. न्यू इंडिया एक्यौरस कंपनी लिमिटेड
- 3. युनाइटेड इंडिया फायर जनरल इंग्यौरस कंपनी लिमिटेड
- 4. को-ग्रापरेटिव्ह जनरल इंग्यौरस सोसायटी लिमिटेड

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने कृषि-पुनर्वित्त निगम के 30 जून 1975 तक के संलग्न तुलन-पत्न और निगम के उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न लाभ-हानि लेखों की जांच की है और हम यह रिपोर्ट देते हैं कि----

- हमें जिस जानकारी और जिन स्पष्टीकरणों की जरूरत थी, वे सब हमने प्राप्त कर लिये हैं और वे संतोषजनक पाये गये हैं।
- 2. हमारी राय में श्रौर जहां तक हमारी जानकारी है तथा हमें जो स्पष्टीकरण दिये गये हैं, उनके श्रनुसार श्रौर निगम की बहियों में दर्शाये गये श्रनुसार यह तुलन-पन्न पूर्ण श्रौर सही हैं श्रौर इसमें सभी श्रावश्यक नियरण दिये गये हैं तथा यह तुलन-पन्न निगम के श्रिधिनियम श्रौर सामान्य विनियमों के श्रनुसार उचित ढंग से इस तरह तैयार किया गया है कि इससे निगम के कार्यों की सच्ची श्रौर सही हालत का पता लग सके।

एन० एम० रायजी एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

20 धगस्त 1975
यूनिवर्सेल इंग्यौरस बिल्डिंग
फीरोज शाह मेहता रोड
बंबई-400001

श्रनुबंध कृषि पुनवित्त 30 जून 1975 को

देसताएँ 1. पूंजी ए ए पे ए ए ए ए		.··				30 जून 197	o +hT
प्रापिकत पूँची प्रत्येक 10,000 रुपयों जाले 25,000 शेयर जारी की गई, स्रविद्य और प्रदत्त पूँजी प्रत्येक 10,000 रुपयों वाले 20,000 प्रदत्त क्षेत्रर 20,90,00,000.00 15,00,00,000.00 15,00,00,000.00 2. सारक्षित निधि भीर सिक्षेत्रथे धारिक्षत निधि भीर क्षम्पार वकाया(नीट 1) प्रदादये : 1973-74 के दौरान सरकार को चुकाये गर्म राजकीय ऋण 14,13,896.05 विदेश सिक्ष प्रिणित निभि भी शेवरित राणि (वित्त प्रिणित निभ भी 10% भंतरित राणि (वित्त प्रिणित निभ भी 10% भंतरित राणि (वित्त प्रिणित निभ भी निभ भी भीतित राणि (वित्त प्रिणित निभ भी भीतित राणि (वित्त निभ भी भीतित राणि (वित्त प्रिणित निभ भी भीतित राणि (वित्त निभ भी भीतित राणि (वित्त प्रिणित निभ भी भीतित राणि (वित्त निभ भीतित राणि (वित्त भीतित राणि (· 		30-6-197	4 को
प्रत्येक 10,000 क्यमों वाले 25,000 क्यम 25,000 क्यम 25,00,00,000.00 25,00,00,000.00 25,00,00,000.00 25,00,00,000.00 31,00,000.00 15,00,00,000.00 15,00,00,000.00 15,00,00,000.00 25 आरक्षित निधि और प्रश्चिष प्रारक्षित निधि पिछले तुजनपत्र के धनुसार बकामा (नीट 1) 1,49,72,000.00 81,61,000.00 वटाइये : 1973-74 के दौरान सरकार को बुकामे गये राजकीय ऋण 14,13,896.05 67,47,103.95 विश्व : (i) वर्तमान लाम की 10% धंतरित राणि 45,00,000.00 31,00,000.00 (विश्व ध्रीधिनयम,1971 के अनुसार) (ii) लाभ-हानि लेखे से अंतरित राणि 77,63,000.00 51,25,896.05 2,72,36,000.00 1,49,73,000.00 साभ-हानि लेखे : आगे लाया गया लाभ 775.18 464.35 हस वर्ष का लाम 1,86,23,173.97 1,17,51,206.88 1,17,51,206.88 1,66,23,949.15 7,63,000.00 51,25,896.05 51,25,896.05 66,25,775.18 लामोण की व्यवस्था के लिए अंतरित राणि 88,60,616.44 332.71 775.18 66,25,000.00 88,60,616.44 332.71 775.18	1. पूंजी	र्∘	पै०	रु०	पै०	₹0	4 °
जारी की गई, प्रजिदत्त धौर प्रवस पूंजी प्रत्येक 10,000 रुपयों वाले 20,000 प्रवत सेगर . 20,00,00,000.00 15,00,00,000.00 2. प्रार्गकित निधि धौर प्रशिक्षणेष धारिक्षत निधि प्रौर प्रशिक्षणेष धारिक्षत प्रौर प्रशिक्षणेष धारिक्षत निधि प्रौर प्रशिक्षणेष धारिक्षत प्रशिक्षणेष धारिक्षणेष धारिक्षत प्रौर प्रशिक्षणेष धारिक्षणेष धारिक्षणेष धारिक्षणेष धारिक्षणेष धारिक्षत प्रशिक्षणेष धारिक्षणेष	**						
प्रतिक 10,000 रुपयों वाले 20,000 प्रदत्त सेवर 20,000,000.00 15,00,00,000.00 15,00,00,000.00 2. प्रारक्षित निधि और प्रतिक निधि पिछले तुलनपत के मनुसार बकाया (नोट 1) 1,49,72,000.00 81,61,000.00 घटाइये : 1973-74 के दौरान सरकार को चुकाये गये राजकीय ऋण 14,13,896.05 67,47,103.95 वोड़िये : (i) वर्तमान लाभ की 10% भंतरित राणि 45,00,000.00 31,00,000.00 (विक्त प्रशितियम,1971 के सनुसार) (ii) लाभ-हानि लेखे ते संतरित राणि 77,63,000.00 51,25,896.05 2,72,36,000.00 1,49,73,000.00 लाभ-हानि लेखे : मागे लाया गया लाभ 775.18 464.35 हस वर्ष का लाभ 1,66,23,173.97 1,17,51,206.88 464.35 इस वर्ष का लाभ 1,66,23,173.97 1,17,51,671.23 51,25,896.05 88,60,949.15 66,25,775.18 लाभांण की व्यवस्था के लिए प्रंतरित राणि 77,63,000.00 51,25,896.05 66,25,775.18 लाभांण की व्यवस्था के लिए प्रंतरित राणि 88,60,616.44 332.71 775.18	प्रत्येक 10,000 रुपयोवाले 25,000 शेयर			25,00,00	000.00	25,00,00,000	.00
प्रतिक 10,000 रुपयों वाले 20,000 प्रदत्त सेवर 20,000,000.00 15,00,00,000.00 15,00,00,000.00 2. प्रारक्षित निधि और प्रतिक निधि पिछले तुलनपत के मनुसार बकाया (नोट 1) 1,49,72,000.00 81,61,000.00 घटाइये : 1973-74 के दौरान सरकार को चुकाये गये राजकीय ऋण 14,13,896.05 67,47,103.95 वोड़िये : (i) वर्तमान लाभ की 10% भंतरित राणि 45,00,000.00 31,00,000.00 (विक्त प्रशितियम,1971 के सनुसार) (ii) लाभ-हानि लेखे ते संतरित राणि 77,63,000.00 51,25,896.05 2,72,36,000.00 1,49,73,000.00 लाभ-हानि लेखे : मागे लाया गया लाभ 775.18 464.35 हस वर्ष का लाभ 1,66,23,173.97 1,17,51,206.88 464.35 इस वर्ष का लाभ 1,66,23,173.97 1,17,51,671.23 51,25,896.05 88,60,949.15 66,25,775.18 लाभांण की व्यवस्था के लिए प्रंतरित राणि 77,63,000.00 51,25,896.05 66,25,775.18 लाभांण की व्यवस्था के लिए प्रंतरित राणि 88,60,616.44 332.71 775.18	•			——————————————————————————————————————			
शेयर							
2. म्रारक्षित निधि भीर मधिणेष मारक्षित निधि पिछले तुलनपत के प्रतुसार बकाया (नोट 1) 1,49,72,000.00 81,61,000.00 पटाइये : 1973-74 के दौरान सरकार को चुकाये गये राजकीय ऋण . 14,13,896.05 67,47,103.95 जोड़िये : (i) वर्तमान लाम की 10% मंतरित राणि 45,00,000.00 31,00,000.00 (विश्त मधिनियम,1971 के प्रनुसार) (ii) लाभ-हानि लेखे ते अंतरित राणि 77,63,000.00 51,25,896.05 2,72,36,000.00 1,49,73,000.00 लाभ-हानि लेखे ते अंतरित राणि 775.18 464.35 इस वर्ष का लाभ 1,66,23,173.97 1,17,51,206.88 1,66,23,949.15 1,17,51,671.23 घटाइये : म्रारक्षित निधि की अंतरित राणि 77,63,000.00 51,25,896.05 88,60,949.15 1,25,896.05 66,25,775.18 लामाण की व्यवस्था के लिए मंतरित राणि 88,60,949.15 66,25,775.18 66,25,000.00 88,60,616.44 332.71 775.18	_			20,00,00,0	00.00	15.00.00.000	. 00
प्रारक्षित निधि पिछले तुलनपत के मनुसार वकाया(नीट 1) प्रतिक तुलनपत के मनुसार वकाया(नीट 1) प्रतिक तिधि पिछले तुलनपत के मनुसार वकाया(नीट 1) प्रतिक तिधि को चुकाये गये राजकीय ऋण				= 3, \$ 3, \$ 3, \$		1 4, 0 0, 0 0, 0 0	
घटाइये : 1973-74 के दौरान सरकार को जुकाओ गये राजकीय ऋण							,
को बुकाये गये राजकीय ऋण	पिछले तुलनपक्ष के म्रनुसार बकाया (नोट 1)	1,49,73,	000.00			81,61,000	.00
जोड़िये : (i) वर्तमान लाम की 10% मंतरित राशि	घटाइये : 1973-74 के दौरान सरकार			•			
पोड़िये : (i) वर्तमान लाभ की 10% मंतरित राशि 45,00,000.00 31,00,000.00 (विश्त भ्रमितियम,1971 के अनुसार) (ii) लाभ-हानि लेखे से अंतरित राशि 77,63,000.00 51,25,896.05 साभ-हानि लेखे : प्रामे लाया गया लाभ 775.18 464.35 इस वर्षे का लाभ 1,66,23,173.97 1,17,51,206.88 1,66,23,949.15 1,17,51,671.23 घटाइये : म्रारक्षित निधि की भ्रंतरित राशि 77,63,000.00 51,25,896.05 88,60,949.15 66,25,775.18 लामांग की व्यवस्था के लिए श्रंतरित राशि 88,60,949.15 66,25,775.18 लामांग की व्यवस्था के लिए श्रंतरित राशि 88,60,616.44 332.71 775.18	को चुकासे गर्से राजकीय ऋण					14,13,896	. 05
(i) वर्तमान लाम की 10% मंतरित राशि 45,00,000.00 31,00,000.00 (विस म्रिशिनियम,1971 के अनुसार) (ii) लाभ-हानि लेख से मंतरित राशि . 77,63,000.00 51,25,896.05 2,72,36,000.00 1,49,73,000.00 लाभ-हानि लेखा: मागे लाया गया लाभ					24-9	67,47,103	3.95
(वित्त प्रधितियम,1971 के प्रनुसार) (ii) लाभ-हानि लेखे से अंतरित राशि . 77,63,000.00 51,25,896.05 2,72,36,000.00 1,49,73,000.00 लाभ-हानि लेखा : भागे लाया गया लाभ . 775.18 464.35 इस वर्षे का लाभ . 1,66,23,173.97 1,17,51,206.88 1,66,23,949.15 1,17,51,671.23 घटाइये : प्रारक्षित निधि की अंतरित राशि 77,63,000.00 51,25,896.05 88,60,949.15 66,25,775.18 लाभांग की व्यवस्था के लिए प्रंतरित राशि 88,60,616.44 332.71 775.18 3. विशेष जमा 1,78,92,086.54 1,40,56,386.54	जोड़िये :			-			
सागे लाया गया लाभ	• /	45,00,	000.00			31,00,000	. 00
लाभ-हानि लेखा : ग्रागे लाया गया लाभ	(ii) लाभ-हानि लेखे से अंतरित राशि .	77,63,6	000.00			51,25,896	. 0 5
भागे लाया गया लाभ	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,72,36,	000.00	1,49,73,000	0.00
इस वर्ष का लाभ	लाभ-हानि लेखाः						
घटाइये : ग्रारक्षित निधि की ग्रंतरित राणि 77,63,000.00 51,25,896.05 88,60,949.15 66,25,775.18 लाभांग की व्यवस्था के लिए ग्रंतरित राणि 88,60,616.44 332.71 775.18 3. विशोष जमा	भागे लाया गया लाभ		775.18			464	1.35
घटाइये : म्रारक्षित निधि की म्रंतरित राशि 77,63,000.00 51,25,896.05 88,60,949.15 66,25,775.18 लाभांश की व्यवस्था के लिए म्रंतरित राशि 88,60,616.44 332.71 775.18 3. विशेष जमा 1,78,92,086.54 1,40,56,386.54	इस वर्षे का लाभ	1,66,23,1	173.97		•	1,17,51,206	. 88
घटाइये : म्रारक्षित निधि की म्रंतरित राशि 77,63,000.00 51,25,896.05 88,60,949.15 66,25,775.18 लाभांश की व्यवस्था के लिए म्रंतरित राशि 88,60,616.44 332.71 775.18 3. विशेष जमा 1,78,92,086.54 1,40,56,386.54		1, 66, 23,	949.15			1,17,51,671	. 23
लाभांश की व्यवस्था के लिए म्रंतरित राशि 88,60,616.44 332.71 775.18 3. विशेष जमा 1,78,92,086.54 1,40,56,386.54	घटाइये : ग्रारक्षित निधि की ग्रंतरित राणि						
लाभांश की व्यवस्था के लिए म्रंतरित राशि 88,60,616.44 332.71 775.18 3. विशेष जमा 1,78,92,086.54 1,40,56,386.54		88.60.	949.15			66.25.775	. 18
88,60,616.44 332.71 775.18 3. विशेष जमा 1,78,92,086.54 1,40,56,386.54	कार्याण की व्यवस्था के लिए श्रंतरित राणि	,,					
	वाचाव का न्यवरवा क विद्र तकारत वर्ष	88,60,	616.44		332.71		
			 -		-	·	
ग्रागे से जाया गया जोड़ 24,51,28,419.25 17,90,30,161.72	3. विशेष जमा			1,78,92,0	86.54	1,40,56,386	. 54
	भ्रामे लेजाया गया जोड़			24,51,28,4	119.25	17,90,30,161	.72

and the control of th

निगम	
सुलन-पत्न	•

	,				
भ्रास्तिया ं					30-6-1974 को
_	स ०	पै०	रु० पै०	रु०	पै०
1. नकदी					
(क) हाथ में		2,385.24			2,321.08
(ख) भारतीय रिजर्न वैंक के पास .	24,8	33,717.07			7,36,635.04
(ग) दूसरों के पास :					
(i) भारत में	7	4,454.63			45,622,84
(ii) त्रिदेश में					
			25,60,556.9	4	7,84,578.96
2. ऋण					
(क) पुनर्वित के रूप में	63,04,6	1,375.00		38	3,23,13,971.00
(ख) अन्य					
घटाइये : ग्रशोध्य ग्रौर संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था					
3. डिबेंचर			63,04,61,375.0		3,23,13,971.00 1,51,40,033.83
4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश			040,10,10,402.0		
(लागत पर)					
 निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज 			_ -	-	
 धन्य श्रास्तियां 					
(क) फर्नीचर, फिटिंग्स श्रौर जुड़नार कार्यालयीन उपस्कर ग्रादि					
10,64,731.44					8,35,165,92
जोड़िये: इस वर्ष की वृद्धि 3,36,704.04				 _	2,29,728,52
14,01,435.48					10,64,894.44
घटाइयें : बेची गई/समंजित मर्दे 5,436,40					163.00
13,95,999.08					10,64,731.44
घटाइये : ग्राज की तारीख 4,36,619.00					3,18,122.07
तक का मूल्य ह्रास			0.050.00		
(ख) सरकारी विभागों श्रीर ग्रन्य संस्थाय्रों			9,359,80.0	8	7,46,609.37
के पास जमाराशियां			1,48,391.60	ŝ	1,24,956.66
श्रागे ले जाया गया जोड़	11,0	7,771.74	406,43,37,414.33	2 309	,82,38,583.79

कृषि पुनर्वित्त 30 जून 1975 को

والمراقب وال				30 जून 1975 का
देयताएं		Δ.		
	र्०	पै०	रु० पै०	रु० पै०
भागे लाया गया जोड़			24,51,28,419.25	17,90,30,161.72
4. बांड और डिबेंचर				
5र्रे% कृषि पुर्निवत्तः निगम बांड 1982 ——> २०२०	1000.00	000		
पहली सीरीज	10,93,77,	000.00		
5 १ % कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1982	0.50.50.4	200 00		
दूसरी सीरीज	8, 52, 50, 6	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
5्र्र्रे% कृषि पुर्नावत्त निगम बांड 1984 तीसरी सीरीज	9 25 00 0	00 00		
तासरा साराज $5^3_4\%$ कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1985	8,25,00,0	00.00		
<u>-2.62.6.</u>	11,00,00,0	100 00°		
चाया साराज $5^3_4\%$ कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1985	11,00,00,0	J u 0.00		
54 /₀ कृषि भुगायस समयम बाङ 1985 पांचवीं सीरीज	16,50,00,0	00 00		
$5^2_1\%$ कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1986	10,50,00,0	00.00		
54./७ श्राप पुताबरा समस्य पाउ 1980 छठी सीरीज	11,00,00,0	00 00		
6% कृषि पुनर्वित्त निगम बांड 1984	11,00,00,0	00.00		
	16,50,00,0	00 00		
सातवा साराज 6% कृषि पुनर्वित्त निगम बाड 1985	10,30,00,0	00.00		
भ्राठवीं सीरीज	16,50,00,0	00 00		
	10,00,00,0			
5. केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋण			99,21,27,000,00	66,21,27,000.00
(क) श्रधिनियम की धारा 19 के प्रधीन .	5,00,00,0	00.00		5,00,00,000.00
(ख) भ्रन्य ऋण	191,62,14,6	55.00		158,50,23,185.00
6. श्रन्य उधार			196,62,14,655.00	162 50 02 105 00
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये उधार :			100,02,14,000.00	163,50,23,185.00
(1) दीर्घकालीन उधार	88,20,00,0	00.00		54,00,00,000.00
$\left(\stackrel{\cdot}{a} \right)$ श्रत्यकालीन उधार	4,50,00,0	90.00		11,60,00,000.00
(नोट 2)				, = =, = 0, 000, 00
(ख) दूसरों से लिये गये उधार :			92,70,00,000.00	65,60,00,000.00
(ख) दूसरा सालय गय उवार. (1) भारत में				
(2) विदेश में				
१८) । प्राचिक जमाराशियां				
(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की				~-
(ख) दूसरों की	88,60,61	6 44		
8. लाभांशों की व्यवस्था	00,00,00			
लाभहानि लेखे से श्रंतरित की गई राशि				66.05.000
जोड़िये : श्रिधिनियम की धारा 28 के साथ			•	66,25,000.00
पढ़ी जानेवाली धारा 6 के श्रनुसार केंद्रीय			88,60,616.44	
सरकार द्वारा की जानेवाली श्रदायगी			-,00,010.4 7	
(देखिए दुतरफा लांभांण थाटा लेखा)				
· -			ے جسے سرج سے و سم سے و سماع کست سرج سام کسام سے و سام کا مساح	66,25,000.00
श्रागे ले जाया गया जोड़ :			413,93,30,690.69	313,88,05,346.72
در در استراده و سنزد در فسنزد و در و سنزده و در در فسناره برسد و سنزده و سنزده و الدواوس و هرا و سنزده و سنزد	-,,,,,,,,,,,,,,,,	· ·		

मास्तिया <u>ं</u>	क्० पै०	क्० पै०	र ० पै ०
नागे लाया गया जोड़	1,07,771.74	406,43,37,414.32	309,82,38,583.79
9. (जारी)	•		
(ग) फुटकर श्रग्रिम	78,55,059.25		9,29,088.61
(घ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत ब्याज .	11,44,01,897.91		8,35,15,027.2
(ङ) पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों पर			
प्रोद्भूत ब्याज	1,51,50,880.33		75,53,486.50
(च) कृषि पुनर्वित्त निगम बांडों पर छूट .	31,51,500.00		

,		कृषि पुनर्वित्त 30 जून 1973 को
	ह० पै०	रू० पै०
भागे लाया गया जोड़	413,93,30,690.69	313,88,05,346,72
9. कराधान की व्यवस्था (नोट 3)	1,60,59,341.00	1,20,52,113.00
10. श्रम्य देयताएं फुटकर लेनदार .	48,07,366.53	51,05,598.50
तिम्नलिखित पर प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं है : (क) केन्द्रोय सरकार से लिये गये ऋण .	3,09,07,893.77	2,42,05,462.40
(ख) बांड भ्रौर डिबेंचर	1,48,99,231.56	1,09,39,231.56
ग्रा कस्मिक देयताएं		
[(क) भारत के बाहर से पूंजीगत माल खरीदने के लिए श्रस्थगित श्रदायगी पर दी गई ्गारंटी के बाबत		
(ब) श्रन्य मदें		
जोड़	420,60,04,523.55	319,11,07,752.18

नोट :1. इसमें वित्त प्रधिनियम 1971 के अनुसार विशेष आरक्षित निधि के 66,50,000/- रुपये शामिल हैं।

- 2. डिबेंचरों को गिरवी रखकर घट्पावधि उधार प्राप्त किये गये हैं।
- कराधान के लिए व्यवस्था करों की श्रिप्रिम श्रदायगी के लिए समंजन करने श्रौर स्रोत पर काटे गर्य कर के बाद की गई है।

कें० ग्रार० सुब्रह्मण्यम् वरिष्ठ निदेशक, वित्त ग्रीर प्रशासन इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के श्रनुसार एन० एम० रायजी एण्ड कं० सनदी लेखाकार बंबई 20 श्रगस्त 1974

बंबई, 19 ध्रगस्त 1974

PART III—Sec. 41 T	THE GAZETTE OF INDIA,	FEBRUARY 21, 1976	(PHALGUNA 2, 1897)
--------------------	-----------------------	-------------------	--------------------

निगम तुलनपत्न

भागे लाया गया जोड़

₹०

पै०

रु०

₫ ०

₹०

पै० -

1133

420,60,04,523.55

319,11,07,752.18

420,60,04,523.55

319,11,07,752.18

स्रार० के० हजारी

बो० एस० विश्वनाथन् एम० ग्रार० पटेल सी० डी० दाते

एम० ए० चिदंबरम्

ग्रध्यक्ष

निदेशक

प्रबंध निदेशक

बंबई

19 म्रगस्त 1974

कृषि पुनर्वित्त 30 जून 1975 को समाप्त हुए

		— 		— <u>—</u> — — — — — — — — — — — — — — — — —			ह ं पै०	पिछले वर्ष रु० पै०
1.	श्रदा किया गया ब्याज	•	•				16,22,04,806.83	11,34,20,889.45
2.	वेतन ग्रौर भत्ते .						93,27,112.28	65,20,378.40
3.	कर्मचारी भविष्य निधि,	पेंशन और श्र	न्य निधिय	ों में श्रंशदान			7,63,027.81	6,01,511.38
4.	निदेशकों श्रौर समिति के	सदस्यों की फी	स	-	•		1,100.00	1,500.00
5.	निदेशकों श्रीर समिति	के सदस्यों की	वैठकों व	के संबंध में	यात्रा क	गौर		
	ग्रन्य भत्ते .	•	•	•	•		20,973.00	18,160.00
6.	किराया, उपकर, बीमा	बिजली इत्या	दि			•	8,03,607.54	6,8 1,5 95 . 8 7
7.	यात्रा व्यय .	•	•		•	•	7,31,761.69	4,86,796.88
8.	छपाई घौर लेखन सामग्री	· .					2,37,301.44	1,73,018.58
9.	डाक, तार और टेलीफोन		•			,	1,94,272.14	1,53,988.25
10.	संपत्ति की मरम्मत	•	•	•	•	•	23,160.18	11,552.24
11.	लेखा परीक्षकों की फीस	•	•			•	10,000.00	10,000.00
12.	कानूनी व्यय .		•.			•	9,899.76	17,353,59
13	विविध व्यय (नोट 1)		•			•	28,09,281.59	22,55,375.69
14.	मूल्य ह्रास .	•			•		1,20,000.68	93,747.01
15.	विशेष ग्रारक्षित निधियो	ंको भ्रंतरण	जो वित	श्रधिनियम	197	1 के		
	श्रधीन वर्तमान लाभ का	10% है	•	•	•	•	45,00,000.00	31,00,000.00
16.	कराधान की व्यवस्था	•		•			2,30,41,923.00	1,60,18,595.38
1 7.	तुलनपत्न को लं जाया गय	ा मुद्ध लाभ	•	•		•	1,66,23,173.97	1,17,51,206.88
	जोड़	•	٠.,	•			22,14,21,491.91	15,53,15,669.60

नोट: 1 इनमें ये राशियां शामिल हैं: (1) बांडों स्रीर शेयरों पर मुद्रांक शुल्क

19,80,333. 25 ह० और (2) बांड

भाजन सातवीं ग्रौर ग्राठवीं सीरीज रु०

1,48,500.00 হ৹ 737,790.55 €0

नोट : 2 इस राशि में ग्रभिदस्त डिबेंचरों पर प्राप्त भाजन शामिल हैं---

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के भ्रनुसार

के० प्रार० सुब्रह्मण्यम्, वरिष्ठ निदेशक, वित्त और प्रशासन बंबई, 19 घ्रगस्त 1974 एन० एम० रायजी एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार वंबई, 20 ग्रगस्त 1974

3 निगम वर्षका साभ हानि लेखा

				ि	ाछले वर्ष
		रु०	पै०	रु०	पै०
1. प्राप्य ब्याज					
(क) ऋणों ग्रौर डिबेंचरों पर	21,14,69,035.49			14,98,	76,623.91
(ख) निवेशों पर (स्रोत पर काटा गया कर रु०)	98,81,563.65	•		5 3,	70,316.19
•		22,13,5	- 50,599.14	15,52,	46,940.10
2. भांजन, कमीशन श्रादि					
3. श्रन्य मर्दे					
(क) शेयर भ्रतरण गुल्क					2.00
(ख) विविध प्राप्तियां (नोट 2) .	38,117.98				31,026.76
(ग) वायदा प्रभार	32,774.79				37,700.74
		7	- 70,892,77		68,729.50

जोड़ 22,14,21,491.91 15,53,15,669.60

> म्रार० के० हजारी बी० एम० विश्वनाथन्

घध्यक्ष

एम० धार० पटेल सी० डी० दाते

निदेशक

एम० ए० चिदंबरम्

प्रबंध निदेशक

षंबर्ष, 19 धगस्त 1975

STATE BANK OF INDIA

· OFFICE MANAGER'S DEPARTMENT

NOTICE

New Delhi-110001, the 28th January 1976

No. OMD/819.—Shri R. N. Srivastava, Staff Officer Gr. III, Area Superintendent, Region III, will officiate as Administrative Officer (Loans) in place of Shri H. S. Gupta, Staff Officer Grade III who has proceeded on leave for 44 days with effect from 29th December, 1975,

Sd/- ILLEGIBLE
Office Manager

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 2nd January 1976

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified:---

Shri S. Bashyam has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office staff as from the 1st January 1976.

The 20th January 1976

The following appointment on the Bank's staff is hereby notified:—

Shri H. N. Puri has been appointed as Deputy Branch Inspector on the Central Office staff as from the 19th January 1976.

T. R. VARADACHARY, Managing Director

STATE BANK OF PATIALA HEAD OFFICE

Patiala, the 1st November 1975

No. SBOP.62.—The following transfers and changes in the postings of Bank's Supervising Staff are hereby notified:—

1, Shri Inder Bhushan Gupta, Officer Grade II to be Manager Darya Ganj, Delhi branch as from the commencement of business on 24-10-75.

S. D. GANDA Managing Director

STATE BANK OF SAURASHTRA

Bhavnagar, the 30th January 1976

No. 1/76.—The following changes in the posting of Bank's staff are hereby notified:—

Shri G. Sridharan, Officer Grade I held temporary charge of Madras branch as from the close of business on 17-5-1975 to the commencement of business on 16-6-1975 vice Shri B. N. Pardia, Officer Grade I.

Shri A. A. Kidwai, Officer Grade I, held temporary charge of Kanpur branch as from the close of business on 3-5-1975 vice Shri L. R. Arora, Officer Grade I.

Shri A. M. Naik, Officer Grade I held temporary charge of Fort Branch, Bombay as from the close of business on 2-6-1975 to the commencement of business on 14-6-1975 vice Shri B. R. Desai, Officer Grade 'A'.

Shri Abhirami Sahu, Officer Grade I held temporary charge of Hyderabad branch as from the close of business on 3-9-1975 to the commencement of business on 15-9-1975 vice Shri B. G. Dange, Officer Grade 'A'.

B. S. NAWATHE Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110001, the 15th January 1976

No. 5-CA(1)/21/75-76.—With reference to this Institute's Notification No. 4-CA(1)/22/71-72 dated 1-7-71 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964 that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 24th December, 1975, the name of Shri Nitya Nand Pathak, A. C. A., Dodoma, Regional Training Co. Ltd., P. O. Box 971, Dodoma, Tanzanla (M. No. 11627).

The 24th January 1976

No. 4-CA(1)/14/75-76.—In pursuance of Regulation 16 of the Chartered Accountes to Regulations, 1964, it is hereby notified that in exercise of the poewers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen:—

Sl. No.	Membership No.	Name and Address	Date of removal	
1. 1948		Shri B. S. Kabra, Lakshmi Bhawan, Birhana Road, Kanpur.	6-1-1976	
2.	6957	Shri G. Misquith, 6, Maria Mansion, C.T.S. Road, Kalina, Bombay-29.	6-7-1975	

No. 8-CA(1)/18/75-76.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled for the period mertioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

SI. No.	Membership No.	Name and Address	Period during which the Certificate shall stand cancelled
1.	3101	Shri S. R. Tambane, A.C.A., "Surayodaya" Ranade Road Extension, Shivaji Park Area, Dadar, Bombay-28.	1-1-1976
2,	8823	Shri B. K. Singhania, F.C.A., 8, Ramanand Chatterji Street, Calcutta-700009.	1-1-1976
3.	16493	Shri J. M. Khanna, A.C.A., B-3/19, Krishan Nagar, Delhi.	25-8-1975

The 27th January 1976

No. 5-CA(1)/22/75-76.—With reference to this Institute's Notification No. 4-CA(1)/21/(74-75) dated 4th February, 1975, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the

Chartered Accountants Regulations, 1964 that in exercise of the powers conferred by regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from 29th December, 1975 the name of Shri Jatan Raj Gulecha, A.C.A. (M. No. 15548) C/o Geeta Iron, Bajuva, Distt. Baroda (Guirat).

The 31st January 1976

No. 13-Exam(1)/M/76.—In pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Entrance Examination will be held on 3rd, 4th, 5th & 6th May 1976, the Intermediate examination under the old syllabus on 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th May 1976, the Intermediate Examination under the New syllabus on 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th and 10th May 1976 and the Final Examination on 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 10th and 11th May 1976 under the said Regulations. The Examinations will be held at the following centres, provided that sufficient number of candidates present themselves for the examination at each of the centres:—

- 1. Agra
- 2. Ahmedabad
- 3. Allahabad
- 4. Bangalore
- 5. Baroda
- 6. Belgaum
- 7. Bombay
- 8. Calcutta.
- 9. Chandigarh
- 10. Coimbatore
- 11. Delhi
- 12, Ernakulam
- 13. Gauhati
- 14. Hyderabad
- 15. Indore
- 16. Jaipur
- 17 To House
- 17. Jodhpur
- Kanpur
 Ludhiana
- 20. Madras
- 21. Madurai
- 22. Mangalore
- 23. Mysore
- 24. Nagpur
- 25. Patna
- 26. Poona
- 27. Rajkot28. Trivandrum
- 29. Udaipur
- 30. Vishakapatnam
- 31. Vijayawada.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the prescribed forms, copies of which may be obtained from the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg. Post Box No. 268, New Delhi-110001. Each such application together with the necessary certificates and a demand draft or Indian Postal Order payable at New Delhi and drawn in favour of the Secretary referred to above, for the examination fee of Rs. 60/- in the case of Entrance Examination. Rs. 55/- in the case of Intermediate Examination under the Old Syllabus, Rs. 75/- in the case of Intermediate Examination under the New Syllabus and Rs. 80/- for admission to both the groups or Rs. 55/- for admission to one group only for the Final Examination, must be sent so as to reach the Secretary to the Council not later than the 3rd March 1976,

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 20-PG(Exam)/M/76.—In pursuance of Paragraph 5 of Schedule 'C' to regulation 179 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to direct that an examination in Management Accountancy Course—Part I under the said Regulations shall be held on 3rd, 4th, 5th and 6th, May 1976. The examination will be held at the following centres.—

- 1. Agra
- 2. Ahmedabad
- 3. Allahabad
- 4. Bangalore
- Baroda
- 6. Belgaum
- 7. Bombay
- 8. Calcutta
- Chandigarh
- Coimbatore
- 11. Delhi
- 12. Ernakulam
- 13. Gauhati
- 14. Hyderabad
- 15. Indore
- 16. Jaipur
- 17. Jodhpur
- 10 Vannus
- 18. Kanpur
- 19. Ludhiana
- 20. Madras
- 21. Madural
- 22. Mangalore
- 23. Mysore
- 24. Nagpur
- 25. Patna
- 26. Poona
- 27. Rajkot28. Trivandrum
- 29. Udaipur
- 30. Vishakapatnam
- 31. Vijayawada.

Applications for admission to the examination are required to be made on the prescribed from, copies of which may be obtained from the Secretary, Institute of Chartered Accountants of India, Post Box No. 268, Indraprastha Marg, New Delhi-1. Each such application together with the necessary documentary evidence and a Demand Draft for Rs. 100/- payable at New Delhi and drawn in favour of the Secretary must be sent so as to reach him not later than the 3rd March 1976.

The 9th February 1976

No. 1-CA(87)/75.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has made the following amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, the same having been previously published and approved by the Central Government as required under subsection (3) of the said section.

In the said Regulations :-

- In sub-regulation (1) of regulation 63, for the words "six hundred" substitute the words "seven hundred."
- II. In sub-regulation (4) of Regulation 112, for the words "three hundred" substitute the words "three hundred and fifty".

P. S. GOPALAKRISHNAN, Secretary

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

1138

Calcutta-700016, the 14th January 1976

No. 18-CWR(24)/76.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the power conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 9th January 1976 the name of Shri V. Jagannathan, B.COM, BL, MBA, AICWA, Chief Accountant, Model Neighbourhood Drug Abuse Programs Inc., 4707 Woodward Avenue, Detroit, M 148201, U.S.A. (Membership No. 1721).

S. N. GHOSE Secretary.

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 4th February 1976

No. 4-8/75-EP.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971, namely:—

- (1) These Regulations may be called the Food Corporation of India (Staff) (28th Amendment) Regutions, 1976.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 27th January, 1976.
- 2. The following further proviso shall be added to Regulation 9(a) after the existing proviso of the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971, namely:—

"Provided further that such of the employees who were recruited on daily-rate basis for periods of less than 3 months or on purely temporary basis and whose services have been retained after allowing periodical breaks, shall also be eligible to be considered for appointment against direct recruitment along with candidates sponsored by the respective employment exchanges."

V. P. KAPOOR Joint Personnel Manager

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 29th January 1976

No. N. 17/13/76 (P&D)(5),—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 31st January, 1976 as indicated in the table given below:—

Set	First contrib	oution period	First benefit period				
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of			
A	31-1-1976	31-7-1976	30-10-1976	30-4-1977			
В	31-1-1976	27-3-1976	30-10-1976	25-12-1976			
C	31-1-1976	29-5-1976	30-10-1976	26-2-1977			

SCHEDULE :

"The areas comprising the Industrial Estate, Chikhalthana, District Aurangabad, in the State of Maharashtra."

> FAQUIR CHAND Director (Planning & Development)

Jaipur, the 5th, February 1976

No. R/18-7-73-Estt.—It is hereby notified that the Local Committee consisting of the following members has been reconstituted for LAKHERI AREA under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 w.e.f. the date of notification.

CHAIRMAN:

Under Regulation 10-A (1) (a)

District Medical & Health Officer. BUNDI.

MEMBERS:

Under Regulation 10-A (1) (b)

Regional Dy. Labour Commissioner, KOTA.

Under Regulation 10-A (1) (c).

Medical Officer, Incharge. A.C.C. Works, Hospital, LAKHERI.

Under Regulation 10-A (1) (d)

Shri A. G. Pathrose, Personnel & Welfare Officer, Lakheri Cement Works, LAKHERI.

Under Regulation 10-A (1) (e)

Shri Abdul Habib Pathan, Lakheri Cement Kamgar Sangh, LAKHERI.

Under Regulation 10-A (1) (f)

The Manager, Mini. Local Office, LAKHERI.

> U. P. SAXENA Regional Director

(REGIONAL OFFICE MAHARASHTRA)

Bombay-13, the 1st January 1976

No. B/Est-II-18(24).—It is herey notified that the Local Committee set up vide this office Notification No. B/Est-II-18 (24), dated 12th June, 1973, for Kalyan area under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 has been reconstituted with the following members with effect from the date of Notification.

Chairman

Under Regulation 10-A-1(a)

(1) The Asstt. Commissioner of Labour.

Members

Under Regulation 10-A-1 (b)

(2) The Senior Administrative Officer to the Administrative Medical Officer, E.S.I. Scheme, Bombay-28.

Under Regulation 10-A-1 (c)

 The Medical Officer Incharge, Specialist Centre, E.S.I. Scheme, Kalyan,

Under Regulation 10-A-1 (d)

- (4) Shri S. S. Prasad. (Representative of Kalyan Ambernath Manufacturers' Association) Labour and Welfare Officer, National Rayon Corporation, Shahad.
- (5) Shri Ashok Dharmadhikari, (Representative of Kalyan Ambernath Manufacturers' Association) Senior Personnel Officer, Dharmsi Morarji Chemical, Ambernath,

Under Regulation 10-A-1 (e)

- (6) Shri Namdeo B. Patil, (Representative of Rayon Workers' Union) Treasurer, Rayon Workers' Union Shahad, Kalyan, District-Thana.
- (7) Shri V. G. Nimbkar, (Representative of Rashtriya Chemical Kamgar Sangh) General Secretary, Rashtriya Chemical Kamgar Sangh, Near Railway Station, Ambernath.

Under Regulation 10-A-1 (f)

 The Manager, Local Office, Kalyan, E.S.I. Corporation, Kalyan.

No. B/Estt-II-18/42.—It is hereby notified that the Local Committee set up vide this office Notification No. B/Estt-II-18 (42) dated 28-9-71 for Amalner area under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations,

1950 has been reconstituted with the following members with effect from the date of notification.

Chairman

Under Regulation 10-A-1 (a)

1. Asstt. Commissioner of Labour, Jalgaon.

Members

Under Regulation 10-A-1(b)

 The Senior Administrative Officer to the Administrative Medical Officer, E. S. I. Scheme, Nagpur.

Under Regulation 10-A-1(c)

3. The Insurance Medical Officer Incharge E. S. I. Dispensary, Amalner.

Under Regulation 10-A-1 (d)

- Shri P. W. Joshi, Labour & Welfare Officer, M/s. The Pratap Spg. Wvg. & Mfg. Co. Ltd., 'Pratap Nagar', Amalner.
- Shri Mohanlal Murlidas Shah.
 Labour Officer,
 M/s. Western India Vegetable Products Ltd..
 Post Box No. 12,
 Amalner (Dist-Jalgaon).

Under Regulation 10-A-1 (c)

- Sbri Dajiba Parvat Patil (M.L.A.) General Secretary, Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, Amalner.
- Shri Lala Budha Patil, Kunte Road Near Municipal School No. I, Amalner, Dost.—Jalgaon.

Under Regulation 10-A-1 (f)

Member-Secretary

The Manager,
 Local Office Amalner,
 E. S. I. Corporation,
 Pratap Charitable Hospital,
 Amalner.

BY ORDER

K. V. KEDARE Joint Regional Director

[REGIONAL OFFICE (TAMIL NADU)]

Madras-34, the 19th January 1976

No. TNR/CO-3(38)/71-I.—It is notified that the Local Committee for Usilampatti area constituted in 18th February 1972 vide this office notification No. TNR CO-3(38)/71-I is hereby reconstituted under Reg. 10A E.S.I. (General) Regulations, 1950 with effect from the date of this notification.

Chairman

Under Reg. 10A(1)(a)

 The District Medical Officer, Tiruchirapalli,

Members

Under Reg. 10A(1)(b)

2. The Labour Officer, Tiruchirapalli.

Under Reg. 10A(1)(c)

3. The Medical Officer-in-charge, E.S.I. Dispensary, Usilampatti.

Under Reg. 10-A (1)(d) (Employers' side)

- 4. Thiru C.T. Valliappan, Spinning Master, Thiakesar Alai (P.O.), Manapparai.
- Thiru A. S. Ganapathy, Time Keeper, Thiakesar Alai, Manapparai.
- Thiru R. Rajaraman, B.Sc., Balani Andavar Rice & Oil Mills, Manapparai.
- Thiru S. S. R. Velusamy, Sri Vel Murugan Mills, Manapparai.

Under Reg. 10A(1)(e) (Employees' side)

- Thiru K. Eswaramoorthy, The Sree Meenakshi Mills Staff Union, Manapparai.
- Manappara.

 9. Thiru A. Rajagopal,

 Vice-President,

 Thiakesar Alai,
 Staff and Jobbers National Union,
 Manapparai.
- Thiru K. Muthuviravan. Thiakesar Alai Workers Progressive Union, Manapparai.
- 11. Thiru R. Kanniyan,
 Tiruchy District Textiles Workers Union,
 (Branch) Thiakesar Alai,
 Manapparal.

Under Rev. 10A(1)(f)

Member-Secretary,

 The Manager, Local Office, ESt Corporation, Tiruchirapalli,

BY ORDER

S. ARUNACHALAM, Regional Director & Ex-Officio Member-Secretary, Regional Board, E.S.I.C., Tamil Nadu.

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION Bombay, the 30th September 1975

No. G.S.R.—In pursuance of Section 32(2) of the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 (10 of 1963), the re-

port of the Board on the working of the Corporation for the year ended 30 June 1975 and balance sheet and profit and loss account of the Corporation for the year ended 30 June 1975 are published hereunder.

ARC AT A GLANCE

Rs lakhs

												Rs. lakhs
	· · ·	Y	car ended	30 June	;		T.T	. \ 		Year et	nded 30 Ju	ne
Sources		1973	1974	19	7 <u>5</u>		Uses		19	973	1974	1975
Paid-up share capital and resc	erves	1082	1650	22	272 R	ofinance pr (outstandi) ;				
Borrowings from: GOI		12485	16350	196	St 62	ate Land D	evelopme	ent Banks	19	560	27151	34382*
(Of which IDA/IBRD assistan RBI	ice)	(4521)	(8386)	(1169	(11698) (of which under IDA projects) Scheduled Commercial Banks			77) 1 111	(11984) 2708	(16756) 5150		
LTO Fund		3450	5400	88	20							
Short Term		370	1160	4	50 (o	(of which under IDA/IBRD Projects)			(1	(05)	(433)	(1388)
Open Market		3871	6621	99	21 St	ate Co-ope	rative Ba	nks		944	1115	1154
				ROWTH	I SIN	CE INCE	PTION					
											I	Rs. lakhs
Position as at the end of June	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	197.	3 1974	1975
Paid-up share capital and	500	500	500	500	500		509	523	1044	108	2 1650	2272
Special deposit	. –	11	24	36	49		74	87	. 1044	11		179
Subvention loans	3	5	11	12	14		14	14	14			_
Borrowigs:												
(1) From GOI	500	500	500	500	800	2575	4475	6675	7713	1248:	5 16350	19662
(2) From RBI			_		_		_	752	839	3820	6560	9270
(i) Short term	_		→	_			_	752	339	37	0 1160	450
(ii) Long term			.—			·	` 	_	500	3450	5400	8820
(3) Bonds and Debentures		_	_		-		1094	1946	2771	387		9921
Refinance granted (net)	_	45	490	697	1263		5889	8893	12341	2161		40686
(i) Debentures (ii) Loans		45 	475 15	667 30	1190 73		5460 429	8124 769	10964 1377	1956 205		34382* 6304
Other assets	205	5	12	22	51		159	258	360	63		
Investment and cash reserves	820	992	552	358	85		250	1003	2		$\tilde{4}$ $\tilde{8}$	26
Gross income	37	40	43	50	60		273	427	606	92		2214
Profits before tax	35	36	39	44	43		67	69	109	17		442
Tax payable	18	18	23	24	24		37	34	58	8		231 211
Profits after tax Dividend paid	17 21	18 21	16 21	20 21	19 21		30 21	35 21	51 31	8 4		211 89
Isitiatina pata		41				. 4-1	2-1					

^{*} Includes disbursement of Rs 68 401akhs for which debentures were floated after 30 June 1975.

Table 1
DISBURSEMENT OF REFINANCE—PURPOSEWISE

Rs. lakhs

									IVS. Jakiis
	Upto –				During				Total
Purposo	30 June 1968	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	(upto 30 Јиле 1975)
Minor irrigation	129	1154	2233	2306	2674	8418	8530	8378	33822
Land development/ Reclamation/ Soil conservation Farm mechanization	(10·2) 1012 (80·0) 3	(64 · 7) 376 (21 · 1) 11	(78 · 1) 332 (11 · 6) 16	(75·3) 437 (14·3) 11	(76 · 4) 237 (6 · 8) 36	(89 · 4) 230 (2 · 4) 218	(87 · 1) 178 (1 · 8) 375	(78 · 7) 201 (1 · 9) 1223	(79 ·9) 3003 (7 ·1) 1893
Plantation/Horticulture	(0·3) 101 (7·9)	(0 ·6) 106 (5 ·9)	(0.6) 150 (5.2)	(0 ·4) 199 (6 ·5)	(1·0) 205 (5·9)	(2·3) 149 (1·6)	(3.9) 219 (2.3)	(11 ·5) 200 (1 ·9)	(4·5) 1329 (3·1)
Poultry/Sheep breeding	_	$(0\cdot 1)$	6	_	`. 	(0 · 2)	(0·1)	(0·6)	96 (0·2)
Fisheries	(<u>-)</u> 20	` 36	(0·2) 36	()	· ()	12	86	` 178	464
Dairy development	(1 ·6) — · (—).	(2 0)	$(1\cdot3)$	(1·2) — (—)	(1 ·7) 39 (1 ·1)	(0.1) 26 (0.3)	(0·9) 82 (0·8)	(1·7) 158 (1·5)	(1·1) 305 (0·7)
Storage/Market yards) 	100	(<u>—</u>). 87	72	248	` 346	293	237	1383
Agricultural aviation	()	(5·6) — (—)	(3·0) — (—)	(2·3)	(7·1) — (—)	(3·7) — (—)	(3·0) 12 (0·1)	(2·2) (—)	(3·3) 12 (0·1)
, Total	1265 (100·0)	1784 (100 ·0)	2860 (100·0)	3062 (100·0)	3498 (100-0)	9 <mark>414</mark> (100·0)	9784 (100 ·0)	10640 (100·0)	42307 (100·0)

Figures in parentheses are percentages of the total.

Table 2
DISBURSEMENT OF REFINANCE—AGENCYWISE

Rs. lakhs

	I lata	During								
Agency	Upto 30 June 1968	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	Total (uto 30 June 1975)	
State Land Development Banks	1190 (94·1)	1595 (89·4)	2675 (93 · 5)	2665 (87·0)	2839 (81 ·2)	8614 (91 ·5)	7776 (79 · 5)	7706 (72 · 4)	35060 (82·9)	
of which IDA assistance Scheduled Commercial Banks	55 (4·3)	53 (3·0)	56 (2·0)	278 (9·1)	537 326 (9·3)	6358 449 (4·8)	5292 1736 (17 · 7)	5198 2787 (26·2)	17385 5740 (13 ·6)	
of which IBRD assistance IDA assistance				111	8	4	1 342	10 979	134 1321	
State Co-operative Banks	20 (1 ·6)	136 (7·6)	129 (4·5)	119 (3·9)	333 (9·5)	351 (3 · 7)	272 (2·8)	147 (1·4)	1507 (3·5)	
Total	1265 (100·0)	1784 (100·0)	2860 (100 ·0)	3062 (100·0)	3498 (100·0)	9414 (100·0)	9784 (100 ·0)	10640 (100 ·0)	42307 (100·0)	

Figures in parentheses are percentages of the total.

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION TWELFTH ANNUAL REPORT 1974-1975

During the year July 1974 to June 1975, the Corporation's disbursement of refinance assistance exceeded Rs. 100 crores for the first time to reach Rs. 106 crores (Table 1). Disbursement during the previous year aggregated Rs. 98 crores inclusive of Rs. 6 crores transferred from the loans under 'normal' programmes of land development banks to IDA projects. Exclusive of this transfer, disbursement increased over the year by 15 per cent. In the context of the prevailing scarcity conditions, shortage of power and overdues in many parts of the country, the disbursement can be considered satisfactory though it has not come up to the levels projected earlier.

1.2. Gross disbursement since inception now exceeds Rs. 423 crores. Disbursement by the Corporation in respect

of IDA-assisted schemes has exceeded Rs. 187 crores resulting in foreign exchange inflow of nearly \$ 145 million. There has been a definite increase in the operations of the Corporation in the less developed areas. The activities of the Corporation have been extended to almost every district in the country. The Corporation has been able to do more development work in the less responsive areas. Apart from negotiation of four specific credit agreements with IBRD/IDA during the year, the Corporation has obtained a general line of credit from IDA which has established a still closer relationship between ARC and IDA.

1.3. During the last three years, there has been a marked reshuffle of the positions of individual States which account for nearly 90 per cent of the Corporation's aggregate disbursement,

Table 3

RANKING OF STATES ACCORDING TO THE AMOUNT OF REFINANCE DRAWN FROM THE CORPORATION

State	1972-73	1973-74	1974-75	cumulative *
Uttar Pradesh	1	1	1	1
Maharashtra	5	2	2	2
Famil Nadu	2	3	8	3
Haryana	4	5	4	4
Karnataka	7	4	5	
Madhya Pradesh	9	7	3	6
J ujarat	3	6	ı 9	7
andhra Pradesh	8	10	7	Ŕ
lihar	10	8	6	9
unjab	6	9	10	10

^{*} For the three-year period 1972-75. Excludes amount transferred from 'normal, programmes.

Table 4

DISBURSEMENT OF REFINANCE--STATEWISE

Rs. lakhs During Upto 30 June 1968-69 Region/State/Union Territory Total 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 (upto 30) 1968 June (1975)I. NORTHERN REGION Delhi (0.1)(0.1)(0.2)(0.1)1020 1075 263 362 326 803 Haryana 4152 (9.2)(10 1) (13.7)(11.8)(9.3)(8.2)(10.8)

		ieni in ces		-(Contd.)		rruner			Rs, Lakhs
	יע	ISBURSEN	MENI OF	KEFINAL	NCE—STAT				KS, Dakits
Region/State/Union Territory	Upto - 30 June 1968	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	— Total (up to 30 June 1975)
Himacha) Pradesh							(0·1)	(0·1)	(0 · 1)
Jammu & Kashmir	11	21 (1·2)	20 (0·7)	11 (0·4)	(0.2)		(0 1)	(0-1)	(0·1) (0·1)
Punjab	(0·9) 76	577	654	556	386	607	489	407	3751
Rajasthan	(6·0)	(32·3) 6	(22 ·9) 77	(18 ·2) 77	(11 ·0) 83	(6·5) 136	(5·0) 283	(3 ·8) 350	(8·8) 1012
-		(0 ·3)	(2 · 7)	(2 · 5)	(2 · 4)	(1 ·4)	(2.9)	(3 · 3)	(2 · 4)
	146 (11 ·6)	848 (47 ·5)	1020 (35 · 7)	1006 (32 ·9)	802 (22 ·9)	1763 (18 ·7)	1586 (16·3)	1848 (17·4)	9019 (21 ·3)
II. NORTH EASTERN REGION Assam	26	44	4	_	32		29		134
Meghalaya	(2 ·0)	(2 ·5) →	(0 ·1)	_	(0.9)	_	(0·3) —	_	(0 ·3)
Nagaland -		-		<u>-</u>		 	(0·1)	(0·1)	(0·1)
	26 (2·0)	44 (2·5)	(0·1)	_	32 (0·9)	_	33 (0·4)	(0·1)	142 (0·4)
III. EASTERN REGION				¬					
Bihar	-	8 (1·0)	61 (2·1)	113 (3·7)	67 (1·9)	154 (1·6)	585 (5·9)	932 (8·8)	1931 (4·6)
Orissa	_	(0·2)	18 (0·6)	6 (0·2)	8 (0·2)	(0·1)	8 (0·1)	82 (0·8)	(137 (0·3)
West Bengal		(0·1)	(0·1)	10 (0·3)	5 (0·2)	(0·1)	(0 · 2)	69 (0·6)	112 (0·3)
-		24 (1·3)	80 (2.8)	129	80 (2.3)	169 (1·8)	615 (6·2)	1083 (10 · 2)	2180 (5·2)
IV. CENTRAL REGION		(1.3)	(2-6)	(4 · 2)	(2-3)		(0.2)	(10-2)	(3.2)
Madhya Pradosh	-	(1·8)	49 (1·7)	91 (2·9)	187 (5·3)	319 (3 · 4)	645 (6·6)	123 4 (11 ·6)	2557 (6·0)
Uttar Pradesh	_	122 (6 ·8)	256 (9·0)	293 (9·6)	604 (17·3)	1143 (12·1)	1498 (15·3)	1849 (17·3)	5765 (13 · 6)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	153 (8·6)	305 (10·7)	384 (12 · 5)	791 (2 1 · 6)	1462 (15·5)	2143 (21·9)	3083 (28 ·9)	8322 (19 · 6)
V. WESTERN REGION							, .		
Goa		_	_	_	-		(0·1)	5 (0·1)	-
Gujarat	14 (1·1)	193 (10·8)	131 (4·6)	190 (6·2)	262 (7·5)	2794 (29 · 7)	788 (8·0)	427 (4·0)	4800 (11·3)
Maharashtra	108 (8·5)	81 (4·6)	349 (12·2)	233 (7·6)	456 (13·0)	732 (7·8)	1271 (13·0)	1358 (12·7)	4589 (10 ·8)
-				·····		·			
	(9 6)	274 (15 ·4)	480 (16·8)	423 (13 ·8)	718 (20 · 5)	3526 (37 · 5)	2062 (21 ·1)	1790 (16·8)	
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradosh	637 (50 · 4)	172 (9 ·6)	607 (21 ·2)	342 (11 ·2)	28 5 (8 · 2)	847 (9·0)	423 (4·3)	892 (8 · 4)	4205 (9·9)
Karnataka	125 (9·9)	136 (7-6)	166 (5·8)	274 (8-9)	325 (9·3)	405 (4·3)	1099 (11 ·2)	1008 (9·5)	3539 (8 -4)
Kerala	10 (0·8)	7 (0 -4)	35 (1·2)	82 (2·7)	97 (2·8)	28 (0·3)	103 (1·0)	100 (0·9)	461 (1·1)
Pondicherry	_	-	— (1 ·2)	(2 /)	(a 0)		8 (0·1)	15 (0·1)	23 (0·1)
Tamil Nadu	199 (15·7)	126 (7·1)	(5·7)	422 (13 ·8)	368 (10·5)	1213 (12·9)	1712 (17·5)	817 (7·7)	5019
	971 (76·8)	441 (24·7)	970 (33 ·9)	1120 (36·6)	1075 (30 ·8)	2493 (26·5)	3345 (34·1)	2832 (26·6)	13247 (31 · 3)
Total (1 to VI)	1265 (100·0)	1784 (100·0)	2860 (100·0)	3062 (100·0)	3498 (100 ·0)	9414 (100 ·0)	9784 (100 ·0)	10640 (100·0)	42307 (100 ·0)

Figures in parentheses are percentages of the total.

During 1974-75, Uttar Pradesh maintained the lead for the largest share of disbursement (Rs. 18 crores) followed by Maharashtra (Rs. 14 crores) and Madhya Pradesh (Rs. 12 crores). Bihar (Rs. 9 crores) which had consistently lagged behind took the sixth position (Table 4). Since inception, the largest beneficiaries of the Corporation's assistance which received more than 10 per cent each of the total disbursement are Uttar Pradesh (Rs. 58 crores), Tamil Nadu (Rs. 50 crores), Gujarat (Rs. 48 crores) and Maharashtra (Rs. 46 crores) while four other states have received between 8 and 10 per cent each, viz., Haryana and Andhra Pradesh (Rs. 42 crores each), Punjab (Rs. 38 crores) and Karnataka (Rs. 35 crores). Disbursement exceeded the previous year's performance in Northern, Eastern and Central regions but declined in the North-Eastern, Western and Southern regions.

1.4. Minor irrigation remains the principal purpose of assistance but its relative importance in individual states has shifted slightly (Table 1). With the emphasis on increased agricultural production, quickening of lending for this purpose will be necessary alongside a programme of careful scientific study of the availability of water resources. Intensification of work of the department in charge of groundwater investigation in individual states will reveal the potential for scientific exploitation of the existing groundwater resources. Schemes for land development and soil conservation have still not picked up. Three IDA-assisted projects for on-farm development in command area projects have been finalised. There has been an intensification of studies in other command areas for similar on-farm development and some

- of these are expected to fructify in the near future. There has been greater response for schemes for farm mechanisation poultry and sheep breeding, fisheries and dairy development. Under farm mechanisation, while Rs. 5 crores of ARC disbursement was on IDA account in Punjab and Haryana, demand picked up in other states such as Gujarat, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh; apart from the demand from individual farmers for tractors, the setting up of agroservice centres was a new feature. Substantial disbursement for farm machinery is expected since imported tractors have started arriving in respect of Punjab and Haryana projects. IDA has now agreed to include finance for indigenous tractors when international competitive bidding is followed. Though sizeable commitments have been made under plantation and horticulture, disbursement has not picked up yet owing to the emphasis on production of improved seedlings and other essential preparatory work.
- 1.5. Disbursement as a percentage of commitments upto the end of last year and this year is indicated below (Table 5) Agrregate drawals under all the schemes during the years formed nearly 57 per cent of the Corporation's commitment of Rs. 188 crores as against 52 per cent during the previous year (Statement 1).
- 1.6. Fifty-seven member-banks now participate in the refinance programme of the Corporation comprising 16 land development banks, 30 commercial banks and 11 state cooperative banks. Land development banks (LDBs) continue as the main agency for disbursement of refinance (Table 2). The amount disbursed through them during the year was

Table 5
DISBURSEMENT AS PERCENTAGE OF COMMITMENTS

Rs. Crores

	Purpose	ARC commitment upto 1973-74	Amount drawn upto 30 June 1974	Per cent of 4 to 3	ARC commitment upto 1974-75	Amount drawn upto 30 June 1975	Per cent of 7 to 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Minor irrigation	335 · 3	254 - 5	75 - 9	465 · 8	338 -3	72.6
2.	Land development and soil conservation	41 -0	28 .0	68 · 3	46 - 9	30 ⋅0	64 ⋅0
3.	Farm mehanisation	10 ⋅ 2	6 7	65 · 7	32 · 7	18 · 9	57 ·8
4.	Plantation and horticulture	20 ·8	11 -3	54 - 3	25 -0	13 · 3	53 • 2
5.	Poultry and sheep breeding	1 •4	0 · 3	21 ·4	2 · 1	1 -0	47 · 6
6.	Fisherics	4 • 4	2 - 9	65 - 9	8 • 3	4 · 6	55 ⋅4
7.	Dairy development	4 · 8	1 - 5	31 · 3	9 - 7	3 · 1	32 .0
8.	Storage facilities and market yards	17 • 6	11 -5	65 · 3	18 · 3	13 ·8	75 • 4
	Total	435 ⋅ 5	316 · 7	72 · 7	608 ·8	423 -0	69 · 5

only marginally lower than the previous year at Rs. 77 crores but the percentage to the total disbursement was much lower at 72 per cent as against 79 per cent last year. Since inception, the aggregate disbursement to these institutions stands at Rs. 351 crores or 83 per cent. Commercial banks, on the other hand, have significantly improved their position; their availment of Rs. 28 crores during the year was almost equal to their aggregate drawal in all the previous years. Refinance availed of by the state co-operative banks recorded a decline and amounted to Rs. 1.5 crores or nearly half of what they did in the previous year.

1.7. Though the expected achievement for the year was originally placed at Rs. 150 crores, this programme was revised, as a result of a mid-year review, to Rs. 120 crores. The disbursement of Rs. 106 crores fell short of even the revised expectation. The IDA-assisted tractor programme involving a lending of nearly Rs. 48 crores in Punjab, Haryana and Karnataka was expected to be completed during the year but had to be carried over due to delays in completion of formalities. States like Gujarat and Tamil Nadu which did sizeable lendings during the earlier years could accomplish only a limited programme mainly due to scarcity conditions, shortage of power, heavy overdues in lending institutions, etc.

Assistance to Gujarat LDB declined from Rs. 27.9 crores in 1972-73 to Rs. 6.7 crores in 1973-74 and Rs. 3.1 crores in 1974-75. For Tamil Nadu LDB the decline was from Rs. 16.6 crores in 1973-74 to Rs. 7.1 crores in 1974-75. Shortage of power almost throughout the country handicapped the progress of energisation of wells. The progression of discipline both on the technical and financial sides also resulted in a slowing down of the programme.

1.8. The trends in the business of the Corporation indicate that the multi-agency approach has come to stay. Commercial banks which were late entrants in the field of agricultural credit have picked up business rapidly. Co-operative banks have many inherent advantages but they have been slow to re-orient themselves to meet the needs of development and changes in technology. This is largely a matter of organization and state support, mainly in terms of 'extension' support and partly by way of resources. Though the names of the erstwhile 'land mortgage banks' have in most states been changed to 'land development banks', one does not notice any basic change in their approach or method of operations. There is an urgent need to revamp the structure and functioning of management of LDBs so that qualified professional management is available at various levels in the

organization. The absence of any linkage or integration between the short-term and long-term wings of the co-operative credit system places them at a disadvantage compared to the commercial banks. Progress has been stalled in those states where the state governments are not willing to give equal opportunities to the commercial banks as is happening in Gujarat and Tamil Nadu. Though the Talwar Committee recommendations have been before the states for a number of years, positive action has not been initiated in many of them. Where the states have come forward with a more

Tubewells
Dugwells
Electric pumpsets/oil engines
Lift irrigation
Others (boring and rahats)

	Hectares
Coffee 1	6,400
Toa	1,5501
Rubber]	1,200
Cardamom	1,250]
Cashewnut	1,100
Tobacco	480

During the 12 years of its activities, the Corporation has assisted in bringing about 8.22 lakh hectares under multiple cropping. While lands developed under the command area of major irrigation projects stood at 3.5 lakh hectares, the area improved under soil conservation schemes has marginally

Storage

Market yards
Tractors
Combines/harvestors/bulldozers/power tillets
Trawlers/mechanised boats
Milch cattle
Poultry birds
Sheep
Agricultural aircraft

SANCTIONS

There was a significant increase in the number of schemes sanctioned during the year. As many as 623 schemes were sanctioned involving financial assistance of Rs. 236 crores, of which the Corporation's commitment was Rs. 204 crores, against 550 schemes with financial assistance of R3. 251 crores and ARC commitment of Rs. 220 crores during the previous year (Statement 2). Minor irrigation continues to occupy a leading position, accounting for 303 schemes (49 per cent), the Corporation's commitment being Rs. 148 crores or 72 per cent of its total commitment. There has, however, been an appreciable increase in schemes sanctioned for other purposes, numbering 320 and involving ARC refinance of Rs. 56 crores. Of these, schemes for farm mechanisation and fisheries are sizeable accounting for commitment of Rs. 33 crores and Rs. 6 crores respectively, as against Rs. 9 crores and Rs. 1 crore during the previous year.

- 2.2. Commitment of funds during the year was heavy in the states of Haryana, Bihar, Orissa, Uttar Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. The decrease in the Corporation's commitments in Madhya Pradesh and Maharashtra during the year as compared to 1973-74 is due to the fact that the Corporation had already approved sizeable programmes under the IDA projects which are being implemented vigorously (Statement 3).
- 2.3. Land development banks accounted for 116 schemes sanctioned during the year as against 139 during the previous year (Statement 4). ARC's commitments in regard to these schemes were also smaller at Rs. 115 crores as against Rs. 133 crores during the previous year. This was principally due to the insistence of the Corporation on preparation of schemes for compact areas which would ensure better technical standards and supervision. Schemes sanctioned in favour of commercial banks increased from 407 during 1973-74 to 501 during this year. The amount committed also went up marginally from Rs. 85 crores to Rs. 87 crores. The number of schemes sanctioned in favour of the state co-operative banks was small at 6 with the Corporation's commitment of Rs 2.3 crores which was slightly less than the commitment 11—469GI/75

open mind, progress is encouraging as in the case of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

1.9. The aggregate disbursement by the Corporation since its inception amounting to Rs. 423 crores would represent investment at ground level of approximately Rs. 530 crores, inclusive of contributions by member-banks, state governments and ultimate beneficiaries. The achievement in physical terms under various schemes on the basis of the latest data available is indicated below:

	 1,18,000 2,33,000	units units
	 3,33,000 425	units units
	 8,900	units
Coconut Arecanut Apple	# Hectares 17,800 1,000 6,500	
Citrus and other fruits	4,000	

risen to 2.30 lakh hectares. The total area developed under various schemes for plantation and horticulture is of the order of 41,300 hectares.

Other activities which have received reliuance facilities from the Corporation are as under:

9.60 lakh t	onne
capacit	у
6	units
7,615	units
300	units
808	units
20,700	animals
2,30,000	chicks
16,800	animals
2	units

during the previous year. (State co-operative banks advance medium-term loans for agricultural investments largely out of borrowings from the Reserve Bank of India).

Of the 2053 schemes sanctioned upto 30 June 1975, 826 schemes were in favour of the land development banks, 1176 schemes were to be implemented through the commercial banks and 51 were sanctioned to the state co-operative banks (Statement 7). Of the total commitments of Rs. 877.4 crores against the sanctioned schemes, commitments in favour of LDBs, commercial banks and state co-operative banks were Rs. 628,4 crores, Rs. 223,2 crores and Rs. 25.8 crores respectively.

Schemes under consideration

2.4. As at the end of June 1975, 520 schemes were under consideration. 136 schemes were complete in most respects while the remaining 384 schemes were held up for want of additional data. Of the pending schemes, 262 schemes pertained to the states in the less developed/underbanked areas. Details are given in Statement 12. In addition, 379 proposals which were incomplete in many respects were at various stages of scrutiny or correspondence.

Regional Imbalances-

Response from state governments

2.5. The correction of regional imbalances in investment between different states is indeed a difficult process. The state governments have a definite role to play in the implementation of the investment programme in providing various infrastructural facilities and fixing suitable rates for services to be rendered. Where the state governments would like the investment programme to be implemented through LDBs or specially constituted corporations, certain equity participation and other types of financial assistance will be needed. Some of the states have been slow in making these commitments and consequently the commencement of schemes has been delayed. Certain states which in the past availed of substan-

tial assistance from the Corporation, seem to have slipped back and consequently states which were less developed have come to the forefront. If these states are able to sustain their position, the prospects during the next year will be better.

- 2.6. In the last report, three characteristic groups of states were indicated. Reviewing the position on the basis of performance during 1974-75, the breakthrough achieved in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar is being sustained. To maintain this progress on the basis of financial discipline and administrative efficiency, efforts have to be made to reduce the imbalances even in the regious within the same states. With realistic support from the state governments, this should be possible of achievement. Rajasthan has now four IDA-assisted projects, the largest number of specific projects for an individual state. These are in fields other than minor irrigation. With active support for minor irrigation available from the Corporation, the stage is now set for all-round development in the state. With the recent reorganisation in the state government departments, further programmes should be possible. As regards West Bengal, an IDA-assisted agricultural development programme has been sanctioned for six districts and its implementation will commence shortly as soon as the necessary formalities are completed. In Orissa, as a continuation of the efforts of the previous year, schemes with ARC assistance have been sanctioned amounting to Rs. 16.8 crores to be financed by the SLDB and commercial banks. With the commencement of the implementation of these schemes during the year, the progress in Orissa should be substantial.
- 2.7. The Corporation is not satisfied with the progress in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Assam, Maghalaya. Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura despite persistent efforts (Statement 6). In Jammu and Kashmir, the Corporation has decided to associate itself with IDA and the state government in preparing a scheme for horticulture development. On the basis of a study of the potential for piggery development in some of the states in the North-Eastern region specific schemes were prepared and presented to the state governments and interested banks for their acceptance. pre-investment study by a Team was conducted on the potential for plantations, horticulture and forestry development in the North-Eastern region. The Chairman of the Corporation toured the area extensively on two occasions to have discussions with state government officials and other concerned An officer from the Consultancy Unit in Calcutta has made frequent visits to Assam to assist state authorities to identify programmes. Seminars were organised in Assam, Manipur and Tripura to explain the project approach to agricultural investment. In July 1974, a regional conference was convened at Calcutta to explain the procedure for identifying programmes for development of minor irrigation. These developments have been dealt with in detail, later in this report.
- 2.8. An analysis of the schemes sanctioned by the Corporation indicates that, except for 36 districts, every district in the country has one type or other of ARC scheme sanctioned for implementation. The states where such districts existed at the end of June 1975 are:

Himachal Pradesh	7
Jammu and Kashmir	5
Rajasthan	5
Assam	3
Bihar	3
Meghalaya	2
Nagaland	2
Uttar Pradesh	2
Gujarat	2
Pondicherry	2
Orissa	1
West Bengal	1
Madhya Pradesh	1

2.9. During the year, the Corporation sanctioned 19 schemes sponsored by the SFD/MFAL agencies including schemes in the Eastern and North-Eastern regions. At the end of June 1975, the total number of schemes sanctioned under the aegis of CFD/MFAL agencies stood at 104 (Statement 8) 58 schemes are to be implemented through LDBs,

- 41 schemes through commercial banks and 5 through state co-operative banks. Of these, 62 are for minor irrigation investment and the remaining 42 schemes are for dairy development (22), poultry (9), sheep breeding (3), land development (2) and plantation and horticulture (6).
- 2.10. Drawals under these schemes during the year amounted to Rs. 4.7 crores; the commercial banks availed of a sum of Rs. 54 lakhs while the drawals by the LDBs aggregated Rs. 4.2 crores.

IMPORTANT DECISIONS DURING THE YEAR

The Corporation reviewed its refinance rate with reference to the general rise in the interest rate structure consequent upon the increase in the Bank Rate in July 1974. The Reserve Bank put up the rate on loans from the LTO Fund to 6 per cent and there was also a slight revision in the rates on market borrowings. The Reserve Bank also revised the minimum rate to be charged by land development banks on the loans issued by them from 10 per cent to $10\frac{1}{2}$ per cent. Taking into account the factors prevailing at the time, it was decided that in respect of all schemes sanctioned on or after 13 August, 1974, the Corporation's refinance rate to the eligible institutions would be 7½ per cent per annum for minor irrigation and land development schemes and 8 per cent per annum for other types of schemes. The lending rate to charged to the ultimate borrowers by the financing institu-tions was to be 10½ per cent per annum for minor irrigation and land development schemes and 11 per cent per annum for other schemes. In the case of small farmers, especially in regard to schemes for poultry, dairy and animal husbandry, the banks are allowed to charge 10½ per cent per annum, if so desired. It was also decided that in states where the land development banks desired to have a larger spread between their borrowing and lending rates, they might charge a higher rate and in such an event, the commercial banks operating in the state would also be free to charge the same higher rate on the loans issued by them. It was also clarified that there should be only one rate to the ultimate borrower for the entire period of the loan once the scheme was approved by the Corporation irrespective of the point of time at which the refinance was availed of.

- The Corporation had agreed to make available refinance to member-banks in areas where minor irrigation proiects are undertaken, for giving loans to the farmers for keeping deposits with the electricity boards towards energising pumpsets in areas other than those covered by the schemes of the Rural Electrification Corporation. The deposits of the Rural Electrification Corporation. covered the cost of laying the low tension transmission line and certain miscellaneous items. The quantum of deposit was subject to a ceiling of Rs. 3.000 per well. In view of the overall increase in the cost of various materials, the Corporation enhanced the amount to Rs. 4,500 in respect of electric connections given after 1 August, 1974. The banks will reimburse directly the state electricity boards in respect of future connections given at this rate on receipt of a certificate from the concerned state electricity boards listing the names of beneficiaries whose pumpsets have been energised. The period of these deposits would be 7 years as in the case of loans for pumpsets. The rate of interest payable by the state electricity boards on the deposits kept with them will be the same as payable by the farmer to the banks.
- 3.3. In order to expedite the clearance of proposals for refinance received from the subsidiaries of the State Bank of India, the scrutiny of drawal applications received from these banks is now entrusted to the concerned regional officers of the Corporation in whose jurisdiction the head offices of the subsidiaries are located. In so far as schemes implemented in areas outside the jurisdiction of the regional offices, the drawal applications from the banks will continue to be attended by the head office of the Corporation. The feasibility of making similar arrangements in respect of refinance proposals from other banks is being considered when requests are received.
- 3.4. The Corporation has been hitherto charging an additional interest at the rate of 4½ per cent per annum on the deferred interest in cases where this facility was extended. This rate was enhanced to 6 per cent per annum for schemes sanctioned on or after 18 November. 1974 where such facility for deferment of interest was given by the Corporation. On a review by the Board of the Corporation this rate has since been raised further (to be on level with the current rates of

interest on loans) to $7\frac{1}{2}$ per cent per annum for minor irriganon and land development schemes and 8 per cent per annum for other types of schemes in respect of all schemes sanctioned on or after 9 June, 1975.

- 3.5. In cases where the member-commercial banks were minary submitting proposals instead of applications in the proforma for remance prescribed by the Corporation, it was the practice of the Corporation to convey interim sanctions and on receipt of regular loan applications, to issue the linar sanctions conveying the terms and conditions. The Corporation has since decided to discontinue the issuance of interim sanctions. A revised form of loan application to be submitted by the member-commercial banks along with the schemes has been prescribed by the Corporation.
- 3.6. The Corporation has also constituted an internal committee with a view to rationalising the returns to be submitted by the member-banks. This is mainly with a view to avoiding duplication of information being called for periodically by different divisions and regional offices and to reduce the submission of data to the minimum extent necessary.
- 3.7. As a special case, the Corporation has been extending 100 per cent remance for schemes sponsored under the aegis of SFD/MFAL agencies. This facility which was available upto 30 June, 1975 has since been extended upto 31 December, 1975.
- 3.8. Mention was made in the last year's annual report to the amendment to Section 22 (4) of the Agricultural Rennance Corporation Act, 1963, which vests powers with the Board of Directors of the Corporation to waive both government guarantee and other security in respect of refinance provided to engible institutions, for reasons to be recorded in writing. Pursuant to this amendment, the Board of Directors of the Corporation had decided that depending on the merits of each case, no government guarantee or other security need be taken for granting of accommodation by way of remance to the State Bank of India, its subsidiaries and 14 nationalised commercial banks and any other licensed scheduled commercial bank which are shareholders of the Corporation, in respect of schemes in which these banks en-countered difficulty in creating security in favour of the Corporation. Some of the scheduled state co-operative banks nave been representing that the procedure of routing the applications for refinance through the respective state governments and obtaining guarantee from them is cumbersome and time consuming and have therefore, been suggesting that they may also be allowed to approach the Corporation directly and avail themselves of accommodation without providing any security for refinance. After considering this request, to expedite the availability of timely financial accommodation to the ultimate borrowers, the Board of the Corporation has decided to waive 'other security' and or government guarantee in respect of accommodation to be granted to state co-operative banks subject to the conditions that: (i) the scheme in respect of which such accommodation is sought for is technically feasible and economically viable; (ii) the concerned state co-operative bank is a scheduled bank having 'A' class audit classification; (iii) the central co-operative bank and/or primary co-operative credit society or the primary co-operative bank participating in the scheme is in 'A' class audit classifi-cation and has a recovery performance of 80 per cent of demand and; (iv) the security to be obtained by the co-operatives conforms to the terms prescribed by the Reserve Bank of India from time to time.

AMENDMENTS TO THE AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION ACT, 1963

The range and volume of business transcated by the Corporation have expanded considerably during recent years and would gain further momentum during the Fifth Five Year Plan period. In order to realize its aspirations, it was necessary to have a fresh look at the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 so that the existing statutory limitations do not handicap the formulation of suitable operational policies and mobilisation of adequate resources. An internal committee set up by the Corporation examined the existing

provisions of the ARC Act and suggested certain amendments. These were given final shape after discussions with the Reserve Bank and GOI. A Bill seeking to amend some of the provisions of the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 was introduced in Parliament in April 1975.

4.2. In order to emphasise the developmental and promotional role being played by the Corporation in addition to its refinancing role, the Corporation would be re-styled as the 'Agricultural Refinance and Development Corporation.' The other amendments to the ARC Act may be broadly grouped under three heads, viz., (1) amendments of financial importance for facilitating expansion of business by the Corporation and strengthening of its resources position, (ii) amendments of an administrative nautre and (iii) amendments of a routine nature.

Amendments of a financial nature

- 4.3 The term eligible institution' is being enlarged to include such other institutions as may, on the recommendations of the Reserve Bank, be approved by the Central Government in this behalf. The scope of 'eligible institutions' has been enlarged to enable the Corporation to provide direct financial assistance to certain types of institutions. The intention, however, is to limit such direct financing for the present to selected Government development corporations and co-operative societies, after applying the same technical and financial criteria as for similar projects to be implemented by others.
- 4.4. As the present authorized capital is only Rs. 25 crores of which Rs. 20 crores has already been paid up, there is need to take early action to increase the present limit. The expectation is that the authorised share capital of the Corporation may be raised to Rs. 100 crores by the Reserve Bank with the previous approval of the Central Government. The Reserve Bank would be holding not less than 50 per cent of the authorised share capital issued pursuant to the increase of the authorised share capital.
- 4.5. A new clause (Section 20 (1) (e) has been added which would enable the Corporation to receive gifts, grants, donations or benefactions from government or any other source. These items will not be treated as income, profits and gains of the Corporation. This new provision is intended to take care of any situation in which the Corporation may obtain grants, subsidies, etc., either from the Central Government or from the state in cases, for example, in which any state government is prepared to subsidise the rates of interest or outright grants are made available by the Central Government
- 4.6. The Corporation can purchase or subscribe to the bonds and debentures of any eligible institution repayable within a per oil not exceeding twenty-five years from the dates on which they are issued and sell such bonds or debentures. This clause would replace the provision in the principal Act under which the Corporation can only subscribe to new issues of the debentures of any eligible institution.
- 4.7. Section 22(3)(d) of the principal Act permits the Corporation to guarantee deferred payments in connection with the purchase of capital goods from outside India. The restriction on the power of the Corporation to stand such a guarantee for the purchase of capital goods within India is being removed by omitting the words "from outside India."
- 4.8. Mention was made in the last report to the amendment to section 22(4) of the ARC Act. The amended Section vests powers in the Board of Directors of the Corporation to waive both government guarantee and "other security" to be obtained by the ARC for its refinance to cligible institutions on the merits of each case. In order to avoid delays and in the interest of flexibility, a new clause has been added to this section which would facilitate the waiver of security in respect of an eligible institution or any class of eligible institutions or having regard to the nature and scope of the scheme or schemes for which accommodation is granted by the Corporation.

^{*}The Bill has since been passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha in July-August 1975 and has received the assent of the President of India.

- 4.9. The restriction in the principal Act that the Corporation cannot provide working capital funds is proposed to be removed. This would pave the way for the Corporation to provide integrated credit, both long-term and short-term, to eligible institutions in selected cases.
- 4.10. In the interests of operational efficiency, the existing provision that enjoins the Corporation to seek the per-mission, in writing, of the Reserve Bank in respect of any transaction involving Rs. 50 lakhs and above is proposed to be deleted.

Amendments of an administrative nature

4.11. An amendment to Section 17 of the Act would cuable the Corporation to delegate powers to the committees constituted by the Board of Directors of the Corporation. A new clause has been added to Section 22 of the principal Act which would enable the Corporation to undertake researches, surveys and techno-economic studies on its own or through an agency approved by the Corporation in this behalf. Thus, the Corporation may initiate pre-investment nan. Thus, the Corporation may imitate greenvestiment surveys especially in the less developed or under-banked regions of the country so that the large untapped potential for agricultural development can be identified and harnessed for the good of the community.

Amendments of a routine nature

4.12. The amendments in this category are necessitated by the fact that the 'central land mortgage banks' have come to be known as 'central land development banks' and there has been a change in name from 'Banking Companies Act' to 'Banking Regulation Act.' An amendment also provides for the setting up of a regional office in Bombay which is not feasible under the existing provisions. In order to cope with the expanding business of the Corporation, the appointment of more than one auditor may be necessary for auditing the Corporation's acounts expeditiously and this has been suggested.

IDA/IBRD PROJECTS

Five more projects for agricultural development were sanctioned with assistance from IDA during the year, viz., Rajasthan and Madhya Pradesh dairy development projects. West Bengal agricultural development projects, Madhya Pradesh Chambal command area development project and Agricultural Refinance Corporation credit project. The Corporation was also associated with the negotiation of the drought prone areas project to be implemented in six districts in the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan and Maharashtra. The on-farm investments under this programme will be reimburseable either under the ARC credit project or under the on-going IDA credit projects in the concerned states.

At the end of June 1975, the 22 projects assisted by the IBRD/IDA comprised 11 agricultural credit projects, 3 command area development projects, 3 dairy development projects, 2 market yards projects, an apple processing and marketing project, a seed project and a general line of credit to the Corporation. Two of these projects, viz., Tarai seeds project and Chambal command area development project are being assisted by the IBRD while the remaining projects will be financed by IDA. The summary position indicating purpose-wise, the aggregate lending programme, the disbursements made so far and the amounts reinbursed by IDA as at the end of June 1975 is presented in Table 6. The detailed particulars of individual projects are given in Statement 10.

Table 6 IDA/IBRD PROJECTS ACCORDING TO PURPOSE

Rs. Crores Total Amount of IDA/IBRD Refinance Amount of reimbursement provided

	Purpose	programme	assistance for ARC programme	by ARC as on 30 June 1975	from IDA/ IBRD through GOI, as on 30 June 1975
1.	Minor irrigation	417 · 5	240 · 6	175 · 3	108 -9
2.	Land development	16 ⋅ 6	10 .9	3 - 3	3 · 1
3.	Farm mechanization	78 -4	47 · 5	7 -7	3 · 7
4.	Market yards development	23 - 7	16 9	0.8	_
5.	Processing and marketing of perishable horticulture produce	4.5	3 · 7		_
6.	Dairy development	72 ⋅0	45 · 5	· —	_
7.	Command area development	48 - 5	25 · 7		-
8.	Seeds production	9 · 3	6 · 7	1 · 3	1 · 3
9.	Diversified purposes	9:0	4 · 0	_	
	Total	679 · 5	401 · 5	188 -4	117 ·0

\$1 million will be made available by IDA under the ARC Credit Project for training programmes and undertaking studies.

At the end of June 1975, the gross disbursements by the Corporation under the IDA/IBRD projects aggregate Rs. 188 crores. The pace of disbursement has been showing a steadily increasing trend. The Corporation has so far reimbursed itself from the Government to India Rs, 117 crores or 29 per cent of World Bank/IDA commitments. (The Corporation is eligible for reimbursement of a specified percentage of the disbursements either at its level or at the beneficiarles level.)

5.3. The credit allocated for various items of development was fully utilised in respect of the first agricultural ciedit project sanctioned for Gujarat in 1970 by IDA. In view of the potential for agricultural development in that state, the state government has formulated proposals for a further programme. The original credits allocated for minor

irrigation category in the projects being implemented in Andhra Pradesh, Haryana and Tamil Nadu have been fully utilised. In view of the greater demand for this type of investment, realocation of credit from other categories of investments on which adequate progress could not be made, namely, land development to minor irrigation category has been effected after obtaining concurrence of IDA. The re-allocated credits have also been fully drawn in the Tamil Nadu and Andhra Pradesh projects while a small balance remains in the Haryana projects which will be utilised in 1975-76. In the Karnataka and Maharashtra credit projects, a sizeable portion of the minor irrigation programme has already been done and the blance would be completed according to schedule.

5.4. The recently sanctioned Uttar Pradesh. Rihar and Madhya Pradesh projects are in various stages of implementation and the disbursement of funds has been quite encouraging. In Uttar Pradesh, the disbursements by PLDBs/PcBs were of the order of nearty Rs. 15.5 crores at the end of June 1975. At the end of the same period, ARC had released refinance to the extent of Rs. 8 crores to LDB/PcBs under the Bihar project. In Madhya Pradesh the disbursements made by PCBs/LDB amounted to Rs. 13.9 crores by the end of June 1975. There has, however, been a slight set-back in the progress in these projects, mainly due to the difficulty in energising pumpsets owing to shortage of power. The issues are being sorted out and it is hoped that the disbursements will pick up in the coming months.

- 5.5. The agricultural credit projects for Gujarat, Punjab, Haryana, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu include funds for farm mechanization equipment. The original stipulation that the tractor component in the on-going projects should be imported from other member countries of the World Bank has since been modified by IDA to include the procurement of indigenous fractors also. Under the Punjab agricultural credit project which is intended exclusively for procurement of farm mechanization equipment such as tractors, harvesters, self-propelled combines and discs and plough bottoms, the first lot of about 1,000 tractors has been procured. Recently, formalities have been completed for procuring the second lot of about 4,000 tractors and the response has been very good. The Haryana Agro-Industries Corporation has placed order for 2,800 tractors under the Haryana agricultural credit project white under the Andhra Pradesh and Karnataka projects, the formalities for procurement of tractors are nearing completion. In the Tamil Nadu project, preliminary steps have been taken for procurement of tractors. In view of these developments, the procurement of tractors envisaged under the various projects is expected to be completed or nearly completed in the current year. The aggregate of lending to be completed is about Rs. 60 crores.
- 5.6. The Corporation made the first disbursement aggregating Rs. 84 lakhs under the Bihar market yard project. Both in Bihar and Karntaka projects, certain constraints have been experienced such as delay in acquisition of land for the markets, delay in audit of accounts of the market committees and shortfall in the collection of market fees. Steps have been initiated to resolve these issues.
- 5.7. In the dairy projects of Karnataka, Rajasthan and Madhya Pradesh the organisational structure necessary for implementing and co-ordinating the programme including the setting up of the dairy development corporations in these states has come into being. The banking arrangements for financing the dairy unions have also been finalised by the ARC. The training of the executive staff involved in implementing the programmes is expected to be taken up by the respective dairy development corporations shortly. Guidelines are being worked out for preparing the projects reports of individual dairy unions.
- 5.8. In Rajasthan, two Command Area Development Authorities have been set up which would be responsible for planning and implementation of all irrigation and on-farm development works under the command area development projects in the Rajasthan canal and Chambal region in the state. The Rajasthan Land Development Corporation, the agency which would be actually executing the projects works and carry out other activities incidental to the main project, has also been set up. Preinainary steps to draw up the work plan are under way. Metawhile, a consultant of the IDA has initiated work under the extension programme.
- 5.9. The Corporation has been making efforts, as a matter of deliberate policy, to promote agricultural development in the less developed states particularly in the Eastern and North-Eastern regions. In this context, the sanctioning of an integrated agricultural development project in West Bengal with IDA assistance assumes considerable significance. The project, inter alia, envisages on-farm investments such as construction of both shallow and deep tubewells, the latter through co-operatives and the Minor Irrigation Corporation, the completion of nearly 600 river lift schemes already commenced by the state government, setting up of agro-service centres and construction of three markets. In view of the small and fragmented land holdings in the state

the project places considerable reliance on the shallow tubewells programme. As the co-operative credit structure in the state continues to be weak, the commercial banks in the area have been given a greater share of responsibility and are expected to finance about 70 per cent of the total onfarm investments under the project.

- 5.10. A reference was made in the last annual report to the proposal for a general line of credit from IDA. After a series of discussions with the Government of India and the IDA officials, the formal negotiations for the project were successfully concluded by the GOI and the Corporation with IDA in February-March 1975. The Agricultural Refinance Corporation credit project is distinct from the other on-going IDA credit projects wherein funds are committed for individual states or parts of the state and for specific items of development. In recognition of the competence of the Corporation to appraise agricultural development projects for different types of landing, the responsibility under the ARC credit projects for identifying and appraising the projects and committing funds has been left to the Corporation. It will have sufficient flexibility to deploy investments in the different regions and for different purposes taking into account the responsibility to treature purposes taking into account the organisational structure available. In areas where specific credits are available under IDA-assisted programmes for the same purpose, the Corporation will be able to continue the investments after the earlier credits are fully availed of. Details of this projects are given in an Appendix.
- 5.11. Some more IDA projects are in the pipeline. The Corporation has been associating itself with the various IDA missions in the preliminary stage itself so that there will be less problems at the implementation stage. An IDA mission visited India in May 1975 for updating the data in regard to the integrated cotton development project. Two World Bank/FAO Reconnaissance missions came to India, at the request of GOI, to identify the possibility of promoting investments in tree crops and marine fishery development in the country. In addition, preparation missions for a forestry project in Madhya Pradesh, a horticultural project in Jammu and Kashmir and an All-Ir dia seeds project also paid visits. Members of IDA staff have explored the possibilities of assisting command area development projects in Maharashtra, Orissa and Andhra Pradesh. When these projects materialise, there will be considerable diversification in the volume and content of agricultural credit assistance to India from the World Bank Group.

INSTITUTIONAL SYSTEM FOR DEVELOPMENT

The reorganisation and streamlining of the operational procedures within the Corporation have been fruitful. The flow of schemes for consideration has increased and at the same time the number of schemes accepted has reached nearly 625 as against 550 last year. In the context of the expanding business activities of the Corporation, its regional offices have a vital role in translating the aspirations of the Corporation into concrete programmes of action by assisting the various agencies in formulating viable schemes of agricultural development with refinance facilities and also help the financing banks in overcoming bottlenecks in the implementation of sanctioned schemes. The staff position was adequately strengthened for this purpose. The regional offices have also an important responsibility in canvassing and mobilising adequate resources to fulfil the lending programme of the Corporation.

6.2. Keeping these in view, a joint meeting of senior officers of the central office and the in-charges of the regional offices was convened at Bombay in March 1975. The discussions centred round issues such as the progress of performance budgeting introduced in the Corporation, the areas and scope for diversification of agricultural investments in the various states, the pace of implementation of on-going IDA-assisted projects and removal of bottlenecks in implementation, ways of reducing delays in sanctioning schemes submitted by the financing institutions, simplification in procedures relating to drawal and documentation, methodology for financial appraisal of schemes, technical aspects relating to scheme formulation and follow-up and evaluation studies of sanctioned schemes. The participants were briefed on the salient features of the ARC credit project which had just then been negotiated with IDA. The briefing enabled the regional offices to understand the various provisions in

the agreements and their responsibilities in implementing the project. Since reimbursement from IDA under this project would be to the extent of only 55 per cent of disbursements of relinance by the Corporation, considerable effort would be involved in mobilising adequate resources. The regional offices will have, therefore, greater responsibility in canvassing for bonds and shares of the Corporation to be issued from time to time so that requisite resources would be available to fulfil its commitments.

6.3. Schemes of minor irrigation, the largest single purpose of ARC refinance, have been showing a declining trend in some states both in number and amount. In order to maintain the tempo of lending, the need for diversification of business particularly by the SLDBs which are the major recipients of refinance, received attention at the meeting.

Scheme formulation

6.4. The states in the North-Eastern region have yet to develop sufficient expertise in formulating viable agricultural development schemes which can be readily refinanced. At the district level particularly, the need is keenly felt for properly identifying, promoting and formulating schemes and also in implementing them. Towards this end, the Corporation organised seminars in Assam, Manipur and Tripura for the benefit of state and district level officers in these states. During these seminars, the techniques of formulation of different types of schemes of development with refinance assistance from ARC were explained to the participants. Besides the representatives of the state governments, officials of commercial and co-operative banks operating in these states also took advantage of the seminars.

The technical soundness of a project is an important criterion in the appraisal of agricultural development schemes. In order to help the various state governments and financing institutions to appreciate the need for observance of necessary technical requirements and to enable refinements being adopted while drawing up of schemes by the technical personnel of various agencies, the Corporation organised two seminars, one in September 1974 in Bombay and the other in February 1975 at Lucknow. Represented of state governments, commercial and co-operative banks participated in the seminars.

Consultancy Service Units

6.5. The second Consultancy Unit organised at Calcutta commenced functioning from December 1973. Consequently, the Consultancy Unit at Lucknow was reorganised to cover the states of Himachat Pradesh, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh. The diction of the Calcutta Unit was limited to Bihar, Bengal, Orissa, Assam and North-Eastern areas. The officers of the Consultancy Units visited the states for discussions with the authorities about the possibilities of new schemes being formulated. The response from these states in regard to lending programme and the number of schemes that have been sanctioned is a reflection partly of the efforts put in by the Consultancy Units in assisting the state authorities in formulating schemes acceptance to the Corporation. The Consultancy Unit at Calcutta was specifically associated with the formulation of schemes relating to piggery development in the North-East area, development in Assam through Gaon Panchayat Co-operatives and the pre-ment survey for plantation/horticulture and forestry. the pre-investplayed an important role in the identification of minor irrigation programmes in Orisa, a good part of which is materialising. Similarly they are involved. In association with IDA, in a pre-investment study of horticulture programmes in Jammu and Kashmir. Both the Consultancy Units studied the organisational pattern of land development banking system in their areas and their findings assisted the head office in taking a view on the lines of development in these states.

Appraisal

6.6. The Corporation had constituted an Internal Review Team to review the existing procedures, methods and content of economic appraisal of schemes and scope of utilisation (follow-up) studies and suggest improvements. The findings of the Team were broadly endorsed by the ARC

Review Committee. Detailed instructions have since been issued to the rgional offices for their adoption at the field level

6.7. The assessment of benefits and costs of a scheme with reterence to a single farm model based on representative was found inadequate and particularly unsintable in holding' those schemes where due to wide inter-farm variations or differences in soil-crimatic conditions within the scheme area, the levels of benefits and costs are expected to be varying significantly for different farmers. More than one model might be necessary even in respect of schemes with a homogenous soil-climate complex. This necessitated appraisal of schemes adopting multi-model exercises by preparing a number of farm models so as to reflect the costs and benefits which accrue to the different categories of framers (small farmers and others), irrigated and unirrigated farms, etc. The criterion for judging the financial feasibility of the schemes merely with reference to annual capital was also madequate as it might not be valid in all cases. Future appraisal will, therefore, be based on two separate tests for ussessing the financial feasibility and bankability of schemes. The financial feasibility will have to be determined with reference to the internal rate of return while the bankability will be conditioned by the approximation. be conditioned by the annual repaying capacity of the borrower. The concept of repaying capacity of the beneficiary should be properly defined and the norms are to be evolved in apportioning the amounts towards loan instalments, keeping in view the framework suggested by the Review Team in this regard. In order to avoid subjectivity in appraisal, the regional offices would also collect comprehensive data for farm budget analysis such as costs of cultivation, cropping patterns, yields of crops, cropping intensities, prices, etc., in 'with' and 'without' the project situations.

Land Development Banks

- 6.8. Although there has been some progress in the introduction of production-oriented lending procedures, the land development banks seem to be facing the prospect of a reduction in their fresh business. The enforcement of the disciplines inherent in an orderly and scientific utilisation of available groundwater resources does not seem to have been supportd by an adequate machinery to keep continuous monitoring of projects under implementation and a dynamic effort to continue detailed investigation of potentialities. For example, in states such as Gujarat, Haryana and Tamil Nadu where considerable exploitation of ground-water has already been done in the past, the scope for fresh business in minor irrigation schemes might apparently look diminished but studies have shown that potentialities do exist and investment could be promoted on a selective basis at least in some of On the other hand, there are areas where considerable scope exists but it would take some time before optimum levels of exploitation are reached. Thus, for the system as a whole there is scope for further lending, the business in individual states would depend very much on intensifying further studies of groundwater potential,
- 6.9. Very little attention in the past was devoted to ensuring better utilisation of surface water resources, lift irrigation where scope exists and avoidance of loss by seepage in transit which would enable more land to be irrigated. This would call for appropriate strengthening of the relevant state departments and the building up of competent technical cells in the individual banks themselves. The banks should have also rethinking about the spectrum of business they are accustomed to do. At this stage of their long career there is need for diverification of their lending in order to maintain the volume of their business.
- 6.10. The continuance of a high level of overdues at the primaries/branches level is another discomforting feature. The overdues of the LDBs increased considerably from Rs. 12.89 crores in 1969-70 to Rs. 76.33 crores in 1972-73. There was, however, an improvement in recovery, the overdues coming down to Rs. 62.17 crores (provisional) at the end of 1973-74. It is a good augury that the banks have been able to maintain the pressure for recovery. The pre-liminary figures for 1974-75 indicate continuation of this downtrend in overdues.
- 6.11. The banks will, however, have to be vigilant and continue effective measures to bring down the level of overdues further. While several explanations could be given for the level of overdues, the remedy lies in th SLDBs ensuring

improved appraisal for loans issued, lesser dependence on departmental staff and pointed attention of the managements to the problem. Uniform criteria for regulating the lending programme of LDBs commencing from 1975-76 have since been evolved and communicated to them. The regulation of the programme will be mainly with reference to the level of overdues to demand at the primary/branch level.

Commercial Banks

- 6.12. Commercial banks have been participating actively in agricultural development programmes on a large scale during recent years. However, there is still no wider acceptance by many state governments of the multi-agency approach. State governments of Gujarat and Tamil Nadu are still hesitant to permit commercial banks to play their legitimate role. Bulk of the lending by commercial banks has taken place in the underbanked areas and has been equally spread under minor irrigation and diversified purposes.
- 6.13. During 1974-75, commercial banks were sanctioned 501 schemes with a financial assistance of Rs. 104.5 crores as compared with 116 schemes with an assistance of Rs. 129 crores for LDBs. The Corporation has so far sanctioned 1176 schemes to these banks involving a commitment of Rs. 223.2 crores. These formed 52 per cent of the total number of schemes sanctioned by the Corporation upto the end of June 1975. The schemes cover a broad spectrum and include such purposes as minor irrigation, land development, farm mechanisation, plantation and horticulture, poultry and dairy as well as market vard projects.
- 6.14. During 1974-75, the commercial banks availed themselves of refinance of Rs. 28 crores which formed 26 per cent of the total disbursement made by the Corporation during the year and was nearly equal to the aggregate of the drawals made by them during all the preceding years. The drawals were sizeable in Uttai Pradesh, Haryana and Madhya Pradesh. Commercial banks have been actively participating in the IDA-aided projects in the various states. The Corporation and the commercial banks will be venturing into a new field of activity, viz., financing forest development schemes in various states in the country. In view of the comperity and magnitude of the programme and in order to gain sufficient expertise besides pooling their resources, the Corportion is having in view, multibanking arrangements for financing such programmes.

Training

- 6.15. The ARC has to equip itself for handling a large volume of business projected for future years. The building-up of sufficient expertise in the financing institutions is also necessary for the successful implementation of programmes. This will be facilitated only if adequate complement of trained staff is in position. An Informal Committee on Training appointed by the Corporation had examined this question and suggested a two pronged training programme—one for senior and middle level personnel and another for junior officials.
- 6.16. The ARC credit project also has placed responsibility on the Corportion to prepared a training programme primarily for senior and middle level LDB staff which can include officials of other institutions connected with project implementation as well as government officials. The framework of this programme has already been drawn up. The principal aim of the training will be to enhance the skills and functional efficiency of the staff concerned with project implementation. It will cover items such as project promotion, identification and formulation, appraisal (technical and economic), drawal, documentation and disbursement, post-sanction verification repayment and recoveries of defaulted loans and prudent financial management.
- 617. The training programme of senior and middle level staff would be for the chief executives of state land development banks, heads of agricultural finance departments in commercial banks and a few officers drawn from the Reserve Bonk of India, ARC and the state governments. Initially, two pilot courses would be organised to serve as aids for determining the content of future courses. The first pilot course for chief executives will lay stress on aspects such as revamning of the bank's management and organisation for meeting the new challenging demands.

- 6.18. The Corporation has set up a Training Cell which will initiate and pursue action for discharging the responsibility devoiving on it under the ARC credit project. This Cell would prepare the syllabi, teaching materials etc. required for the training course. The faculty of the RBI College of Agricultural Banking, Poona would be strengthened adequately to meet these requirements. A Committee headed by the Chairman is being constituted to advise the ARC on various aspects of training.
- 6.19. Under the ARC credit project, the Corporation has also to assess the training requirements of the junior-level LDB staff, prepare a training programme acceptable to IDA and implement it. In order to determine the training needs of junior-level LDB staff, a team is being set up for each state comprising officers from ARC, chief executives of the concerned SLDBs and a nominee of the Registrar of Cooperative Societies. The guidelines for the study would be prepared by the Training Cell in the Corporation which will also exercise general supervision over the conduct of the study by the state level teams.
- 6.20. During the year, two officers of the Corporation were deputed to the Rural Credit Projects course conducted by the Economic Development Institute at Washington while another office: participated in the Agro-Industries Course.
- 6.21. Two senior officials of the Corporation were associated with IDA Missions appraising agricultural credit projects in Tanzania and Turkey as part of their training programme in the IBRD/IDA.
- 6.22. The Corporation arranged a repeater workshop in Bhopal during the year for the benefit of representatives of the SLDB and commercial banks participating under the IDA project.

Evaluation

- 6.23. In the wake of larger investments, it is important to systematically assess the benefits accruing to the farmers so as to compare the pre-investment assumptions with post-investment achievements. Such evaluation of projects brings out not only the gains in terms of taltaual additional output and feed-back data for project-formulation in future but also the difficulties faced by the beneficiaries in realising the maximum benefit from the investment. It was with these objectives in view that the Corporation had established an Evaluation Cell.
- 6.24. As part of evaluation, the Corporation has taken up studies of 4 schemes, viz., new dugwells with pumpsets schemes in 4 taluks of Sholapur district (Maharashtra), installation of shallow tubewells under Karnal I scheme (Haryana), Nagarjunasagar land development project in Miryalguda taluka of Nalgonda district (Andhra Pradesh) and Bhadra land development project in Davanagere and Harihar talukas of Chitradurga district (Karnataka) and accordingly has set un 4 field units. The survey method has been adopted to collect faim business data through appropriate schedules in respect of a sample and selected cultivators under each scheme. The field investigations have been completed in respect of Karnal I scheme while in respect of other schemes, the investigations are in an advanced stage. The work relating to the process/tabulation of the data so collected through the schedules has since been taken up.

PERSPECTIVE

There is now increasing recognition of the role of the Corporation in spear-heading efforts for agricultural development in the country. The main thrust of the activities of the Corporation will be to work towards fulfilling the objectives framed for the Corporation namely, to provide support for technically and financial sound investment in agriculture, promote investment in areas where sufficient funds were not flowing ensure that as large a number of small farmers and the weaker sections of the community obtained resources to make investments and achieve a larger degree of diversification in the purposes for which loans are made available. The achievement of the objectives underlines the need for necessary resources support for the Corporation and to ensure this a continuous dialogue is maintained with the Government of India and the Reserve Bank. Increasing recourse to market borrowings has been a feature of the recent efforts at resource mobilisation.

- 7.2. The Corporation is striving to promote development in the less developed and underbanked areas in the country. With a view to generating the requisite dynamism in the North-Eastern region the Corporation set up a Study Team comprising officials of the Corporation to examine the potentialities for bankable investments in horticulture, plantation crops and forest development. The Study Team, in its report submitted in April 1975, came to the conclusion that development of forests and plantation crops can be programmed in this region once an appropriate organisation such as a Forest and Plantation Crops Development Corporation is established. The progress of investments for these developments would depend on the speed with which the organisa-The problem of tional structure is brought into being. horticultural development is more difficult in view of the highly competitive market for processed fruit products both within the country and outside. For this reason, the success of any developmental scheme for horticultural crops would hinge on a complementary scheme for the processing of the fruits and the ultimate success of such ventures would de-pend on effective marketing of the end product. In order to draw attention to the marketing aspect, the Team has recommended the establishment of a Horticultural Development and Processing Company for the region as a jointsector undertaking to ensure proper arrangements for quality production and competitive marketing,
- 7,3. Tea plantations play an important role in the area. However, several estates categorised as 'sick' are capable of being rehabilitated. The Team has recommended the setting up of a revolving fund in the ARC with an initial contribution of Rs. 15 crores from the Central Government.
- 7.4. It will be a matter of satisfaction if the Team's report generates sufficient enthusiasm and provokes further thinking in the state governments in these regions and induces them to take up developmental work on a scale commensurate with their capabilities for promotion of horticulture, plantations and forestry in their areas.
- 7.5. The Corporation had conducted a pre-investment survey for piggery development in the North-Eastern region with the help of a firm of consultants. Subsequently, follow-up studies were undertaken by a team of technical officers of the Corporation in four states, viz., Assam, Meghalaya, Manipur and Nagaland. While recognising the scope for and the need to provide institutional finance for piggery development, the team felt that the nature of loans as also the purpose would have to be different in these states having regard to the peculiarities in the situation prevailing in these states.
- 7.6. On the basis of these studies, firm proposals for integrated piggery development have been formulated for the states of Nagaland and Manipur to be implemented through commercial banks. The main objective behind the schemes is to provide a profitable subsidiary occupation to small farmers and increase their income by emphasising qualitative as well as quantitative aspects of piggery farming in the states.
- 7.7. Reference was made in the last report to the setting up of an Informal Advisory Committee for studying the problems of small planters in the Southern region. In accordance with the decision of this Committee, a study of identify the problems of small growers of coffee in Saklaspur area (Karnataka Sinte) was conducted by the officials of the Corporation with the help of representatives of commercial and co-operative banks. The study was confined to small coffee planters, i.e., those having less than 25 acres under coffee in this area. Bulk of the small planters in the area have coffee lands less than two acres. The study has highlighted the illa affecting small planters and has identified the scope available for increasing productivity of coff-e in existing plantations besides enlarging the area under coffee. The small planters would need a package of assistance both technical and financial. The Team has estimated that about 4.000 acres will require rehabilitation and about 3.000 Extension acres each will need replanting and new planting. work would be necessary to sort out the problems of individual estates and recommend corrective measures. The rehabilitation of the estates of the small planters is estimated to increase their income by Rs. 600 per acre from the fourth year onwards while replanting/new planting is expected to increase the income to Rs. 490 per acre from the seventh year. The project is of a pilor nature and will provide valuable experience and feedback for extension to other types of plantations elsewhere

- 7.8. Another anxiety of the Corporation is to channel a substantial part of the relinance provided to small farmers and other weaker sections of the community. The Corporation has entered into a commitment with 1DA under the ARC credit project that it will ensure that alleast 50 per cent of the refinance will be for the benefit of this category. Taking into account the 'poverty' line generally arrived at for the country as a whole, a liberal interpretation is placed to arrive at the definition of these weaker sections. This is clearly an improvement over the definition adopted earlier.
- 7.9. As part of the process of performance budgeting, individual meetings with the representatives of state governments and some of the land development banks and commercial banks were arranged. Such meetings served to evaluate the progress of schemes sanctioned to the banks, focus attention on the problems faced by them in implementing the approved programmes and their expectations of future performance by way of drawals from the Corporation.
- 7.10. The Corporation's assessment of the disbursements to the member-banks has revealed that while scheme formulation and obtaining ARC sanction have received the attention of the various agencies, the actual implementation of the approved programmes leaves scope for improvement. There is still considerable shortfall in the amount committed by the Corporation and the actual drawals by the financing banks. This slow pace of implementation should receive serious attention of all those connected with agricultural development programmes.
- 7.11. A new type of activity into which the Corporation is nturing is financing forest development. The National Comventuring is financing forest development. mission on Agriculture in its interim report on "Production Foresty—Man-made Forests" has focussed attention on the development of the forest wealth in this country by selling up of forest development corporations. The approach recommended is a dynamic programme of production forestry as against the traditional conservation-oriented approach. Forestry development will involve large outlays and long gestation periods. The developmental activities connected with forests are also varied and complex. While the responsibility for creating the necessary infrastructure facilities should come from normal budgetary allocations of the state governments, funds for actual development of forests may have to be met by institutional finance. The Corporation is of the view that a programme of this nature would require a multi-banking arrangement for successful implementation. Normally, two or three commercial banks will be expected to participate in a project. ponsibility for supervision common security for all the financing institutions, documentation, etc., can be settled once the broad approach is decided upon
- 7.12. The Corporation has, in principle, approved three forestry projects for West Bengal, Bihar and Andhra Pradesh. The banking arrangements for financing these projects will be settled soon. Maharashtra, Madhya Pradesh, Andaman and Nicobar Islands, Orissa and Kerala have also prepared programmes for forest development in their regions. A forestry mission from IDA had useful discussions with the Corporation regarding the three projects approved by the Corporation. If the development of forests on commercial lines in the various states in the country is taken up speedily, funds from IDA can also flow for such development. In this process it is gratifying to note that some of the state governments, especially those in the Eastern and North-Fastern regions have taken up the initialitie for setting up of forest development corporations in their respective states.
- 7.13. Owing to various reasons, irrigation facilities created by major irrigation works have remained, by and large, under-utilized. The Irrigation Commission and the National Commission on Agriculture have stressed that co-ordination among the concerned departments dealing with irrigation, soils and agriculture is vital for a fuller use of the available irrigation facilities to maximise agricultural production. It is against this background that the GOI decided on the setting up of autonomous command area development authorities to ensure inter alla co-ordinated action in different disciplines and provision of adequate credit to the cultivators. While institutional finance will be available for on-farm expenditure on items such as land shaping and land levelling, plan resources will have to take care of rehabilitation and modernic sation of irrigation systems as well as strengthening or creating of infrastructure facilities such as roads and markets,

7.14. The Corporation is actively associated with the provision of institutional finance in command area development projects. The IBRD/IDA has sanctioned three command area development projects, two in Rajasthan and another in Madhya Pradesh. The funds for on-farm investments under these projects will be routed through the Corporation.

7.15. During the year, the Corporation convened a meeting of the representatives of state governments of Andhra Pradesh and Maharashtra in which the Planning Commission also participated, to discuss the outstanding issues concerning institutional finance for command area development prog-

rammes in these states. Issues such as the modalities of financing farmers through the State Land Development Corporation, collection of mortgages and recoveries of bank loans have since been resolved.

FINANCES

The principal sources of funds of the Corporation for financing its lending programme during the two years 1973-74 and 1974-75 as well as the trends in various items during the five years 1970-71 to 1974-75 are presented in the table below:

Table 7
SOURCES OF FUNDS

Rs. crores

	Sources	1973-74	Percent of total	1974-75	Percent of total	July 1970- Juno 1975	Percent of total
1.	Paid-up share capital and reserves/surplus	0 .68	• 0.7	6.22	5 · 1	17 · 63	4 · 5
2.	Special deposit by Reserve Bank of India	0.24	0 · 2	0.38	0.3	1.04	0 -3
3.	Barrowings from Government of India IDA funds	38.62	37 - 8	33 · 12	27 ·1	115 · 75	29 -8
	(b) Others	0.03		_	<u> </u>	36.07	9.3
4,	Borrowings from Reserve Bank of India						
	(a) N.A.C. (LTO) Fund	23 · 00	22 · 5	40 .00	32 · 8	98 -00	25 -2
	(b) Others	7 ·90	7 .7			15.73	4 · 1
5.	Bonds	27 ·50	26.9	33 .00	27 · 1	88 - 27	22 - 7
6.	Repayments by banks	4 · 23	4.1	9 · 27	7 · 6	16.00	4 · 1
,	Total	102 · 20	100 -00	121 -99	100 00	388 -49	100 -00

Share Capital

8.2. During the year the Corporation issued the fourth series of shares with paid-up value of Rs. 5 crores. The minimum guaranteed dividend on these shares was kept at 6 per cent

per annum. The aggregate share capital of the Corporation stood at Rs. 20 crores on 30 June 1975. The contributions of various categories of shareholders to the share capital as on 30 June 1975 are as follows:

Table 8
CONTRIBUTIONS TO SHARE CAPITAL—SOURCES

Rs. Crores

fugitus! - n	Share	b		
Institution	No.	Value	Per cent of total	
Reserve Bank of India	11,529	11 -53	57.65	
Central land development banks	3,263	3 · 26	16 · 30	
State Co-operative Banks	1,762	1 · 76	8 -80	
Scheduled commercial banks	3,231	3 · 23	16 - 15	
Life Insurance Corporation of India	193	0 · 19	0.95	
Other insurance and investment companies	21	0.02	9.10	
Co-operative insurance societies	1	0.01	0.05	
Total	20,000	20.00	100.00	

8.3. In terms of one of the amendments to the ARC Act, 1963, the Reserve Bank can, with the previous approval of Central Government, increase the authorised capital of the Corporation to Rs. 100 crores from the present limit of Rs. 25 crores. Since the borrowing power of the Corporation is restricted to 20 times of the paid-up capital and reserve fund, it may be necessary for the Corporation to strengthen its share capital and consequently its borrowing power in order to meet the growing demand for agricultural investments. The Corporation proposes to come up with a fresh issue of share capital for Rs. 5 crores shortly.

12—469 GI/75

Borrowings from the Government of India

8.4. The borrowing from the Government of India during the year towards reimbursement of the rupee equivalent of credits under IDA/IBRD projects amounted to Rs. 33.1 crores raising the total borrowings from GOI to Rs. 196.6 crores. During the year under review the Government of India stepped up their lending rates effective from 1 August 1974 by ½ per cent to 6½ per cent and 7½ per cent with ½ per cent rebate for prompt payment of interest in respect of 9 and 15 year loans respectively.

Market borrowings

8.5. During the year the Corporation entered the market twice, first in October 1974 (VII series) and again in May 1975 (VIII series) to raise a total sum of Rs. 33.00 crores. The bonds were issued at Rs. 99.00 carrying interest at

6 per cent per annum and maturing in 10 years. At the end of the year, market borrowings aggregated Rs. 99.21 crores. The following table shows the amount received from various categories of subscribers for the two series issued during the year and their cumulative contributions for the previous issues.

Table 9
SUBSCRIPTIONS TO BONDS

Rs. Crores

Subscribers	l to VI	VII	VIII	Total
1. State Bank of India and subsidiaries	15 · 89	3 19	3 · 68	22 - 76
2. Nationalised banks	30 · 66	6 · 60	7 · 20	44 -46
3. Other commercial banks	3 -83	0 • 97	1 -33	6 - 13
4. Life Insurance Corporation of India	0 -65	0.15	0.15	0.95
5. Other insurance companies	0 ·13	0.06	0.02	0.21
6. Co-operative banks	14 ·80	5 · 42	3 · 69	23 -91
7. Others	0 -25	0.11	0 ·43	0 ·79
Total	66 - 21	16.50	16.50	99 -21

Borrowings from Reserve Bank of India

8.6. During 1974-75 the Reserve Bank of India sanctioned a further limit of Rs. 40 crores for drawal from the National Agricultural Credit (Long-term Operations) Fund and this limit was fully availed of. After allowing for repayment of Rs. 5.80 crores in respect of the earlier loans, the balance due from the Corporation to the Reserve Bank stood at Rs. 88.20 crores as at the end of June 1975.

8.7. In addition, the Corporation also enjoys a limit of Rs. 15.00 crores for short-term loans from the Reserve Bank of India and there was an outstanding of Rs. 4.50

crores under this account on 30 June 1975. Since this facility is available only at the Bank Rate, which at present is high at 9 per cent per annum, the borrowings under this category have been utilised only for the minimum period and to the extent absolutely necessary to cover disbursements in excess of current resources, pending receipt of funds from other sources.

Repayments

8.8. Repayaments from members-banks amounted to Rs. 9.27 crores against Rs. 4.23 crores during the previous year. The agency-wise break-up of the aggregate repayment of Rs. 16.21 crores as at the end of 30 June 1975 is as under:

Table 10 REPAYMENTS

Rs. Crores

Agency	Repaymen	nts	Total
	ARC. schemes	IDA-assisted schemes	•
Scheduled commercial banks	5 · 26	0.67	5 . 93
2. State land development banks	0 -46	6 · 29	6.75
3. State co-operative banks	3 -53	<u> </u>	3 - 53
Total	9 · 25	6.96	16.21

8.9. The repayment of loans by member-banks during the year was higher by Rs. 5 crores as compared to the previous year. This larger accrual was possible because of annual redemption of LDB debentures under on-going IDA credit projects. This is expected to facilitate a quicker turnround of funds available with the Corporation,

Members

8.10. Two more banks, viz., Algemene Bank Nederland, N.V. and Purbanchal Bank Ltd. became members of the Corporation. The Krishnaram Baldeo Bank Ltd. ceased to be a member. The total membership of the Corporation as on 30 June 1975 stood at 110 as against 109 at the end of June 1974.

Board of Directors

8.11. The Board of Directors met 6 times during the year.

Shri Tribhuvan Prasad Singh who was a Director of the Corporation from 18 April 1970 to 3 November 1972 passed away in May 1975. The Board has conveyed its deep sympathies to the family.

Use of Hindi

8.12. The Corporation has been represented on the Official Languages Intolementation Committee of the Reserve Bank of India to popularise the use of Hindi in the day-to-day working of the Corporation. All letters received in

Hindi are being answered in Hindi. All the official notifications, press communiques, etc. are published simultaneously in English and Hindi. The Corporation's Annual Report is published both in English and Hindi. The Corporation is associating itself with the steps taken by the Reserve Bank of India for popularising the use of Hindi and providing training facilities in Hindi for members of the staff.

Profits

8.13. The net profits of the Corporation during the year 1974-75 available for appropriation amounted to Rs. 166.24 lakhs after providing a sum of Rs. 45 lakhs towards special reserve being 10 per cent of the current profits as permissible under the Finance Act, 1971. The Directors recommend appropriation of the profits as under:

			R s. lakhs
Transfer to	Reserve	Fund	 77.63
Dividend on sl	hares		 88.61
			166.24
		_	

On behalf of the Directors

R. K. Hazari Chairman

19 August 1975

APPENDIX

Agricultural Refinance Corporation Credit Project

The International Development Association sanctioned a credit of \$75 million for the ARC Credit Project and the relative agreements with IDA were signed on 28 April 1975. The Project comprises a two-year programme to finance investments by the beneficiaries in minor irrigation and other diversified agricultural projects for which refinance will be provided by ARC in respect of loans made by the participating banks. The credit sanctioned by the IDA will be exclusive of the credits sanctioned for on-going IDA credit projects currently under implementation in some of the states. The closing date of the Project is 31 December 1977. The Project components are as follows:

- (i) financing minor irrigation and other diversified agricultural investments; \$69 million has been ea marked by the IDA for reimbursement under the minor irrigation category while \$5 millision will be available for lending under diversified purposes other than minor irrigation;
- (ii) a study on the feasibility of merging the short-term and long-term co-operative credit institutions;
- (iii) a study of the training needs of the junior-level staff of LDBs and training of such staff; and
- (iv) an intensive two-year training programme for the senior and middle level staff of LDBs, financing institutions and other agencies connected with the implementation of the Project.

A credit allocation of \$1 million has been made for meeting the expenditure to be incurred for implementing items (ii) to (iv) indicated above.

The other features of the Project are set forth in the following paragraphs.

I. Beneficiary

'Beneficiary' has been defined as any person, group of persons, co-operative society, corporation or other entity which is eligible for receiving a loan from a participating bank under the Project.

II. Banks eligible to participate under the Project

The state land development banks, their branches and the primary land development banks, state co-operative banks and scheduled commercial banks are eligible for participation under the Project. However, the amount which can be claimed from the IDA in respect of refinance provided to state co-operative banks is not to exceed \$ 500,000. Participating banks will have to observe the technical and financial disciplines envisaged under the Project.

The ARC will be entering into separate refinance agreements with each of the participating banks detailing terms and conditions under which the funds should be made available to the ultimate borrowers and refinance availed of thereagainst under the Project.

III. Minor Irrigation

(A) Eligible Purpose

The term "minor irrigation" would cover exploitation of groundwater and surface water resources and would include such devices as dugwells, shallow tubewells, deep tubewells, pumpsets, lift irrigation units, etc. Minor irrigation would

also include an element of loan for development of command area of the irrigation sources financed and construction of water courses.

(B) Terms of lending

(a) Currently, under the on-going IDA Projects "small farmer" has been dlined as one having a post-development net income of Rs. 2,400 with a ceiling of Rs. 10,000 in the cost of investment. Small farmers, as defined in this manner, are eligible for concessionary lending terms, viz., lower down payment and longer maturity period of loans. This definition has been modified and made more liberal under the ARC Credit Project. The term "small farmer" is now defined to cover any farmer cultivating land providing a pre-development net return to family resources to such farmer and his family not exceeding Rs. 2,000 based on 1972 prices. This amount can be adjusted to take care of any price changes during subsequent years by applying the Consumer Price Index Numbers for Agricultural Labourers for the state in which the land is situated. For the purpose of determining the said net return to family resources, "land" shall include all lands actually cultivated by the farmer whether owned or otherwise. "The net return to family resources" has been defined as gross family income from land less costs actually incurred (including cash value of the farmers' own input, including seed, fertilizer, hired human labour, hired bullock labour, feed consumed by family bullocks, itrigation charges, land revenue, interest on crop loan and rent on leased land).

The Corporation has since worked out with reference to the calendar year 1974 the revised figures corresponding to the figure of Rs. 2,000 based on 1972 prices. The regional offices of the Corporation will undertake field visits to compile basic farm data to estimate pre and post development income per acre for different investments. Based on these studies, the income limits will be translated into acreage limits. With the help of multi-farm models the regional offices would be in a position to identify the acreage level for the different groups of farmers.

There is no ceiling on the cost of investment undertaken by the small farmers to become eligible for concessions. This casts a heavier responsibility on the financing institutions to ensure that the investments would be liquidated from the increnental income generated.

Another feature of the project is that fifty per cent of the credit for minor irrigation and diversified investments, viz., \$37 million has been earmarked for refluancing loans advanced to small farmers.

(b) Down payment

The beneficiaries will have to contribute own labour and other contributions in cash or kind to cover a part of the investment cost. In the case of land development banks the down payment would include the farmer's obligatory purchase of LDB shares. For the purposes of down payment beneficiaries have been grouped under three categories: (i) small farmers having a pre-development net return upto Rs. 2,000 based on 1972 prices; (ii) farmers with a pre-development net return ranging between Rs. 2,004 and Rs. 3,500 based on 1972 prices; (iii) other farmers, those with pre-development net return of Rs. 3,501 and above. The stipulations in regard to downpayment for these three categories of farmers are as follows:

Changer of formary	Percentage of ir	ivestment cost 原。
Category of farmers	Pumpsets	Other minor irrigation investments
(1) Small farmers	5	5
(2) Farmets in category (ii)	10	10
(3) Other farmers	10	15

There is no objection to the LDB collecting the obligatory share capital in one or two instalments in the case of small farmers,

(c) Maturity period of loans

The period of loans to the beneficiaries under the Project would be based on their repayment capacity and will also

be conditioned by the useful life of the asset but shall not exceed the periods indicated below:

Small farmers	Other farmers
7 years	7 yeras
15 years	9 years

(1) Pumpsets whether financed as separate loan or part of composite loans

(2) For other minor irrigation purposes

Suitable grace periods not exceeding 23 months from the date of the first instalment of the loan taking into account a full 'Kharif' and 'Rabi' crop may be granted at the discretion of the Corporation provided that the repayment periods indicated above are not exceeded.

The participating banks are required to repay refinance availed of under the Project in annual instalments, the quantum of which will be linked to the instalments payable by the beneficiaries. In the case of land development banks this would means annual redemption of a part of special development debentures.

(d) Technical discipline

In regard to minor irrigation investments the participating banks are required to ensure that well-spacing and density criteria as Iaid down in the Project Agreement are observed. Before a scheme for minor irrigation purpose is approved, a detailed technical study of the groundwater resources should be made. The Central Groundwater Board in consultation with the Groundwater Directorates in various states will draw up a list of areas in which there is a danger of over-exploitation of groundwater. Before undertaking fresh financing in these areas the State Groundwater Directorates should carry out a special study justifying the investment.

The LDB and its primary banks participating in the Project are required to apply the same lending terms and criteria for all their similar lendings outside the Project. The participating commercial banks are expected to apply in the project areas the same lending terms to all similar types of lendings and shall not offer more favourable terms except in regard to schemes of Small Farmers Development Agencies.

Overdues (% of demand) PLDB/ Branch of SLDB

0-25	
26-35	
36-45	
46-55	
56-60	
61-100	

ARC may take into account redeemable equity capital paid by the state governments to reduce such overdues, provided the amount of such equity shall not exceed 10 per cent of demand.

In order to ensure that the recovery performance achieved during a particular year does not slip back, a penal clause will be stipulated providing for review of cases where the overdues have increased by more than 10 per cent of demand over the level of overdues in the previous year.

In the case of state co-operative banks—their branches and primary societies the recovery level should be 65 per cent of demand which together with the state government's contribution upto 10 per cent of demand should not be less than 75 per cent of demand.

(f) Security for refinance

The security for the loans given by the participating banks and for the refinance provided by ARC will be determined by ARC for each scheme,

(g) Interest rate

The rate of interest to be charged by ARC on the refinance as well as the rates to be charged to the ultimate borrowers

(e) Overdues criteria

One of the major considerations which is relevant for ARC appraisal of schemes of land development banks is the financial soundness of the primary land development banks or branches of state land development banks which will be implementing the schemes. The increase in the level of overdues of the LDBs has been causing concern to GOI, RBI and ARC. Under the IDA Projects in operation in the states of Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh and Bihar, ARC is prohibited from refinencing those PLDBs/branches of SLDBs the overdues of which exceeded 25 per cent of the demand for the year, unless the excess overdues are notionally brought down by injection of share capital contribution by the respective state governments. The Reserve Bank of India has also been applying certain norms for regulating the ordinary debentures programmes of the LDBs with reference to their level of overdues. The time was, therefore, propitious for adopting uniform criteria in this regard.

Beginning from 1 October, 1977, or such other date as the IDA shall agree, the SLDBs, their branches and primary land development banks are expected to reach a cash recovery level of 65 per cent of demand each year which together with the state government's contribution to equity upto 10 per cent of demand should effectively raise the recovery rate to 75 per cent of demand or more.

As an interim measure up to 30 September 1977, the amount of refinance to be made available to SLDB for lending through the branch of SLDB or a primary bank is to be determined with reference to the total amount of all loans issued in the previous year (July-June) by the PLDB/branch on the following basis:

Maximum loans to be issued (% of previous year's issue)
Unrestricted 80
70
60
50
Nil

under the Project will be laid down by ARC in the relative sanction letters. The rates will not be less than 7.5 per cent per annum for refinance and 10.5 per cent per annum to the ultimate borrowers. In addition, the participating banks would be allowed to charge a "once for-all" evaluation fee of 0.5 per cent of the investment cost.

(h) Maintenance of occounts, etc.

The participating banks should maintain separate accounts for project lending and for fendings to small farmers. The banks should submit their annual audited accounts to the IDA through the ARC within 4 months after the close of their fiscal year together with a statement of project lending certified by ARC.

(i) Financial rate of return

The Corporation will refinance only sound schemes which on the basis of careful study are considered to be financially viable and have a minimum financial rate of return of 15 per cent and are backed with satisfactory technical and administrative management.

(C) Co-ordination between ordinary and special development debentures programme

The RBI will also adopt similar norms for overdues as spelt out above, while regulating ordinary debenture programme of land development banks. A committee is being appointed for the purpose of monitoring LDB financial performance and the issuance of all LDB debentures.

(D) SFDA schemes

For the present, no reimbursement will be available under the Project in respect of refinancing done under SFDA schemes as these involve an element of subsidy. However, the GOI and ARC might take up the matter with IDA for inclusion of these programmes also under the ARC Credit Project.

IV. Diversified lending

(a) Eligible purposes

The purposes under diversified lending would include dairy poultry, sericulture, fisheries, horticulture, plantation, etc. The purposes are flexible except that the schemes for marketing or storage related thereto cannot be granted under the Project without prior approval of IDA.

(b) Terms of lending

The beneficiaries for the purposes of diversified lendings have also been classified under the same three entegories as in the case of minor irrigation category for the purposes of down payment. In regard to these schemes a small farmer beneficiary has been defined "as any person primarily engaged in an activity relevant to a scheme other than minor irrigation which provides a pre-development net return to family resources of such person and his family not exceeding Rs. 2,000". To preclude the possibility of big farmers taking advantage of this definition, the Corporation proposes to stipulate that in the case of loans for starting non-land activities the fresh income ceiling (for identifying small farmers) should apply to the total net annual income of the applicant and his family from the known activities.

(c) Down payment

The contribution of the small farmers, farmers with a pre-development net income ranging between Rs. 2001 to Rs. 3500 and other farmers would be 5 per cent, 10 per cent and 15 per cent respectively of the investment cost. Farmers' contribution would also include obligatory purchase of LDB shares and own labour and other contributions in cash or kind.

(d) Maturity period

The repayment periods of the loans would be based on the repayment capacity of ultimate borrowers but shall not exceed 15 years (including grace periods where necessary).

(e) Financial rate of return

The schemes should be financially viable and have a minimum rate of return of 15 per cent and should be backed by sufficient technical and administrative management.

Individual schemes for diversified lending involving ARC refinance of \$0.5 million (Rs. 40 lakhs) will have to be submitted to the IDA with the appraisal report and relevant data for their prior concurrence.

(f) Interest rate

The interest rates to be charged for diversified purposes on ARC refinance as well as the rates to the ultimate borrowers under the Project will be laid down by ARC in the relative sanction letter. The rate will not be less than 8 per cent per annum for ARC refinance and 11 per cent per annum to the ultimate beneficiaries. The participating banks may also charge a "once and for all" evaluation fee of 0.5 per cent of the cost of investment.

V. Study and Training

(a) Study

The Land Development Banks Act and the relevant provisions in the Co-operative Societies Act in operation in the states do not permit the land development banks to advance short-term loans. Consequently, the borrower of capital loan from the LDBs will have to approach either the village co-operative societies or the commercial banks for their production loans. On the other hand, in the case of commercial banks the borrowers can have the full package of credit both, long-term and short-term from the same source. In order to study the problems and feasibility of merging the short-term and long-term co-operative credit institutions, the ARC Credit Project envisages setting up of a study team.

(b) Training

In order to have adequately trained personnel in project lending, ARC is required to conduct a study for assessing the training needs of junior-level LDB staff before 31 October 1975; it has to prepare and furnish to IDA for its approval a training programme based on this study; and thereafter implement such programme as agreed to between IDA and ARC. In conducting this study, the state land development banks would be actively involved.

The Corporation will also implement an intensive twoyear training programme for the senior and middle level personnel of the participating institutions.

The funds (\$0.8 million) allocated by IDA under these categories would be available to ARC from GOI on a grant basis.

EXPLANATORY NOTES

- 1. The amounts have been rounded off to the nearest lakh of rupees.
- 2. The following symbols /abbreviations have been used in the Statements.

Symbols @ Latest available data —Nil or negligible,

1hbreviations

eviations				
Purpose:		Ml		Minor irrigation
		LD		Land development/ Reclamation/ Soil conservation
		FM		Farm mechanization
		P/H		Plantation/ Horticulture
		P/SB	_	Poultry/Sheep breeding
		${f F}$		Fisheries
		DD	_	Dairy development
		S/M		Storage/ Market yards
		ΛA	=	Agricultural aviation
Agency:	1:	SLDB	==	
	2:	Com. Bk.	-	Scheduled Commercial Banks
	3;	SCB	_	State Co-operative Bank

Statement 1 TRENDS IN AVAILMENT OF REFINANCE IN RELATION TO COMMITMENTS

Rs. Lakhs

Year	No. of schemes sanctioned		ARC commitments as phased		Disbursement		Disbursements as per- centage of commitment	
(July-June)	at the end of the year	During the year	Upto the end of the year	During the year	upto the end of the year	During the year	Upto the end of the year	
1963-64	3							
1964-65	13	447	447	45	45	10 · 1	10 -1	
1965-66	36	828	873	445	490	53 - 7	56 - 1	
1966-67	42	940	1430	208	698	22 -1	48 - 8	
1967-68	128	1850	2548	567	1265	30 .6	49 ⋅6	
1968-69	233	4594	5859	1784	3049	38 ⋅ 8	52 -0	
1969-70	371	6166	9215	2860	5909	46.4	64 -1	
1970-71	458	6658	12567	3062	8971	46.0	71 -4	
1971-72	711	8633	17604	3498	12469	40 · 5	70 - 8	
1972-73	923	16671	29140	9414	21883	56 · 5	75 · Ì	
1973-74	1457	18820*	43556*	9784	31667	52 ⋅0	72 - 7	
1974-75	2053	18754	60873	10640	42307	56 ⋅8	69 - 5	

^{*} Exclutling Rs. 557 lakhs switched over to IDA Project.

Statement 2
SANCTIONS DURING 1974-75—PURPOSEWISE

Rs. lakhs

Purpose	No of. schemes	Financial assistance	ARC commitment	Commitment of State Govern- ments/Banks	
Minor irrigation	303	16610	14817	1793	
Land development/ Reclamation/ Soil conservation	1	290	232	58	
Farm mechanization	129	4214	3338	876	
Plantation/ Horticulture	35	458	364	94	
Poultry/ Sheep breeding	26	158	134	24	
Fisheries	77	681	563	118	
Dairy development	39	887	742	145	
Storage/ Market yards	13	287	249	38	
Total	623	23585	20439	3146	

Statement 3 SANCTIONS DURING 1974-75—REGIONWISE AND STATEWISE

Region/ State/ Union Territory	No. of schemes	Financial assistance	ARC commitment	Commitment of State Govern- ments/ Banks
I. NORTHERN REGION Delhi Haryana Himachal Pradosh Jammu & Kashmir Punjab Rajasthan	1 26 1 1 15 16	76 3704 6 34 702 990	61 3171 6 26 566 851	15 533 — 8 136 139
	60	5512	4681	831
II. NORTH-EASTERN REGION A55am Meghalaya Nagaland	3 2	80 5	, 78 5 —	2
	5	85	83	2
III. EASTERN REGION Bihar Orissa West Bengal	28 38 9	2294 1844 142	2069 1684 127	225 160 15
,	75	4280	3880	400

Region/State/Union Territory	No. of schemes	Financial assistance	ARC commitment	Commitment of State Govern- ments/Banks
IV. CENTRAL REGION Madhya Pradesh Uttar Pradesh	38 75	922 4273	795 3714	127 559
	113	5195	4509	686
V. WESTERN REGION Goa Gujarat Maharashtra	14 15 175	54 748 2787	43 623 2357	11 125 5430
	204	3589	3023	566
VI. SOUTHERN REGION Andhra Pradesh Karnataka Kerala Pondicherry Tamil Nadu	49 36 51 1 29	3329 850 225 6 514	2960 685 184 6 428	369 163 41 86
	166	4924	4263	661
Total (I to IV)	623	23585	20439	3146

Statement 4 SANCTIONS DURING 1974-75—AGENCYWISE

Rs. lakhs

Agency		No. of schemes	Financial assistance	ARC commitment	Commitment of State Govern- ments/Banks
State Land Development Banks		116	12883 (54 · 6)	11469 (56·0)	1414
Scheduled Commercial Banks		501	10452 (44 ·3)	8741 (42 · 9)	1711
State Co-operative Banks		6	250 (1·1)	229 (1·1)	. 21
	Total	623	23585 (100·0)	20439 (100 ·0)	3146

Figures in parenthesis are percentage of the total.

Statement 5 DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1975—PURPOSEWISE

Purpose		No. of schemes	Financial assistance	ARC commitment	Commitment of State Governments, Banks	Disburse- ment
Minor irrigation		1139	74312	66661	7651	33822
Land development/Reclamation/Soil conservation		91	8138	6416	1722	3003
Farm mechanization		244	6679	5219	1460	1893
Plantation/Horticulture		262	5251	4136	1115	1329
Poultry/Sheep breeding		56	327	270	57	96
Fisherics		97	1480	1092	388	464
Dairy development		119	2165	1807	358	305
Storage/Market yards		44	2355	2125	230	1383
Agricultural aviation	•	1	16	12	4	1
	Total	2053	100723	. 87738	12985	42307

Statement 6
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1975 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

<u> </u>				Einon	ARC Con	nmitment	,	Disbursen	ent
Region/State/Union	Agency Code	Purpose	No. of schemes	Finan- cial assis-	Total	Phasing	— ———	During 1974-75	Upto 30 June
Territory	Code		schemes	tance		Upto 1974-75	During 1974-75	19/4-73	1975
I. NORTHERN REGION									
Delhi	2	FM P/SB	2	91 20	73 16	35 16	30	11	17
		$\mathbf{D}\mathbf{D}$	1	28	28	17	9	1	2
	3	P/SB	1	12	12	12			6
			5	151	129	, 80	39	12	25
Haryana	1	MI LD	32	4818 234	4337 194	2693 106	743 84	431 17	2658 20
		FM	32 2 2 2	558 54	419 40	419	382	174	211 30
	2	P/H ; Mľ	29	1859	1533	1533	799	258	785
		FM P/SB	14 2	564	42 5 17	425		152 2	159 2
		DD	8	328	286	76	- 50	24	29
	3	DD S/M	2 3	130 243	108 243	108 243	18	17	15 243
			96	8806	7602	5650	2471	1075	4152
Himachal Pradesh	1	P/H	1	37	28	10	6	4	8
	2	P/SB DD	1 1	63	. 6	3	2		·
			3	46	37	15	8	4	8
Jammu & Kashmir	1	LD	1				3	<u></u>	
		FM P/H	1 3	34 130		89		_	$\overline{71}$
	2	P/SB DD	2 1					=	_
			8	190	148	105	12		71
Punjab	1		28	3148	2856			109	
		LD FM	11 2 2	638 190	143	143	_	114	167 114
	2	P/H MI	2 10						
	_	FM P/SB	20	237	179	179	157		118
		DD S/M	6	129	_				
	3		1	18	16	5 16	16		
		DD S/M	4		7 89 7 730) 32 93	22	
			90	6422	5605	5 4937	859	407	3751
Rajasthan	1	MI LD	42	2493	2297	1400	561	209	751
		P/H	2	1 39	340	9 20) 9	1 3	
	2	2 MI LD	8	311 2 218	1 248 3 174	4 _			
		FM P/SP	<u>'</u>	3 100) 7:	9 39		30	
		MI LD FM P/SB S/M		7 230		3 13	9 9	33	$\overline{53}$
			68	3850	3354	4 2028	83.5	350) 1012
			270	1946	1687:	5 1281.	5 4224	1848	9019

Statement 6 (Contd.)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1975 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

				Α	RC Comn	nitment	Disbursement		
Region/State/Union	Age- Purpose	No. of '	Finan- cial		Phasing	;	ر <u>-</u> _		
Territory	ncy Code	schemes	assis- tance	Total -	Upto 1974-75	During 1974-75	During 1974-75	Upto 30 June 1975	
11. NORTH-EASTERN REGION Assam	1 P/H		5	4	1	1			
	2 MI	2	127	124	88	88	_	_	
	FM P/H∦	1 8	3 160	3 138	138	_	· —	134	
	DD S/M	1 1	11 29	11 26	2 14	2 14	_ -	_	
	3 P/H	1	6	6	6		_		
•	····	15	341	312	249	10.5	5 <u>-</u>	13	
Meghalaya	3 P/SB DD	. 2	5 2	5 2			_		
		3	7	7	2				
Nagaland	3 LD	1	30	30	16	8	4	. 8	
		19	378	349	267	113	. 4	142	
III. EASTERN REGION									
Bihar	1 MI LD	11 1	3599 112	3238 83	1578 83	891	712	1390 83	
	P/H 2 MI	1 25	14 2065	11 1833	1 787	1 397	74	277	
	LD FM	1 4	4 227	4 189	1 127	1 92	61	. <u>-</u> 9 6	
	S/M 3 DD	12 2	340 70	305 53	177 32	177 23	85	85	
		17	6431	5716	2786	1582	932	1931	
Orissa	1 MI	9	J448	1327	159		29	29	
,	LD FM	5 1	95 80	72 60	41 30	20	7	' 8	
	P/H 2 MI	8 25	244 1129	192 1065	110 96	30 83	4 2 0		
	LD	3	92	77	44	32	7	7	
	FM P/H	1 3	25 86	20 73	8 21	5 11	1 2	. 2	
	$^{ m DD}$	1	9	8	2	2		–	
	3 F DD	1 1	18 19	18 19	11 6	7 4			
		58	3245	2931	528	366	82	137	
West Bengal	1 MI	. 10	298	273	160		28		
	P/H 2 MI	6 7	48 63	44 56	14 50	20	20	38	
	FM P/H	4	71 28	64	26	26 8	ϵ	i (
	F	$\frac{3}{2}$	2 2 9	24 2	14 2 4		11 1		
	DD	2		8		_			
		34	519	471	270	163	69		
		149	10195	9118	3584	2111	1083	2180	
IV. CENTRAL REGION	4 3.57	0.5	£ 000	F310	A # 0 -	1.000			
Madhya Pradesh	1 MI LD	82 3	5888 166	5310 125	3586 89	1630 47	7 9 6	1871 11	
	FM	1	100	75	75	_	28	71	
	2 MI FM	91 18	3411 329	3048 263	1879 91	1117 91	31 <i>6</i> 94		
	DD 3 S/M	1 1	10 27	8 20	1 20	1 9		_	
	,	197	9931	8849	5741		123	4 255	

Statement 6 (Contd.)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1975 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

				 _					ls. lakhs
		<u></u>		Finan-	ARC C	ommitment		Disbursen	ent
Rogion/State/Union Territory	Agency Code	Purpose	No, of schemes	cial assis-	Total	Pha		During 1974-75	Upto
				tance		Upto 1974-75	During 1974-75	1974-75	30 June 1975
Uttar Pradesh	1	MI	114				1735	1326	4715
		LD P/H	2 8	10 182			$\frac{1}{26}$	_	2
	2	MI	49	1418			463	186	245 134
		LD FM	1 77		1501	662	446	10 320	487
	_	DD	5				23	7	32
	3	DD S/M	2 1					_	150
			259	16123	3 14174	7785	2710	1849	5765
			456	26054	4 2302:	3 13526	5605	3083	8322
V. WESTERN REGION									
Goa	2	Mi F	1 15	5 5:	5 5 4	3 4 7	, <u> </u>	5	3 5
			16	5 60) 4	7 10	6	5	8
Gujarat	1	MI	51			7 5427	_	313	4314
		FM P/H	1 2			3 263 2 22			233 22
	2	MI	1	I	1	1 1	. —		. 1
		FM F	2 9	9 61 1 1) 178 3 3		
		DD S/M		2 20	9 17	4 90	5 58	3 32	78
		F		2 19	8 17	0 10 19 7	7 69	5 =	
		S/M			2		2 –		2
			9		65	78 618	1 30	8 427	4800
Maharashtra	1	MĬ LD	4:	5 52 5 8 41					3706 198
		FM			57 .	50			_
	2	P/H 2 MI	19						
	-	$\mathbf{F}\mathbf{M}$	4	0 43	33 33	13	8 8	1 22	2 22
		P/H P/ SB		6 3	[1 31 ;	23 2	3 1		23 - 7
		F DD				10 22 15	4 10	1 - 6 8	- 7 4 90
		S/M		1 :	70 :	56 5	4 1	8	9 47
	:	3 F					4 2		
			36						
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradosh		1 MI	11	10 49	85 45	12 280	50 117	74 71	2 2615
		1 MI LD P/H	- 2	20 19	66 15	96 150	58 11	10 5	0 1285
		P/SB		1	14	10	3	3 -	9 23
		DD		2	44	33		-	
		2 MI LD	,	1	50	38	38 -	16 9 	$\frac{207}{2}$ $\frac{203}{3}$
		FM P/SB		4 1	24 1	00	72		.1 13
		DD			77 1 74 1	60 43		4.4	$\frac{3}{2}$
		3 F		1	48				
			2	210 84	170 73	351 54	02 16	68 89	92 420

Statement 6 (Contd.)

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1975 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE Rs. lakhs

				Finan-		ARC Com	mitment	Disbur	sment
Region/State/Union	Agency	Purpose	No. of	cial	Total	Ph	asing	During 1974-75	Up to
Territory	Čode		schemes	assis- tance	Total	Upto 1974-75	During 1974-75	1974-73	30 June 1975
Karnataka	1		15	4594	4183	4061	545	717	2177
		LD P/H	13 26	1531 1079	1148 809	1092 637	197 99	34 44	493 312
	2	Μl	23	398	359	312	223	22	39
		LD	3	84	63 409	45	25 177	55	62
		FM P/H	13 82	515 450	368	216 220	64	28	136
		P/SB	15	44	36	28	23	16	19
		F DD	6 9	111 62	90 50	72 32	72 20	44 —	44
		S/M	9	243	185	114	92	12	29
	3	P/H	.2	165	165	165	_		25
	_	F	$\overline{2}$	208	143	143	6		137
		S/M	2	132	113	71	41	36	66
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	1 1 1 -1 -1 -	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	220	9616	8121	7208	1584	1008	3539
Kerala	1	MI	2	74 99	69 7 4	58 50	11 30	_	47 13
		LD P/H	4 20	691	518	216	50 67	6 4 3	139
	2	MI	1	39	30	30	9	13	29
	2	LD	1	375	375	375	335		40
		FM	2	28	22	22	22	7	7
		P/H	19	144	135	127	8	2	109
		P/SB	3	12	11	9	4	_	_
		\mathbf{F}_{-}	40	66	53	52	52	28	28
		DD	3	14	13	13	6	1	1
	3	P/SB F	1	22 204	22 154	11 119	11 16	_	48
			99	1769	1476	1082	571	100	461
Pondicherry	1	ΜI	1	16	16	16			
	2	ΜI	1	6	6	6	6	_	_
	~	DD	3	45	40	32	21	3	11
	3	F	1	22	15	15	15	12	12
		-	6	89	77	69	42	15	23
Tamil Nadu	1	MI	78	5342	4833	4474	690	662	4164
		LD	3	629	472	472	7	12	469
		P/H	15	902	676	218	101	37	118
	2	LD	1	5	4	4			3
		FM	2		16	2	2		<u> </u>
Tamil Nadu (Contd.)		P/H	35	162	149	139	12	13	124
		F	12	235	184	149	139	52	57
		P/SB	1	1	1 49	. 1 32	1 21		1
		DD AA	5 1	60 16	48 12	12		_1	5 12
	3		2	104	74	64		20	46
	J	F P/SB	1	51	38	38	21 38	20	20
			156	7527	6507	5605	1032	817	5019
			691	27471	23532	19366	4897	2832	13247
					87738	60873	18754		

Statement 7

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1975—AGENCYWISE

Rs, lakhs

Agency	No. of schemes	Financial assistance	ARC commitment	Commitment . of State Govts/Banks	Disbursoment
State Land Development Banks	826	71179 (70 ·7)	62840 (71 ·6)	8339	35060
Scheduled Commercial Banks	1176	26555 (26 ·4)	22322 (25 · 4)	4233	5740
State Co-operative Banks	51	2989 (2·9)	2576 (3·0)	413	1507
Total	2053	100 723 (100·0)	87738 (100·0)	12985	42307

Pigures in parenthesised italics are percentages of the total.

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD/MFAL AGENCIES UPTO 30 JUNE 1975

Region/State/Union	Agency	Purposo	No. of	Financial -	ARC	Commit	mont	Disbusrset	nent
Territory		- 6		assistance	Total	Phasing	i	During	Upto
					· · · · ·	Upto 1974-75	During 1974-75	1974-75	30 June 1975
I. NORTHERN REGION									
Deihi Haryana	Com, Bk, SLDB Com, Bk,	DD LD P/SB DD	1 1 1 3	28 17 11 112	28 17 11 112	17 10 2 34	17 5 2 27	1 - 2 16	$\frac{2}{\frac{2}{16}}$
Himachal Pradesh	Com. Bk.	P/SB DD	1 1	6	6	2 2	2 2	_	
Jammu & Kashmir	SLDB Com, Bk.	LD P/SB P/SB DD	1 1 1 1	6 3 6 10	6 3 6 10	2 3 3 7	2 2 1 5		-
Punjab	SLDB Com. Bk.	MI P/SB DD	4 ! 5	228 1 96	228 1 96	228 	$\frac{72}{32}$	45 8	109
Rajasthan	SLDB	MI	5	540	540	348	209	117	204
			27	1067	1067	714	378	189	355
II. NORTH-EASTERN REG	ION								
Assam	Com, Bk.	MI DD	? 1	98 11	98 11	66	66 2	_	_
Meghalaya	SCB	P/SB DD	2	5 2	5 2		<u>-</u>	-	
			6	116	116	68	68		
III. EASTERN REGION									
Bihar	Com, Bk,	MI	1	61	61	18	18		_
Orissa	SLDB Com, Bk,	MI MI P/H DD	3 2 2 1	242 397 14 5	242 397 14 5	41 59 1 1	41 47 1 1	12 —	5 12
	SCB	ΩQ	1	16	16	5	3	-	_
West Bengal	SLDB	MI P/H	4 3	49 21	49 21	29 4	12 3	6	16
	Com, Bk,	MI DD	3 1	19 5	19 5	15	7 2	10	10 3
			21	829	829	175	135	36	46

Statement 8—(contd.)

SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD/MFAL AGENCIES UPTO 30 JUNE 1975

Rs. lakhs

		D	N I - C	122	ARC	Commitm	nont	Dinks	
Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	No. of schemes	Financial assistance	Total	Phas	ing		rsement
					-	Upto 1974-75	During 1974-75	During 1974-75	Upto 30 June 1975
IV. CENTRAL REGION									
Madhya Pradesh Uttar Pradesh	SLDB SLDB Com. Bk.	MI MI MI DD	7 7 1 1	242 773 12 15	242 773 12 14	164 634 10 14	83 163 5 8	104	525 1
			16	1042	1041	822	259	104	526
V. WESTERN REGION		•							<u> </u>
Gujarat Maharashtra	Com. Bk. SLDB Com. Bk.	DD MI P/H DD	1 9 1 1	12 106 97 5	12 16 97 5	106 11 5	55 7 3		9 2
			12	220	220	122	65	10	11
VI. SOUTHERN REGION									
Andhra Pradesh	SLDB Com. Bk.	MI MI P/SB DD	3 1 1	257 18 8 31	257 18 8 28	223 10 3 18	82 7 3 18	63 1 —	106 2 —
Karnataka	SLDB Com. Bk.	MI MI P/SB	3 2	484 54 4	484 53 4	464 37 2	112 31 2	69 —	244 —
Kerala	Com. Bk.	P/SB DD	2	8 7	8 7	8 7	3 3	=	Ξ
Pondicherry	SCB SLDB Com, Bk,	P/SB MI DD	 	22 16 20	22 16 20	11 16 20	$\frac{11}{13}$		
Tamil Nadu	SLDB	MI	4	158	158	138	77		2 <u>ĭ</u>
			22	1087	1083	957	362	133	379
Total (I to VI)			104	4361	4356	2858	1267	472	1317

Statement 9

IDA/IBRD PROJECTS—BRIEF DESCRIPTION OF EACH PROJECT

The agricultural credit projects assisted by the World Bank envisage large investments in minor irrigation (such as dugwells, dug-cum-borewells, shallow, medium and deep tubewells, lift irrigation units the installation of pumpsets, laying of pipelines and incidental land levelling), land development and financing the purchase of imported and indigenous tractors, harvesters and combines. In the case of other projects, the names would indicate the items of development proposed to be undertaken under each of them. ARC Credit Project is of a general nature supporting the lending activities of the Corporation in minor irrigation and other approved diversified purposes.

Brief particulars of each project showing the total cost, IDA/IBRD assistance, assistance to be routed through the Corporation, agencies implementing the project, outline description of the nature of development envisaged and progress of the projects are given below:

- 1. A. ARC Credit Project.*
 - B. Cost of the Project—\$ 168.5 million (Rs. 135 erores)—IDA assistance \$ 75 million (Rs. 60 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. Financing programme of agricultural lending supporting the activities of the Corporation for investments in minor irrigation and other diversified

forms of lending training of personnel of institutions associated with the implementation of the project and a study on the feasibility of merging the short-term and long term co-operative credit institutions in the country.

- D. State co-operative land development banks, state co-operative banks and scheduled commercial banks.
- E. Two years-closing date 31 December 1977.
- F. Action has been initiated by ARC towards fulfilment of conditions precedent to effectiveness of the credit. The subsidiary loan agreement with the Government of India has been signed. A programme for training of officials, of financing institutions, particularly LDBs has been forwarded to GOI. Terms of reference and composition of the committee for monitoring LDB financial performance and issuance of debentures have been conveyed to GOI. A general circular has been issued to the various agencies detailing the features of the project.
- 2. A. Andhra Pradesh Agricultural Credit Project.
 - B. Cost of the Project—\$ 45 million (Rs. 33.8 crores)—IDA assistance \$ 24.4 million (Rs. 18.3 crores)—\$ 24.2 million (Rs. 18.1 crores) to be routed through the Corporation
- A: Name of the Project. B: Cost of legend Project, IDA assistance and amount to be routed through ARC.
- C: Project description. D: Implementing agency. E: Period of implementation. F: Progress of the Project.

* Indicates projects sanctioned during 1974-75.

- C. Financing minor irrigation investments, land development and farm mechanization equipment.
- D. Andhra Pradesh Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd. and selected commercial banks.
- E. Three years—closing date 30 June 1974; since extended to 30 June 1975 and closed as on that date for minor irrigation and land development. Further extended to 30 June 1977 for farm mechanization equipment.
- F. Project completed except for farm mechanization programme. Formalities for procuring tractors nave been completed,
- 3. A. A Bihar Agricultural Credit Project.
- B. Cost of the Project—\$60 million (Rs. 45 crores)—1DA assistance \$32 million (Rs. 24 crores) to be routed through the Corporation.
- C. Minor irrigation programme including sinking of tupewells, installation of diesel pumpsets for low inft pumping from surface water.
- D. Bihar State Co-operative Land Development Bank Ltd. and selected commercial banks.
- E. Three years—closing date December 1976,
- F. The SLDB has made disbursement of the order of Rs, 8.5 crores. Certain constraints such as delay in receipt of technical celarance from MID and non-implementation of Talwar Committee recommendations have slowed down the progress.
- 4. A. Bihar Market Yards Project.
 - B. Cost of the Project—\$23.3 million (Rs. 16.9 crores)
 —IDA assistance—\$ 14 million (Rs. 10.1 crores)—
 \$ 13.8 million (Rs. 10 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. For investment in market facilities in about 50 towns in Bihar including civil works such as construction of entrance, roads, surfacing, fencing, godowns, traders' shops etc.
 - D. State Bank of India.
 - E. Five years-closing date 30 June 1978.
 - F. The Corporation has made the first disbursement of Rs. 84 lakhs under the project. The Corporation has accorded sanction for 13 markets. The slow progress in implementing the project is attributed mainly to delays in acquiring lands for market yards and handing over possession thereof to the market committees. The issue is being sorted out.
- 5. A. Gujarat Agricultural Credit Project.
 - B. Cost of the Project—\$67 million (Rs. 50.2 crores)— 1DA assistance \$35 million (Rs. 26.3 crores) of which \$34.7 million (Rs. 25.3 crores) to be provided through the Corporation,
 - Financing of minor irrigation investments and farm mechanization equipment (tractors) and groundwater study.
 - D. Gujarat State Co-operative Land Development Bank Ltd.
 - E. Three years—closing date 30 June 1974 was extended to 31 March 1975.
 - F. The project has since been completed. Repeater Project is being formulated by the state government.
- 6. A. Haryana Agricultural Credit Project.
 - B. Cost of the Project—\$62.2 million (Rs. 45.2 crores)
 —IDA assistance \$25 million (Rs. 18.2 crores) to
 be routed through the Corporation.
 - C. Financing of minor irrigation investments comprising installation of shallow tubewells and imported and indigenous farm mechanisation equipment viz., tractors, harvesters and self-propelled combines.
 - D. Haryana State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd. and selected commercial banks.

- E. Inrec years—closing date 31 March 1975 since extended upto 31 March 1976.
- F. Minor irrigation programme originally contemplated under the project was fully utilized. A credit reallocation of \$8 million from tractor category to minor irrigation category was approved by IDA. A small balance of this programme remains to be completed. Haryana Agro-Industries Corpoartion has placed orders with suppliers for 2,800 tractors.
- A. Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing Project. (ARC programme).
 - B. Cost of the Project—\$ 21.5 million (Rs. 16.1 crores)—IDA assistance \$ 13 million (Rs. 9.8 crores)—IDA assistance to be routed through the Corporation is Rs. 3.7 crores.
 - C. To finance improvements in the appie processing and marketing industry in Himachal Pradesh through establishment of Horticultural Produce Processing and Marketing Corporation—Assistance will cover construction of packing houses, collecting station, transhipment centre, cold storage units and juice concentrate plant. Erection of aerial ropeways and construction of new roads for timely transport of produce are also envisaged.
 - D. Selected commercial banks,
 - E. Four years—closing date 31 December 1978.
 - If. Tentative allocation has been made among the three participating banks for financing 12 packing houses, 3 collection centres and 4 cold storage units. The manner in which these items are to be financed is being finalised.
- 8. A. Karnataka Agricultural Credit Project.
 - B. Cost of the Project—\$75.4 million (Rs. 54.9 crores)
 —IDA assistance—\$40 million (Rs. 29.1 crores) of
 which \$37.7 million (Rs. 30.8 crores) to be routed
 through the Corporation.
 - C. Financing of minor irrigation investments and land reclamation and purchase of tractors and land reclamation equipment.
 - D. Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd. and selected commercial banks.
 - E. Three years—closing date 31 October 1975 since extended to 31 December 1976.
 - F. A sizeable portion of minor irrigation component has been disbursed. Formalities for purchase of tractors been disbursed. Formalities for purchase of tractors The financing banks have collected applications for about 2,800 tractors against a provision of 2,000 tractors.
- 9. A. Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project.
 - B. Cost of the Project—\$13 million (Rs. 9.5 crores)—IDA assistance \$8 million (Rs. 6.4 crores)—\$7.9 million (Rs. 6.4 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. Market facilities including civil works, structures, utilities, equipment, etc.
 - D. Selected commercial banks.
 - E. Five years—closing date 31 December 1979.
 - F. The Corporation has approved 7 markets involving financial assistance of Rs. 1.3 crores.
- 10. A. Karnataka Dairy Development Project.
 - B. Cost of the Project—\$43.5 million (Rs. 34.8 crores)
 —IDA assistance—\$30 million (Rs. 24 crores) of which \$20.9 million (Rs. 16.7 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. An integrated programme for increasing the production of milk in rural areas of Karnataka state by providing technical services for quality cross-breeding and animal health and the development of facilities for milk collection, processing and marketing.
 - D. Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd., Karnataka State Co-operative Apex Bank Ltd., and selected commercial banks.

- E. Eight years—closing date 31 March 1982.
- F. The Corporation has drawn up a banking plan for financing four dairy unions. The Karnataka Dairy Development Corporation has appointed spearhead to the corporation has appointed spearhead teams to identify milk routes in the project areas.
- 11. A. Madhya Pradesh Agricultural Credit Project.
 - B. Cost of the Project—\$60.3 million (Rs. 45.2 crores)
 —IDA assistance—\$33 million (Rs. 25 crores) to
 be routed through the Corporation.
 - C. Financing the on-farm investments including construction of dugwells, improvement in existing wells, installation of electric and diesel pumpsets and persian wheels and incidental land leveiling.
 - D. Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank Ltd. and selected commercial banks.
 - E. Three years-closing date 31 December 1
 - F. The LDB/PCBs have disbursed Rs. 18 crroes. Progress is satisfactory. However, the pace of dirbursed ments was recently affected by delays in getting electric connections, payment of stamp duty by certain borrowers of PCBs etc. The issues are receiving attention of the State Government. ing attention of the State Government.
- 12. A. Madhya Pradesh Dairy Development Project.*
 - B. Cost of the Project—\$31.2 million (Rs. 25 crores)
 IDA assistance \$16.4 million (Rs. 13.1 crores)—
 \$13.7 million (Rs. 10.9 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. Scheduled commercial banks.
 - D. Scheduled commercial banks.
 - E. Six years—closing date 30 June 1982.
 - F. Banking Plan has been finalised, State Government has initiated a training programme for officers connected with project implementation.
- 13. A. Madhva Pradesh Chambal Command Area Development Project.*
- B. Cost of the Project—\$45.8 million (Rs. 36.6 crores)—IDA assistance \$24 million (Rs. 19.2 crores)—\$3.1 million (Rs. 2.5 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. Irrigation and drainage works, on-farm development, roads, ravine erosion control, mechanical equipment and technical assistance.
 - D. Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank Ltd. and scheduled commercial banks.
 - E. Three years—closing date 31 December 1979.
 - F. The Project has been recently sanctioned by IDA.
- 14. A. Maharashtra Agricultural Credit Project.
 - B. Cost of the Project-\$52.4 million (Rs. 38.2 crores) —IDA assistance \$30 million (Rs. 21.8 crores)— \$25.4 million (Rs. 18.5 crores) to be routed through
 - C. Minor irrigation programme including tubewells, lift irrigation, dugwells, dugwell improvements, energi-sation of wells and land levelling investments.
 - D. Maharashtra State Co-operative Land Developments Bank Ltd. and selected commercial banks,
 - E. Three years—closing date 31 December 1975.
 - F. The propress in carrying out the dugwells programme is satisfactory. The State Groundwater Survey and Development Agency has carried out detailed studies on elementary watersheds throughout the state. Credit for project equipments will be routed through the ΛRC .
- 15. A. Punjab Agriculutral Credit Project,
 - B. Cost of the Project—\$40 million (Rs. 30.1 crores)— IDA assistance \$27.5 million (Rs. 20 crores) to be provided through the Corporation.
 - C. Financing the purchase of imported and indigenous tractors, harvesters and self-propelled combines.

 D. Puniab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
 - and selected commercial banks.

- E. Two years-closing date which was carlier stipulated as 37 December 1972 was extended upto 31 December 1973 and further extended by two years upto 31 December 1975.
- F. Distribution of first lot of 1,000 tractors under the Project was completed. The response for the second lot of tractors (4,000) is good.
- 16. A. Chambal Command Area Development Project RC Programme)—Rajasthan.
 - B. Cost of the Project—\$12 million (Rs. 9.6 crores)—IBRD assistance \$6.5 million (Rs. 5.2 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. The Project would include drainage, lining of canals, increasing the capacity of canals, building or im-proving control structures, on-farm development including irrigation and drainage ditches, land shaping, construction of roads, afforestation and erosion control and supply of fertilizers.
 - D. Selected commercial banks.
 - E. Six years—closing date 30 June 1981.
 - F. State Government have set up a Command Area Development Authority. Plans for development on 'chak' basis are being drawn up in consultation with the Corporation.
- 17. A. Rajasthan Canal Command Area Development Project (ARC programme)
 - B. Cost of the Project—\$39.8 million (Rs. 31.8 crores)—IDA assistance \$22.5 million (Rs. 18 crroes) to be routed through the Corporation.
 - C. The Project would cover lining of distributory canals, construction of roads, pasture development, afforestation, provision of fertilizers and on-farm development including land shaping, reclamation and lining of water courses.
 - D. Selected commercial banks
 - E. Five years—closing date 30 June 1980,
 - F. State Government have set up a Command Area Development Authority. Plans for development on 'chak' basis are being formulated in consultation with the Corporation.
- 18. A Rajasthan Dairy Development Project.*
 - B. Cost of the project—\$51.8 million (Rs. 41.4 crores) IDA assistance \$27 million (Rs. 21.6 crores) \$22.3 million (Rs. 17.2 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. Formation of about 1.800 Dairy Co-operative Societies grouped in 5 milk producers' unions equipped with dairy and feed plants.
 - State Land Development Bank. State Co-operative Bank and scheduled commercial banks.
 - E Seven years—closing date 31 December 1982.
- F. Banking Plan is being finalized.
- 19. A. Tamil Nadu Agricultural Credit Project.
 - B. Cost of the Project—\$62.3 million (Rs. 46.8 crroes)
 —IDA assistance \$35 million (Rs. 26.2 crores) of which \$29.8 million (Rs. 22.9 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. Financing of minor irrigation investments including sinking of filter point wells, shallow and medium tubewells, land levelling, land drainage and tractors.
 - D. Tamil Nadu State Co-operative Land Development Bank Ltd.
 - Three years-closing date 31 December 1974 since extended upto 31 December 1976.
 - F. Minor irrigation component of the credit (including amounts reallocated from land development and land drainage) has been fully drawn. Credit allocation in respect of farm mechanization programme has not been utilized; hence the closing date of the Project is extended. The Government of Tamil Nadu and the LDB have taken on hand the procurement of tractors and have advised the PLDBs

- to collect loan application from farmers according to their choice of models.
- 20. A. Tatai Seeds Project-Uttar Pradesh.
 - B. Cost of the Project—\$22.4 million (Rs. 16.8 crores)— —1BRD assistance \$13 million (Rs. 9.8 crores)— \$9 million (Rs. 6.8 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. Land development in the Tarai area of Uttar Pradesh with a view to increasing the availability of high yielding varieties of foodgrains.
 - D. State Bank of India.
 - E. 30 June. 1974.
 - F. Extension of closing date of the Project is to be taken up with GOI.
- 21. A. Uttar Pradesh Agricultural Credit Project.
 - B. Cost of the Project—\$72.5 million (Rs. 54.3 crores)
 —IDA assistance \$38 million (Rs. 28.5 crores) to be routed through the Corporation.
 - C. Financing of on-farm investments such as construction of masonry wells or dugwells shallow tubewells, medium depth tubewells, persian wheels and installation of electric and diesel pumpsets.

- D. Uttar Pradesh State Co-operative Land Development Bank Ltd. and selected commercial banks.
- E. Three years-closing date 31 December 1976.
- F. The LDB/PCBs have disbursed Rs. 15.5 crores. Progress in loaning is quite satisfactory.
- A. West Bengal Agricultural Development Credit Project*.
 - B. Cost of the Project—\$59 million (Rs. 47 crores)—IDA assistance \$34 million (Rs. 27.2 crores)—\$15 million (Rs. 12 crores) will be routed through the Corportaion.
 - C. Construction of shallow and deep tubewells, establishment of agro-service centres, development of markets and completion of river lift irrigation.
 - D. West Bengal State Co-operative Land Development Bank Ltd., scheduled commercial banks and West Bengal State Minor Irrigation Corporation.
 - E. Four years-closing date 31 March 1980.
 - F. Subsidiary Loan Agreement with GOI has been signed. Preliminaries towards fulfilling the conditions of effectiveness of the credit are being completed. Guidelines to participating banks and switching over of schemes already financed by them are under preparation.

Statement 10 POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1975

Rs lakhs

							Rs. lakhs
	Project	Purpose	Total lending programme	Amount of IBRD/IDA assistance admissible to ARC	Disburse- ment by PLDBs/ PCBs	Disburse- ment by ARC	Amount received from Government of India.
	D PROJECTS Tarai Seeds Project (Uttar Pradesh)	LD	927	675	182	134	125
(b)	Chambal Command Alea Development Project (Rajasthan)	LD	619	520	_		_
	,		1546	1195	182	134	125
B. IDA	PROJECTS						
(a)	ARC Credit Project	MI Other	11100	5520	_	٠ ـــ	_
		purposes	900	400			
			12000	5920			
(b)	Agricultural Credit Projects						
	1. Andhra Pradesh	MI	2111	1393	2413	1872	} 137°
		LD FM	230 383	154 383	252	151	_
		_	2724	1930	2665	2023	1377
	2. Bihar	MI	3943	2400	848	790	449
	3. Gujarat	MI	4027	2344	4027	3635 ე	2550
		FM	351	182	319	239 }	2530
			4378	2526	4346	3874	255
	4. Haryana	MI MI	1962	903	1852	16897	
		FM	1433	917	139	304	80:
			3395	1820	1991	1993	80
	5. Karnataka	MI	2548	1682	1963	1665	} 1120
		Ľ D FM	768 820	574 8 2 0	209	126	
			4136	3076	2172	1791	1120

Continued....

Statement 10 (Contd.)

POSITION OF IBRD/IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1975

Projec	rt	Purpose	Total lending programme	Amount of IBRD/IDA assistance admissible to ARC	Disburse- ment by PLDBs/ PCBs	Disbursc- ment by ARC	Amount received from Government of India.
6. M	adhya Pradesh	MI	3763	2395	1809	1388	835
		& LD	158	100	} 1809	1368	633
			3921	2495	1809	1388	835
7. M	aharashtra	ΜI	2748	1651	2699	2429	1561
		LD	415	198		<u></u>	1301
			3163	1849	2699	2429	1361
8. Pu	njab	FM	4002	2002	305	223	186
9. Tai	mil Nadu	·MI	3001	1861	3001	2762	1022
		LD	88	61	188	52	1922
		FM	702	364	_	_	-
			3791	2286	3089	2814	1922
10. Ut	tar Pradesh	MI	4594	2850	1547	1297	764
11. We	est Bengal	MI	1953	1072	<u> </u>	,	_
		FM S/M	152 85	80 48	_	_	_
	:	_, .	2190	1200			
			40237	24434	21471	18622	11573
ject 2. Him Proc	ar Market Yards Pro-	·	1491	1002	94	84 ,	-
Who	nataka Agricultural olesale Markets Pro-		452	372	_	_	
ject 4. Kar lopr	nataka Dairy Deve- nent Project		792 2750	635 1672	_		
	mbal Command Area elopment Project (M.P.)		1840	246	_		_
5. Cha Dev	·						
Dev 6. Mac	dhya Pradesh Dairy		2497	1091	-	_	
6. Mac Dev 7. Raja man	dhya Pradesh Dairy elopment Project asthan Canal Com- id Area Development		2497 2395	1091 1800	_	_ _	_
6. Mac Dev 7. Raji man Proj 8. Raji	dhya Pradesh Dairy elopment Project asthan Canal Com- id Area Development				- -	_ _	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
6. Mac Dev 7. Raji man Proj 8. Raji	dhya Pradesh Dairy elopment Project asthan Canal Comda Development ject asthan Dairy Deve-		2395	1800		84	<u>-</u>

Statement 11
DISBURSEMENT DURING 1974-75 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs Contribution Debentures Total amount of debentures floated/loans subscribed to/ loans disbursed of State Region/State/Union Agency Purpose Governments/ Territory Banks raised by ARC I. NORTHERN REGION Farm mechanization 3 14 11 Delhi Com. Bk. Dairy development 1 15 12 3 Minor irrigation Land development 47 431 SLDB 478 Haryana 17 230 56 Farm mechanization 174 287 258 29 Minor irrigation Com. Bk. Farm mechanization Poultry 51 203 152 Dairy development 25 $2\overline{4}$ 1 17 17 **SCB** Storage/Market yards 1264 1075 189 SLDB Plantation/Horticulture 5 4 1 Himachal Pradesh 109 7 SLDB Minor irrigation 116 Punjab Land development 12 64 Farm mechanization 152 114 38 Minor irrigation 34 45 8 Com. Bk. 43 Farm mechanization Dairy development Storage/Market yards 61 16 6 29 23 Storage/Market yards 24 22 2 SCB 497 407 90 Minor irrigation Land development Rajasthan SLDB 220 209 11 2 Plantation/Horticulture 3 5 74 92 18 Com. Bk. Minor irrigation Farm mechanization 37 42 30 7 Storage/Market yards 33 397 350 47 II. NORTH-EASTERN REGION Land development 4 4 SCB Nagaland III. EASTERN REGION SLDB Minor irrigation 791 712 79 Bihar Minor irrigation Com. Bk. 135 74 61 118 61 85 Farm mechanization 57 Storage/Market yards 97 12 1141 932 209 SLDB Minor irrigation 31 29 2 Orissa Land development 7 1 3 2 10 Farm mechanization 4 Plantation/Horticulture 6 Minor irrigation 27 26 1 Com. Bk. Land development Farm mechanization 8 1 3 1 2 1 Plantation/Horticulture 93 82 11

Continued....

Statement 11 (Contd.)

DISBURSEMENT DURING 1974-75 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

Rs. lakhs

Continued

Rogion/State/Union Territory	Адепсу	Purpose	Total amount of debentures floated/loans raised	Dobentures subscribed to/ loans disbursed by ARC	Contribution of State Governments/ Banks/
West Bengal	SLDB	Minor irrigation	31	28	3
	Com. Bk.	Minor irrigation	20	20	_
		Farm mechanization	6	6	_
		Plantation/Horticulture	11	11	_
		Fisheries	1	1	_
		Dairy development	3	3	_
			72	69	3
IV. CENTRAL REGION					
Madhya Pradesh	SLDB	Minor irrigation	881	796	865
		Farm mechanization	37	28	9
	Com. Bk.	Minor irrigation	352	316	36
		Farm mechanization	117	94	23
			1387	1234	153
Uttar Pradesh	SLDB	Minor irrigation	1460	1326	134
	Com. Bk.	Minor irrigation	207	186	. 21
		Land development	12	10	2
		Farm mechanization	406	320	86
		Dairy development	8	7	1
			2093	1849	244
v. Western Region					
Goa	Com. Bk.	Fishories	5	5	w.
Gujarat	SLDB	Minor irrigation	348	313	35
	Com, Bk,	Farm mechanization	100	82	18
		Dairy development	37	32	5
			485	427	58
Maharashtra	SLD B	Minor irrigation	1125	1013	112
	Com. Bk.	Minor irrigation	220	200	20
		Farm mechanization Poultry/Sheep breeding	28 18	22	6
		Dairy development	105	14 84	4 21
		Storage/Market yards	11	9	21
	SCB	Fisheries	16	16	_
		•	1523	1358	165

Statement 11 (Contd.) DISBURSEMENT DURING 1974-75 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE

		······································	Total amount	Debentures	Contribution
Region/State/Union Territory	Agency	Purpose	of debentures floated/loans raised	subscribed to/ loans disbursed by ARC	of State Governments/ Banks
VI. SOUTHERN REGION					
					-
'Andhra Pradesh	SLDB	Minor irrigation Land development	785 167	712 50	73 17
		Plantation/Horticulture	12	9	3
	Com, Bk,	Minor irrigation	114	97	17
		Farm mechanization	14	11	3
		Poultry/Sheep breeding	17	13	4
			1009	892	117
Karnataka	SLDB	Minor irrigation	768	717	51
		Land development	45	34	11
		Plantation/Horticulture	59	44	15
	Com. Bk.	Minor irrigation Farm mechanization	25 72	22 55	3 17
		Plantation/Horticulture	33	28	5
		Poultry/Shoep breeding	19	16	3
		Fisheries	60	44	16
	SCB	Storage/Market yards Storage/Market yards	39 36	12 36	27
	JCB	Stolingo/Market Julus			140
			1156	1008	148
Kerala	SLDB	Land development	8	6	2
		Plantation/Horticulture	57	43	14
	Com. Bk,	Minor irrigation Farm mechanization	16	13	3 1
		Plantation/Horticulture	8 2	7 2	1
		Fisheries	36	28	8
		Dairy development	1	1	-
		•	128	100	28
Pondicherry	Com. Bk,	Dairy development	3	3	,
Politicherry	SCB	Fisheries	12	12	_
			15	15	
- day 1	CI DH	Min - a invitation	736	662	77 A
Tamil Nadu	SLDB	Minor irrigation Land development	16	12	74 4
		Plantation/Horticulture	49	37	12
	Com. Bk,	Plantation/Horticulture	16	13	3
		Fisheries	65 1	52	13
	COR	Dairy development		1 20	_
	SCB	Fisheries Poultry/Sheep breeding	26 27	20	6 7
		-	936	817	119
		m-1 1 (1 / - 1/T)			
		Total (I to VI)	12225	10640	1585

Statement 12
SCHEMES UNDER CONSIDERATION AS ON 30 JUNE 1975

	No	of schemes under consi	deration
Region/State/Union Territory	Total	Complete in most respects	Additiona data required
I. NORTHERN REGION			
Delhi	3	2	1
Haryana	14	4	10
Himachal Pradesh Jammu & Kashmir	5	-	5
Punjab	9	1	8
Rajasthan	43	14	29
	74	21	53
I NORTH-EASTERN REGION	,		
Assam	4	_	4
Meghalaya	9	_	9
Nagaland	_		_
	13		13
III EASTERN REGION			
Bihar	24	16	8
Orissa	60	1	59
West Bengal		32	2
			69
V CENTRAL REGION			
Madhya Pradosh	61	43	18
Uttar Pradosh	52		
	113	<u>62</u>	_
WESTERN REGION			
Goa	2	_	2 .
Gujarat	24 77	3	24
Maharashtra			74
	103	3	100
VI SOUTHERN REGION			
Andhra Pradosh	67	21	46
Karnataka	29	_	29
K e rala	8	4	4
Pondicherry Tamil Nadu		_	 . 25
Y OHIT TARRE	129	25	104
Total (I to VI)	520	136	
TOTAL (C TO AT)	320	130	384

Statement 13

LIST OF SHAREHOLDERS AS ON 30 JUNE 1975 I. RESERVE BANK OF INDIA

II. STATE LAND DEVELOPMENT BANKS (19)

- 1. The Andhra Pradesh Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
- 2. The Assam Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
- 3. The Bihar State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
- 4. The Gujarat State Co-operative Land Development Bank Ltd.
- The Haryana State Co-operative Land Development Bank Ltd.
- The Himachal Pradesh Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
- 7. The Jammu & Kashmir Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
- The Karnataka State Co-operative Land Development Bank Ltd.
- The Kerala Co-operative Central Land Mortgage Bank Ltd.
- 10. The Madhya Pradesh State Co-operative Land Development Bank Ltd.
- 11. The Maharashtra State Co-operative Land Development Bank Ltd.
- The Orissa State Co-operative Land Development Bank Ltd.
- 13. The Pondicherry State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
- 14. The Punjab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
- 15. The Rajasthan Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
- 16. The Tamil Nadu Co-operative State Land Development Bank Ltd.
- 17. The Tripura Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.
- The Uttar Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
- The West Bengal Central Co-operative Land Mortgage Bank Ltd.

III. STATE CO-OPERATIVE BANKS (24)

- 1, The Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd,
- 2. The Assam Co-operative Apex Bank Ltd.
- 3. The Bihar State Co-operative Bank Ltd.
- 4. The Delhi State Co-operative Bank Ltd.
- 5. The Goa State Co-operative Bank Ltd.
- 6. The Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
- 7. The Haryana State Co-operative Bank Ltd.
 - 8. The Himachal Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
 - 9. The Jammu and Kashmir State Co-operative Bank
- 10. The Karnataka State Co-opertaive Apex Bank Ltd.
- 11. The Kerala State Co-operative Bank Ltd.
- 12. The Madhya Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
- 13. The Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
- 14. The Manipur State Co-operative Bank Ltd.
- 15. The Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd. 16. The Nagaland State Co-operative Bank Ltd.
- 17. The Orissa State Co-operative Bank Ltd.
- 18. The Pondicherry State Co-operative Bank Ltd.
- 19. The Punjab State Co-operative Bank Ltd.
- 20. The Rajasthan State Co-operative Bank Ltd.
- 21. The Tamil Nadu State Co-operative Bank Ltd.
- 22. The Tripura State Co-operative Bank Ltd.
- 23. The Uttar Pradesh Co-operative Bank Ltd.
- 24. The West Bengal State Co-operative Bank Ltd.

IV. SCHEDULED COMMERCIAL BANK (62)

- 1. State Bank of India.
- 2. State Bank of Bikaner and Jaipur.

- 3. State Bank of Hyderabad.
- 4. State Bank of Indore.
- 5. State Bank of Mysore.
- 6. State Bank of Patiala.
- 7. State Bank of Saurashtra.
- 8. State Bank of Travancore.
- 9. Allahabad Bank.
- 10. Bank of Baroda.
- 11. Bank of India.
- 12. Bank of Maharashtra.
- 13. Canara Bank,
- 14. Central Bank of India.
- 15. Dena Bank.
- 16. Indian Bank.
- 17. Indian Overseas Bank.
- Punjab National Bank.
- 19. Syndicate Bank.
- 20. Union Bank of India,
- 21. United Bank of India.
- 22. United Commercial Bank.
- 23. Andhra Bank Ltd.
- 24. Bank of Karad Ltd.
- 25. Bank of Madura Ltd.
- 26. Bank of Rajasthan Ltd.
- 27. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
- 28. Belgaum Bank Ltd.
- 29. Benares State Bank Ltd.
- 30. Catholic Syrian Bank Ltd.
- Corporation Bank Ltd.
- 32. Federal Bank Ltd.
- 33. Hindustan Commercial Bank Ltd,
- 34. Karnataka Bank Ltd.
- 35. Karur Vysya Bank Ltd.
- 36. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
- 37. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
- 38, Laxmi Vilas Bank Ltd.
- 39. Narang Bank of India Ltd.
- 40. Nedungadi Bank Ltd.
- 41. New Bank of India Ltd.
- 42. Oriental Bank of Commerce Ltd.
- 43. Punjab & Sind Bank Ltd.
- 44. Purbanchal Bank Ltd.
- 45. Ratnakar Bank Ltd.
- 46. Sangli Bank Ltd.
- 47. South Indian Bank Ltd. 48. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
- 49. United Industrial Bank Ltd.
- 50. United Western Bank Ltd.
- 51. Tanjore Permanent Bank Ltd.
- 52. Vijaya Bank Ltd.
- 53. Vysya Bank Ltd.
- 54. Algemene Bank Netherlands N.V.
- 55. American Express International Banking Corporation
- 56. Bank of America Trust and Savings Association.
- 57. Bank of Tokyo Ltd.
- 58. Banque National De Paris.
- 59. Chartered Bank.
- 60. Grindlays Bank Ltd.
- 61. Mercantile Bank Ltd.
- 62. Mitsui Bank Ltd.

V. LIFE INSURANCE CORPORATION, INSURANCE AND INVESTMENT COMPANIES, ETC. (4)

- 1. Life Insurance Corporation of India.
- New India Assurance Company Ltd.
- 3. United India Fire & General Insurance Company Ltd.
- 4. Co-operative General Insurance Society Ltd.

REPORT OF THE AUDITORS

We have examined the annexed Balance Sheet of the Agricultural Refinance Corporation as at 30th June 1975 and also the annexed Profit and Loss Account of the Corporation for the year ended upon that date, and report that:

- We have obtained all the information and explanations which we have required and have found them to be satisfactory.
- 2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and shown by the books of the Corporation the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing all necessary particulars and properly drawn up in accordance with the Act and the General Regulations of the Corporation, so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation.

N. M. RAIJI & CO., Chartered Accountants

20th August 1975, Universal Insurance Building Pherozeshah Mehta Road Bombay 400 001

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION

	LIABILITIES							As at 30-6-197-
					•	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1.	Capital							
	Authorised							
	25,000 shares of Rs. 10,000 each			• •			25,00,00,000 ·00	25,00,00,000 -00
	Issued, Subscribed and Paid-up 20,)00 sl	hares of	Rs 10	.000			
	each Paid-up				,		20,00,00,000 -00	15,00,00,000 .00
2.	Reserves and Surplus							.,,.
	Reserve Fund:						,	
	Balance as per last Balance Sheet (No Less: Subvention loan repaid to				 	1,49,73,000 -00		81,61,000 .00
	1973-74 .,) A OFFIELD	31FL 61E	H Hrf	_		14,13,896 -05
		,		,,			_	14,13,070 0.
								67,47,103 -95
	Add: (i) 10% of current profit tra	nefar	red (în	1ermo	o e			
	Finance Act, 1971)					45,00,000 -00		31,00,000 -00
	(ii) Transfer from Profit and 1					77,63,000 .00		51,25,896 ·05
	(,, = 1, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2				··· -	,	_	
				,		•	2,72,36,000 .00	1,49,73,000 .00
	Profit and Loss Account :							
	Profit brought forward					775 -18		464 - 35
	Profit for the year					1,66,23,173 97	•	1,17,51,206 -88
	•				_	1 66 00 040 15	-	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	Law Tunnsformed to Datamore Fund					1,66,23,949 -15		1,17,51,671 ·23
	Less: Transferred to Reserve Fund		• •	•••		77,63,000 -00	_	51,25,896 ·05
	•			•		88,60,949 ·15		66,25,775 -18
	Transferred to Provision for Dividend					88,60,616 -44		66,25,000 -00
					_	·	332 ·71	775 -18
3.	Special Deposit					•	1,78,92,086 -54	1,40,56,386 -54
	_							, ,
4.	Bonds and Debentures					10.02.77.000.00		
	51 % ARC Bonds 1982 I Series 51 % ARC Bonds 1982 II Series	•••	• •	• •	• •	10,93,77,000 .00	•	
	51 % ARC Bonds 1984 III Series	• •	••	••	••	8,52,50,000 ·00 8,25,00,000 ·00		
	54 % ARC Bonds 1985 IV Series	,,	•••	••	••	11,00,000,00 00		
	5‡ % ARC Bonds 1985 V Series			••	••	16,50,00,000 ·00		
	54 % ARC Bonds 1986 VI Series	••			• •	11,00,00,000 ·00		
	6 % ARC Bonds 1984 VII Series			.,		16,50,00,000 .00		
	6 % ARC Bonds 1985 VIII Series					16,50,00,000 .00		
	- 70				_		00 71 77 000 00	(C 01 07 000 00
							99,21,27,000 -00	66,21,27,000 -00
5.	Loans from the Central Government							
	(a) Under Section 19 of the Act	• •	• •	• •	• •	5,00,00,000 ·00		5,00,00,000 -00
	(b) Other loans	• •	• •	, .	·· _	191,62,14,655 ·00		158,50,23,185 00
					_		196,62,14,655 .00	163,50,23,185 -00
			`					
							320,34,70,074 -25	

	BALA	NCE SHEET AS AT	30TH JUNE 1975
ASSETS			As at 30-6-1974
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
. Cash			
(a) In hand	2,385 ·24 24,83,717 ·07		2,321 ·08 7,36,635 ·04
(c) With others: (i) In India	74,454 ·63 —		45,622 84
		25,60,556 94	7,84,578 -96
. Loans			
(a) By way of refinance	63,04,61 375 ·00 —		38,23,13,971 ·00
Less: Provision for Bad & Dodolidi Deois		63,04,61,375 ·00	38,23,13,971 -00
Debentures		343,13,15,482 - 38	271,51,40,033 ·8
Investment in Central Government Securities (At Cost)	J.	~	
Insterest Accrued on Investments			.0
Other Asseis	•		
(a) Furniture, Fixture and Fittings Office Equipment, etc. (Cost upto 30-6-1974) 10,64,731 ·44			8,35,165-92
Add: Additions during the year 3,36,704.04			2,29,728 -52
14,01,435 · 48		-	10,64,894 4
Less: ftems sold/adjusted 5,436·40		_	163 .00
13,95,999 ·08			10,64,731 -44
Less: Depreciation to date 4,36,619.00			3,18,122 ·07
	9,59,380 ·08		7,46,609 -37

1,48,391 66

11,07,771 -74

124 956 -66

406,43,37,414 · 32 30,982,38,583 · 79

Carried Forward

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION

LIABILITIES							As at 3	0-6-1974
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	Р.
Brought Forward	٠.		320,34,70,	074 -25			247,61,8	0,346 ·72
6. Other Borrowings								
(a) From the Reserve Bank of India:								
(i) Long Term	٠.	.,	88,20,00,	000 -000			54,00,0	00.000
(ii) Short Term (Note 2)		••	4,50,00,				11,60,0	0,000 -00
		_			92,70,00	.000 .000	65,60,0	0,000 -00
(b) From Others:								
(i) In India		• •						-
(ii) Outside India	٠.	٠.						_
7. Fixed Deposits ;								
(a) From Central or State Governments						_		
(b) Others	••	• •				_		_
8. Provision for Dividend				•				
Amount transferred from Profit & Loss Account			88,60,	616 · 44			66,2	5,000 00
Add: Payment to be made by Central Gov pursuance of Section 6 read with Section Act (vide Dividend Deficit Account as per	n 28 c	of the		_				_
					88,60,	616 •44	66,2	5,000 00
9. Provision for Taxation (Note 3)	٠.				1,60,59,	341 -00	1,20,5	2,113 .00
10. Other Liabilitires : Sundry Creditors	. <i>.</i>				48,07,3	366 -53	51,0	5,598 -50
Interest accrued but not due on:								
(a) Loans from Central Government					3,09,07,	8 93 -77	2,42,05	,462 -40
(b) Bonds and Debentures					1,48,99,	231 -56	1,09,39	9,231 -59
Contingent Liabilities:								
(a) On account of guarantee given against de ments in connexion with purchase of ca from outside India								
(b) Other items						_		

Notes: 1. Includes Special Reserve Fund in terms of Finance Act, 1971-Rs. 66,50,000/-.

- 2. Short term borrowings are secured by pledge of debentures.
- 3. Provision for Taxation is after adjusting of advance tax paid and tax deducted at source.

K. R. Subrahmanyan Senior Director Finance & Administration Bombay, 19 August 1975 As per our Report of even date attached
N. M. Raiji & Co.

Chartered Accountants

Bombay 20 August 1975

BALANCE SHEET AS AT 30 JUNE 1975

	ASSETS				_			As at 30-6-1974
					<u> </u>	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
	Brought Forward					11,07,771 ·74	406,43,37,414 · 32	309,82,38,583 · 79
(c)	Sundry Advances	.,				78,55,059 -25		9,29,088 ·61
(d)	Interest accrued on debentures			-	•	11,44,01,897 91	•	8,35,15,027 -25
(e)	Interest accrued on loans by way	of refi	nance			1,51,50,880 -33		75,53 486 -50
(f)	Discount on ARC Bonds					31,51,500 .00		•
							14,16,67,109 -23	9,28,69,168 · 39

Total 420,60,04,523 - 55 319,11,07,752 - 18

R. K. HAZARI

Chairman

B. S. VISHWANATHAN M. R. PATEL C. D. DATEY

Directors

M. A. CHIDAMBARAM Managing Director

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

												Previous Year
,											Rs. P.	Rs. P.
1.	Interest paid									V 1	16,22,04,806 -83	11,34,20,889 ·45
2.	Salaries and Allowances		, ,								93,27,112 - 28	65,20,378 -40
3.	Contribution to Staff Pro	vident,	Pensi	on a n d	other	Funds					7,63,027 ·81	6,01,511 -38
4.	Directors' and Committee	e Memi	ers' I	-ces						••	1,100.00	1,500 -00
5.	Travelling and other a Members' Meetings	llowanc	es in	conne	xlon 	with D	irector	s' and	Comn	nittee	20,973 -00	18,160 -00
6.	Rent, Rates, Insurance, I	_ighting	etc.								8,03,697 -54	6,81,595 -87
7.	Travelling Expenses										7,31,761 ·69	4,86,796 -88
8.	Printing and Stationery			• •							2,37,301 -44	1,73,018 -58
9.	Postage, Telegrams and	Telepho	nes							• •	1,94,272 ·14	1,53,988 -25
10.	Repairs to Property	••		• •		• •		• •	••		23,160 ·18	11,552 -24
11.	Auditor's Fees										10,000 -00	10,000 -00
12.	Legal Charges										9,899 -76	17,353 -59
13.	Miscellaneous expenses (Note 1)				• • •					28,09,281 -59	22,55,375 -69
14.	Depreciation	• •			••				• • •	••	1,20,000 -68	93,747 -01
15.	Transfer to Special Rese	rve beir	ig 10 9	% of th	e curr	ent pro	fit in te	rms of	the Fi	nance	45,00,000 .00	31,00,000 -00
16	Provision for Taxation										2,30,41,923 00	1,60,18,595 -38
1 7.	Net Profit carried to Bala				••	•				.,	1,66,23,173 97	1,17,51,206 ·88
		Total			• •	4.					22,14,21,491 ·91	15,53,15,669 -60

Notes: 1. Includes: (i) stamp duty on Bonds and Shares and (ii) Bond Discount on VII and VIII series	• •	Rs. Rs.	19,80,333 ·25 1,48,500 ·00
2. Includes discount received on debentures subscribed to		Rs.	37,790 -55

K. R. Subrahmanyan

Senior Director

Finance & Administration

Bombay 19 August 1975

As per our Report of even date attached

N. M. Rahi & Co.

Chartered Accountants

FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 1975

						Previous	Year
		Rs.	Р.	Rs.	P.	Rs.	Ρ.
1.	Interest Received						
	(a) On loans and debentures	21,14,69,03	5 · 49			14,98,76,6	523 -9
	(b) On investments (Tax deducted at source Rs. 43,21,348.00)	9 3,81,5 6	3 -65			53,70,3	16 -19
	_			22 13,50,599	·14	15,52,40,5	40 ·10
	Discount, Commission, etc				-		
	Discount, Commission, etc				-		
			_		_		2.00
	Other items (a) Share Transfer Fees	38,117	<u> </u>		_	31,0	
2.	Other items (a) Share Transfer Fees	38,117 32,774			-		2 ·00 26 ·76 00 ·74

Total 22,14,21,491 -91 15,53,15,669 .60

R. K. Hazart

Chairman

B. S. Visirwanathan M. R. Patel C. D. Datey

Directors

Bombay, 19 August 1975

M.A. CHIDAMBARAM

Managing Director

•		
·		
•		